राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का सत्ताईसवां दिवस [संख्या: 12

सोमवार,

07 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

43. **श्रीमती संतोष** (अनूपगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कितने उप स्वास्थ्य व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के केन्द्रों में चिकित्सकों, मेल नर्स व गायनिक चिकित्सकों व ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से एवं कितने-कितने पद रिक्त हैं? केन्द्र के स्थान सहित रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 60 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित केन्द्रों में चिकित्सकों, गायनिक चिकित्सक, नर्स श्रेणी प्रथम, नर्स श्रेणी द्वितीय एवं ए.एन.एम. के रिक्त पदों का केन्द्रवार एवं पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को पी.जी. पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव शीघ्र भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी (दंत) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर यथासम्भव भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों को भविष्य में होने वाली पदोन्नति से तथा नर्स श्रेणी द्वितीय एवं ए.एन.एम. के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर यथासम्भव भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने के लिए बार-बार आग्रह किया गया है, लेकिन प्रश्न के जवाब में यथासम्भव भरने की सूचना ही दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि इन पदों को यथासम्भव कब तक भरा जायेगा?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जब सवाल लगाया, उसके बाद मैंने वहां पर चार चिकित्सक लगाये हैं। एक गायनिक का एवं तीन और लगाये हैं। एक नाहरावाली पीएचसी में लगाया है और तीन अनूपगढ़ में लगाये गये हैं। जब भी हमारे पास पीजी पूर्ण करके चिकित्सक आयेंगे, उनमें से प्राथमिकता से इनके विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में लगाने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सदस्य, एक मिनट। वे जॉइन नहीं कर रहे हैं, ऐसी समस्या पहले भी आयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या बैठें। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, चाहे सरकार आपकी रही हो या सरकार हमारी रही हो, यही उत्तर आता है। दुर्भाग्य यह है कि सदस्य इसलिये दुःखी होकर पूछता है कि उसके यहां पर 31 पद स्वीकृत हैं, उनमें से केवल 16 पद भरे हैं और 15 खाली हैं। उसके दर्द का शब्दों में चयन न करके कोई स्थायी हल करने के लिए सरकार को पुख्ता व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिये। नये आगे बढ़ने से पहले एक बार जो हैं, उनको हम स्ट्रेन्थन कर दें, ताकि लोगों को राहत मिले।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा कि 31 पदों में से 15 रिक्त हैं और 16 लगे हैं तो निश्चित रूप से यह चिन्ता का विषय है। अभी हमने एक प्रयास किया कि कई जगह पर एक्सेस लगे हुए हैं। 40 की जगह पर 70 लगा रखे हैं

(श्री परसादी लाल)

और 20 की जगह पर 40 लगा रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने प्रयास किया है कि वे जो वेतन आहरण कर रहे हैं, उस पर हमने प्रतिबन्ध लगाया है और एक्सेस चिकित्सकों को वेतन नहीं देंगे। नौकरी करेंगे जयपुर में, वेतन लेंगे नाथद्वारा से, सीकर या हनुमानगढ़ से। उस चीज को हमने प्रतिबन्धित किया है। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्या कह रही थीं कि कइयों ने जॉइन नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं कि उनको जॉइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी नौकरी भी चली जाये तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हम सख्ती से इस चीज को करेंगे। जिसकी जहां पर ड्यूटी है, वहां पर वह डाक्टर रहे और वहां पर काम करे। यह जो कार्य व्यवस्था या डेपुटेशन है, उसको मैंने आने के बाद समाप्त कर दिया है। इसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं, आपके सहयोग से उसको भी दूर करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पहले भी कई बार ये प्रयोग हुए हैं, लेकिन दबाव के कारण से हर बार हम फेल हो गये। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अगर इसका अक्षरशः पालन हुआ तो राजस्थान की जनता आपको दुआएं देगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गिरधारीलाल।

बीकानेर, सीकर व श्रीगंगानगर जिलों में डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान

44. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वित्तीय वर्ष 2021-22 में बीकानेर, सीकर व श्रीगंगानगर जिलों में कुल कितने डिग्गी (POND) स्वीकृत किये गये? जिलेवार स्वीकृत व अनुदानित राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वित्तीय वर्ष में स्वीकृत डिग्गी (POND) के कितने काश्तकारों का अनुदान बकाया है? सरकार उक्त को अब कब तक बकाया का भुगतान करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इकाई लागत बढ़ने के कारण सरकार उक्त अनुदान की राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह जनवरी, 2022 तक कृषि विभाग द्वारा बीकानेर, सीकर व श्रीगंगानगर जिलों में कुल 2 हजार 970 डिग्गी एवं 737 फार्म पौण्ड स्वीकृत किये गये हैं

(कृषि मंत्री)

तथा उद्यान विभाग द्वारा बीकानेर, सीकर व श्रीगंगानगर जिलों में 24 सामुदायिक जल स्रोत एवं 01 एकल फार्म पौण्ड स्वीकृत किये गये हैं। जिलेवार स्वीकृत व अनुदानित राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह जनवरी, 2022 तक कृषि विभाग द्वारा उक्त जिलों में स्वीकृत 2 हजार 970 डिग्गियों में से कृषकों द्वारा विभागीय दिशा निर्देशानुसार पूर्ण निर्मित 600 डिग्गियों का भुगतान किया जा चुका है एवं स्वीकृत 737 फार्म पौण्ड में से पूर्ण निर्मित 381 में से 346 का भुगतान किया जा चुका है व 35 फार्म पौण्ड का अनुदान भुगतान प्रक्रियाधीन है।

उद्यान विभाग द्वारा स्वीकृत 24 सामुदायिक जल स्रोतों एवं 01 एकल फार्म पौण्ड का भुगतान कृषकों द्वारा कार्य अभी तक पूर्ण नहीं करने के कारण बकाया है।

जिलों में उक्त वित्तीय वर्ष में स्वीकृत डिग्गी, फार्म पौण्ड व जल स्रोतों में शेष रहे कार्यों का कृषकों द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

(3) भारत सरकार के स्तर से योजना के दिशा-निर्देशों में अनुदान प्रावधान में बदलाव करने पर कृषकों को देय अनुदान में परिवर्तन किया जा सकेगा। कृषि विभाग द्वारा जिलों से इकाई लागत में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव लिये जा रहे हैं, जिनके विश्लेषण उपरान्त राज्य से भी भारत सरकार को इस हेतु प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में विचार कर लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही जानना चाहूंगा कि नहरी और बारानी क्षेत्र में 2 लाख और 90 लाख दे रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकार हिस्सा राशि बढ़ाने की मंशा रखती है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है। भारत सरकार की गाइडलाइन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यह बात सही है कि नहरी क्षेत्र और बारानी क्षेत्र में अनुदान में अन्तर है। हमने भारत सरकार को 3 नवम्बर, 2021 को एक पत्र लिखा है, जिसकी कापी मेरे पास है। मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए विश्वास दिलाऊंगा कि हम दूसरा पत्र शीघ्र लिखेंगे और भारत सरकार की गाइडलाइन में यदि परिवर्तन होगा तो हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि उनके बदलाव के बाद इसमें परिवर्तन हो।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें आपने जो परिशिष्ट-1 लगाया है, उसमें उद्योग विभाग का है। उसमें आपने लिखा है कि इन चार जिलों में सामुदायिक जल स्रोत 24 स्वीकृत किये थे और इनकी प्रशासनिक स्वीकृति आपने दे दी है, वित्तीय स्वीकृति नहीं दे पाये। फार्म पौण्ड में भी आपने एक की प्रशासनिक स्वीकृति दी, पर वित्तीय स्वीकृति नहीं दे पाये। प्रशासनिक स्वीकृति कब देते हैं और उसमें ऐसी क्या अड़चन आती है कि वित्तीय स्वीकृति नहीं दे पाते हैं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनमें कुछ में तो स्वीकृति जारी हुई है जिनका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। प्रश्न लगने के बाद कुछ रिकार्ड में आया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। जैसे बीकानेर जिले में शेष रहे 35 फार्म पौण्ड में 25 फार्म पौण्ड की राशि 18 लाख 72 हजार का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। शेष फार्म पौण्ड का भी राज्य मद से देय राशि 1 लाख 14 हजार रुपये है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, उद्यान वाला बतायें। पार्ट-बी वाला, जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति तो दे दी, पर वित्तीय स्वीकृति जीरो है।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): उद्यान विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन में सामुदायिक जल स्रोतों के विकास हेतु कृषक समूह द्वारा 10 हैक्टेयर क्षेत्र के कमाण्ड क्षेत्र में..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप क्या बता रहे हैं।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): मैं योजना के बारे में बता रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप वित्तीय स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका क्या कारण है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): वित्तीय स्वीकृति के लिए हमने थोड़ा प्रावधान किया है। जुलाई में जो भारत सरकार की मद से पैसे आते थे, उनके एकाउंट चेंज कर दिये गये हैं। उसमें अब बैंक भी चेंज हो गया, अब बैंक आफ बड़ौदा हो गया । बैंक की भी दिक्कत है और खातों की भी दिक्कत आ रही है। यह बात भी हमको परसों पता चली है। अभी हाल ही में उन्होंने बैंक आफ बड़ौदा को एकाउंट दे दिया। जो भारत सरकार की जुलाई में नयी गाइडलाइन आयी है। उसमें हर योजना के अलग खाते खुलवाये हैं, उसके कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसकी पूरी जानकारी लेकर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अविनाश।

जैतारण में परिवहन निगम की बसों का संचालन

45. श्री अविनाश (जैतारण): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित नहीं हो रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार जैतारण से मेड़ता रूट व जैतारण से वाया निम्बोल, मेड़ता रोड तक परिवहन निगम की बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कोरोनाकाल में प्राइवेट बसों के बन्द हो जाने के कारण उनको हुए नुकसान की भरपाई हेतु कोई टैक्स में छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निम्न समयानुसार बसें संचालित हैं :-

क्र. सं.	मार्ग	समय	जुड़े हुए गांवों के नाम
1	पाली-बूंटीवास	14.00	गरनिया, बांजाकुडी, घोडावड, बलाडा, टूकडा, बूंटीवास
2	पाली-बाबरा	13.30	बर, बिराटिया, गिरी, बूंटीवास, रास, बाबरा

निगम के सीमित संसाधनों के कारण जैतारण से मेड़ता व जैतारण से वाया निम्बोल, मेड़ता रोड तक फिलहाल निगम बस संचालित किये जाने का कोई विचार नहीं है।

(2) कोरोना काल में प्राइवेट बसों के बंद हो जाने के कारण उनको हुये नुकसान की भरपाई हेतु टैक्स में छूट देने के संबंध में विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.06.2020, 11.08.2020 एवं 04.08.2021 जारी की गई है, जिनकी प्रति परिशिष्ट-1, 2 व 3 पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा विधान सभा क्षेत्र होने के बाद भी माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, सिर्फ दो बसें

(श्री अविनाश)

संचालित हैं विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, पाली बूंटीवास और पाली से बाबरा। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन रहेगा कि इससे पहले भी...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए, माननीय।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं वही पूछ रहा हूं। इससे पहले जैतारण से बिरोल, डिगरणा-बोरूंगा तक, जैतारण से मेड़ता रूट पर, करमावास से पाटवा होते हुए जोधपुर तक और कानूजा बगड़ी कलाल होते हुए ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें पूर्व में निगम की बसें संचालित थीं। क्या कारण है कि वह बसें बन्द कर दी गयीं? एक तो सवाल यह है। दूसरा मेरा सवाल यह रहेगा कि माननीय मंत्री महोदय ये बताएं कि इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद में क्या सिर्फ दो बसें ही संचालित होने से, जहां तीन लाख वोटर हैं, पांच लाख की आबादी है मेरे विधान सभा क्षेत्र की तो दो बसों में लोगों का आना-जाना पर्याप्त है? मुझे इसका उत्तर बताएं?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, कुछ बस सर्विस तो कोरोना काल में बन्द की गयी हैं, जो तीन रूट पर बन्द की गयी हैं। अब स्थिति सामान्य हो रही है, हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। कुछ बसें इसलिए बन्द की गयी हैं कि यात्रीभार कम था और रोडवेज की जो आय हो रही थी, खर्चा उससे चार गुना अधिक हो रहा था, इसलिए बन्द की गयी थीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही हमारी तरलता की स्थिति ठीक होगी, आप मुझे दे देना जो जरूरी बसें हों, हम उस पर पूरी तरह विचार कर लेंगे।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं प्लीज, नॉट अलाउड। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

प्रश्न संख्या 46

अगला प्रश्न। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल।

जल जीवन मिशन योजना में स्वीकृत बजट

47. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना में अब तक केन्द्र सरकार व राज्य सरकार ने कितना बजट स्वीकृत किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(2) कोटा संभाग में उक्त मिशन के तहत हर घर तक नल पहुंचाने के लिए कितने कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था व अब तक कितने कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में उक्त संभाग में कितना बजट व्यय किया गया एवं कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हु आ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 (दिनांक 31.01.2022 तक) की अवधि में रुपये 4,027.30 करोड़ की हिस्सा राशि राज्य सरकार को अब तक जारी की गई है।

उक्त मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उक्त वर्णित अवधि में रुपये 3,225.34 करोड़ की राशि का बजट स्वीकृत किया गया।

वर्षवार राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कोटा संभाग के कोटा, बून्दी, बारां एवं झालावाड़ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत क्रियाशील घरेलू जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वृहद् पेयजल परियोजनाओं एवं इन परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य जल योजनाओं में घर-घर जल सम्बन्ध जारी करने हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं दिनांक 06.02.2022 तक जारी किये गये जल संबंधों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जल जीवन मिशन के अंतर्गत कोटा संभाग के उक्त वर्णित जिलों हेतु 30 वृहद् पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृति के विरुद्ध 17 परियोजनाओं तथा 359 अन्य जल योजनाओं की स्वीकृति के विरुद्ध 332 जल योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश अब तक जारी किये जाकर, वृहद् पेयजल योजनाओं अंतर्गत रुपये 924.33 लाख एवं अन्य जल योजनाओं अंतर्गत रुपये 4,216.53 लाख, इस प्रकार कुल 5,140.86 लाख का व्यय माह जनवरी, 2022 तक किया गया है।

इस प्रकार वृहद् पेयजल परियोजनाओं अंतर्गत 0.12 प्रतिशत तथा अन्य जल योजनाओं अंतर्गत 8.35 प्रतिशत वित्तीय प्रगति रही है। संभाग की उक्तानुसार शेष रही परियोजना/अन्य योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति/निविदा संबंधी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर इनका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन योजना, 2019-2020 से चालू है। उसकी अभी तक जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वह एक परसेंट से भी नीचे है। क्या 2024 तक इस योजना को हम समयबद्ध रूप से पूरा कर सकेंगे?

प्रश्न नंबर 2, चूंकि राजस्थान में फ्लोराइड पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी की जो मंशा है, जल जीवन मिशन के तहत घर पर जो कनेक्शन देने का है कि लोगों को बीमारी से मुक्ति मिले।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): जहां पर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, क्या वहां पर पहली प्राथमिकता के आधार पर जल जीवन मिशन योजना के तहत घर-घर कनेक्शन देने की कार्ययोजना प्रारम्भ करेंगे?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने एक नई योजना के तहत काम शुरू किया है। हम तीन-तीन महीने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हमारी कोशिश है, यह निश्चित बात है, माननीय सदस्य ने सत्य कही है कि हमारी इस योजना की जो प्रगति है, वह शुरू में काफी धीमी रही। लेकिन पिछले लगभग दस महीने से हम लोगों ने इस योजना की प्रगति को काफी तेज करने की कोशिश की है। हम उम्मीद करके चलते हैं कि अगर सारी परिस्थितियां ठीक रही तो हम अपने लक्ष्य को हासिल करने का जो 2024 का लक्ष्य है, उसको पूरा प्रयास करेंगे।

जहां फ्लोराइड की मात्रा या पेयजल बिलकुल इस तरीके का उपलब्ध नहीं है, हम नवाचार भी कर रहे हैं। जहां फ्लोराइड की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है या कोई नवाचार करके पेयजल ठीक ढंग से उपलब्ध कराया जा सकता है तो उस तरफ भी हमारी कोशिश है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि फ्लोराइड और क्वालिटी एफेक्टेड हैबिटेशन को प्रायोरिटी में लिया जायेगा। साथ ही जो मैंने सैंक्शन की बात की है, वर्ष 2021 तक हमने काफी जो मैं बात कह रहा हूं कि इस जल जीवन मिशन को हम एक त्वरित गति से आगे बढ़ाएंगे। हमने काफी सैंक्शन इसमें 2021 तक निकाल दी हैं और योजनाबद्ध तरीके से हम इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैं एक कमेंट करना चाहता हूं इस

(श्री अध्यक्ष)

पर, जल जीवन योजना, राजस्थान में एक परसेंट पानी है, जब तक आप जल जीवन को इर्रिगेशन के साथ जोड़कर सतही पानी बरसात का रोकने का नहीं करेंगे तब तक हम घर-घर कनेक्शन दे दें, पानी एश्योर नहीं कर पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि विभाग पहले यह एश्योर करे कि हमारे पास इतना पानी उपलब्ध है, जितने पानी से हम कनेक्शन दे सकें। तब तो इस योजना का लाभ मिल पाएगा अन्यथा पहले भी जितनी योजनाएं बनीं, उस योजना का हश्र यह होगा कि हमने कनेक्शन दे दिए, सोर्स हमारा आगमेंट नहीं हुआ तो हम पूरे पानी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इर्रिगेशन डिपार्टमेंट और पी एच ई डी डिपार्टमेंट दोनों बैठकर भारत सरकार से पी.एच.ई.डी. का पैसा इर्रिगेशन के सतही बांध बनाने के लिए ईयर मार्क करावें तब जाकर इफेक्टिवली आपकी योजना लागू होगी। इस पर गंभीरता से जरूर निर्णय करें।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी..

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, कटारिया जी कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, ये तो हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पानी है। ये कोटा डिवीजन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हमने फिगर पढ़े हैं उस हिसाब से केन्द्र ने आपको पहले साल में 1,300 करोड़, दूसरे साल में 2,500 करोड़ और तीसरे साल में 10 हजार करोड़ रुपया दिया है, ऐसा अलाटमेंट आपको हुआ है। उसके तहत आपने केवल 4 हजार करोड़, मतलब 13 हजार की जगह 4 हजार करोड़ ही क्यों केन्द्र से मिला, इसका क्या कारण रहा जिसके कारण से केन्द्र से ये पैसा उठा नहीं सके?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहले तो जो आपने सुझाव दिया, मैं समझता हूं एक बहुत व्यावहारिक और उचित सुझाव है। कल भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारी पी.एच.ई.डी. की रिव्यू मीटिंग की थी, उसमें जल संसाधन मंत्री को और जल संसाधन सचिव महोदय को बुलाकर गंभीरता से चर्चा की, जिस तरफ आपने इंगित किया है। इस तरफ हमारी कोशिश है कि ऐसा नहीं हो, नल लगे रह जाएं और उनके अन्दर पानी न आए। यह हम सबकी चिन्ता है। उधर भी चिन्ता है और इधर भी चिन्ता है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे जहां नल लगे हैं, वहां पानी

(डा. महेश जोशी)

अवश्य आये। इस तरफ के वाटर रिजर्वेशन के लिये भी, हम निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। हमारी कल भी मीटिंग हुई थी। जेजेएम में अब तक हमने 5,081 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष महोदय को यह आश्वस्त करना चाहता हूं। मैंने खुद स्वीकार किया कि हमारी गति शुरू में धीमी रही। उसके बहुत सारे कारण हैं। हम उस गति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी चिन्ता हमारे लिये निश्चित रूप से एक चुनौती के रूप में है। हम जो पैसा कम खर्च पाये हैं, उस पैसे को हम अब तेज गति बढ़ाकर, मैंने जो आपको निवेदन किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको इस बारे में कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। हमारी जो योजना बनी है, उस योजना से आप भी सन्तुष्ट हो पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, वाटरशैड डिपार्टमेंट, इर्रिगेशन डिपार्टमेंट और पीएचईडी डिपार्टमेंट, तीनों मिशन मोड में आकर काम नहीं करेंगे तो हम इस व्यवस्था को नहीं कर पाएंगे। सरकार गम्भीरता से सोचे कि क्या हम मिशन मोड में वाटरशैड डिपार्टमेंट, इर्रिगेशन डिपार्टमेंट और पीएचईडी डिपार्टमेंट तीनों के साथ बैठकर, कितना पानी उपलब्ध है, हम कितना पानी बरसात का सिंचित कर सकते हैं, कितना हम ऑगमेंट कर सकते हैं, इस तरह से पूरी व्यवस्था मिशन मोड में नहीं करेंगे, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से, मैं समझता हूं कि पीने के पानी का जो अलग से है, वह पूरे रूप में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसमें गम्भीरता से सोचेंगे।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश को शिरोधार्य करते हुए इस बारे में शीघ्र ही हम मीटिंग रखकर, इस बारे में विचार करके एक योजना बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप सिंह।

बारां में जनजाति क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के लाभार्थी

48. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां के जनजाति क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु जनवरी, 2019 से फरवरी, 2022 तक संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विधान सभा क्षेत्र छबड़ा का वर्षवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री प्रताप सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ज़िले में उक्त अवधि में जनजाति बहुल क्षेत्रों में सरकार द्वारा विद्यार्थियों की कोचिंग, शिक्षा व छात्रवृत्तियों के वितरण में भेदभाव किया गया है? यदि हां, तो क्यों? लम्बित प्रकरणों का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि बारां ज़िले में जनजाति क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु जनवरी, 2019 से फरवरी 2022 तक संचालित विभागीय योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया है। बारां ज़िले के जनजाति क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु सहरिया, माडा, माडा क्लस्टर एवं बिखरी क्षेत्र अन्तर्गत योजनाएं संचालित की जा रही हैं। संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से फरवरी, 2022 तक लाभान्वितों की सूचना परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि जिला बारां में जनजाति बहुल क्षेत्रों में विद्यार्थियों की कोचिंग, शिक्षा व छात्रवृत्तियों के वितरण में उक्त अवधि में भेदभाव किया गया है। माडा, माडा क्लस्टर एवं बिखरी योजना के अंतर्गत जनवरी, 2019 से फरवरी, 2021 तक जिला बारां में कोई आवेदन पत्र लम्बित नही है। वर्ष 2021-22 में फरवरी, 2022 तक शैक्षिक प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 186 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिन्हें जिला परिषद् स्तर पर निस्तारित करने की कार्यवाही की जा रही है। माडा, माडा क्लस्टर एवं बिखरी योजना के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

जिला बारां के सहरिया क्षेत्र में "महाविद्यालय स्तर के छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता योजना के अतिरिक्त अन्य किसी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 के कोई आवेदन लम्बित नहीं है। वर्ष 2019-20 में महाविद्यालय स्तर के छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता योजना में 1,074 छात्र-छात्राओं के प्राप्त आवेदनों में से 570 को लाभान्वित कर दिया गया है। शेष रहे 504 छात्र-छात्राओं को भी शीघ्र ही लाभान्वित कर, निस्तारित किया जाएगा। सहरिया क्षेत्र में लम्बित प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-"द" पर संलग्न है।

वर्ष 2021-22 हेतु ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी, 2022 तक प्राप्त किये जाकर निस्तारण की कार्यवाही की जावेगी।

(सूचना एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में जो इलाका जनजाति बहुल क्षेत्र है, एसटी के लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर पेयजल, बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, श्रम एवं नियोजन, रोजगार, सौर ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, राजस्व, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, सहकारिता, सामाजिक न्याय...

श्री अध्यक्ष: डिमाण्ड पर बोल रहे हैं कि प्रश्न पूछ रहे है?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैं सवाल पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता इत्यादि विभागों की वर्ष 2019 से अब तक की विभागवार, वर्षवार, निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों की प्रगति रिपोर्ट से अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, आप राइटिंग में लिखकर भेजें, जब आयेगा। प्रश्न लिखा हुआ है, उसमें सप्लीमेंट्री पूछो। ऐसे नहीं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): वह ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। यह कहां लिख रहे हैं। नया प्रश्न पूछ रहे हैं, यह लिखा हुआ नहीं है। आप सीनियर मैम्बर है। आपने जो प्रश्न पूछा है, सप्लीमेंट्री पूछें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): लिखा हुआ पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, गलत बात। No. I am not allowing you. नैक्स्ट प्रश्न।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): लिखा हुआ पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: गलत बात।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): साहब, इसको पूछने तो दो, जरूरी है।

श्री अध्यक्ष: कहां पूछ रहे हैं आप? आपने प्रश्न पूछा, प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है। प्रिंटेड प्रश्न है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 1,074 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलनी थी, 570 को दी है, 504 बाकी है, उनको कब तक दे दी जायेगी?

श्री अध्यक्ष: बस, धन्यवाद। अब आप बैठो। पहले इसका जवाब आने दो। आपने पूछा उसका जवाब आने दो।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): बेरहम..

श्री अध्यक्ष: हुकम, बेरहम नहीं, बहुत रहमशील हैं। आप बैठो, उसका उत्तर आ रहा है। (व्यवधान) बेरहम तो पूरे ही बेरहम हैं। अगला प्रश्न। बैठो भई, मंत्री जी। बेरहम हो रहे हैं, तो पूरे ही हो रहे हैं। अगला प्रश्न। गोपाल शर्मा। ...(व्यवधान) आपने बेरहम ही कह दिया, बाकी बचा क्या अब?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप जितना रहम दिल ...(व्यवधान) आप जितना रहम दिल कोई है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: मान्यवर, कोई वकील की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप बड़े रहम दिल हैं।

श्री अध्यक्ष: कोई वकील की जरूरत नहीं है। आप बैठिये। अगला प्रश्न। (व्यवधान)

मान्यवर, कोई वकील की जरूरत नहीं है, आप बैठो। जहां वकालत करनी है, वहां तो करते नहीं हो, मेरे सामने वकालत कर रहे हैं। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वह जगह बता दो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको भी मालूम है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। अगला प्रश्न।

माण्डलगढ़ की किसान सहकारी समितियां

49. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की पांच किसान सहकारी समितियों को ग्राम सेवा सहकारी समिति में हस्तान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त समितियों में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या सरकार द्वारा इनके सभी लाभांश रोक रखे हैं? यदि हां, तो सरकार अब कब तक देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त समितियों का ऋण माफी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में 2 एफएसएस यथा कोटड़ी एवं सिंगोली चारभुजा कृषक सेवा सहकारी समिति है। एफएसएस को ग्राम सेवा सहकारी समिति में हस्तान्तरण करने सम्बन्धी प्रावधान राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 एवं नियम, 2003 में नहीं होने के कारण ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) कोटड़ी एफएसएस में 12 कर्मचारी हैं तथा सिंगोली चारभुजा एफएसएस में 5 कर्मचारी हैं। सरकार द्वारा इनके लाभांश नहीं रोके गये हैं।

(3) राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण माफी होने पर उक्त एफएसएस की ऋण माफी सम्भव होगी।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो एफएसएस हैं, बाकी सभी जीएसएस हैं। पूरे विधान सभा क्षेत्र में सबका लोन माफ हुआ। एफएसएस की समितियां हैं, उनमें अब तक लोन माफ नहीं हुआ। क्या सरकार सभी किसानों को समान रूप से लाभ देना चाहती है या नहीं देना चाहती?

दूसरा मेरा क्वेश्चन है। जो भी नियम हैं, राज्य सरकार नियम बनाती है, क्या सरकार उन समितियों के लिये नियम नहीं बनाना चाहती? मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ किसानों को लाभ नहीं देना चाहती? सबका कर्जा माफ हुआ, मेरे उस क्षेत्र में कर्जा माफ नहीं हुआ।

तीसरा क्वेश्चन है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण माफी, आम किसानों को यह पता ही नहीं होता है कि जीएसएस व एफएसएस में कौनसे बैंक से लोन मिलता है, मंत्री जी, आप अध्यक्ष महोदय की मार्फत बताये?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन बिन्दु उठाये, उनका जवाब मैं दे चुका हूं। पुन उन्हीं बिन्दुओं को वापस उठाकर बता रहे हैं। उत्तर में यह सब आ चुका है जो इन्होंने वापस पूरक प्रश्न किये हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: जवाब है ही नहीं, तो क्या देंगे। बैठो आप। श्री रामलाल शर्मा।

खाद्य सुरक्षा योजना की विचाराधीन अपीलें

50. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने हेतु अपीलीय अधिकार उपखण्ड अधिकारी को दिया गया है? यदि हां, तो उपखण्ड अधिकारी चौमूं के पास वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक कितनी अपीलें दर्ज हुई व अपील के निर्णयानुसार कितने नाम जोड़े गए तथा कितनी अपील अस्वीकार की गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर विगत 2 वर्षों से नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। उपखण्ड अधिकारी चौमूं के पास वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक 9,907 (नौ हजार नौ सौ सात) अपील प्राप्त हुई जिनमें से 7,381 (सात हजार तीन सौ इक्यासी) आवेदनों के नाम जोड़े गये तथा 828 (आठ सौ अट्ठाईस) अपील अस्वीकार की गई।

(2) भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। प्रदेश में चयनित लाभार्थियों की संख्या अधिक होने पर भारत सरकार को समय-समय पर सीलिंग सीमा में वृद्धि किये जाने हेतु पत्र लिखे गये। भारत सरकार द्वारा कवरेज में कोई भी संशोधन, अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद ही सम्भव होने के कारण वर्तमान में दिनांक 18.05.2020 से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि एक विधान सभा क्षेत्र में दस हजार अपील आती हैं, सरकार ने यह स्वीकार किया है कि दस लाख अपील प्रदेश के अन्दर विचाराधीन हैं और सरकार ने बजट में यह घोषणा भी की है कि इन दस हजार अपीलों को खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का काम हम करेंगे तो एक तो यह बता दें कि यह नाम किस महीने तक जुड़ जायेंगे।

दूसरा, यह है कि पिछले दस-पन्द्रह साल में कई ऐसे अपात्र व्यक्ति थे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Please be precise about Chomu. जनरल नहीं, प्रश्न पूछा है चौमूं का और अपन राजस्थान में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नहीं, मेरे यहां की बाकी की शेष अपीलें हैं उनको कब तक जोड़ देंगे, 873 जो अपीलें हैं?

दूसरा, मेरा यह पूछना है कि जो अपात्र व्यक्ति हैं, जो खाद्य सुरक्षा में शामिल हैं, क्या उनका नाम हटाने का आप कोई अभियान चलायेंगे?

तीसरा, मेरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक उपखण्ड के अन्दर कई अपात्र व्यक्ति भी खाद्य सुरक्षा की सूची में जुड़े हुए हैं। अपात्र सूची में जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम हटाकर और पात्र व्यक्तियों को जोड़ने के डाइरेक्शन उपखण्ड अधिकारियों को क्या आप जारी करेंगे?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपात्र व्यक्तियों के नाम की यदि इनके पास कोई सूची है तो ये उपलब्ध करवा दें। अपात्र व्यक्तियों के नाम काटे जा रहे हैं, आप बताएंगे तो। पात्र व्यक्तियों का जहां तक सवाल है, मई, 2020 में भारत सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया और राजस्थान सरकार को यह कह दिया कि आप 4 करोड़ 46 लाख लोगों का गेहूं उठाते हैं। हम जब 4 करोड़ 46 लाख लोगों का गेहूं उठाते हैं तो हमारे अधिकारियों ने सरकार की भावना वहां जाकर प्रस्तुत की और बताया कि हमारे यहां पर 30 लाख लोग ऐसे हैं जो नाम तो जुड़े हुए हैं तो आप उन 30 लाख लोगों के नाम की जगह संख्या निर्धारित कर लें, वे पात्र भी हैं, लेकिन वे जिस महीने लेने नहीं आते यह 30 लाख नाम के हम दूसरे लोगों को दे दें और हम आपको बता देंगे, यह तो ऑनलाइन है पूरा डिपार्टमेंट तो आप यदि यह अनुमानित जो गेहूं की संख्या हमको पूरी दे देंगे तो राजस्थान को फायदा होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की तरफ से आपके जरिये इन सबसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि 25 एम.पी. लेकर जायें और इसमें हमारी मदद करें। सात बार मुख्य मंत्रीजी पत्र लिख चुके हैं तो यह बड़ा काम हो जायेगा और सबके नाम जुड़ने शुरू हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अशोक लाहोटी।

सांगानेर में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की योजना

51. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के सांगानेर कस्बा, मानसरोवर, प्रताप नगर, पृथ्वीराज नगर, भांकरोटा क्षेत्र, गोपालपुरा बाईपास व दुर्गापुरा क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामनारायण मीणा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछना है।

श्री अध्यक्ष: जी नहीं के बाद प्रश्न क्या बचा है? आप बैठें। श्री रामनारायण मीणा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मेरे दो स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री है इनका।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने कहा है जी नहीं, मेरा तो प्रश्न बाकी है न।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वकालत की जरूरत ही नहीं है। यह बहुत स्पष्ट है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो क्वेश्चन ही आज लगा है और आज ही आप ऐसे कर रहे हो। सप्लीमेंट्री तो पूछने दो।

प्रश्न संख्या 52

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीना।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री बलजीत यादव। (व्यवधान) सप्लीमेंट्री बाद में पूछेंगे, जी हां, हो जायेगी जब। अभी तो बैठो आप। विराजो आप।

नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में धर्मकांटा हेतु भूमि का आबंटन

53. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र

(श्री बलजीत यादव)

में धर्मकांटा स्थापित करने हेतु भूमि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो कब व किसको? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि पर वर्तमान में धर्मकांटा स्थापित है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या रीको द्वारा उक्त भूमि का भू-रूपान्तरण कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) जी हां। यह सही है कि अलवर जिले के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में धर्मकांटा स्थापित करने हेतु दो भूखण्ड संख्या सीसी-7 व डब्ल्यूबी-1 का आबंटन क्रमश: दिनांक 20.11.2000 व दिनांक 17.08.2015 को मैसर्स इन्द्र कुमार व मैसर्स सीटीसी स्पीड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को किया गया है। आबंटन पत्र की प्रतियां परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न हैं।

(2) आबंटित भूखण्ड संख्या डब्ल्यूबी-1 पर वर्तमान में धर्मकांटा दिनांक 28.07.2018 से स्थापित है।

भूखण्ड संख्या सीसी-7 पर वर्तमान में धर्मकांटा स्थापित नहीं है। इस भूखण्ड संख्या सीसी-7 पर धर्मकांटा दिनांक 11.03.2014 को स्थापित कर लिया गया था, परन्तु वर्तमान में इस भूखण्ड पर बिना स्वीकृति होटल संचालित है। इस हेतु आबंटी को समय-समय पर नोटिस जारी किये गये तथा 45 दिवस की अवधि का अन्तिम कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.02.2022 जारी किया गया है।

परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। रीको द्वारा धर्मकांटा हेतु आबंटित भूखण्ड संख्या सीसी-7 का भू-रूपान्तरण होटल उपयोग हेतु नहीं किया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आप रीको के भूखण्ड अलग-अलग प्रयोजन के लिए देते हैं तो क्या कोई मॉनिटरिंग भी की जाती है या कोई चेक करने का कोई सिस्टम आपके है क्या? जैसे भूखण्ड इंडस्ट्री लगाने के लिए दिया तो कहीं पर मॉल बन गया, कहीं पर कुछ और बन गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें। आपका स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह इस प्रकार से भूखण्ड आप किसी और प्रयोजन के लिए देते हैं, और काम के लिए देते हैं और कोई दूसरा काम उस पर करता है तो इसको कण्ट्रोल करने के लिए आपने क्या उपाय कर रखे हैं या कोई उपाय करेंगे?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई भूखण्ड किसी इंवेस्टर को किसी पर्सनल एक पर्टीकुलर एक विभाग का नाम देकर, एक मैसर्स का नाम देकर जब भूमि आबंटित होती है तो फिर अगर उसका बिजनस नहीं चल रहा है तो वह उसको भूमि रूपान्तरण कर सकता है तो जो भी यह इस तरीके की भूमि आबंटित होती है उनकी टाइम टू टाइम जांच भी होती है और इसकी टाइमवार, डेटवार जांच के कागज संलग्न हैं, वे माननीय सदस्य को उपलब्ध भी करवा दिये गये हैं।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह भी जानना चाहता हूं कि मेरे नीमराना में बहुत से भूखण्ड ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न एक स्पेसिफिक पूछ रहे हो और आप जनरल पर जा रहे हैं। आप सीधा प्रश्न पूछिये कि इस प्लाट पर यह हो गया, इसकी क्या कार्यवाही हुई है? आप कहां जा रहे हो, समझ में नहीं आया मेरे को। दो प्लाट का पूछा है, एक प्लाट के बारे में लिखा है, आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): जवाब आ गया, साहब।

श्री अध्यक्ष: मान लिया आपने? बैठे रहें चुपचाप।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि हम नोटिस देते रहे हैं तो मैं लालच में आ गया था कि ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्लीज प्रश्न पूछें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं यह जानना चाहता हूं कि यह नोटिस देते रहे हैं तो इन नोटिस पर क्या कार्यवाही अब तक हुई है और क्या नोटिस देने का ही काम आपका विभाग करेगा या उस पर कोई कार्यवाही भी होगी?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): समय-समय पर नोटिस देने के बाद में जो मालिक है उसने अपनी एप्लीकेशन लगायी है लैण्ड चेंजिंग के लिए, लेकिन जब कार्यवाही कोई करते या उसको चेंज करते, उससे पहले ही

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक रिट पिटीशन लगा दी गयी, उसके कारण से वह कार्य वहीं पर, रुकावट उसमें आ गयी और जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आयेगा, वह उस आधार पर निर्णय करके कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बिहारीलाल।

नोखा के आयुर्वेद औषधालय का क्रमोन्नयन

54. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या बजट 2021-22 में आयुर्वेद औषधालय नोखा को ''ए'' श्रेणी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त आयुर्वेद औषधालय को ''ए'' श्रेणी में क्रमोन्नत कर पद सृजित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) (राज्य मंत्री, आयुर्वेद के स्थान पर): (1) जी हां। बजट वर्ष 2021-22 में आयुर्वेद चिकित्सालय, नोखा को ''ए'' श्रेणी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी जिसके क्रम में निर्देशानुसार नवीन पदों पर कार्य-व्यवस्थार्थ स्टाफ लगाया जाकर प्रारम्भिक रूप से चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा है।

इस संबंध में की गई बजट घोषणा की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

कार्य व्यवस्थार्थ लगाये गये कार्मिकों की सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

नोट-विभागीय चिकित्सालयों/औषधालयों के नवीन वर्गीकरण में ''ए'' श्रेणी चिकित्सालयों को राजकीय चिकित्सालय के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे आयुष नीति 2021 में ब्लाक आयुष चिकित्सालय के नाम से वर्गीकृत किया गया है। प्रति परिशिष्ट-''स'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। आयुर्वेद औषधालय को चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर पदों के सृजन की सहमति प्रदान की गई है। प्रति परिशिष्ट-''द'' पर संलग्न है।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि ''ए'' ग्रेड में क्रमोन्नत आयुर्वेद हास्पिटल, नोखा में 21 पद स्वीकृत हैं, वरिष्ठ चिकित्सक से लेकर परिचारक तक के,

(श्री बिहारीलाल)

पर मात्र दो का ही पदस्थापन है। एक डाक्टर का और एक नर्स का। 21 पद स्वीकृत हैं और केवल मात्र दो का ही पदस्थापन है और कार्य व्यवस्था के लिए आपने जो चार नाम लिखे हैं वे नोखा के ही दूसरे सेंटर्स से उठाकर लगा देंगे तो वहां काम भी प्रभावित होगा। इन 21 पदों की नियुक्ति आप कब तक कर देंगे?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि स्वर्गीय खूबचंद गट्टानी ट्रस्ट जिसने यह भूमि दान दी और पांच करोड़ रुपये बिल्डिंग पर लगाये, एम.ओ.यू. के तहत उनका नाम भी राजकीय आदेश में आना चाहिए था, वह क्यों नहीं आया? वह कब तक आप कर देंगे, मेरा माननीय आपसे यही आग्रह है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुरूप चिकित्सकों के पद भी स्वीकृत हो गये हैं पर यह सही है कि अभी वहां पर चार चिकित्सक और अन्य स्टाफ लगाया गया है और यह वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के ज्यों ही प्रमोशन होंगे तो वहां पर पदस्थापन कर दिया जायेगा। जमीन वगैरह के बारे में आपने जो जानकारी दी है, उसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, पर उसकी भी जानकारी करके निश्चित रूप से जो भी नियमानुसार होगा, वह कार्यवाही करने के लिए विभाग को निर्देश जारी करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

बामनवास में मिलावटी शराब के दर्ज प्रकरण

55. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विगत तीन वर्षों में अवैध शराब की तस्करी और मिलावटी शराब के कितने मामले दर्ज हुए? उक्त पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में कई धार्मिक स्थानों और विद्यालयों के पास शराब के ठेके संचालित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त नियम विरुद्ध संचालित शराब की दुकानों को बंद करवा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

आबकारी मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र

(आबकारी मंत्री)

बामनवास में उक्त अवधि में अवैध शराब की तस्करी और मिलावटी शराब का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1956 के नियम 75 के अनुसार धार्मिक स्थानों और विद्यालयों के लिये निर्धारित दूरी 200 मीटर की सीमा में जिला सवाई माधोपुर में कोई शराब का ठेका संचालित नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई गांव और कस्बों के अन्दर छोटी-छोटी ब्रांच खोलकर जो लोग चोरी से शराब बेचते हैं, उनके खिलाफ कई बार ग्रामीण इलाके के लोगों के द्वारा शिकायतें की जाती हैं, तो क्या आने वाले समय में उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, इस तरह की अवैध शराब की कोई जानकारी विभाग को नहीं मिली है और न कोई शिकायत मिली है। दूसरा, कहा कि अवैध और हथकढ़ जो है, उसके बारे में समय-समय पर कार्यवाही होती रहती है और उसमें कार्यवाही की गई है। जो कार्यवाही हुई अवैध और हथकढ़ के बारे में, वह पूरा विवरण माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दूंगा। जो मापदण्ड हैं, निश्चित रूप से उसके अनुसार अवैध शराब की दुकान सवाई माधोपुर में हमारी जानकारी में, विभाग की जानकारी में आज तक कोई भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर (पाली) में परिवहन कार्यालय का भवन निर्माण

56. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सुमेरपुर शहर में जिला परिवहन कार्यालय कब स्वीकृत हुआ? उक्त में कितने व कौन-कौन से पद स्वीकृत हुए? वर्तमान में उक्त कार्यालय कहां संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कार्यालय हेतु भूमि आबंटित कर भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कार्यालय खुलने के पश्चात् वाहनों की फिटनेस जांच

(श्री जोराराम कुमावत)

उक्त शहर में हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त जांच उक्त शहर में ही करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) विभागीय आदेश क्रमांक एफ.1(31)परि/स्था/2021/8776 दिनांक 11.05.2021 द्वारा सुमेरपुर उप परिवहन कार्यालय को नवीन जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। कार्यालय में स्वीकृत पद निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**पद का नाम**	**कुल स्वीकृत पद**
1.	जिला परिवहन अधिकारी	1
2.	परिवहन निरीक्षक	4
3.	परिवहन उप निरीक्षक	4
4.	लेखाकार (AAO-II)	1
5.	सूचना सहायक	4
6.	वरिष्ठ सहायक	2
7.	कनिष्ठ सहायक	4
8.	वाहन चालक	4
	सहायक कर्मचारी	2
	योग	**26**

वर्तमान में जिला परिवहन कार्यालय, सुमेरपुर पूर्व में संचालित उप परिवहन कार्यालय के भवन (राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के पास) में संचालित है।

(2) जी हां। जिला परिवहन कार्यालय सुमेरपुर हेतु भूमि आबंटन के लिए प्रस्ताव जिला कलेक्टर पाली के पत्रांक 4337 दिनांक 19.08.2021 द्वारा नगरीय विकास विभाग को भिजवाया गया है। प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। कार्यालय भवन हेतु भूमि आबंटन होने के बाद भवन निर्माण कराया जा सकेगा।

(3) जी नहीं। वर्तमान में फिजा 2018 के अनुसार जिन राजस्व जिलों में विभाग द्वारा अधिकृत निजी फिटनेस सेन्टर स्थापित हैं उन जिलों में परिवहन वाहनों की फिटनेस नवीनीकरण का कार्य अधिकृत निजी फिटनेस सेन्टर पर होता है। जिला परिवहन कार्यालय, सुमेरपुर, पाली राजस्व जिले के

(राज्य मंत्री, परिवहन)
क्षेत्राधिकार में आता है जहां पर अधिकृत निजी फिटनेस सेंटर संचालित होने के कारण जिला परिवहन कार्यालय सुमेरपुर में वाहनों की फिटनेस नहीं की जा रही है। वर्तमान में वाहनों की फिटनेस परिवहन कार्यालय स्तर पर किये जाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित नहीं है।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि सुमेरपुर में दस महीने पहले जिला परिवहन कार्यालय शुरू किया जिसमें 26 पद स्वीकृत हुए। 26 पदों में से कितने पद रिक्त हैं और कितने भरे हुए हैं तथा सरकार उनको कब तक भरेगी?

दूसरा प्रश्न, छह महीने पहले जिला कलेक्टर महोदय ने प्रस्ताव बना कर सरकार को भेजा भूमि आबंटन के लिए। सरकार कब तक जिला परिवहन कार्यालय हेतु भूमि आबंटन करेगी?

तीसरा प्रश्न, जिला परिवहन कार्यालय सुमेरपुर में खोला और फिटनेस 75 किलोमीटर दूर पाली में होती है तो सुमेरपुर में सरकार कब फिटनेस सेन्टर खोलेगी?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, भूमि आबंटन का जो प्रकरण है, वह नगरीय विकास विभाग की एम्पावर्ड कमेटी के पास विचाराधीन है। दूसरा जो आपने पूछा है कि कितने पद भरे हैं और कितने खाली हैं। 8 पद भरे हुए हैं और 18 पद खाली हैं। चूंकि कार्य का वर्कलोड इतना वहां नहीं है। वहां यह कार्यालय 18 अगस्त, 2021 को शुरू हुआ और तब से लेकर 10 फरवरी, 2022 तक सिर्फ 159 निजी वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं और 77 वाहन कामर्शियल वहां रजिस्टर्ड हुए हैं। ज्यों ही वर्कलोड बढ़ेगा, हम इसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। आपने फिटनेस सेन्टर के बारे में भी पूछा। पाली में एक फिटनेस सेन्टर है। सुमेरपुर के लिए दो एप्लीकेशन हमारे पास आयी हैं और गुण-दोष के आधार जल्दी ही उन पर निर्णय कर लिया जायेगा और हम कोशिश करेंगे कि सुमेरपुर में भी निजी अधिकृत फिटनेस सेन्टर चालू हो जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगसी राम।

रेवदर में क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत

57. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगसी राम)

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर में बांधों, नहरों के कारण भराव क्षमता में कब से कमी बनी हुई है? विगत पांच वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र के बांधों व नहरों की मरम्मत पर व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के बांधों व नहरों के जीर्णोद्धार फीडरों में सुधार की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर में जल संसाधन विभाग के अधीन निर्मित बांध, एम.आई.टी. एवं एम.एस.टी. की भराव क्षमता में 46 मीटर घन फुट की कमी हुई। यह कमी वर्ष 2017 की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त 5 एम.आई.टी. को पुन: निर्माण हेतु उपयुक्त/फिजिबल नहीं पाये जाने से हुई। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र रेवदर में जल संसाधन विभाग के अधीन बांधों एवं नहरों की मरम्मत पर विगत 5 वर्षों में किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) रेवदर विधान सभा श्रेत्र में जल संसाधन विभाग के अधीन बांधों, नहरों के जीर्णोद्धार/नवीनीकरण अंतर्गत वर्तमान में 03 कार्य स्वीकृत एवं प्रगतिरत हैं तथा 01 कार्य के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि एमआईटी- वरमाण, रामपुरा, पिथापुरा द्वितीय, धनपुरा और खाण के लिए 2017 का जो जिक्र आपने किया है, क्या इनका पुन: जीर्णोद्धार करवाने का विचार रखते हैं? नम्बर 2, पिछले दो सालों में विधान सभा क्षेत्र के अन्दर नये एनिकट और बांध कितने स्वीकृत किये हैं? नम्बर 3, विधान सभा क्षेत्र में भीलमगरा एनिकट के नाम से जाना जाता है वाडका में और एक कोरावाला एनिकट सरलेयाखेड़ा, क्या आप इनका भी एस्टीमेट बनवाकर नये सिरे से स्वीकृत करवाने का प्रयास करेंगे?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2017 में जो क्षतिग्रस्त हुए हैं वह वापस बनने की स्थिति में हैं ही नहीं, बिलकुल साफ हो चुका है। इसलिए विभाग का यह मानना है कि इसका

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है। दूसरा, वरमाण, रामपुरा, पिथापुरा द्वितीय के अन्दर जो काम हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो मैं बता सकता हूं कि इन पर कितना पैसा खर्च किया गया है। वरमाण की भराव क्षमता 10.14 एम.सी.एफटी. है और इसकी सीसी है है 80.94 हैक्टेयर। रामपुरा बांध के अन्दर 13.07 एम.सी.एफटी. है और इसकी सीसी है 105.22 हैक्टेयर। पिथापुरा द्वितीय का 8.23 एम.सी.एफटी. है और 64.75 हैक्टेयर इसकी सिंचाई का क्षेत्रफल है। आपने एक या दो एनिकट के बारे में पूछा है जिसका यहां पर जिक्र नहीं किया है, मैं विभाग से इसकी जानकारी लेकर अगर बनने की स्थिति में होंगे तो गुणावगुण के ऊपर इनको बनवाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्षों का हिसाब इन्होंने पूछा है, और पांच वर्षों में इसके रख-रखाव और मरम्मत के लिए लगभग 4 करोड़ 68 लाख रुपये आबंटित किया है 2017 से लेकर अब तक। परिशिष्ट "स" जो है, उसमें सब कार्यों में प्रगति हो रही है। मतलब कार्य पूर्णता किसी में भी नहीं है। अगर पांच वर्ष तक इस छोटे से अमाउण्ट को भी फाइनल रूप में भी नहीं ला सकता तो विभाग क्या कर रहा है?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय ने जो प्रश्न किया है, उसमें मेरा यह अनुमान है और मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रगतिरत है, उसको बहुत जल्दी पूर्ण करवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। संदीप शर्मा।

कोटा के श्रीनाथपुरम में नवीन फिल्टर प्लांट

58. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में कोटा शहर के किन-किन क्षेत्रों में 24 घण्टे जलापूर्ति हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त शहर को कितने शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है तथा उक्त के लिये कितने जल आपूर्ति संयंत्र कार्यरत हैं व उनकी क्षमता क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(3) क्या यह सही है कि उक्त शहर के श्रीनाथपुरम में नवीन फिल्टर प्लांट निर्माणाधीन है? यदि हां, तो उक्त पर कितनी लागत आयेगी एवं इसकी क्षमता क्या होगी तथा कब तक बनकर तैयार हो जायेगा व इससे कितना क्षेत्र लाभान्वित होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) कोटा शहर में 24 घण्टे पेयजल आपूर्ति वाले क्षेत्रों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) कोटा शहर की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 15 लाख (फ्लोटिंग जनसंख्या सहित) हेतु कुल 300 मिलियन लीटर प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता है।

सतही जल स्रोत चम्बल नदी से उक्त जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु अकेलगढ़ एवं सकतपुरा में क्रमश: 280 एवं 130, इस प्रकार कुल 410 मिलियन लीटर प्रतिदिन छनन क्षमता के 02 जल जलशोधन संयंत्र वर्तमान में निर्मित एवं क्रियाशील हैं तथा इन संयंत्रों से जल उपचारित किया जाकर स्वच्छ पेयजल वर्तमान में वितरित किया जा रहा है।

(3) जी हां। कोटा शहर के श्रीनाथपुरम में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा 50 मिलियन लीटर प्रतिदिन छनन क्षमता का नवीन जलशोधन संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य माह अगस्त, 2022 तक पूर्ण होना संभावित है।

उक्त जलशोधन संयंत्र के निर्माण एवं इससे संबंधित राइजिंग मुख्य लाइनों के कार्यों पर कुल रुपये 51.97 करोड़ की लागत आयेगी।

कोटा शहर स्थित मुख्य हैडवर्क्स अकेलगढ़ से वर्तमान पेयजल आपूर्ति वाले क्षेत्रों यथा अजय आहूजा नगर, विनोबा भावे नगर, गणेश नगर, मेडिकल कालेज, स्वामी विवेकानन्द नगर, आर.के. पुरम, ट्रांसपोर्ट नगर, विश्वकर्मा नगर, दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुभाष नगर, बालाजी नगर, आरोग्य नगर, श्रीनाथपुरम, राजीव गांधी नगर इत्यादि को उक्त निर्माणाधीन नवीन जलशोधन संयंत्र से जोड़कर पेयजल आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है एवं अकेलगढ़ पर शेष उपलब्ध पानी से कोटा शहर के अन्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में सुधार सम्भव हो सकेगा।

उक्त जलशोधन संयंत्र के चालू होने के उपरान्त नये कोटा शहर की लगभग 2.50 लाख की आबादी को लाभान्वित किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्षजी, मैं मंत्री महोदय

(श्री संदीप शर्मा)

से जानना चाहता हूं कि आपके जवाब के अनुसार 410 मिलियन पानी की उत्पादक क्षमता है और आवश्यकता 300 मिलियन लीटर जल की है तो यह जो शुद्ध जल है, वह कहां व्यर्थ बह रहा है? इसके कारण तथा उपायों के विषय में माननीय मंत्री महोदय बताएं तथा बिन्दु संख्या-2 में जिन लाभान्वित होने वाली कालोनियों के नाम बताये हैं, क्या उन क्षेत्रों में जो मल्टीस्टोरीज हैं, उनमें हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विचार रखते हैं?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 410 एम.एल.डी. पानी की जो आपूर्ति है, उसका पूरा विवरण मैं देना चाहूंगा कि वर्तमान आबादी 15 लाख हेतु जल मांग 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 300 एम.एल.डी., संस्थागत जल मांग 300 एम.एल.डी., राइजिंग मैन एवं वितरण पाइप लाइन छीजत 63 एम.एल.डी., औद्योगिक जल मांग 15 एम.एल.डी., मिलिट्री क्षेत्र की जल मांग 2 एम.एल.डी., कुल 410 एम.एल.डी.। इसके अलावा कोटा शहर में वर्ष 2037 की आबादी के अनुसार जल मांग और अधिक रहेगी। उसका भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग 19 लाख 50 हजार की आबादी की संभावना है, उसके लिये 310 एम.एल.डी., 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जरूरत पड़ेगी। संस्थागत जल मांग 39 एम.एल.डी., राइजिंग मैन एवं वितरण पाइप लाइन छीजत 79 एम.एल.डी., औद्योगिक जल मांग 19 एम.एल.डी., मिलिट्री क्षेत्र की जल मांग 3 एम.एल.डी., कुल 530 एम.एल.डी. जल की आवश्यकता रहेगी। पानी कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा है। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं कि जल की मांग हमेशा बनी रहती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम किसी प्रकार से जल को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह हमारे विभाग का ही नहीं, राजस्थान की जनता का संकल्प है, क्योंकि जल है तो कल है। यह बहुत बड़ी बात है और हम इस बात का प्रयास सिर्फ कोटा में ही नहीं, पूरे राजस्थान में हमारे इस बात के प्रयास रहेंगे कि हम जल को व्यर्थ न बहने दें।

आपने जो दूसरा सवाल किया मल्टीस्टोरीज और कृषि भूमि के मामले में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जलदाय विभाग की ओर से कृषि भूमि पर विकसित कालोनियों हेतु सहभागिता योजना बनायी थी लेकिन यह योजना सफल नहीं हो पायी है। इसी

(डा. महेश जोशी)

प्रकार हमने मल्टीस्टोरीज के लिये भी योजना बनायी थी, यह भी अब तक सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसमें हमने भूखण्डधारी का अंशदान भी रखा था, फ्लैट वालों का भी रखा था, तो हम इसकी व्यावहारिकता को दिखवा रहे हैं और क्या इस अंशदान को कम करना चाहिए और कुछ सुधार करना चाहिए। इन दोनों नीतियों के बारे में विचार करके विभाग नये सिरे से नीतियों का निर्धारण करेगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रीब्यूटरी तरीके से जीर्ण-शीर्ण है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि डिस्ट्रीब्यूटरी को परिवर्तित करने के लिये जो प्रस्ताव विभाग ने भेजे हैं, उन पर क्या सरकार विचार करेगी?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्थानीय स्तर से जो भी प्रस्ताव आएंगे, सम्भाग स्तर से, जिला स्तर से, उनको हम बहुत गम्भीरता से लेंगे और जीर्ण-शीर्ण जो पाइपलाइन है, उसको जितना अधिक से अधिक हम बदलने में कामयाब हो पाएंगे, उतना अधिक से अधिक हम जल को व्यर्थ बहने से भी रोक पाएंगे और लोगों को भी बीमारी से बचा पाएंगे, यह हमारी प्रायोरिटी का क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज

59. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्ष में प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज कई बार बढ़ाया गया है? यदि हां, तो उक्त अवधि में कब-कब कितनी-कितनी राशि बढाई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चार्ज के बढ़ाये जाने से उक्त अवधि में प्रदेश में कुल कितने उपभोक्ताओं पर कितना आर्थिक भार पड़ा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) माननीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ रेगुलेशन की अनुपालना में विद्युत खरीद की निर्धारित दर एवं वास्तविक खरीद मूल्य में अन्तर की राशि को

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

फ्यूल सरचार्ज के रूप में वसूल किये जाने का प्रावधान है। फ्यूल सरचार्ज का निर्धारण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

गत तीन वर्ष में वसूले गये फ्यूल सरचार्ज का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के कृषि उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं पर लगाये गये फ्यूल सरचार्ज का वर्षवार एवं डिस्कॉमवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। कृषि उपभोक्ताओं पर भारित ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) की राशि कृषि उपभोक्ताओं से न वसूल की जाकर राज्य सरकार द्वारा ही वहन की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि गत सरकार में पांच वर्षों में पांच बार फ्यूल चार्ज बढ़ाया गया और इस सरकार ने तीन वर्षों में आठ बार फ्यूल चार्ज बढ़ाया?

दूसरा, क्वेश्चन मेरा यह है कि क्या यह सही है कि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता कोयला और सस्ती गैस उपलब्ध हुई, जिसके कारण गुजरात और हरियाणा में फ्यूल सरचार्ज में कमी की गयी और हमारे प्रदेश में बढ़ायी गयी, इसका क्या कारण है?

तीसरा, क्वेश्चन यह है कि खण्ड-1 में आपने फ्यूल सरचार्ज की अलग-अलग में अलग-अलग दर बतायी है। यह दरें अलग-अलग क्यों हैं? क्या इसके लिये विद्युत नियामक आयोग से दर निर्धारण से पूर्व स्वीकृति ली गयी थी? ली गयी तो क्या और नहीं ली गयी, तो क्यों?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि फ्यूल सरचार्ज का जो निर्धारण है, उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। नियामक आयोग विद्युत की खरीद के लिये स्थायी और परिवर्तनीय दरें तय करता है। स्थायी जो दरें हैं, वह पावर प्लाण्ट लगाने में जो इन्वेस्ट होता है, उसके आधार पर स्थायी फिक्स चार्ज हो जाते हैं और वैरिएबल जो कोस्ट है, प्लाण्ट को चलाने का जो खर्चा है, उसमें ईंधन के रूप में कोयला, गैस या रेल-ट्रांसपोर्ट आदि के द्वारा जो खर्चा आता है, उसमें खर्चा ज्यादा होता है और मूल्य में जो हर माह परिवर्तन होता है, उसके आधार पर ही वैरिएबल कोस्ट का निर्धारण करते हुए नियामक आयोग के

(श्री भंवर सिंह भाटी)

द्वारा दिये गये फार्मूले के आधार पर फ्यूल सरचार्ज का निर्धारण किया जाता है। वैरिएबल कोस्ट के सरचार्ज का निर्धारण त्रैमासिक उपभोक्ताओं से लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि कृषि का फ्यूल सरचार्ज राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है और फ्यूल सरचार्ज हम नियामक आयोग के द्वारा दिये गये फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद ही करते हैं और उसमें इसका वैरिफिकेशन वह स्वतंत्र आडिटर के द्वारा परीक्षण करवाने के बाद ही उपभोक्ताओं से बिलों के माध्यम से वसूल किया जाता है।

इसके अलावा, जो पांच सालों की बात कही है माननीय सदस्य ने, तो उसमें यह 2012-2013 से लगातार फ्यूल सरचार्ज उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है। यह हमेशा लिया जाता है। इसमें वैरीएबल कोस्ट में जो भी अन्तर 3 महीने में आता है, उसके आधार पर यदि कम कोस्ट आती है तो उसका कम फ्यूल सरचार्ज लगता है। किसी माह में ज्यादा कोस्ट आती है कोयले की कीमत, ट्रांसपोर्ट, डीजल, रेलवे के भाड़े आदि में तो उसके अनुपात में जो हमारा निर्धारित फार्मूला है, उसके आधार पर ही फ्यूल सरचार्ज का निर्धारण होता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(समय: 12.00 बजे)

व्यवस्था

दिनांक 04 मार्च, 2022 को विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2022 पर हुई बहस अभिलेख पर कार्य सलाहकार समिति के अनुसार रखी जायेगी

माननीय सदस्यों को मुझे सूचित करना है कि कल फाइनेंशियल एप्रोप्रिएशन बिल को जब पास किया गया था, जो बिजनस एडवाइजरी कमेटी में निर्णय किया था कि बिना डिस्कशन किये किया जायेगा। उसमें जो संशोधन करना है, वह संशोधन कार्यवाही करके, जो निर्णय किया गया है, उसी के अनुरूप कार्यवाही को रिकार्ड किया जायेगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में कोविड के दौरान एनएचएम विभाग द्वारा संविदा पर लगे नर्सिंग कर्मचारियों को नियमित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर निगम कोटा दक्षिण में निर्माणाधीन कार्यों को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से चिकित्सा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं में कार्यरत संविदा नर्सेज को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उपखण्ड कोटड़ी में पदस्थापित मुख्य ब्लाक चिकित्साधिकारी, कोटड़ी द्वारा वित्तीय अनियमितताएं किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के सभी टोल प्लाजाओं पर टोल कर्मियों द्वारा किये जा रहे दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा सहित बारां जिले में वन विभाग की भूमि पर वन विभाग के कर्मियों की मिलीभगत से किये जा रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विद्युत वितरण, प्रसारण एवं उत्पादन कंपनियों में कर्मचारियों के परस्पर स्थानान्तरण हेतु पालिसी बनाये जाने के संबंध में।

(9) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र नीमराना कस्बे से पैट्रो कैमिकल पदार्थों से भरे ट्रकों के परिवहन के मापदण्ड सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के उपखण्ड घड़साना कस्बे में डिग्गियों में पानी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में नदियों पर पुल निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अमृतलाल मीणा, श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, श्रीमती संतोष एवं श्री जोराराम कुमावत को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा नगर विकास न्यास के इंजीनियर को नियम विरुद्ध पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में अतिवृष्टि के कारण किसानों की नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर जिले के गोगेलाव औद्योगिक क्षेत्र में ई-आक्शन के जरिये आबंटित 38 भूखण्डों का आबंटन बिना किसी सूचना के निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर में स्वीकृत की गयी सड़कों का निर्माण नहीं होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से जीडीसी घग्घर नदी पर रावतसर से सूरतगढ़ रोड पर जर्जर पुलों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ में राजस्व विभाग के सैटलमेंट विभाग द्वारा खातेदारों के नाम दर्ज

(श्री अध्यक्ष)

जमीनों का भूमि रूपान्तरण नहीं किये जाने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(8) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में विलुप्त होती धरोहर हस्तशिल्प कला को संरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से ग्रामीण पंचायतों में जनता जल योजना में एग्रीकल्चर उपयोग में आने वाले नलकूपों का कनेक्शन वाणिज्यिक किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री रोहित बोहरा, सदस्य की ओर से धौलपुर स्थित तीर्थराज मचकुण्ड धाम को स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की ग्राम पंचायत खांगटा में बाँध एवं डाइवर्जन चैनल का निर्माण करवाकर बरसाती पानी का संरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल में हरो बांध की भराव क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत के किसानों को फसल खराबे का बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री अमर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना में भरतपुर जिले के बांध बारेठा में पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण सिंचाई हेतु चम्बल लिफ्ट परियोजना से पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री गणेश घोघरा, सदस्य की ओर से आशापुरा सिक्योरिटी गार्ड एवं भूतपूर्व सैनिक सोसायटी बाली, जिला पाली द्वारा डूंगरपुर हास्पिटल में कार्यरत संविदाकर्मियों को वेतन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जायेगा।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें)

श्री अमृतलाल मीणा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

विद्युत वितरण, प्रसारण एवं उत्पादन कम्पनियों में कर्मचारियों की परस्पर स्थानान्तरण पालिसी

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 50 के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग इंटर डिस्काम, प्रसारण और उत्पादन के बारे में बोलने की अनुमति देने के लिये धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में ऊर्जा विभाग 2000 से पहले पूरे राजस्थान में एक था, लेकिन डिस्काम बनने के बाद अजमेर डिस्काम, जोधपुर डिस्काम, जयपुर डिस्काम एवं उत्पादन और प्रसारण में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी पिछले 20 वर्षों से परेशान हैं। अपने नजदीक के एरिये में नहीं जा सके हैं। ऐसी पालिसी को बदलकर क्या सरकार एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्काम में कर्मचारी, अधिकारियों को भेजे जाने का विचार रखती है? यही मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

दूसरी बात, राजस्थान कृषि वितरण कम्पनी बनाने की घोषणा हुई है। वितरण कम्पनियों में पालिसी बनाते समय क्या कुछ इस तरह की नीति बनायी जायेगी जिससे निगमों का पुनर्गठन, एकीकरण होने के साथ ही कर्मचारियों, अधिकारियों का ऊर्जा विभाग के सभी निगमों में स्थानान्तरण हो सके। उक्त प्रकरण का स्थगन राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 50 के तहत मैं लाया हूं।

मेरा यह भी कहना है कि बजट 2021-22 में राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी, खेती हेतु पर्याप्त बिजली की...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (अनुपस्थित)।

श्रीमती संतोष।

घड़साना (अनूपगढ़) में डिग्गियों में पानी का अभाव

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के घड़साना कस्बे में पिछले 7 दिन से जनता को पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है। स्थानीय

(श्रीमती संतोष)

प्रशासन को वास्तविकता का पता होने के बावजूद भी न तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है और न ही डिग्गियों में समय पर पानी भराया गया है।

कुछ समय पूर्व लगभग साढ़े 8 करोड़ रुपये की लागत से घड़साना वाटर वर्क्स की स्कीम में डिग्गियों का निर्माण हुआ था। घटिया निर्माण के कारण डिग्गी जमीन में बैठ गयी व पाइप लाइनें भी टूट गयीं। आगामी लगभग 7 दिन तक पीने का पानी वहां उपलब्ध नहीं हो पायेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि घटिया निर्माण की जांच करवायी जाये। समय पर पेयजल की व्यवस्था नहीं करने के लिये स्थानीय प्रशासन को दंडित किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार का मामला पिछले साल रामसिंहपुर में हुआ था। जब आन्दोलन हुआ और हमने प्रशासन से लेकर डिग्गियां भरवायीं।

श्री अध्यक्ष: अलग से, नया है।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): वैसी स्थिति इस बार भी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जाये। गर्मियां शुरू होने वाली हैं। जनता के लिये सुचारु रूप से पेयजल की व्यवस्था की जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर में नदियों पर पुल निर्माण

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में खांगड़ी से बांगड़ी नदी पर पुल नहीं है। पावा से भाचुन्दा नदी पर भी पुल नहीं है। जवड़िया से गिरादड़ा नदी पर भी पुल नहीं है। भारुन्दा से कोरटा जाने वाली नदी पर भी पुल नहीं है। कानपुरा से पुराड़ा जाने वाली नदी पर भी पुल नहीं है। गुन्दोज में सम्पर्क सड़क पर भी पुल नहीं है। सोनेही माझी रास्ते पर भी पुल नहीं है। सोनेही माझी से आइसिया के बीच में बड़ी नदी है। वहां पर भी पुल नहीं है। केरला से रूपावास नदी पर भी पुल नहीं है। यह नदियां बरसात के मौसम में आती हैं तो भारी बहाव से आती हैं। उस समय ये सारे रास्ते 3-3 महीनों तक बंद रहते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन नदियों पर पुल बनाने का श्रम

(श्री जोराराम कुमावत)

करें जिससे उन 3 महीनों में लोगों को कष्ट से निजात मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा-निर्देशों में अस्पष्टता एवं विसंगति

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा के नियम 131 के तहत अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किये जाने सम्बन्धी नवीन दिशा-निर्देशों में अस्पष्टता एवं विसंगति होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.01.2014 को जारी अधिसूचना अनुसार अधिसूचित अल्पसंख्यक यथा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदायों के व्यक्तियों को अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान द्वारा पत्रांक 19/11/अल्पवक्फ/2018/आरके/01251, दिनांक 16.12.2019 को जारी दिशा-निर्देश के अन्तर्गत जांच उपरान्त सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं।

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पत्रांक 104/नियमावि/प्रमाण पत्र/2016/2283, दिनांक 14.08.2017 के द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही कठिनाइयों के सन्दर्भ में प्राप्त ज्ञापनों के विभाग द्वारा परीक्षण उपरान्त कठिनाइयों को दूर करने हेतु दिनांक 14.08.2017 को जारी आदेशों में सरलीकरण करते हुए पत्रांक 19/अल्पवक्फ/2018/आरके/0125/दिनांक 16.12.2019 द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के नवीन दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं। विभाग द्वारा दिनांक 16.12.2019 को जारी दिशा-निर्देश

(श्री शाले मोहम्मद)

अन्तर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है:-

1. राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र
2. पता प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता सूची, किरायानामा, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल या गैस कनेक्शन, इनमें से कोई एक।
3. अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज-

i. शपथ पत्र

ii. उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र, दिशा-निर्देश के परिशिष्ट 'अ' में उत्तरदायी व्यक्तियों में, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, राजकीय अधिकारी, कर्मचारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, नगर निकाय अध्यक्ष, पार्षद, ग्राम सेवक, पटवारी आदि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

iii. पत्र में हलका पटवार जांच रिपोर्ट अनिवार्य है।

- इस प्रकार उक्त समस्त वांछित दस्तावेज एवं जांच उपरान्त सक्षम अधिकारी के द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तथा उक्त प्रमाण पत्र सम्बन्धित व्यक्ति के उस समुदाय से सम्बन्धित रहने तक ही मान्य है। अल्पसंख्यक वर्ग के सन्देहास्पद एवं फर्जी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी होने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों का निराकरण किये जाने का प्रावधान है। कार्यालय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के पत्रांक 1320, दिनांक 13.12.2021 के क्रम में जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर, मसूदा जिला अजमेर की अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा पत्रांक 01251 दिनांक 16.12.2019 को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

(समय: 12.11 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, यह विषय गम्भीर स्थिति में आ रहा है। उसका कारण है। विशेष चीता, मेहरात और काठात, जो राजस्थान के चार जिलों में मुख्य रूप से निवास करते हैं। जिसमें पाली है, राजसमन्द है, भीलवाड़ा है और स्वयं अजमेर है। इसके लिये बहुत पहले से, एक तरह से भारत सरकार के प्रकाशित राजपत्र वर्ष 1955 में जारी सार्वजनिक, 1955 का जो गजट है, इस गजट के अन्दर प्रकाशित है।

माननीय सभापति महोदय, यह विषय बहुत गम्भीरता की ओर जा रहा है। अल्पसंख्यक के बारे में ब्यावर के आसपास काठात और रावत समाज की जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, उन लोगों के बारे में प्रश्न है। यह भारत सरकार का 1955 का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आपका पार्ट 14, राजस्थान, इसमें कौन-कौनसी जातियां ओबीसी में हैं, इसमें 10 पर चीता, ओबीसी में है और मेहरात 39 नम्बर की जाति की जो लिस्ट है उसमें ओबीसी के अन्तर्गत है। इसी तरह से केन्द्र सरकार ने 20.10.1994 को भी इसके बारे में प्रकाशित भारत सरकार के राजपत्र में क्रमांक 37 पर इनको ओबीसी में सम्मिलित किया गया है। अब यहां विषय इस बात का आ रहा है कि इन लोगों को ओबीसी की जगह अब अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र देने का विषय आकर खड़ा हो गया है इस एरिये में, जिसके कारण से भारी असन्तोष है। राजस्थान सरकार ने भी 16 दिसम्बर, 2017 में एक अपनी तरफ से आदेश जारी किया अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के दिशा-निर्देश, ये राजस्थान सरकार के हैं। पूरा तो बहुत लम्बा-चौड़ा है पर इसमें आवश्यक पार्ट जो है, वह मैं पढ़ देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सक्षम अधिकारी द्वारा अपने अधिकार, अधीनस्थ कार्मिक तथा पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार आदि से सन् 1957 के आवेदन के पैतृक, स्वयं के राजपत्र रिकार्ड, चार पीढ़ी की सजरा, गंवाई दस्तूर, दस्तावेज आदि से उनके अल्पसंख्यक जाति प्रमाण समुदाय का परीक्षण करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो शैक्षणिक रिकार्ड नगरपालिका, ग्राम पंचायत रिकार्ड परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जा सकेगा जिससे उसके स्वयं और उसके पैतृक जाति की पुष्टि हो सके। यह बहुत स्पष्ट आदेश राजस्थान सरकार ने भी 2017 में इसको जारी कर दिया। हमारी सरकार के आने के बाद इनके दिमाग में भगवान जाने क्या सोचकर किया, ये तो ये ही बतायेंगे। इन्होंने 16 दिसम्बर, 2019 को एक नया आदेश जारी किया। इस नये आदेश में इन्होंने केवल दो चीजें मांगी। कोई भी काठात या

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मेहरात अगर दो डाकुमेंट दे दे तो उनको यह प्रमाण पत्र मिल सकता है। ये कौनसे मांगे, अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाणित हेतु अल्पसंख्यक दस्तावेज, स्वयं का प्रमाण पत्र, एक तो स्वयं का प्रमाण पत्र दे दे और दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र, जिनके नाम हमने गिनाये हैं, उनमें से अगर कोई दे दे कि हां, यह है तो कर दिया जाये। वास्तव में अल्पसंख्यक होने के लिए जिस प्रकार के डाकुमेंट पहले तय करने थे उसके आधार पर राजस्थान सरकार का है, केन्द्र सरकार का नोटिफिकेशन है, 2019 में आपकी सरकार होते हुए भी उस समय फिर उसमें ओबीसी प्रमाण पत्र देने के लिए उन्होंने दिशा-निर्देश, सारे के सारे जारी कर रखे हैं लेकिन आपने ये जो 2019 का आदेश निकाला, इस आदेश के कारण से उस क्षेत्र में एक प्रकार से आपस में संवेदनहीन वातावरण बनता जा रहा है और इस बारे में एक दूसरे से कई बार संघर्ष हो चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, यहां तक ही नहीं रहा मामला, मामला इससे और गम्भीर हुआ और उसमें लगता है कि हमारी मंशा ही कुछ गड़बड़ है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के डाकुमेंट के आधार पर लोग धर्म परिवर्तन के रास्ते पर जायें और एक वर्ग संघर्ष की स्थिति आये। मैं पूरा पढ़ रहा हूं, आपसे क्षमा चाहते हुए, जलालुद्दीन काठात, संरक्षक, राजस्थान चीता-मेहरात महासभा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिनांक 28.12.2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता से भेंट कर ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि अजमेर जिले में ब्यावर और मसूदा उप खण्ड में चीता, मेहरात, गिरदावरी के लोगों को उनकी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में होने के आधार पर, उनके ओबीसी होने के आधार पर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। यह उन्होंने, इनसे मिले होंगे, रिक्वेस्ट की होगी। उस रिक्वेस्ट का परिणाम जो निकला, वह देखें आप। अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में जारी, यह जो आपने बताया अभी आदेश क्रमांक 1251 और 16.12.2019 के स्पष्ट प्रावधानों में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, यह जो 27.01.2014 का रेफरेंस देकर कलेक्टर पर यह दबाव बनाया कि यह तो पहले से ही आदेश निकला हुआ है। मैं आपको यह बताता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस आदेश का इन्होंने रेफरेंस दिया, यह केवल और केवल उन पर भ्रमित करके दबाव..., इस आदेश में कितना है, वह मैं पढ़ रहा हूं। जो केन्द्र सरकार के आदेश का इन्होंने हवाला देते हुए कलेक्टर को दबाव में लाने का प्रयास किया, "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

धारा 2 खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 816 (अ), दिनांक 23.10.1993 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में पहले से ही अधिसूचित अर्थात् मुस्लिम, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों और पारसियों के अलावा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती है।" कारण कि जैन समुदाय पहले अल्पसंख्यक में नहीं था। यह 2014 का नोटिफिकेशन निकला, इसके पीछे उस समय जो मंशा थी, वह केवल और केवल यह थी कि ये भी अल्पसंख्यक हैं और यदि ये चाहें तो इन्हें भी अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र मिल सकता है। आपने इसका आधार लेकर कबाड़ा किधर कर दिया, इधर कर दिया। कबाड़ा यह किया है कि अल्पसंख्यक मामलात का आपने रेफरेंस दिया न वह 16.12.2019 के तहत ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय जो बताये हैं इन्होंने- मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन, आवेदक को अधिसूचित समुदाय का व्यक्ति होने के आधार पर दिशा-निर्देशानुसार सम्बन्धित उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उप-खण्ड अधिकारी को दिशा-निर्देशानुसार अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी करवाने हेतु इस कार्यालय से अवगत कराएं। आदेश किसने दिया? स्वयं मंत्री ने। मैं सोचता हूं, कलेक्टर को भी अगर लिखे तो इनका विभाग लिखे, इनके विभाग का अधिकारी लिखे तो समझ में आ सकता है। शाले मोहम्मद जी, मंत्री महोदय के आदेश से इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनाकर आप धर्म परिवर्तन के लिये लोगों को रास्ता देकर असन्तोष पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कानून के तहत अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र देने का अधिकार है। उन पूर्तियों को करते हुए आप अधिकार दे सकते हैं। पहले भी था। 1955 से ही एक तरह से हमने इसका नोटिफिकेशन करके आगे की सारी व्यवस्था कर रखी है।

आपने राजस्थान में 2017 में आदेश में बहुत स्पष्ट कर दिया, क्या-क्या देना है, लेकिन यहां एक तरह से इस क्षेत्र में धर्म परिवर्तन करने के लिये स्वयं मंत्री और जिस आदमी का नाम ले रहे हैं, यह जलालुद्दीन वही है, जो उस क्षेत्र में आज दिन तक कई बार संघर्ष की स्थिति लाकर के जिस प्रकार का वहां

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ताण्डव नृत्य हुआ है, यह उसी का एक आदमी है। उस व्यक्ति के आधार पर एक मंत्री चिट्ठी लिखे कलेक्टर को। यह शायद पहली बार है, मैं सबको सावधान करना चाहता हूं, अगर इस प्रकार की मनोवृत्ति के आधार पर काम करने का प्रयत्न किया तो क्षेत्र तो अशान्त होगा जो होगा, सम्पूर्ण राजस्थान में आपकी नीयत पर इतना सन्देह खड़ा हो जायेगा कि आप जान-बूझकर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र का लालच देकर हॉस्टल में भर्ती करने का बहाना बनाकर लोगों को अल्पसंख्यक बनाने के लिये, धर्म परिवर्तन के लिये रास्ता खोज रहे हैं।

यह रास्ता किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। समय रहते इसे ठीक कर लें। स्वयं मंत्री को अगर कलेक्टर को आदेश लिखना पड़े तो यह शायद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पहली बार रही है। अगर मैंने भी कोई आदेश दिया होगा तो मेरे सैक्रेटरी ने निकाला होगा, मेरे किसी अधिकारी ने निकाला होगा, लेकिन मंत्री स्वयं सीधा, बिना किसी विभाग की जानकारी के इस प्रकार का आदेश कलेक्टर को देकर धर्म परिवर्तन के लिये रास्ता खोल रहा है, उकसा रहा है, इसके लिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

(समय: 12.24 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर लिमिट है। यदि आपको हल्ला करना है तो मैं वाइंड-अप करता हूं। You don't want a serious debate, you just want to have a political score. This is very unfortunate.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात भी ऐसी नहीं बोली...

श्री अध्यक्ष: तो फिर हल्ला करने की जरूरत कहां है, जब आप बोल रहे हैं? आपके सीनियर लीडर बोल भी रहे हैं और आप हल्ला भी कर रहे हैं। दो चीजें नहीं होतीं। आपने पाइंट आउट किया, वाइंड-अप करें प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात रखी, केन्द्र सरकार के 1955 के राजपत्र को आधार बनाया, 1994 के केन्द्र सरकार के निर्देश को बनाया। उसके पहले जाति प्रमाण पत्र, राजस्थान सरकार के 2017 के निकले हुए आदेश को बताया, लेकिन 2019 के बाद नयी सरकार आने के बाद इन्होंने एक रास्ता निकालने का प्रयत्न किया। उसमें भी जब सफलता नहीं मिली तो कलेक्टर को स्वयं एक मंत्री आदेश देता है...

श्री अध्यक्ष: यह सुन लिया पूरा मैंने आपका।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं, इस प्रकार के कृत्य ठीक नहीं।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत कुछ बातें कही हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, शंकर सिंह जी को एक बार बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट शंकर सिंह जी को बोलने दें। शंकर सिंह जी, जो कटारिया जी ने कहा, क्या आपको कोई नयी बात एड करनी है उसमें?

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): जी अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने जो आदेश निकाला है...

श्री अध्यक्ष: इतना अच्छा प्रजेंटेशन कटारिया जी ने कर दिया, what else does He want?

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मंत्री महोदय का आदेश क्रमांक 122/83 दिनांक 14.08.2017, इसके तहत मंत्री महोदय ने लिखा है, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के लिये जारी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी, मरने तक। इसमें ये कह रहे हैं कि साहब, वे समय-समय पर साल भर में अपना परिवर्तन कर सकते हैं। अभी बोला है। दूसरी बात है साहब, भारत सरकार की गाइडलाइन में कहीं पर भी इन जातियों का नाम, जो काठात, मेहरात हैं, इनका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। उस आदेश की प्रति मेरे पास भी है। 16.11.2017 का जो आदेश बता रहे हैं, इसमें भी कहीं पर भी जिक्र नहीं है। इन माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो कलेक्टर पर दबाव डालकर उनके द्वारा जो दिया गया आदेश है...

श्री अध्यक्ष: बस हो गया अब। कटारिया जी की बात में यह सब आ गया। आप कोई नयी बात नहीं कर रहे हैं।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): एक मिनट, मैं वही बताना चाह रहा हूं। उस समाज से मैं भी हूं साहब।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, ध्यानाकर्षण की लिमिट है। प्लीज, ये सब कटारिया जी ने बोल दिया। नयी बात क्या बोल रहे हैं आप?

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): एक मिनट, नयी बात यह है...

श्री अध्यक्ष: No, I will not allow it. रिकार्ड नहीं होगा। जब इतनी अच्छी ढंग से प्रजेंट कर दिया, बात खतम हुई।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: Now please, I will not allow it. माननीय मंत्री जी।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कुछ बातें कहीं। आप बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं और समाज का ताना-बाना बनाये रखने में आपका हमेशा सहयोग रहा है। आप जैसा व्यक्ति यदि कोई ऐसी बात कहता है कि हमारी जो मंशा है, वह ठीक नहीं है, स्पष्ट है, हमने 16.02.2019 को जो आदेश निकाला है, उसमें मेरे पास 31.07.2018 को जयपुर जैन सभा समिति के लोग आकर मिले थे, उसके अध्यक्ष हैं सन्दीप बागड़ा जी। उन्होंने मांग करके मुझे कहा था कि जो सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं, उनमें सरलीकरण किया जाए।

आप कह रहे हैं कि हमने सिर्फ दो जातियों के लिये, पहली बात, अल्पसंख्यक जातियां जो हैं, वे स्पष्ट हैं इसमें, कोई अलग से ओबीसी में है, मुस्लिम लोगों की ओबीसी में अलग-अलग जातियां हो सकती हैं, पर भारत सरकार द्वारा जो अधिसूचित जातियां हैं, उनमें मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय हैं। अब समुदाय में अलग-अलग जातियां हो सकती हैं। कोई ओबीसी में हो सकती हैं, कोई नहीं भी हो सकतीं। ये जो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र हम जारी कर रहे हैं, कोई धर्म का सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं। हम इतना ही जारी कर रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं हैं, उनका फायदा उन्हें मिलना चाहिये।

हमारे पास समय-समय पर डेलीगेशंस मिलने आते हैं। उन्हें जो-जो दिक्कतें दिखती हैं, उन्हें हम ठीक करते हैं। अब उसमें हमने कौन-सा चेंज कर दिया? जब 16.12.2019 की बात आपने कही, इस परिपत्र का हवाला दिया, आपने पूरा तो दिया नहीं। सिर्फ इतना कह दिया कि आप शपथ पत्र पर उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जबकि हमने इसमें अतिरिक्त प्रावधान किया है। चाहे हम आधार कार्ड ले रहे हैं, चाहे भामाशाह कार्ड ले रहे हैं, चाहे पासपोर्ट ले रहे हैं, चाहे मतदाता सूची, किरायानामा, पानी, बिजली, टेलीफोन, ये सब तो मांग ही रहे हैं, पर उसके बाद में अतिरिक्त हमने मांगा है कि स्वयं के शपथ पत्र पर भी आप ले सकते हैं। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति गलत सर्टिफिकेट जारी करेगा तो वहां पर कमेटी बनी हुई है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी है। राज्य स्तर पर प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में

(श्री शाले मोहम्मद)

कमेटी बनी हुई है। वहां जाकर आप शिकायत दे सकते हैं। यदि कोई गलत सर्टिफिकेट देगा, गलत काम करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। हमारी मंशा साफ है। अभी आपकी केन्द्र में सरकार है। आपकी सरकार के द्वारा भी इन योजनाओं में लोगों को लाभ दिया जा रहा है। हमारी इतनी ही मंशा है कि जो लोग इन योजनाओं में आते हैं, उन्हें लाभ मिलना चाहिये। जो डेलीगेशन मेरे पास आया, उन्हें वास्तव में कठिनाई आ रही थी। उनकी कठिनाई को दूर करने की बात थी।

दूसरी बात, मेरे द्वारा जिला कलेक्टर को लिखने की आपने बात कही, मैंने स्पष्ट लिखा है, जो मेरे यहां से जारी हुआ है दिनांक 31.12.2021 को, मैंने उन्हें यह हवाला दिया है कि जो हमारा परिपत्र जारी किया हुआ है उसके तहत आप कार्रवाई करें। मैंने उन्हें यह कतई नहीं कहा है कि आप जबरदस्ती काम करें। मैंने कहा है, आपके अधिकारी यदि राजस्थान सरकार द्वारा जारी इस परिपत्र के तहत काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें। ऐसा कभी नहीं कहा है कि आप इस पर कार्रवाई करें।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड, आप बैठो। मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं कि मुझे इनके पत्र पर जो एतराज पैदा हुआ वह इस कारण से हुआ कि इन्होंने श्री जलालुद्दीन काठात, संरक्षक राजस्थान चीता, मेहरात महासभा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल द्वारा 28.12.2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता से भेंट कर ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि अजमेर जिले के ब्यावर और मसूदा उपखण्ड में चीता, मेहरात, काठात, गिरदावरी के लोगों को उनकी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में होने के आधार पर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। यह रेफरेंस नहीं देते तो मैं मंत्री जी को कोट नहीं करता। मंत्री जी ने यह आदेश देकर कलेक्टर पर उस जलालुद्दीन के कहे अनुसार काठात और ब्यावार में उसको रेफरेंस देते हुए आपने जो पत्र लिखा है और जो आपने 2019 में केवल शपथ पत्र का कहा है जबकि आपका कानून पहले से ही था.....

श्री अध्यक्ष: Kataria Ji, I am extremely sorry. Don't extract this much of argument. मैं एक निवेदन करूंगा कि मान लो उन्होंने एक ज्ञापन दिया, कलेक्टर ने दिया तो कलेक्टर पूरा अधिकृत है उन चीजों पर

(श्री अध्यक्ष)

एक्शन लेने का, उन्होंने थोड़े ही कहा है कि कलेक्टर एक्शन नहीं ले। उन्होंने कोई ऐसा आर्डर निकाला हो जिसमें कलेक्टर की पावर, स्टेट गवर्नमेंट की पावर, भारत सरकार की पावर, जहां पर इन चीजों का वायलेशन हो रहा है उसको बाईपास करने का लिखा हुआ है तो आपका कन्सर्न ठीक है। कोई प्रतिवेदन लेकर आया है, उस प्रतिवेदन की क्या भाषा थी, वह भाषा ठीक नहीं हो सकती, इससे मैं सहमत हूं, लेकिन मंत्री जी का यह इंटेंशन नहीं था कि उसमें ये करें। I am extremely sorry. चर्चा समाप्त की जाती है।

श्री ज्ञानचंद पारख। (व्यवधान)

पाली शहर में सोलर प्लांट से उत्पादित यूनिट्स का समायोजन

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैंने बोल दिया सर। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। नहीं, प्लीज। आप क्या कर रहे हैं? यह क्या आर्ग्यूमेंट है? ध्यानाकर्षण की लिमिट है। माननीय कटारिया जी, ध्यानाकर्षण की लिमिट है। आप और ढंग से लगाओ, ध्यानाकर्षण की लिमिट है। माननीय मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं वापस बोल जाऊं साहब, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई रिकार्ड नहीं होगा। (व्यवधान) कोई रिकार्ड नहीं होगा। प्लीज, रिकार्ड नहीं होगा। डोंट डिस्टर्ब। मंत्री जी का जवाब हो रहा है। रिकार्ड नहीं करें। प्लीज, सुनें आप। रिकार्ड नहीं होगा। बायकाट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में लेख है कि जोधपुर डिस्काम में वर्तमान में 500 किलोवाट तक के भार वाले पात्र उपभोक्ताओं को नेट बिलिंग की व्यवस्था की जा रही है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): एवं जोधपुर डिस्काम के पत्र दिनांक 09.08.2019 के तहत रूफटाप....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I will name you. I will expel you. (व्यवधान) आपको बाहर जाना है सदन से? सदन से बाहर जाना है? मैं सदन से बाहर निकालूंगा अभी, खुद आप निकल जाएं भले। माननीय मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ...एवं छोटे सोलर फोटोवाल्टिक ग्रिड सम्बद्ध वाले उपभोक्ताओं की बिलिंग सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुरूप मीटर रीडिंग लेते समय सोलर मीटर एवं नेट मीटर जनरेशन एक्सपोर्ट एवं इम्पोर्ट, तीनों की रीडिंग प्राप्त कर बनाये गये बिल को रोककर उसके स्थान पर नेट मीटर में डिस्काम के ग्रिड में डाली गयी यूनिट की नियमानुसार क्रेडिट देते हुए बिल जारी किये जा रहे हैं। पाली वृत्त के पाली शहर में रूफटाप वाले घरेलू, अघरेलू व औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र के प्रकरणों में उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना में तीनों रीडिंग प्राप्त कर यथासम्भव सभी उपभोक्ताओं को नेट मीटर में डिस्काम के ग्रिड में डाली गयी यूनिट की नियमानुसार क्रेडिट देते हुए ही विद्युत विपत्र जारी किये जा रहे हैं। इसके उपरान्त भी यदि किसी कारणवश किसी उपभोक्ता के नेट मीटर में डिस्काम के ग्रिड में डाली गयी यूनिट का समायोजन शेष रह जाने की स्थिति में उपभोक्ता द्वारा सूचित किये जाने पर अथवा संज्ञान में आने पर तुरन्त प्राथमिकता से उसे नियमानुसार समायोजन कर संशोधित विद्युत विपत्र जारी किया जाता है। पाली शहर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह जनवरी, 2022 तक के जारी विद्युत विपत्रों में उपरोक्त अनुसार समायोजित की गयी विद्युत यूनिटों का उप खण्डवार विवरण परिशिष्ट- "अ" पर उपलब्ध है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जो विभाग ने जवाब दिलवाया है वह सही नहीं है। अभी जो पाली में व्यवस्था चल रही है उसमें डिस्काम जितनी बिजली एक्सपोर्ट करती है उपभोक्ता को, उतना ही बिल डिस्काम उस उपभोक्ता को भिजवाती है चाहे उसके सौर ऊर्जा लगी हुई है और चाहे वह उपभोक्ता घरेलू हो, व्यावसायिक हो या औद्योगिक हो। बाद में जब उपभोक्ता, उसके यहां जो जनरेशन हुआ है, उसने जो बिजली

(श्री ज्ञानचंद पारख)

घर को, डिस्काम को एक्सपोर्ट की है उसकी रीडिंग लेकर जाता है तब कहीं जाकर वापस वे उस बिल को संशोधित करके नया बिल बनाकर देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इसको दुरुस्त कराने में उपभोक्ता को कम से कम 8 या 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपके जयपुर डिस्काम में यह सुविधा है और जितने भी ये सौर ऊर्जा वाले उपभोक्ता हैं उनको आप नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग का बिल भिजवाते हो या 150 एचटी के ऊपर के कनेक्शन हैं जिनके बिल जोधपुर में बनते हैं उनके भी नेट बिलिंग का ही बिल आता है तो यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अनावश्यक चक्कर नहीं लगें और आपके खुद के आफिस के बाबू या कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्यभार नहीं बढ़े तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आपको डवलप करना है जो मुश्किल से 24 घंटे में हो जाएगा। इसलिए आप कम से कम नेट मीटरिंग की व्यवस्था जोधपुर डिस्काम के जो 150 एचटी से कम के उपभोक्ता हैं, उनके लिए आप करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? इस बात का जवाब देना है, कोई बड़ा काम नहीं है यह।

श्री अध्यक्ष: बिल्कुल ठीक।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है उसमें हमने विभाग को दिशा-निर्देश भी जारी किये कि इस तरीके की शिकायतें हैं, हालांकि बहुत कम इस तरह की शिकायतें हैं लेकिन जहां भी आ रही हैं तो भविष्य में नहीं आयें इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को सुधारा जाये और जब मीटर रीडिंग ली जाये तो उसमें उपभोक्ता जितनी खर्च कर रहा है और माननीय उपभोक्ता जितनी बना रहा है उन दोनों.....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सोरी। सीधा है कि ऐसा एप बनाकर यह व्यवस्था करने का काम करना है या नहीं करना है? जस्टिफिकेशन करने का तो है ही नहीं। एक डिस्काम तो कर रहा है, दूसरा डिस्काम करने के लिए आईटी में तो खाली एक एप ही तो बनाना है। एप बनाने से यदि कंज्यूमर को फायदा मिलता है तो वापस करेक्शन करने के लिए उसको सोलर एनर्जी वाले के पास जाना पड़ता है तो वह जाना नहीं पड़ेगा। यह बिल्कुल सिम्पल है। एक सैकण्ड।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 150 एचटी के ऊपर के कनेक्शन में जिसके बिल जोधपुर में बनते हैं उसका नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग का बिल

(श्री ज्ञानचंद पारख)

आता है तो उससे कम के उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था आप करवा दीजिये, यही तो कह रहा हूं मैं।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था पहले से है, और माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है उसमें जयपुर डिस्काम में हमारा जो अपडेटेड साफ्टवेयर है वह अभी वर्तमान में चालू है, लेकिन जोधपुर डिस्काम और अजमेर डिस्काम में बिलिंग प्रक्रिया में सुधार के लिए हम नये टेंडर जारी कर रहे हैं, वह प्रक्रियाधीन है और यह प्रक्रिया पूरी करके नये सॉफ्टवेयर से बिलिंग अतिशीघ्र शुरू हो जाएगी, जिसमें यह दिक्कत पूरी तरह से समाप्त हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

नगरीय विकास विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: प.10(43)नविवि/3/2000 दिनांक 14.02.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.01.2022 के गजट में प्रकाशन की सहवन से टंकित दिनांक 10.01.2021 को संशोधित कर 10.01.2022 किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: प.10(179)नविवि/3/2009 दिनांक 14.02.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.01.2022 के गजट में प्रकाशन की सहवन से टंकित दिनांक 10.01.2021 को संशोधित कर 10.01.2022 किया गया है; एवं

(3) अधिसूचना संख्या: प.10(3)नविवि/कोटा/80 पार्ट-II दिनांक 14.02.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 के गजट में प्रकाशन की सहवन से टंकित दिनांक 11.01.2021 को संशोधित कर 11.01.2022 किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री उदयलाल जी आंजना।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2009-10 से वर्ष 2019-20)

(1) राजस्थान राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 से वर्ष 2019-20; एवं

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20)

(2) राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20.

श्री अध्यक्ष: वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

(1) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में जन लेखा समिति, 2022-23 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2022-23 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2022-23 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2022-23 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में, जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। माननीय चीफ व्हिप।

वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जन लेखा समिति, 2022-23, प्राक्कलन समिति 'क', 2022-23, प्राक्कलन समिति 'ख', 2022-23 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2022-23, प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत

(श्री महेन्द्र चौधरी)

प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम, 230 (1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।

(समय: 12.42 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में सरकारी उप मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव।

घोषणा

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव, जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है, जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिये प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें, जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं। ऐसा मेरा अनुरोध

(श्री सभापति)

है। जब मांग मतदान के लिये आती है, उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं। यह परम्परा इस सदन की रही है।

जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाय, वह अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर नहीं मिले सके, उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जायेंगे। ऐसा मेरा निवेदन है। आय-व्ययक अनुदान।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 405,84,73,34,000/- (चार सौ पांच अरब चौरासी करोड़ तिहत्तर लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(मांग संख्या 24 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें)

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा हो रही है। मुझे मुख्य मंत्री जी का 26 फरवरी, 2022 के कोटा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में दिया भाषण याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में प्रतिबद्धता से काम कर रहा

(श्री वासुदेव देवनानी)

है जिससे प्रदेश के विद्यार्थियों को दूसरे राज्य में उच्च अध्ययन के लिये जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाक्य बड़ा सुन्दर है, सुनने में और देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत क्या है? असलियत क्या है? तो जरा इन उच्च शिक्षण संस्थाओं की जो दुर्दशा की कहानी है, उसको भी सुन लें।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनआईआरएफ, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क राजस्थान के उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्रदर्शन सहित राज्य की शिक्षा में गुणवत्ता पर प्रश्न चिह्न खड़ा करती है। पहले तो आवेदन नहीं किया, लेकिन जिन संस्थाओं ने आवेदन भी किया, वे पहले 200 में कहीं भी जगह नहीं बना सके। कैसे बनाते, धरातल की स्थिति क्या है? राज्य के 372 महाविद्यालय हैं, उसमें से 80 प्रतिशत महाविद्यालय नेक से बाहर हैं। यानी, केवल 73 महाविद्यालयों का NAAC एक्रीडिएशन हुआ और उसमें से 5 को केवल 'ए' ग्रेड मिली। यानी, महाविद्यालयों की जो दुर्दशा बनी हुई है, उससे कैसे उम्मीद करें कि अपना राज्य अग्रणी शिक्षा में गिना जायेगा, उसके लिये हम प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं।

राज्य के 80 प्रतिशत महाविद्यालय बिना प्राचार्य के काम कर रहे हैं, 372 महाविद्यालयों में केवल 70 में नियमित प्राचार्य हैं। यह स्थिति तब है माननीय सभापति महोदय, जबकि यहीं विधान सभा के अन्दर मेरे प्रश्न के समय तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री ने यह कमिटमेन्ट किया था कि अगले सत्र के प्रारम्भ में अर्थात् 2020 के सत्र से पूर्व सारे महाविद्यालयों में प्राचार्य नियुक्ति हो जायेंगे। यानी, सदन की भी कोई गरिमा नहीं, सदन में दिये गये आश्वासन का कोई लेना-देना नहीं है। आज उसको दो साल होने जा रहे हैं। प्राचार्य नहीं, मैंने पता करने की कोशिश की कि आखिर क्यों नहीं डीपीसी हो रही है तो पता लगा कि सीनियरिटी के अन्दर राजीव स्टडी सर्किल के कोई लोग नहीं आ रहे हैं, यानी उनके नहीं आयेंगे तो हम डीपीसी नहीं करेंगे, क्यों? बाकी के लोग आ रहे हैं। यानी, इस प्रकार की संकीर्ण सोच वह शिक्षा को कहां ले जायेगी? जरा इस पर हम विचार करेंगे, और तो और, शारीरिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के 90 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं, कैसे एक्रिडिएशन करवाओगे और कैसे उच्च शिक्षा में देश भर में अपनी स्थिति बनाओगे? आपके स्टाफ प्रयोगशाला सहायक 791 में से 727 खाली हैं। आपने बजटीय प्रोविजन क्या रखा है? केवल सारे महाविद्यालयों के लिए 42 लाख रुपये, अर्थात् प्रत्येक महाविद्यालय को केवल 11 हजार रुपये, इतने में तो केमिस्ट्री

(श्री वासुदेव देवनानी)

और बायोलॉजी के कंज्यूमेबल आइटम भी नहीं आ सकते, क्या प्रैक्टिकल करेंगे? हमारा विद्यार्थी क्या बनेगा? यानी ये विद्यार्थी आगे जाकर के कितने पिछड़ेंगे, इसकी कहीं कल्पना भी की क्या?

लाइब्रेरी हेतु आपने एक महाविद्यालय को केवल 10 हजार रुपये दिये हैं, 10 हजार रुपये में कितनी पुस्तकें आयेंगी? कभी कल्पना की, कोई सोच ही नहीं हैं, हम प्रतिबद्ध हैं। यदि यह प्रतिबद्धता है तो फिर उच्च शिक्षा का तो भगवान ही मालिक है। यहां की पदोन्नति, उसमें तो पैसा नहीं लगता, वह भी लम्बित है, वरिष्ठ वेतनमान, चयनित वेतनमान एवं एसोसिएट प्रोफेसर का पद, पदोन्नतियां गत तीन वर्षों से लम्बित पड़ी हैं, सरकार को फुर्सत नहीं है, पदोन्नतियां नहीं होंगी, शिक्षक नहीं होंगे तो महाविद्यालयों के हाल क्या हैं? यूजीसी के नोर्म्स कह रहे हैं कि यदि विज्ञान कालेज हैं तो स्नातक के लिये 25 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए। यदि कला है तो 30 विद्यार्थियों पर एक होना चाहिए, लेकिन आपके यहां क्या है? 110 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। यानी इस प्रकार की दर्दनाक स्थिति आज मेरे महाविद्यालयों की बनी है। हर वर्ष 10% विद्यार्थी बढ़ाये जाओ। विद्यार्थी बढ़ाओ अच्छा है। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, विद्यार्थी पढ़ने वाले तैयार होने चाहिये लेकिन उस अनुपात में शिक्षक तो नियुक्त करो। शिक्षक नियुक्त नहीं करेंगे और आज भी जो सैंक्शंड पोस्टें हैं उनमें 40% तो शिक्षक पद और शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों के 50% पद खाली हैं। कुल पद हैं 12,799 और खाली हैं 6,432 और नये कालेज खोले जाओ, खोलो, तालियां बजाओ, डेस्क बजाओ लेकिन वह बच्चा कैसे तैयार होगा? आपके टोटल 122 पहले और 55 अभी, 36 पहले दिन और 19 आखिरी दिन टोटल 177 महाविद्यालय हो गये। अब इन महाविद्यालयों के लिए भवन की व्यवस्था क्या है, पोस्टें कहां हैं? पोस्टों के लिए पहले तो आपने कहा, यह मेरे पास आदेश की कापी है कि नये महाविद्यालयों के लिए किसी प्रकार का न तो कोई बजटीय आबंटन होगा, न कोई भवन के लिए पैसा मांग सकेंगे यानी इस प्रकार किया और उसके बाद में निकाला कि सोसाइटी के अंतर्गत चलेंगे, यानी क्या हो रहा है और उसके बाद अभी आप पर जब दबाव पड़ा तो उसके लिए आपने 657 पद तो स्वीकृत किये लेकिन उनकी स्थिति क्या है, 600 पद खाली पड़े हैं। सभापति महोदय, और 157 पद जो भरे भी हैं वह आसपास के महाविद्यालयों से शैक्षणिक व्यवस्था

(श्री वासुदेव देवनानी)

के नाम पर लगाये गये हैं और जब हम टोटल पूछते हैं तो उसकी गणना दोनों जगह करके केवल आंखों में धूल झोंक रहे हैं और बच्चों के साथ तो धोखा किया ही जा रहा है। बिना अध्यापकों के जो विद्यार्थी तैयार होगा आखिर उसकी गुणवत्ता कितनी होगी, कितना इंटेलिजेंट निकलेगा, कितने परसेंटेज मार्क्स आयेंगे, इसके बारे में कभी कल्पना नहीं की, कभी सोचा नहीं और फिर आयुक्तालय में राजीव स्टडी सर्किल के लोगों को, अपने चहेतों को डेपुटेशन पर रखे जाओ। जब पूछते हैं कि कितने हैं तो कहते हैं कि पता नहीं। मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर गत 3 वर्षों में शिक्षा तो पाताल लोक में गुम हो गई है। छात्र व अभिभावक कहीं भवन ढूंढ रहे हैं, कहीं विषय व्याख्याता ढूंढ रहे हैं। न भवनों का पता, न व्याख्याताओं का पता। मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है जब पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री भाटी जी के क्षेत्र में कोलायत में बज्जू, उनके पैतृक गांव हद्दा और देशनोक में छोटी-छोटी जर्जर धर्मशालाओं में, स्कूल भवनों में कालेज चल रहे हैं, यानी हद हो गई बेहाल दो तीन कमरों में और तो और सीएम ने जो हमारे दिवंगत विधायक थे उनके नाम से कालेज तो खोले, उनका नामकरण तो कर दिया लेकिन आज तक सरकार उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर पायी। यहां तक कि राजसमंद में हमारी किरण माहेश्वरी जी के नाम पर आपने महाविद्यालय तो कर दिया लेकिन उस गर्ल्स कालेज में आज भी परमानेंट फैकल्टी बिलकुल नहीं है।

सभापति महोदय, यह स्थिति है और भवन बनाने के लिए बजट में क्या प्रावधान है, बजट में टोटल यदि 177 कालेज बनेंगे तो एक कालेज में 6 से 7 करोड़ रुपये चाहिये तो टोटल आपके पास एक हजार ग्यारह सौ करोड़ का प्रावधान होना चाहिये और आपने बजट में कितना किया है, 177.50 करोड़ 2022-23 की बीई में, उसमें से कौन से महाविद्यालय के भवन बनेंगे? यानी आज भी दरी पर बैठ रहे हैं बच्चे उच्च शिक्षा के। यह दयनीय स्थिति आज उच्च शिक्षा की है और यही हाल विश्वविद्यालयों का है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में 1,016 पद हैं जिनमें से 525 पद खाली पड़े हैं। एमडीएस विश्वविद्यालय, अजमेर जो बहुत पुराना है उसमें 48 पद स्वीकृत किये उनमें से 32 पद खाली हैं, केवल 16 के भरोसे विश्वविद्यालय चल रहा है। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में 59 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 42 खाली

(श्री वासुदेव देवनानी)

हैं। मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर, सीकर, बांसवाड़ा में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें 30 में से 30 पद खाली हैं यानी एक भी महाविद्यालय में कोई प्रोफेसर, कोई अध्यापक, प्राध्यापक नाम की कोई चीज नहीं है। यह इस प्रकार की स्थिति बनी है। और तो और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है उसका भी यह सरकार खुलेआम मखौल उड़ा रही है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मल्टीडिसीप्लीनरी उच्च शिक्षण संस्थाएं खोलेंगे। 3,000 छात्रों का एक महाविद्यालय होगा और उस महाविद्यालय में स्वायत्तता होगी सब कुछ होगा, मल्टीडिसीप्लीनरी केंद्र खोलेंगे लेकिन सरकार दो या तीन कमरों में कालेज खोले जा रही है। बजाओ ताली, खुश करो। वह बच्चा जो 40% में पास होकर निकलेगा विश्वविद्यालय से आपको गालियां देगा जब उसकी कहीं नौकरी नहीं लगेगी, जब वह कहीं का रहेगा नहीं। यह स्थिति आप लोगों ने बनायी है और इस प्रकार यह जो घोषणा है, सीएम साहब ने घोषणा की थी पिछले बजट में की चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करेंगे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के लिए प्राध्यापक भी चाहिये, आपको भौतिक संसाधन भी चाहिये लेकिन एक भी उपलब्ध नहीं हैं। केवल घोषणाओं पर घोषणा से उच्च शिक्षा के साथ अन्याय कर रहे हैं। और तो और आपने गत बजट में 3 यूनिवर्सिटीज की घोषणा की थी। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, 400 करोड़ से जोधपुर में, इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड लर्निंग, जयपुर 200 करोड़ से, राजीव गांधी सेंटर आफ एडवांस टेक्नोलोजी, जयपुर 200 करोड़, कहां गया? पूरा साल भर हो गया, अभी तक तो आप मोमबत्ती से ढूंढो तो कहीं विश्वविद्यालय नाम की कोई जमीन तो क्या, कहीं कोई चिडिया ही नहीं है। इस प्रकार की स्थिति बनी है। एक भी पैसा इसके लिये आबंटित नहीं है। घोषणा किये जाओ।

सभापति महोदय, और तो और, मैं सारे विश्वविद्यालय देख रहा था और देखते-देखते मुझे लगा कि यह सरकार राजस्थान की है कि जोधपुर की है। यानी जो आओ सब जोधपुर और जोधपुर की जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उसकी लिस्ट में पढ़ रहा था, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आईआईएम, एआईआईएमएस एम्स, डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आफ पुलिस, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी, जोधपुर, इंडियन इंस्टिट्यूट आफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, स्टेट

(श्री वासुदेव देवनानी)

इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, फिटनेस रीजनल यूनिवर्सिटी, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सब जोधपुर, मतलब अजमेर ने तो क्या कसूर किया, क्या गाय मारी सरकार की? केवल उसने एक ही काम किया कि चार बार से आपका विधायक नहीं चुना, केवल बीजेपी को लगातार चुना तो उसका परिणाम आज वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। यानी बाकी सारी चीजें कहां गईं तो इस प्रकार की आज उच्च शिक्षा की स्थिति है।

सभापति महोदय, आखिर स्थानांतरण में आपने जिसको राजीव स्टडी सर्कल ने कहा उसका ट्रांसफर कर दिया। आपका अधिकार है आप करो लेकिन आप उसमें न्यायालय के आदेशों की पालना तो करो। न्यायालय ने स्टे दिया, आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, उसको ज्वाइन नहीं करवाओगे। यह हमारी मनमानी है यानी न्यायालय की भी पालना नहीं होगी तो किसकी पालना होगी। यानी इस प्रकार का दृश्य आज खड़ा हुआ है और यहां तक कि वहां के रुक्टा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको 13 महीने से आप वेतन तक नहीं दे रहे हो। यानी केवल मनमानी। हमारा कोई भी नाम आयेगा रुक्टा का है या राष्ट्रीय है या आरएसएस का है किसी ने गलत शिकायत भी कर दी तो उसको भेजो कुशलगढ़, भेजो डूंगरपुर। दूसरी ओर आप चाहे वह रीट के अंदर कितने भी सजायाफ्ता हो, किसी को निलम्बित किया हो उसका हैड क्वार्टर होगा, जयपुर, चाकसू, किशनपोल यानी इस प्रकार की आप स्थिति करोगे तो फिर कह दोगे कि सबको समान रूप से हम व्यवहार कर रहे हैं। कानून के अनुसार काम करिये।

सभापति महोदय, और तो और, विश्वविद्यालयों की स्थिति जो मैंने चर्चा की, सुखाड़िया विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत दयनीय है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर आपने लगा रखा है कभी उसके आचरण का पता किया क्या आपने? वह अपने महिला संकाय सदस्यों को किस प्रकार प्रताड़ित और अपमानित कर रहा है, यहां तक कि वाणिज्य संकाय के एक प्रोफेसर को हार्ट अटैक तक हो गया। उन्होंने राजभवन में आकर भी शिकायतें कीं। संकाय सदस्यों में भय का, आतंक का वातावरण बना हुआ है, केवल प्रायोजित शिकायतें करवाना उनका काम हो गया है। विश्वविद्यालय को आगे ले जाने का कहीं नहीं है। यूजीसी के दिशा-निर्देशों की अवहेलना, मैं भी शिक्षक रहा हूं कालेज में पढ़ाया है। कभी यह नहीं था कि कोई भी विश्वविद्यालय अपने कैंपस के बाहर, अपने परिसर के बाहर कोई कैंपस नया शुरू नहीं कर

(श्री वासुदेव देवनानी)

सकता। आपने बाहर शुरू करने के लिये घोषणा की और उत्तरी परिसर का आपने 25 नवम्बर 2021 को शिलान्यास करवा दिया और राजभवन को गलतफहमी में रखकर के आपने कर दिया और यहां तक कि निम्बाहेड़ा के एक श्री कल्लाजी वैदिक महाविद्यालय के विलय की घोषणा कर दी। विलय आप नहीं कर सकते हो, उसके लिए विधान सभा के अन्दर एक्ट लाना पड़ेगा। परिसर के बाहर आप खोल सकते हो लेकिन उसके लिये विधान सभा के अंदर एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। उधर तो आपका कोई है नहीं, इस प्रकार की स्थिति बनी है।

माननीय सभापति, यह शिक्षा की बड़ी दर्दनाक कहानी कह रहा है। और तो और यदि मैं वाइस चांसलर की नियुक्तियों की बात करूं तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आपने थानवी जी को वीसी बनाया, क्या वे पीएचडी होल्डर थे, क्या यूजीसी के मापदंड पूरे करते थे? एमकॉम में उनके बहुत कम अंक, केवल कह दिया कि पत्रकारिता का अनुभव है। यदि पत्रकारिता के अनुभव पर वीसी बनाया जा सकता है तो फिर विधि विश्वविद्यालय का वीसी कोई एडवोकेट को बना दीजिए, फिर टेक्निकल में किसी टेक्नोक्रेट को बना दीजिए, एग्रीकल्चरल में किसी कृषक को बना दीजिए। फिर काहे के लिए उनके लिए पीएचडी वगैरह मांगते हो। यानी उनके लिए तो आप पीएचडी होल्डर मांगोगे लेकिन पत्रकारिता विश्वविद्यालय में चूंकि आपका चहेता है इसलिए आप जो चाहो नियमों में संशोधन कर दो। इस प्रकार की जो स्थिति बनी है, वह वास्तव में दर्दनाक है और किस प्रकार के लोगों को आप दे रहे हो मैं केवल एक एग्जाम्पल दूंगा। आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में राम लखन मीणा को नोमिनेट किया। राम लखन मीणा कौन है? कोचिंग इंस्टिट्यूट चलाता है और केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ से टर्मिनेट हैं। ऐसे लोगों को यदि आप सिंडिकेट में बनाओगे तो फिर क्या दशा होगी विश्वविद्यालयों की। शिक्षा मंत्री जी, आप जब बोलें तो जरा इस पर अपना प्रकाश अवश्य डालें और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय तो अपनी पराकाष्ठा पर है। कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, उसको सारी कमेटीज ने अयोग्य ठहराया। लेकिन फिर भी आपने

(समय: 13.00 बजे)

BOM के माध्यम से उन सब 28 लैक्चरर्स को रेगुलराइज करा दिया। आज भी उनकी योग्यता उनमें नहीं है और सरकार और राज्यपाल पहल कर चुके। लेकिन नहीं, हम जो कहेंगे वही होगा, इस प्रकार की स्थिति बनी है वह निश्चित रूप से हमारी शिक्षा के लिये बड़ी दयनीय है। शिक्षा का कांग्रेसीकरण और करते जा रहे

(श्री वासुदेव देवनानी)

हैं। यह आपको तो दुःख देगा ही, आगे आने वाली पीढियों को भी दुःख देगा। सीएए के विरोध में राहुल जी की रैली हुई। दबाव में कालेज के लैक्चरर्स को वहां पर लेकर आये। डाक्टर बन्ने सिंह भरतपुर में मंत्री जी के साथ मंच शेयर करते हैं। आप सरकारी कर्मचारी हो, आप राजनीति में भाग नहीं ले सकते हो लेकिन चूंकि वो राजीव समन्वय स्टडी सर्किल के सदस्य हैं। सुभाष यादव, बी.एम. बैरवा, किस किसके नाम लूं? इन सबको निलम्बन में आपने बाहर भेजा, अब हैडक्वार्टर उनका यहां पर कर दिया। इस प्रकार की स्थिति बनी और आपका कोई ध्यान नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में ही है, कभी आपने जाकर वहां देखा है कि वहां पर डिजिटल लाइब्रेरी जो 12 करोड़ से बनाई गई, 3 करोड़ बाद में खर्चा हुआ, आज कतई आपरेटिव मोड में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा की तो बड़ी दयनीय हालत है। अब जरा स्कूल शिक्षा पर आ जाएं। राजस्थान की वर्तमान शिक्षण व्यवस्था के गत तीन वर्षों के नेतृत्व में आम राजस्थानी, आम आदमी, आम अभिभावक व शिक्षार्थी एक ही बात कह रहा है। मैं एक राजस्थानी शेर पढ़ रहा हूं। 'आंधा चढ़गा ऊंट, चढ़ता ही हाक्या घणा, गई नकेला टूट, राम रुखाला राजिया।' यानी यह स्थिति हो गई। एक तो आप देख नहीं पा रहे थे, अब तो राम ही रखवाला है। इस प्रकार की स्थिति बनी और पूरे तीन वर्ष यह अवनति का काल रहा है। भाजपा सरकार के नेतृत्व में हमने पांच साल शिक्षा में नये आयाम स्थापित किये। हर क्षेत्र में शिक्षा की चर्चा होती थी। सरकारी स्कूलों और शिक्षकों को अपनी गरिमा का अहसास होता था लेकिन अब विद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन गये हैं। डीपीसी नहीं, हमने रिकार्ड तोड़ डीपीसी करवाई थी। तीन वर्षों तक न डीईओ की डीपीसी, न प्रिंसिपल की डीपीसी, न लैक्चरर्स की डीपीसी, न सैकण्ड ग्रेड की डीपीसी, किसी की भी नहीं और इसका हश्र यह हुआ कि जयपुर में 543 निरीक्षण अधिकारियों में से 380 तो गये ही नहीं, बाकी ने केवल औपचारिकता पूरी की। अभी तीन दिन पहले आपने डीईओ की डीपीसी करवाई है। समय पर अगर इनकी डीपीसी नहीं कराओगे, तीन-तीन साल डीपीसी नहीं होगी तो कर्मचारी किस उत्साह से आपके उद्देश्यों को पूरा करेगा, आपके लक्ष्यों को पूरा करेगा। इस प्रकार की बातें करोगे तो केवल आप टेबलें जरूर बजवा दोगे लेकिन भला तो नहीं होने वाला।

आपने बड़ी जोर-शोर से 3,800 स्कूलों को सैकण्डरी से सीनियर

(श्री वासुदेव देवनानी)

सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। अच्छा है, करनी चाहिये। हमने भी 7,000 स्कूल क्रमोन्नत किये थे। उनके लिये हमने पोस्टें भी दी थीं। हमने स्टाफ पैटर्न भी लागू किया लेकिन आपने तो सबकी धज्जियां उड़ा दीं। आपने एक और घोषणा की थी, कल्ला जी तो अभी आये हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपके पूर्व शिक्षा मंत्री ने जब वह यहां विपक्ष में थे, बड़ी-बड़ी घोषणांए की थीं कि आपने 22 हजार स्कूल मर्ज कर दिये, हम आते ही 22 हजार शुरू कर देंगे। मैं पूछना चाहूंगा, उसमें से कितने स्कूल आपने रिवाइव किये, कुल मिलाकर 200-250 किये। हमने तो सही किया था लेकिन केवल विपक्ष में रहने के कारण आपके पूर्व शिक्षा मंत्री यहां से खूब जोर-शोर से बोले थे और आज उसका कहीं किसी के पास उत्तर नहीं है। आज 4 हजार से ज्यादा अध्यापक डेपुटेशन के पास है। डेपुटेशन की सीमा देखो, केवल एक उदाहरण दूंगा, 28 अगस्त को सीकर में एक अध्यापिका नियुक्त हुई और 3 सितम्बर को बीकानेर में डेपुटेशन करवा लिया। यानी अपने स्थान पर केवल पांच दिन में। इस तरह के डेपुटेशन हमने सुने नहीं, देखे नहीं लेकिन शिक्षा में जो चाहो मनमानी कर लो।

दूसरा, आप महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बड़ी वाहवाही लूट रहे हो, बड़ी टेबलें बज रही हैं, बड़े खुश हो रहे हो। महात्मा गांधी से भी पूछ लेते कि क्या उनका अंग्रेजी प्रेम था क्या? आप अंग्रेजी स्कूल खोलो, अच्छा है बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा मिलेगी। लेकिन हकीकत में आपने एक भी स्कूल नहीं खोला है। हिन्दी मीडियम स्कूलों को बन्द करके आपने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू करने का केवल बोर्ड लगाया है। अध्यापक वही, बिल्डिंग वही, एक बोर्ड लगा दिया कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, उससे कोई स्कूल शुरू होते हैं? आपको अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का, राजस्थान को ऊंचाई पर ले जाने का विचार है, जरूर कीजिए लेकिन उसके लिये आपको स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल की तर्ज पर नये स्कूल खोलने चाहिये। उस एक स्कूल पर 6 करोड़ रुपये खर्च होता है। आपने पैसा तो खर्च किया नहीं और इन स्कूलों को एक लाख रुपये दिये हैं। एक लाख में कभी स्कूल बनते हैं? एक लाख में अंग्रेजी मीडियम स्कूल और 50 हजार मरम्मत के लिये, डेढ़ लाख में करोड़ों की वाहवाही लूट रहे हो। यह बच्चों के साथ घोर अन्याय है। इस तरह के स्कूल में बच्चे पढ़ कर निकलेंगे, उनकी क्या दुर्दशा होगी, क्या स्तर होगा, एक अध्यापक के नाते उस पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। कल्ला

(श्री वासुदेव देवनानी)

जी भी अनुभवी हैं, अच्छे हैं, इस पीड़ा को जरा आप भी समझें, इसको ठीक करने का प्रयास करें।

आपके अंग्रेजी स्कूलों पर हाईकोर्ट की फटकार भी आपने सुन ली होगी। आप जबरदस्ती हिन्दी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में नहीं बदल सकते। सीएम के गृह जिले जोधपुर के पीलवा गांव में 600 बच्चों वाले स्कूल को आपने अंग्रेजी मीडियम किया, हाई कोर्ट ने उसको गलत करार दिया। यानी आप जबरदस्ती कहीं नहीं कर सकते हो। इस कारण से हिन्दी मीडियम के एक हजार स्कूल बन्द हुए हैं और उसमें भी 350 स्कूल तो गर्ल्स स्कूल हैं। आप यह गर्ल्स स्कूल बन्द कर रहे हो या खोल रहे हो? इन एक हजार हिन्दी मीडियम स्कूल के बच्चे कहां जायेंगे? आज अजमेर के बोराज गांव के बच्चे आये मेरे पास, कि हम कहां जायें, आस-पास कोई हिन्दी मीडियम स्कूल नहीं। इसी तरह उदयपुर के बड़गांव, बारापाल, सायरा, मेनार, ऐसी कई जगह हैं जहां पर आपके अंग्रेजी मीडियम के स्कूल के बोर्ड तो लग गये लेकिन हिन्दी मीडियम के 8-9 हजार बच्चे आखिर कहां जायें? पहले उनकी तो व्यवस्था करते, फिर आप अंग्रेजी शुरू करो। मेरी आपसे मांग है कि हिन्दी मीडियम स्कूल के बच्चों की भी आल्टरनेट व्यवस्था हो। आपने कहा कि पास के स्कूल में चले जाओ, पास में स्कूल है क्या, कैसे जायेंगे? इस प्रकार की कहीं व्यवस्था नहीं।

माननीय सभापति महोदय, गार्गी पुरस्कार, हमेशा बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिये 10वीं और 12वीं में जिनके 75 परसेंट अंक आते थे, हम उनको गार्गी पुरस्कार देते थे। 3 हजार, 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती थी। इस बार प्रसन्नता होनी चाहिये 7 लाख बच्चियों ने अर्हता, योग्यता हासिल की और उसके लिये 383 करोड़ रुपये चाहिये। गांठ में पैसे हैं नहीं, क्या करेंगे कि उनको गार्गी पुरस्कार नहीं, इस प्रकार खतम। क्या है यह, बच्चियों के साथ तो मत खेलो। बाकी बजट में दो कालेज, दो स्कूल कम खोलो, लेकिन उन बच्चियों को तो आप पुरस्कार दो, लेकिन वह देंगे नहीं क्योंकि सरकार की जेब में पैसे नहीं।

आप कह रहे हो कि बिजली की 100 यूनिट में से 50 यूनिट माफ करेंगे। आज 63,858 स्कूलों में से 18,632 स्कूलों में बिजली कनेक्शन ही नहीं हैं। जहां बिजली कनेक्शन हैं वहां बिजली का बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं। आज के युग में जहां बिजली, पानी, इन्टरनेट के बिल काफी आते हैं, जो स्कूल

(श्री वासुदेव देवनानी)

फैसेलिटी ग्रांट थी साढ़े बारह हजार से एक लाख रुपये हमने दिये थे लेकिन आज वह पैसा कम है। अत: मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि स्कूलों के बिजली, पानी के बिल नि:शुल्क कीजिए, तब जाकर इन स्कूलों का भला होगा, नहीं तो स्कूल बिल कहां से चुकायेंगे? बैठने की पहले ही व्यवस्था नहीं।

स्कूलों का नामांकन बढ़ा, बड़े खुश हो रहे हो कि नामांकन बढ़ा। नामांकन आपकी योग्यता के कारण नहीं बढ़ा, नामांकन कोरोना के कारण बढ़ा है क्योंकि जिनके पास प्राइवेट स्कूल के पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने इसमें अपने बच्चों का एडमिशन कराया। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आज 21,500 स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं है। इसके लिये 92 हजार अतिरिक्त कक्षा कक्ष चाहिये और आपने बजट में घोषणा की है कि 3,500 कमरे बनायेंगे। 3,500 कमरों का 92,000 का गैप कैसे भरोगे, कहां मेरा बच्चा बैठेगा? क्या आप स्कूल में पेड़ के नीचे बैठाओगे या धर्मशाला में बैठाओगे, कहां बैठाओगे? फिर कहा कि हम नि:शुल्क शिक्षा दे रहे हैं। नि:शुल्क शिक्षा क्या दे रहे हो, विकास शुल्क के नाम पर 500 से 2,100 रुपये तक आप ले रहे हो। इस प्रकार की स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, और तो और तीन वर्षों से बच्चों को लैपटाप नहीं मिल रहे हैं। यह सरकार की घोषणा है कि 8वीं, 10वीं, 12वीं के बोर्ड के जो बच्चे राज्य स्तर पर हर जिले में टॉप होंगे, उनमें से 27 हजार बच्चों को हम लैपटाप दिया करते थे। आपने तीन वर्षों में लैपटाप योजना बंद कर रखी है। आज 21 हजार बच्चों के साथ यह अन्याय कर रहे हो। कैसे टेक्नालाजी आगे बढ़ेगी, कैसे बच्चों को आप आगे की शिक्षा दोगो, आधुनिक शिक्षा दोगे, उसके बारे में कहीं विचार नहीं।

छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिये हमने दूध की योजना शुरू की थी। आज आपने दूध को बन्द कर दिया। कक्षा 1 से 5वीं तक 100 एमएल, 6 से 8वीं को 150 एमएल दूध देते थे, आपने बन्द कर दिया। बच्चों का कुपोषण ठीक हो गया, इसलिए किसकी चिन्ता करें। अब तो आप भी आ गये। अब आप संभालो। आपने अभी 9 मार्च को एक आदेश जारी किया है कि बच्चों को गर्म भोजन मिलेगा। क्या इस गर्म भोजन के लिए आपने राशि स्कूल तक पहुंचायी है? एक भी स्कूल तक राशि नहीं पहुंची। अब क्या अध्यापक अपने वेतन से काटकर इसकी व्यवस्था करे? इस प्रकार की व्यवस्था से यह कैसे लागू होगा? आपके स्कूल में भी 24 जुलाई, 2020 को

(श्री वासुदेव देवनानी)
नयी शिक्षा नीति लागू हुई। आपने बहुत जल्दबाजी करके 2019 में एक कमेटी बनायी थी, एक रिटायर्ड आई.ए.एस. ओंकार सिंह जी, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? आज तक रिपोर्ट का पता नहीं। क्या पता रिपोर्ट आयी भी या नहीं? जब 2020 में शिक्षा नीति लागू हुई तो उसे पढ़ो तो सही, उसकी तैयारी तो करो। उसमें 10+2 के ढांचे की जगह 5+3+3+4 है। उसमें यह है कि प्री-प्राइमरी शिक्षा प्रारम्भ होगी। आपने कह दिया कि इस बार एक हजार अंग्रेजी स्कूलों के अन्दर प्री-प्राइमरी शिक्षा प्रारम्भ होगी, तो हिन्दी मीडियम के स्कूलों ने क्या कसूर किया है? यह स्टैण्डर्ड हिन्दी मीडियम के स्कूलों के लिए नहीं है। अंग्रेजी मीडियम में पहली और पहली, लोअर केजी, हायर केजी और नर्सरी शुरू कर देंगे, लेकिन हिन्दी मीडियम में नहीं करेंगे। यह योजना हमने शुरू कर दी थी। हम लगभग 18 हजार आंगनबाड़ियों को स्कूल के परिसर में लाये ताकि वे स्कूली शिक्षा के साथ जुड़ जायें। उस योजना को आपने आगे नहीं बढ़ाया। इस प्रकार की नयी शिक्षा नीति में छठी से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात है। आपने व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक पैसा नहीं रखा। आपने कोई योजना नहीं बनायी। इस प्रकार की स्थिति है। त्रि-भाषा पालिसी, अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा एक तीसरी भाषा पढ़ायी जायेगी। उसकी कोई तैयारी नहीं। उसके लिए लोगों ने नहीं पूछा कि कौनसी भाषा पढ़ेंगे? इस प्रकार की स्थिति के कारण जो नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसमें राजस्थान सबसे पीछे है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बाकी प्रान्त तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी करें। कुछ तो यहां पर लागू करना शुरू करें। उच्च शिक्षा मंत्री जी, वहां पर ग्रेजुएशन चार साल का होगा। आपने उस पर विचार नहीं किया। अनुसंधान और ओरिएंटेशन शिक्षा नीति होगी, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं। शिक्षा की तो खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करुंगा कि इसमें जो दुर्दशा हुई। अभी आपके सामने अर्द्धवार्षिक परीक्षा हुई कैसे हुई, यह आपको पता लग गया होगा। किस प्रकार से जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, उदयपुर लगभग प्रत्येक जिले में पेपर के फोटो स्टेट और बाजार में बिक रहे पेपरों के सहारे अर्द्धवार्षिक परीक्षा हुई। यानी अर्द्धवार्षिक परीक्षा का कोई महत्व ही नहीं रहा। इस प्रकार की स्थिति आपके रहते हुई है। फिर आपके पाठ्यपुस्तक मण्डल ने 12वीं की भूगोल की कार्य अभ्यास पुस्तिका नहीं छापी, जिसके कारण से 10 लाख भूगोल की फर्जी पुस्तकें मार्केट में बिकी हैं। कहीं ध्यान दिया गया क्या? आप तक बात आयी होगी।

(श्री वासुदेव देवनानी)

आप खेल के लिए घोषणा करते हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए खेल होना चाहिए। 45 हजार स्कूलों में शारीरिक शिक्षक नहीं हैं, जिसके कारण से आज 65वीं जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं करायी हैं, वे केवल खानापूर्ति हैं। 45 हजार स्कूलों की कोई टीम वहां पर नहीं गयी है। इस प्रकार की स्थिति बनी है। 10 हजार बच्चों की छात्रवृत्ति अटकी हुई है। क्यों अटकी हुई है? बात कहते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी का हम सारा ध्यान रखते हैं लेकिन 2021-22 की छात्रवृत्ति भी अटकी हुई है। आप 2020-21 की अब दे रहे हैं क्योंकि उसकी आपने यूसी नहीं भेजी, इसलिए केन्द्र से पैसा नहीं आया, आपका जो प्रतिशत है, इस कारण नहीं मिली। इसमें बच्चों का क्या कसूर था? आपने यूसी समय पर क्यों नहीं भेजी? यह लगभग दो सौ करोड़ की स्कालरशिप है, उसके लिए कुछ नहीं किया। व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ी हैं कि पूर्व शिक्षा मंत्री की शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि उनको हमेशा रात-दिन आरएसएस, मोदी, भाजपा को केवल गालियां देनी हैं। महापुरुषों का अपमान करना है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच सत्ता का संघर्ष बता दिया। महाराणा प्रताप आन-बान-शान थे और आजादी के स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लड़ाई के जनक थे। वे प्रात: स्मरणीय हैं, लेकिन आपने कह दिया। मैंने पता लगाया कि इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि पूर्व शिक्षा मंत्री इटालियन कोचिंग से सीखकर पढ़ते हैं। यदि आप इटालियन कोचिंग से पढ़कर आयेंगे, लेकिन हमें तो भारतीय कोचिंग से पढ़े हुए मंत्री चाहिये। भारतीय कोचिंग से पढ़े हुए विधायक चाहिये। भारतीय कोचिंग से पढ़े हुए जन चाहिये, लेकिन इटालियन कोचिंग वाले नहीं चलेंगे। वे केवल वीरों का अपमान करेंगे, कभी सावरकर का अपमान करेंगे, कभी सुभाषचन्द्र बोस का अपमान करेंगे, किसी क्रांतिकारी का करेंगे।

आपने ट्रांसफर पालिसी की घोषणा की। उसके क्या हाल हैं? हम भी बनाकर छोड़कर गये थे, उसमें आपको मामूली संशोधन करके लागू करनी थी। आज तीन साल हो गये हैं। शिक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में मुख्य मंत्री जी ने बिड़ला आडिटोरियम में पूछा था कि क्या ट्रांसफर में पैसे तो नहीं लिये जा रहे हैं और सारे शिक्षकों ने जब हां कहा तो सिर शर्म से झुक गया। इस प्रकार की स्थिति है। कम से कम उसकी कुछ तो चिन्ता करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, मैं एक-दो

(श्री वासुदेव देवनानी)

मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। रीट का पेपर। पेपर लीक होना, पेपर और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है। कहां मिलेगा, सबको पता है। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि पहले सारी बातें हो गयी हैं। रीट पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जानता हूं कि इसमें दो मंत्री और जारोली तीनों का त्रिगुट है। अजमेर के जी.के.माथुर हैं। जारोली ने कहा है कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हुआ है। मैं सदन में जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जारोली को गिरफ्तार करो। जारोली से पूछताछ एसओजी करे या बाद में सीबीआई करे तो असलियत सामने आयेगी कि कौन-कौनसे मंत्री भी इसमें संलिप्त हैं? नार्को टेस्ट कराओ तब जाकर मालूम पड़ेगा कि क्या असलियत है? यानी लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़, फिर भी हम चुप? बहुमत के आधार पर आप सीबीआई को नहीं देंगे, लेकिन आप याद रखें कि जब हम सत्ता में आयेंगे तो हम इसकी सीबीआई से जांच करायेंगे, चाहे इसमें बड़े से बड़ा आदमी जेल जाये तो जाये। इसकी जांच हम कराकर छोड़ेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आधा मिनट। यह जो सारा घोटाला है, वह राजीव गांधी स्टडी सर्कल का महा घोटाला है। सारे घपलेबाज राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े हुए हैं। बनेसिंह सुभाष यादव, प्रदीप पाराशर और बैरवा आदि, ये इसके सूत्रधार हैं, हमारे यहां एक मंत्री मोहदय डा. गर्ग। इस प्रकार एक और पेपर आउट हुआ। राजनीतिक विज्ञान के पेपर में डेढ़ सौ क्वेश्चन एक ही बुक से आये हैं। केवल रीट ही नहीं है, इससे कई में प्रश्न हैं। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि जब शिक्षा मंत्री जी जवाब दें तो मेरे मुद्दों पर जरा कुछ बोलें। आप और हम सब बच्चों का भविष्य चाहते हैं। शिक्षा को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसमें अच्छे सुझाव हों, चाहे हमने दिये हों, उसको आप भी मानें, उसको आगे बढ़ायें। कल्ला जी, आप सौम्य और अच्छे आदमी हैं। जरा इसको आगे बढ़ायें। हम आपके साथ हैं, लेकिन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। रीट पेपर में राजनीतिक संरक्षणों का खुलासा करके रहेंगे और इनको जेल भेजकर रहेंगे। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, एक शेर है:-

जरूरी नहीं है, रोशनी चिरागों से ही हो,

शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, जब मैं स्कूल का विद्यार्थी था और जब मैंने आठवीं की परीक्षा पास की, मेरे शिवगंज गांव में दसवीं तक का ही स्कूल होता था। उस समय मुझ में यह तय करने की समझ नहीं थी कि मैं आर्ट्स में एडमिशन लूं, कामर्स में लूं या साइंस में लूं। उस जमाने में कामर्स का बोलबाला था। ऐसा वातावरण बना हुआ था कि कामर्स में एडमिशन लेना बहुत कठिन है तो मेरा भी एडमिशन 9th क्लास में कामर्स में कराया गया। चाहे 10th तक पढ़ा हूं, 11th तक पढ़ा हूं या ग्रेजुएशन तक पढ़ा हूं। मैंने सब कुछ कामर्स में किया है, लेकिन मैं पूरे 12 महीने फिलोसोफी और हिन्दी साहित्य पढ़ता और जब एग्जाम का टाइम आता तो कामर्स में जाकर एडमिशन लेता क्योंकि उस समय मेरे पास ऐसी कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं था कि मेरी इच्छा क्या है, मेरी समझ क्या है और मेरी रूचि क्या है और मुझे क्या पढ़ना चाहिये? मैं कामर्स का ग्रेजुएट होकर फिर लॉ का ग्रेजुएट हो गया। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दूंगा कि मेरे जैसे बच्चे जब स्कूल में आते हैं, उनके सामने वे परिस्थितियां नहीं हैं, जिन परिस्थितियों का सामना मैंने किया है। आज स्कूल के विद्यार्थी के सामने राजीव गांधी करियर पोर्टल मौजूद है, जो उसमें हर तरह की जागरूकता पैदा करता है। उसको कौनसा विषय लेना चाहिये, उसके लिए उसका मार्गदर्शन करता है। माननीय सभापति महोदय, इस बात की जानकारी भी उस छात्र को उपलब्ध कराता है कि किस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं? अपनी क्षमता का प्रयोग करके उसको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिये और कौनसी पढ़ाई करनी चाहिये? वैश्विक परिदृश्य में क्या परिवर्तन हो रहा है? उसकी जानकारी भी हमारे शिक्षा विभाग का यह पोर्टल उपलब्ध कराता है। इस बात की भी पहले कोई व्यवस्था नहीं थी कि विद्यार्थी की लर्निंग आउटकम को हम कैसे ट्रेक करें? आज हमारे शिक्षा विभाग ने शाला सम्बलन एप के जरिये विद्यार्थी की लर्निंग आउटकम को भी ट्रेक करने की व्यवस्था की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा हालांकि विगत दो-तीन साल के समय में कोरोना के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत प्रभावित रही है, हमारे बच्चे बहुत प्रभावित रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, हर क्षेत्र के अन्दर उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो, इसलिए राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने शनिवार को

(श्री संयम लोढ़ा)

नो-बैग डे का फैसला किया। उनका यह फैसला हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक कारक बना। पहला शनिवार-राजस्थान को पहचानो, दूसरा शनिवार-भाषा कौशल विकास, तीसरा शनिवार-खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, चौथा शनिवार-मैं भी हूं वैज्ञानिक और पांचवां शनिवास्बाल सभा मेरे अपनों के साथ। माननीय सभापति महोदय, आपने स्वयं अनुभव किया होगा, जब स्कूल में गये होंगे, आपने बच्चों को पूछा होगा कि शनिवार को तुम्हारे क्या होता है तो सारे बच्चों ने बताया होगा आपको कि हमारे यहां ये होता है। मैं भी अनेक स्कूलों में गया, मैंने जानकारी ली। जिस प्रसन्नता के भाव से विद्यार्थियों ने अपने अनुभव शेयर किये, मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कोविड महामारी के दौरान हर कोई चिंतित था। जैसा कि अभी पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने भी अपनी चिन्ता प्रकट की लेकिन उस चिन्ता के माहौल में अपने बच्चों के लिए हम कैसे व्यवस्था कर सकते हैं, क्या बेहतर हम कर सकते हैं? वह एक लोक कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फोर लर्निंग इनहासमेंट, इसके जरिये 20 हजार वाट्सएप ग्रुप बनाकर 13 लाख विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी गयी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, आओ घर से सीखे, पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए कार्य पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। पहली से बारहवीं के बच्चों के ई-कंटेंट का निर्माण कर यूट्यूब और एप के माध्यम से ई-कक्षा, पाठ्य सामग्री तक उस बच्चे की पहुंच सुनिश्चित की गयी।

माननीय सभापति महोदय, मैंने स्वयं ने शिक्षा मंत्री जी से मिलकर कहा था कि ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं जिसमें बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। आप इसमें रेडियो का प्रयोग कीजिए, दूरदर्शन का प्रयोग कीजिए। उन्होंने मुझे बताया कि हम इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, दोनों के माध्यम से बच्चों के लिए कार्यक्रम शुरू किये गये। इसके साथ ही अनेक तरह के नये नवाचार स्कूली शिक्षा में किये गये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अभी हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जिस निराशा के वातावरण का निर्माण इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन में, राजस्थान के लिए कर रहे थे, राजस्थान के हमारे हजारों-हजार प्रिंसिपल,

(श्री संयम लोढ़ा)

हैड मास्टर, लैक्चरर, उनकी क्षमता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि अगर राजस्थान इतना ही नाकारा है तो नीति आयोग ने देश के सर्वश्रेष्ठ 10 राज्यों के अन्दर राजस्थान को शामिल क्यों किया? नीति आयोग तो अशोक गहलोत का बनाया हुआ नहीं है। वह तो आपके प्रिय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी का पैदा किया हुआ एक संस्थान है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि परफारमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में क्या कारण है कि राजस्थान को 1,000 में से 859 अंक मिले? ग्रेड वन प्लस मिला और ये किसने दिया, भारत सरकार के नीति सहयोग से स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव और प्रगति की मॉनिटरिंग करने हेतु जो पी जी आई कार्यक्रम विकसित किया गया है, नीति आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से राजस्थान को ये ए प्लस स्थान मिला है और राजस्थान ने पिछले साल की तुलना में बैटर परफार्म किया है। जो हमारे पड़ौस के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वे राजस्थान से पीछे हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम इतने ही नाकारा हैं तो भारत सरकार ने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ने जो इंस्पायर्ड अवार्ड योजना शुरू की थी, राजस्थान को 2020-21 में भी 8,027 चयनित बाल वैज्ञानिकों के साथ देश में पहला स्थान राजस्थान ने प्राप्त किया। इतना ही नहीं 2021-22 में भी 10,019 चयनित बाल वैज्ञानिकों के साथ पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। ये सारे अवार्ड हम तय नहीं करते।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया वार्ता नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप उच्च शिक्षा मंत्री जी को बोलो, सारी बात इस कान से घुसेगी नहीं तो फिर राजस्थान में क्या कर पाएंगे?

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी महात्मा गांधी का नाम लेकर आलोचना करने की चेष्टा की। जैसे कोई महात्मा गांधी अंग्रेजी के विरोधी हों। माननीय सभापति महोदय, पूरी दुनिया को यह जानकारी है कि उन्होंने बैरिस्टर-एट-लॉ कहां से किया था, उन्होंने अपनी वकालत कहां से शुरू की थी। यह अलग बात है कि एक अनुभव ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। आज उनके उसी अनुभव को दिल और दिमाग में रखते हुए राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने समाज में सबसे पीछे बैठे हुए उस आदमी के

(श्री संयम लोढ़ा)

बच्चे के बारे में सोचा कि आज जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं उन परिस्थितियों के बीच में एक गरीब का बेटा अपना भविष्य कैसे बनाएगा? अंग्रेजी में पढ़े-लिखे लोगों के सामने वह एक हीन भावना का शिकार हो जाता है। उन कपड़ों के सामने उसका मनोबल कमजोर पड़ जाता है तो ये भी महात्मा गांधी की सोच को आगे बढ़ाने का ही काम है कि आज जब वैश्विक बाजार का दौर है, बाजारीकरण का युग है, उस समय हिन्दुस्तान का हर बच्चा अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई कर सके, एक हिम्मत से वह आगे आए और उन्होंने पहले साल में जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का निर्णय किया।

माननीय सभापति महोदय, 2019-20 में इस योजना को शुरू किया, 558 स्कूल आज की तारीख में संचालित हैं। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री दो-दो बैठे हुए हैं यहां पर, दोनों चले गये। वह बताएं कि उनके कार्यकाल में कभी ऐसा अवसर आया कि किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए लाटरी निकालनी पड़ी हो? हम तो घर-घर अभियान चलाते हैं कि स्कूल में आएं लोग। यह पहला अवसर था कि पूरे राजस्थान के अन्दर लाटरी निकालकर एडमिशन देने पड़े।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि मैं जब पहली बार एम.एल.ए. था, उस बार दो सीनियर सैकण्डरी स्कूल मुझे मिली थीं। अशोक गहलोत साहब ने हर एम.एल.ए. को दो-दो दी थीं। मुझ पर दबाव था कि तीसरा सीनियर सैकण्डरी स्कूल और खुले। खुलवाने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि सबको दो-दो ही दी थीं। इतनी ही घोषणा हुई थी। मैं शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम बनवा कर ले गया, जहां मुझे खुलवाना था और उनसे मैंने एक ही रिक्वेस्ट की कि एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल कर दो। आज राजस्थान के तमाम सैकण्डरी स्कूल एक आदेश से अशोक गहलोत ने बारहवीं कक्षा के स्कूल के अन्दर कर दिये। इससे बड़ा क्रान्तिकारी कोई निर्णय नहीं हो सकता, इससे बड़ी हिम्मत का कोई निर्णय नहीं हो सकता। पिछले तीन साल में भी, मैं आपको निवेदन करूंगा कि इस सरकार ने प्राइमरी स्कूल खोले, मिडिल स्कूल खोले, मिडल से सैकण्डरी खोले और सैकण्डरी से सीनियर खोले, एक्स्ट्रा फैकल्टी खोली, साइंस फैकल्टी खोली, एग्रीकल्चर फैकल्टी खोली, सारी फैकल्टी खोली। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी इस बात पर कोई कमी उन्होंने नहीं आने दी। अभी हमारे मित्र बिड़ला सभागार का जिक्र कर रहे थे कि जब शिक्षकों ने ऐसा कहा तो हमारा सिर शर्म से झुक गया। मैं पूछना चाहता हूं

(श्री संयम लोढ़ा)
जब आपकी पार्टी का, राष्ट्रीय सुरक्षा सौदे के अन्दर दलाली में डॉलर ले रहा था, तब आपका सिर शर्म से क्यों नहीं झुका? मध्य प्रदेश के फाइव स्टार होटल में, वाजपेयी सरकार का मंत्री दिलीप सिंह जूदेव, उस फाइव स्टार होटल में कह रहा था, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, यह भ्रष्टाचार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): केन्द्रीय मंत्री फाइव स्टार होटल के अन्दर पैसे ले रहा था, तब आपका सिर शर्म से क्यों नहीं झुका?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, हमारी सरकार ने शहीदों के लिये भी एक से एक बेहतर रियायतें दी हैं। इतना ही नहीं, हमारा नौजवान, हमारा विद्यार्थी उनसे प्रेरणा ले, इसके लिये अशोक गहलोत राजस्थान के पहले मुख्य मंत्री थे, जिन्होंने यह फैसला किया कि हम शहीदों के नाम पर स्कूल का नामकरण करेंगे। सभापति महोदय, इस सरकार में भी 161 स्कूलों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया गया। हमें इसका दु:ख है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारी सीमाओं पर हमारे बच्चों के शहीद होने की संख्या में इजाफा हो रहा है, इसके लिये हमें दु:ख है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। आपका लम्बा अनुभव है। पहले सिर्फ राज्य स्तर पर शिक्षकों को पुरस्कार देते थे, इस सरकार ने आकर उस परिपाटी में और बदलाव किया। अब जिला स्तर पर भी शिक्षक का सम्मान करते हैं। अब ब्लाक स्तर पर भी शिक्षक का सम्मान करते हैं। यह लाखों लोग हमारे बच्चों का भविष्य बनाने का काम करते हैं। मैं जब बस में बैठकर कालेज में पढ़ने जाता था, तो नेतराम एक स्कूल होता था, उस स्कूल के गेट पर, मेन रोड पर लिखा हुआ था,

"लाओ आपके लाल को, इन्सान बना दूं
दुनिया पूजे, उतना महान बना दूं।"

मैं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हमारे शिक्षक, जो इसमें योगदान कर रहे हैं, उनका सम्मान करने के लिये उन्होंने नया प्रयोग किया।

(श्री संयम लोढ़ा)

अभी हमारे मित्र कह रहे थे, नई शिक्षा नीति। मैं पूछना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति में, यह कहा है कि शिक्षा पर जीडीपी का 6 परसेंट खर्च करेंगे। क्या हिन्दुस्तान की मोदी सरकार ने जीडीपी का 6 परसेंट शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय किया? माननीय सभापति महोदय, दुनिया के दूसरे देश आप देखिये। ब्राजील देखिये, यूके देखिये, जीडीपी का कितना पैसा शिक्षा पर खर्च करते हैं। सिर्फ नई शिक्षा नीति के नाम पर, अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास। आधारभूत ढांचे को ठीक करने के लिये कुछ नहीं करते। स्वदेशी जागरण मंच बनाकर पूरे देश के अन्दर विदेशी चीजों का विरोध करते रहे। जब शासन में आये तो क्या कर रहे हैं? आपको ताज्जुब होगा, विदेशों के सारे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को भारत में अपना कैम्पस खोलने के लिये मोदी सरकार ने अलाउ कर दिया।

अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि इन-इन की कमियां हैं। कमियों को गिना रहे थे। इतना बड़ा शिक्षा का क्षेत्र है, कमियां बनी रहेंगी। सारी कमियों की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। आप 300 से ज्यादा सीटों का बहुमत लेकर हिन्दुस्तान की हुकूमत में आये है, राजस्थान से आप 25 सांसद लेकर गये हैं और यहां राजस्थान की विधान सभा में बिजली नहीं होने की बात गिनाते हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, यह सही है कि राजस्थान में 66 हजार 332 अतिरिक्त कक्षा कक्ष की कमी है। एकल कक्षा कक्ष वाले विद्यालय 1,128 हैं। भवन विहीन विद्यालय 290 हैं। किराये के भवन में संचालित विद्यालय 166 हैं। किराया रहित भवन में संचालित विद्यालय 687 हैं। विद्युत अनुपलब्धता वाले विद्यालय 18 हजार हैं। मरम्मत योग्य विद्यालय 6 हजार 243 हैं। एकल शौचालय वाले विद्यालयों की संख्या 1 हजार 90 हैं। चारदीवारी विहीन विद्यालयों की संख्या 9 हजार 892 है। प्रधानाध्यापक कक्ष की अनुपलब्धता वाले विद्यालयों की संख्या 12 हजार 36 है। यह सच्चाई है।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार की ओर से 2020-21 में, भारत सरकार को 1 हजार 30 करोड़ रुपये के, 49 भवन विहीन विद्यालयों के नवीन भवन, 31 जर्जर विद्यालय हेतु नवीन भवन, 4 हजार 60 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 881 कम्प्यूटर कक्ष, 262 पुस्तकालय कक्ष, 1,260 विज्ञान प्रयोगशाला, 1,178 आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष, प्रधानाचार्य एवं 668 विद्यालय भवनों में मरम्मत कार्य प्रस्तावित किये गये थे, जिसमें भारत सरकार ने 1 हजार 30

(श्री संयम लोढ़ा)

करोड़ के विपरीत 91 करोड़ मंजूर किये। आपको लज्जा नहीं आती? इस विधान सभा में खड़े रहकर बिजली की अनुपलब्धता की बात करते हैं। जिस राजस्थान की जनता ने आपकी पार्टी के 25 सांसद जीताकर दिये, अगर वहां का राज्य आपसे, अपने बच्चों के भविष्य के लिये 1 हजार करोड़ रुपये मांगता है, आप उनको लाकर 91 करोड़ रुपये, ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। आप बार-बार खड़े होकर, इंटरवीन क्यों कर रहे हो?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं इसके आगे भी, आपको निवेदन करना चाहूंगा। मैंने 2020-21 का आंकड़ा आपके सामने पेश किया। मैं आपको 2021-22 का भी निवेदन करता हूं। भारत सरकार से 2021-22 में हमारे शिक्षा विभाग ने 2 हजार 1.66 करोड़ के, 75 भवन विहीन विद्यालयों के नवीन भवन, 75 जर्जर विद्यालय हेतु नवीन भवन, 8 हजार 145 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 1,100 कम्प्यूटर कक्ष, 1 हजार 73 पुस्तकालय कक्ष, 1,380 विज्ञान प्रयोगशाला, 1,408 आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष, 253 प्रधानाचार्य कक्ष, 553 विद्यालय विद्युतीकरण, 438 पेयजल सुविधा, 201 हैंड वाशिंग स्टेशन, 852 विद्यालय भवनों में मरम्मत कार्य प्रस्तावित किये। दो हजार एक करोड़ के विपरीत भारत सरकार ने 2021-22 में 194 करोड़ दिये। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य को, राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में शिक्षा की बहस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार है, माननीय सभापति महोदय?

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। इतना ही नहीं, नाबार्ड को भी राजस्थान सरकार ने 457.17 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। माननीय सभापति महोदय, उसकी स्वीकृति भी अभी अप्राप्त है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह विनती करूंगा, खासतौर से प्रतिपक्ष के नेता से, वह वर्षों शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनको इसकी गम्भीरता को समझना चाहिये और प्रधान मंत्री जी से समय लेना चाहिये। राजस्थान की शिक्षा जगत की जिन कमियों का मैंने जिक्र किया है, सदन में यह आश्वासन देना चाहिये कि वह आने वाले दो-तीन महीनों के अन्दर प्रधान मंत्री से मुलाकात करके हमारी इन कमियों की पूर्ति करेंगे। राजस्थान में, मैंने जितनी भी कमियों का आपको जिक्र किया, 12 हजार 500 करोड़ रुपये अगर भारत सरकार दे दे, तो इन सारी स्कूलों, सारी कमियों को

(श्री संयम लोढ़ा)

खतम करके, शैक्षणिक वातावरण को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, भारत सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई। आपकी जानकारी में है, इनका एजेंडा हमेशा राजनीतिक एजेंडा रहता है। आज भारत में, राजस्थान की कमियां गिनाने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, 11 लाख सरकारी स्कूल भारत में ऐसे हैं, कुल 11 लाख सरकारी स्कूल हैं, उसमें 4 लाख में 50 से भी कम स्टूडेंट हैं। 1 लाख 10 हजार में 20 से भी कम विद्यार्थी हैं, पूरे देश के अन्दर। जो सर्वे एनुअल स्टेट्स आफ एजुकेशन के द्वारा करवाया गया है, सिर्फ 19 परसेंट पीरियड टीचर्स के द्वारा लिये जाते हैं। बाकी का समय किसमें जाता है, हम उनसे कौनसा काम करवाते हैं, इलेक्शन ड्यूटी का। हम कौनसा काम करवाते हैं, डाटा कलेक्शन का। हम कौनसा काम करवाते हैं, मिड-डे मील बांटने का। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षकों की पूरी क्षमता का प्रयोग हमारे बच्चों को पढ़ाने में हो, तो मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री जी से भी और प्रतिपक्ष के नेता जी से भी कि वह इस पर ध्यान दें जिससे हमारे शिक्षक इस अनावश्यक बोझ से मुक्त हों। मैं यह विनती करूंगा कि वे शिक्षक कितना तनाव में रहते हैं इन कारणों से भी, आप उनकी काउंसलिंग करवाइये, आप विदेशों में उनको प्रशिक्षण के लिए भेजें अगर आप उनका स्तर सुधारना चाहते हैं तो जब तक यह सब चीजें आप नहीं करेंगे तो उनके स्तर में सुधार नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह विनती करूंगा कि यह जो बजट शेयर है, बजट में परसेंटेज है, वह लगातार मोदी सरकार के आने के बाद शिक्षा का घट रहा है। जो वर्ष 2011-12 में 11.4 परसेंट था, 2012-13 में 11.6 परसेंट था, 2013-14 में 11.5 परसेंट था, इनके आने के बाद 10.4 परसेंट, 10.6 परसेंट, लगातार इतना ही बना हुआ है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से यह विनती करूंगा कि जो नयी शिक्षा नीति के माध्यम से देश की जनता को भरोसा दिलाया गया है कि हम शिक्षा पर खर्चा बढ़ायेंगे, तो मैं आपके माध्यम से यह विनती करूंगा कि पूरे भारत में शिक्षा में खर्चा बढ़ाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्टेट्स का एक्सपेंडिचर शिक्षा पर है, उसमें पूरे राज्यों का आप औसत

(श्री संयम लोढ़ा)

निकालेंगे तो वह 15.2 परसेंट है और राजस्थान का शिक्षा पर खर्चा 18 परसेंट है। मैं यह निवेदन करूंगा कि 2021-22 के अन्दर राजस्थान ने शिक्षा में 19 परसेंट का प्रोविजन किया था और जो बी.जे.पी. रूलिंग स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश-13 परसेंट, मध्य प्रदेश-17 परसेंट, कर्नाटक-13 परसेंट, गुजरात-14 परसेंट तो इस तरीके से सारे बी.जे.पी. रूलिंग स्टेट के मुकाबले, ज्यादातर बी.जे.पी. रूलिंग स्टेट के मुकाबले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने शिक्षा पर ज्यादा खर्च किया। इतना ही नहीं जो पिछला बजट है, 2021-22 का जो बजट एस्टीमेट है 44,309 करोड़ रुपये, उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट है 44,821 करोड़ रुपये, इस बार बढ़ाकर 2022-23 में 49,627 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले की तुलना में 11 परसेंट ज्यादा है।

अब मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि हमारे बच्चों का मन कोमल होता है। वे एक सफेद कागज की तरह है। आप जैसी चाहे वैसी इबारत लिख सकते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, आपने पढ़ा होगा कि गुजरात के अन्दर बनासकांठा जिले में प्रतियोगिता करवायी गयी, वहां के सरकारी विभाग यूथ डवलपमेंट एण्ड कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से, 'मेरा आदर्श नाथूराम गोडसे' मेरा हीरो नाथूराम गोडसे, माननीय सभापति महोदय, यह शर्म की बात है कि 25 विद्यालयों ने उस प्रतियोगिता के अन्दर भाग लिया, तब लज्जा नहीं आती आपको? तब हमारे बच्चों के दिमाग में आप यह जहर उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि देश के राष्ट्रपिता का हत्यारा उनका हीरो बन सकता है, लेकिन आपको यह शर्म क्यों आयेगी? आपने तो आतंकवादी घटना में शामिल आरोपी को भोपाल से भारतीय जनता पार्टी का टिकट देकर भारत की संसद में बैठा रखा है तो आपको शर्म क्या आयेगी? शर्म तो बेच खायी आपने।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि अभी जो रीट का एग्जाम हुआ हालांकि, सदन में यह बिल पेश हो गया है, जब चर्चा होगी जब होगी लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा शिक्षा मंत्रीजी को कि उन्होंने पेपर लीक, परीक्षा एजेंसी के साथ षड्यंत्र रचकर अनुचित साधनों के प्रयोग, परीक्षा का आयोजन, प्रोक्योरमेंट, पेपर लीक करना, इसमें हैल्प करना, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से, जितने भी लोग जिस रूप में भी जुड़े हुए हों, उन सारों को इस अपराध में शामिल किया है और उसमें सज़ा भी बढ़ाने का उन्होंने प्रावधान किया है। इसके माध्यम से मैं यह समझता हूं कि इस पर

(श्री संयम लोढ़ा)

एक अंकुश लगेगा। एस.पी. स्तर के अधिकारी को जांच देना तय किया है लेकिन मैं आपके माध्यम से यह विनती करना चाहूंगा, शिक्षा मंत्रीजी को यह ज्ञात होगा कि यू.पी.एस.सी. जब अपना आई.ए.एस. का एग्जाम करवाती है तो पेपर ही भारत में नहीं छपाती, उसका पेपर ही विदेश में छपता है तो यह 2005 से पिछले 15-17 साल से लगातार यह देख रहे हैं, हर मामले में पर्चा लीक हो रहा है तो आप कोई यू.पी.एस.सी. के एक्स-चेयरमैन वगैरह को बुलाओ, उनसे चर्चा करो और कोई ढंग से ऐसी व्यवस्था का निर्माण करो जिससे कि यह हर सरकार के माथे पर जो कालिख लग जाती है, वह कालिख नहीं लगे। मैं आपको यह विनती करूंगा कि यह एक तात्कालिक उपाय आपका ठीक है कि आप यह प्रावधान कर रहे हैं। आज हाई कोर्ट एग्जाम करता है, आर.जे.एस. के एग्जाम लगातार हो रहे हैं। क्यों लीक नहीं होते वे पर्चे? यू.पी.एस.सी. का पर्चा आज तक लीक क्यों नहीं हुआ? माननीय सभापति महोदय, बहुत ढंग से इन चीजों को हैंडल करना चाहिए, यह आखिर हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम फील्ड में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौनसा आर.ए.एस. आफिसर बात कर रहा है, वह किस रूप में बात कर रहा है, किस रूप में जवाब देता है, थानेदार किस रूप में जवाब दे रहा है तो मालूम पड़ जाता है कि यह ब्लूटूथ कोटे से आया हुआ है इसलिए मैं आपके माध्यम से यह विनती करूंगा कि इस पर सरकार खास ध्यान दे जिससे आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के साथ न्याय हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में बजट की चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के उप नेता ने एक आरोप लगाया था कि 1,678 करोड़ रुपये का मिड-डे मील कैसे बंटा, स्कूल बंद थे? मैं बड़ा चकित हूं के इस राजस्थान की विधान सभा में लगातार नॉन स्टाप जीत कर आने वाले हमारे वरिष्ठ साथी बहुत ही आदरणीय हैं। क्या उनको फील्ड की यह जानकारी नहीं थी कि वहां मिड-डे मील किस रूप में बंट रहा है?

माननीय सभापति महोदय, खुद भारत सरकार ने वीडियो कांफ्रेंस से भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री ने 28 अप्रैल, 2020 को यह खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में बांटने के निर्देश दिये और उसके बाद 31 जुलाई और 3 जुलाई को लिखित पत्र के जरिए भारत सरकार ने यह निर्देशित किया और बाकायदा तमाम प्रावधानों की पालना करते हुए, तमाम प्रोसेस से यह

(श्री संयम लोढ़ा)

राजस्थान के हर जिले में, हर बच्चे तक यह कॉम्बो पैक की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी और पूरे राजस्थान के अन्दर एक शिकायत कहीं पर आयी हो तो आप बताइये? 11 जिलों के अन्दर जो अभियान चलाते हैं यह सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान, इन 11 जिलों के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, उन्होंने सोशल आडिट किया और सोशल आडिट के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया कि वास्तव में यह सामग्री पहुंचती है या नहीं पहुंचती और सारे अभिभावक खुश थे क्योंकि उनको बेहतर क्वालिटी की सामग्री मिली, मगर यह तथ्यहीन आरोप लगाकर सनसनी फैलाना एक अलग चीज है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से कुछ बातें उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। वह समय था जब जोधपुर विश्वविद्यालय में वी.वी. जोन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, डाक्टर नामवर सिंह और यहां प्रोफेसर उन्नीथान जैसे लोग राजस्थान के विश्वविद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे थे और लगातार राजस्थान के शैक्षिक जगत का एक मान-सम्मान बढ़ा हुआ रहा लेकिन विगत समय में, यह सही है कि अनेकानेक कारणों से इसमें कमी आयी है। यह आवश्यक है कि इसकी जड़ तक जाया जाये।

इसी सदन के अन्दर जब मैं दूसरी बार कांग्रेस पार्टी का विधायक था, वसुन्धराजी की सरकार थी और राजस्थान के इतिहास में पहली बार वह प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल लेकर आयी थीं और तब मैंने उनको सावधान किया था कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पैसे वालों की नालायक औलादों को पिछले दरवाजे से डिग्री प्रदान करने का यह षड्यंत्र है और वह गरीब का योग्यता रखने वाला बच्चा अपने हक से वंचित हो जायेगा लेकिन बाद में जब हमारी सरकार आयी तो उन्होंने भी इसको जारी रखा। फिर ये आये तो इन्होंने भी जारी रखा तो जब हम विपक्ष में हों तो हमारा मत दूसरा, हम सत्ता में हों तो हमारा मत दूसरा। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि यह सरकार को तय करना चाहिए कि उनकी सोच क्या है और मैं यह कहता हूं कि इसको पार्टी में बैठकर, दोनों पार्टियों को डिस्कस करना चाहिए कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कालेज के प्रति आप क्या सोच रखते हैं और तब आप निर्णय लीजिए।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस ने वादा किया था कि हम एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन करेंगे और यह बहुत आवश्यक है और

(श्री संयम लोढ़ा)

इसके सम्बन्ध में लगातार कार्यवाही हुई है। सबसे पहले कैबिनेट की सब कमेटी ने इसकी समीक्षा की 2020 में और उच्च शिक्षा विभाग को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये। अनेक राज्यों के अन्दर रेगुलेटरी काउंसिल है जिसमें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल है। कैबिनेट सब कमेटी के निर्णय के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इसका अनुमोदन किया और जो डबल बैंच में सिविल रिट पिटीशन लगी हुई है राजस्थान सरकार की ओर से, उसमें भी उत्तर प्रस्तुत किया गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस दिशा में जो प्रारूप बना है, पहले राजस्थान राज्य शिक्षा नियामक प्राधिकरण के विधेयक का ड्राफ्ट डा. नईम कमेटी ने गठित किया, जिसने उसको प्रस्तुत किया और उसके बाद डा. देवस्वरूप की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री आज इस सदन में जब जवाब देंगे तो इस सम्बन्ध में घोषणा करेंगे कि वह इस प्राधिकरण का गठन करते हैं, जिससे पूरे राजस्थान के अन्दर लाखों विद्यार्थियों का जो शोषण हो रहा है, हमने नहीं, आप सबने देखा कि किस किस तरह से अनेकानेक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने हजारों डिग्रियां बिना पढ़े ही बांट दी, बिना बच्चों के गये ही बांट दी और इस तरीके से हमारे योग्य बच्चों के हितों पर कुठाराघात हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा सरकारी यूनिवर्सिटी के बारे में और खास तौर पर वाइस चांसलर के अपाइंटमेंट के बारे में। मैं एक चिट्ठी आपको पढ़कर सुनाता हूं जो 17 अगस्त, 2012 को लिखी गयी माननीय मुख्य मंत्रीजी को, "Dear Chief Minister, it has been brought to my notice that there are several matters relating to the state universities which are either awaiting resolution or; are going into litigation for want of an effective dispute resolution and control mechanism at the level of the Chancellor of these universities. In this context while I am given to understand that certain corrective steps are proposed to be taken when finalizing the legislation related to the seven new universities proposed in the state budget 2012-13.

Similar provisions are lacking in the case of the existing

(श्री संयम लोढ़ा)

state universities with exception of Swami Keshvanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner and Rajasthan University of veterinary and Animal Science, Bikaner." इसके बाद में और भी कुछ लिखा है।

सभापति महोदय, इस पत्र की पालना में तत्कालीन राजस्थान सरकार ने संशोधन कर दिया और जो प्रोविजन पहले था हमारी अलग-अलग यूनिवर्सिटीज के एक्ट में, वाइस चांसलर के अपाइंटमेंट को लेकर, "The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor on the advice of State Government upon recommendation of a selection committee consisting of so and so.." अब आपने इस चिट्ठी के बाद में क्या किया? सभापति महोदय, इस चिट्ठी के बाद में आपने संशोधन कर दिया और प्रोविजन कर दिया, 2013 में जो अमेंडमेंट किया, वह यह किया, "The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government." आपने राजस्थान के सारे शिक्षाविदों की इसमें हत्या कर दी। पहले था कि राज्य सरकार की सलाह पर चांसलर करेंगे। अब आपने कर दिया कि उनके कंसलटेशन में करेंगे। पहले होता था, 7-8 आपके लग जाते थे, 2-3 उनके लग जाते थे और अब कहां-कहां के आकर वाइस चांसलर लग रहे हैं। कोई ठिकाना ही नहीं है, क्या बैकग्राउण्ड है इनका। अपनी योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं, जो वाइस चांसलर बनने के लिए योग्यता होती है। उनका बैकग्राउण्ड क्रिमिनल तो नहीं है। आज इस राजस्थान के अन्दर परिस्थितियां उत्पन्न किसलिए हुई, एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट का छापा पड़ रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और सबसे अधिक ताज्जुब की बात यह है, सभापति महोदय, मैं आपको गुजरात यूनिवर्सिटी का भी, एक प्रोविजन हुआ है, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, वह आपको सुना रहा हूं। एक वाइस चांसलर का अपाइंटमेंट गुजरात गवर्नमेंट कैसे कर रही है। "The Vice-Chancellor shall be appointed by the State Government from amongst three persons recommended under subsection (3) by a committee appointed for the purpose under subsection (2)." ये साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का एक्ट है।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप 5 सौ करोड़ रुपये देते हो यूनिवर्सिटी को। स्टेट का देते हो, पब्लिक का देते हो। क्या आपका कोई अधिकार नहीं बनता? इस पैसे का क्या उपयोग किया जा रहा है? आज सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नोडल आफिसर बना दिया। यूनिवर्सिटी में सारे खर्चे कैसे होंगे उसमें, टेंडर प्रोसेस के अन्दर नोडल आफिसर बना दिया और सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी अपना अलग-अलग सॉफ्टवेयर बना रही है। करोड़ों रुपये उस पर खर्च हो रहे हैं। क्या एक दिन भी आपकी यूनिवर्सिटीज ने एनआईसी से बात की? क्या आपकी यूनिवर्सिटीज ने डीओआईटी से बात की? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि इन यूनिवर्सिटीज के द्वारा राजस्थान सरकार के दिये हुए पैसे का किस रूप में उपयोग किया गया है? या तो विधान सभा की समिति बनाकर इसकी जांच कराइये और वह नहीं करवा सकते हैं तो आप सीएजी से उसकी जांच कराइये और वह भी नहीं करवा सकते तो मैं आपसे विनती करूंगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्पेशल टीम बनाकर पिछले तीन साल के अन्दर इन यूनिवर्सिटीज ने राजस्थान की जनता के पैसे का किस रूप से उपयोग किया है, वह देखिये।

सभापति महोदय, अब मैं आपको निवेदन करूं, एक वाइस चांसलर का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि गुलाब चन्द कटारिया जमीनों पर कब्जा करवाने में शामिल हैं।

एक माननीय सदस्य: हो....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हो-हो की बात नहीं है। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर कांग्रेस का ऐसा कौनसा विधायक है कि गुलाब चन्द कटारिया का सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता है और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौनसा विधायक है जो अशोक गहलोत का सम्मान नहीं करता और आदर नहीं करता। यह हम सब और सदन के लिए लज्जा की बात है। जिस आदमी का इतना लम्बा और बेदाग सार्वजनिक जीवन है। एक बाहर से, उत्तर प्रदेश से आये हुए लकड़मबाज की इतनी हिम्मत कि राजस्थान विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता के चरित्र पर उंगली उठाये। मैं समझता हूं कि सरकार को उसी दिन उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी और उसी दिन सरकार को कमेटी बनानी चाहिए थी और मैं आपके माध्यम से विनती कर रहा हूं कि सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कितने कारनामे हैं वह मैं इस सदन में

(श्री संयम लोढ़ा)

आगे और लाऊंगा, सभापति महोदय। मर्जी आये जैसे अपाइंटमेंट करना, मर्जी आये जैसे प्रमाण पत्र देना। आपके दायरे में खर्चा है या नहीं, वह खर्चा करना। यूनिवर्सिटी के नोटिफाइड एरिया से बाहर जाकर उसके लिए खर्चा करना। कौन देखेगा यह?

मैं आपसे विनती करूंगा, अभी प्रतिपक्ष की तरफ से बोल रहे देवनानीजी ने जिक्र किया टीचर्स के अपाइंटमेंट को लेकर। हमें दु:ख है कि आज राजस्थान में, फिगर मैं कोट नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे केवल हमें नहीं, आपको नहीं, इस सदन में बैठे हुए हर व्यक्ति को शर्म आयेगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर केवल तीन प्रोफेसर। तीन प्रोफेसर से हम राजस्थान यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। सीकर, अलवर, भरतपुर की हालत देखिये आप।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हां, करता हूं। सभापति महोदय, मैं आपसे विनती करूंगा कि हम अपाइंटमेंट में रिलेक्टेंट रहते हैं। आप पूरे राजस्थान में पूरे टीचर्स के अपाइंटमेंट की आथोरिटी बनाइये। कमीशन बनाइये एक। जिसके माध्यम से पूरे राजस्थान के अन्दर टीचर्स का अपाइंटमेंट हो। हमने अगर सारे यूनिवर्सिटीज के अन्दर ये उपलब्ध नहीं कराये तो हम कभी खुद को माफ नहीं कर पायेंगे।

सभापति महोदय, अब मैं एक निवेदन आखिरी में करूंगा कि राजस्थान का जो दृश्य अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यूनिवर्सिटीज का पेश किया, वैसा नहीं है। मैं आपको विनती करूंगा कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसने बिट्स पिलानी को 15वें स्थान पर रखा है। बनस्थली को 55वें स्थान पर रखा है। एमएनआईटी, मालवीय नगर, जयपुर को 35वें स्थान पर रखा है। आईआईटी, जोधपुर को 53वें स्थान पर रखा है। कोटा विश्वविद्यालय को 78वें स्थान पर रखा है तो तथ्यों की सही जानकारी प्रस्तुत करिये। राजस्थान के अन्दर बनस्थली, पिलानी आज के नहीं हैं। पचास साल पहले से राजस्थान के प्रतिष्ठित और नामचीन संस्थान हैं और आज भी वहां पढ़े हुए बच्चे केवल राजस्थान और हिन्दुस्तान के नहीं, पूरे मानव जाति के लोगों की सेवा कर रहे हैं तो राजस्थान को इतना कम मत आंकिये। राजस्थान हर दृष्टि से सेवा करने में समर्थ है और NAAC ने भी जो ग्रेडिंग की है, वह भी मैं आपको निवेदन करूंगा। बनस्थली A++, बिट्स पिलानी A,

(श्री संयम लोढ़ा)

(समय: 14.00 बजे)

जनार्दन राय यूनिवर्सिटी A, राजस्थान यूनिवर्सिटी A, एल.एम.एन. A, सुरेश ज्ञान विहार A, सेंट्रल यूनिवर्सिटी A, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर A, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं और आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि राजस्थान का जो शैक्षिक परिदृश्य बन रहा है, उसमें हमारा जो कर्तव्य है और कुछ कठोर कदम आपको उठाने पड़ें, तो आपको उठाने चाहिए।

यह जो चांसलर की व्यवस्था दी गयी है, आप बंगाल में देखिए, क्या हुआ? बंगाल में जगदीप धनखड़ साहब ने अपाइंटमेंट किया एक, उस आदमी ने ज्वाइन करने से इंकार कर दिया और बाद में स्क्रीनिंग कमेटी ने जो नाम दिये, उसमें उन्होंने अपाइंटमेंट नहीं दिये, तो बंगाल की सरकार ने 25 वाइस चांसलर के अपाइंटमेंट कर दिये। राजस्थान की सरकार को भी, मैं समझता हूं, अगर आप इस तरीके से कमजोर पड़ते रहेंगे, खाली यह संविधान पार्क बनाने से कुछ नहीं होगा, आप संविधान कायदों की पूर्ति करो।

मैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में बोर्ड आफ मैनेजमेंट का मैम्बर हूं। माननीय सभापति महोदय, वाइस चांसलर ने मुझे और टोंक जिले से जो माननीय सदस्य आते हैं प्रशान्त बैरवा, दोनों से पूछकर ओम थानवी साहब ने बैठक रखी यूनिवर्सिटी के बोर्ड की। चांसलर आफिस ने बैठक ही निरस्त कर दी। कौन होते हैं? बोर्ड आफ मैनेजमेंट हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी एक्ट के किस सैक्शन में चांसलर को पावर है कि वह बोर्ड की बैठक स्थगित कर सकते हैं? पर सरकार को कुछ नहीं। जो टीचर्स के अपाइंटमेंट का प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस को स्टे कर दिया, क्यों कर दिया? यूनिवर्सिटी एक्ट की कौनसी धारा के अन्दर चांसलर को यह पावर है कि आप जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, उसको स्टे कर सकते हैं?

माननीय सभापति महोदय, डिक्टेट करके राजस्थान की सारी यूनिवर्सिटीज के अन्दर जो गन्दगी फैला रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार को सावधान कर रहा हूं कि आप इस पर खास तौर पर ध्यान दो। हम इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को यह देखना चाहिए कि जनहित में और लोकहित में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और यदि गलत हो रहा है तो चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, आपको कार्यवाही करने का साहस दिखाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिये अवसर दिया। मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व शिक्षा मंत्री रहे अजमेर से आने वाले माननीय विधायक ने पर्याप्त विस्तार से बातें कही हैं, मैं उन बातों का दोहराव नहीं करूंगा। मैं इस पवित्र सदन में दूसरी बार, दो बार पुराने विधान सभा भवन में था।

इस सदन में पूज्य बापू की मूर्ति के नीचे हम बैठकर जब बातें करते हैं, तो उनकी कुछ बातों को मैं याद करना चाहता हूं। 12 जून, 1936 को बंगलौर में हिन्दी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए उन्होंने लिखा था, जो दूसरे दिन हिन्दू अख़बार में छपा था। 'मातृभाषा किसी भी मनुष्य का चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, केवल मातृभाषा के माध्यम से ही पूर्ण मानसिक विकास सम्भव है और जो इससे असहमत हों, उन्हें मैं मातृभाषा का द्रोही समझूंगा।' इतने कठोर शब्दों में बापू हमको संदेश देकर गये हैं।

एक और अवसर पर वे कहते हैं 'मेरी मातृभाषा में कितनी भी कमियां क्यों न हों, मैं उससे उसी तरह चिपका रहूंगा, जैसे कि अपनी मां की छाती से। वही मुझे जीवनप्रद दूध दे सकती है।' ऐसे ही उन्होंने अलग-अलग मौकों पर और कहा है- 20 नवम्बर, 1909 में प्रकाशित हुआ था इण्डियन ओपिनियन अख़बार में, जो उन्होंने लंदन में गुजरातियों की सभा में भाषण देते हुए 05 अक्टूबर को कहा था- 'किसी समय में भारत की शिक्षा के सम्बन्ध में लार्ड मैकाले के विचारों के मोह में पड़ गया था। दूसरे लोग भी मोह में पड़े हैं, लेकिन मेरा वह मोह दूर हो गया। मैं चाहता हूं दूसरों का भी मोह दूर हो जाए।' मारवाड़ के गांधी का मोह कब दूर होगा, मुझे पता नहीं है।

ऐसे ही महात्मा गांधी हरिजन सेवक में 26 मई, 1946 को लिखते हैं। 'अंग्रेजी का प्रभाव और मोह कैसे मिटे, उसे मिटाना स्वराज की लड़ाई का बड़ा हिस्सा है। नहीं, तो स्वराज के मायने ही बदलने होंगे। गुलामी में गुलाम को अपने सरदार के रहन-सहन की नकल करनी पड़ती है। उसे सरदार का लिबास, सरदार की भाषा वगैरह की नकल करनी होगी। यहां तक कि रफ्ता-रफ्ता और कुछ पसन्द ही नहीं करेगा। जब स्वराज आयेगा, जब अंग्रेजी हुकूमत उठ जाएगी, तब अंग्रेजी का प्रभाव भी उठ जाएगा।' यह महात्मा गांधी कहकर गये 1946 में।

इस सारे के बाद में, वह और आगे बोलते हैं 20 नवम्बर, 1917 में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उन्होंने भरूंच में एक शिक्षा सम्मेलन में बोला - 'शिक्षा माध्यम विदेशी भाषा से हानि, विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की पद्धति से अपार हानि होती है। मां के दूध के साथ जो संस्कार और मीठे शब्द मिलते हैं, उसके और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिए, वह विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने से टूट जाता है। मां के दूध और पाठशाला में दी जा रही शिक्षा में मेल होना चाहिए। वह टूटता है अगर आप विदेशी भाषा में पढ़ाते हैं तो।'

उस सारे में परेशान होकर, बहुत गुस्से में आकर बापू एक बार कहते हैं 02 सितम्बर, 1938, काका कालेलकर की एक पुस्तक छपी, उसमें महात्मा गांधी को कोट किया गया है- 'अगर हमारे हाथ में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिये अपने लड़के और लड़कियों की शिक्षा बन्द कर दूं और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरन्त बदलवा दूं या उन्हें बर्खास्त करा दूं।' मैं पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी का इन्तजार नहीं करूंगा शिक्षा मंत्रीजी, महात्मा गांधी कह रहे हैं। वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे-पीछे चली आएंगी। यह एक ऐसी बुराई है, जिसका तुरन्त इलाज होना चाहिए।' महात्मा गांधी यह सब कहकर गये मातृभाषा के लिये। फिर भी आज हम अंग्रेजी से चिपक रहे हैं। अंग्रेजी को 70 साल में भी नहीं छोड़ पाये और छोड़ना तो दूर, हम ज्यादा चिपकते जा रहे हैं। हिन्दी माध्यम के विद्यालयों को हर ब्लाक में एक-एक विद्यालय बन्द करके हम अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय बना रहे हैं, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। नया नहीं खोला है, कन्वर्ट कर रहे हैं। अंग्रेजी के प्रति जो हमारा मोह है, उसको त्यागने के लिये भी महात्मा गांधी बार-बार हमको आग्रह करते रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल करने की बेकार कोशिश के बजाय हम ईमानदारी के साथ अपनी-अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में कुशलता हासिल करने की कोशिश करें। यह 20 सितम्बर, 1921 को श्रीरंगम में बोलते हुए महात्मा गांधी ने फरमाया था।

30 जनवरी, 1946 में मद्रास में वह बोलते हैं-'मातृभाषा की तुलना मां से की जा सकती है और अंग्रेजी के पक्ष में उसका त्याग करना मां का त्याग करने के समान है।' वह और आगे फरमाते हैं। महात्मा गांधी कह रहे है- जो अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं, वे अपने देश और समाज के द्रोही हैं।' 05 अक्टूबर, 1909 को उन्होंने लंदन में यह बात कही थी। मातृभाषा के प्रति इतना कठोर आग्रह था बापू का, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। जिनके

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

अनुयायी होने का सत्तारूढ़ दल दम्भ भरता है। हमारे मुख्य मंत्रीजी अपने आपको मारवाड़ का गांधी कहलाना बहुत अच्छा मानते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं। उन मारवाड़ के गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रभाषा की भी उपेक्षा हो रही है और मातृभाषा की उपेक्षा हो रही है। अब मातृभाषा कौनसी, इस पर मैं आता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यदि आपकी इजाजत हो, तो मैं इससे आगे का मेरा वक्तव्य मेरी मातृभाषा राजस्थानी में रखने की आपसे इजाजत चाहता हूं। मातृभाषा उसे कहते हैं, जो मेरी मां बोलती है। महात्मा गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि स्कूल में कोई बच्चा पढ़कर आवे और वह वापस आकर घर पर बताता है, वह मां-बाप को समझ में आना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या सीखकर आया। वह नहीं समझ पाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से जब बच्चा पढ़कर आता है और घर पर जाकर जॉनी-जॉनी यस पापा कहता है तो न तो मां को समझ में आता है और न बाप को समझ में आता है, न दादा को समझ में आता है और न दादी को समझ में आता है। भगवान जाने वह उल्टा सीख रहा है या सीधा सीख रहा है। मां-बाप को मालूम ही नहीं पड़ता। इसलिए यह स्थिति नहीं होनी चाहिए और जो मातृभाषा है, जो मां भाषा बोलती है, उस भाषा में अपनी शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए।

नई जो शिक्षा नीति 2020 में भारत सरकार ने जारी की है। बहुत सोच-समझ, विचार करके जारी की है। महात्मा गांधी रा दियोड़ा आदेश रे अनुरूप स्वीकार करी है। उनमें उनें कह्यो है कि प्रत्येक प्रान्त आप-आप री मातृभाषा में प्रारम्भिक शिक्षा देबारी व्यवस्था करें। प्रारम्भिक शिक्षा मतलब पहली सूं लेन पांचवीं तक री शिक्षा। पहली सूं पांचवीं तक री शिक्षा मातृभाषा में हो जाये। उनने बाद में आगे री शिक्षा जिन भी भाषा में वो लेवणी चाहवे, वह स्वतंत्र है। वह आगे जाण अपनी भाषा बदल सके।

सभापति महोदय, मैं आपणे निवेदन करूं कि मातृभाषा राजस्थान री कई हो सके, इण बारां में आपां विचार करां। देश आजाद हुयो। देश में राष्ट्रभाषा हिन्दी बननी चाहिजे, वह सब री इच्छा ही। महात्मा गांधी जी री भी इच्छा ही। नेहरू जी री भी इच्छा ही और भी सब विद्यानां री इच्छा ही, नेताओं री इच्छा ही। उनमें विचार-विमर्श हुआ रे बाद में उच्च स्तर माथै निर्णय हुयो के देश रा जितना प्रान्त है, उन प्रान्तां में जो आधा प्रान्त कह दैं कि हम हिन्दी भाषी हां तो हिन्दी राष्ट्रभाषा बन सके, नहीं तो ना बन सके। उन आधा री गिनती करबा लाग्या, वा गिनती कम पड़ गयी। गिनती कम पड़

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

गयी तो महर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन जो बहुत मोटा नेता हा अपना देश रा, विद्वान भी हा, लेखक भी हा, स्कॉलर हा, वे जयपुर पधार्‌या। जयपुर रा तत्कालीन राजप्रमुख और मुख्य मंत्री सूं चर्चा करी। मुलाकात करी। मुलाकात कर्‌या रा बाद निवेदन कर्‌यो कि बहुत जरूरी है हिन्दी न राष्ट्रभाषा बनावनी है तो राजस्थान खुद न हिन्दी भाषी राज्य घोषित करे।

सभापति महोदय, 1947-48 में आपने भी ध्यान है, अच्छी तरह यूं आपने खबर है। एक प्रतिशत आबादी भी मुश्किल हूं हिन्दी जानती व्हला राजस्थान री। उन माहौल में राजस्थान रो मन्त्रिमण्डल बिगर राजस्थान री जनता ने पूछ्यां, राजस्थान राजस्थानी विद्‌वानां सूं कोई चर्चा नहीं करी। पूछताछ नहीं करी। सलाह नहीं ली। सीधो मन्त्रिमण्डल प्रस्ताव पास कर दियो कि राजस्थान हिन्दी भाषी प्रदेश है। जणां जार हिन्दी राष्ट्रभाषा बनी। मनैं कोई तकलीफ नहीं उन बातां सूं। मनैं गर्व है। पन्ना धाय रा वंशज हां आपां तो। राजा रा बेटा न बचार वास्ते खुद का बेटा न मरार परम्परा रही है अठै। उन परम्परा रो आपां निर्वहन कर लियो। हिन्दी न स्थापित करवारे वास्ते, हिन्दी न मजबूत करवारे वास्ते राजस्थानी त्याग करयो। उन बात रो मनैं गर्व है। कोई शिकायत नहीं।

सभापति महोदय, शिकायत आ है कि पुरुषोत्तम दास टण्डन साहब जयपुर रुं जाती वक्त आश्वासन देर गया हा, विश्वास दिलार गया हा कि मैं दिल्ली जातो ही राजस्थानी री पूरी पैरवी करूंला। राजस्थानी रो मान-सम्मान, इज्जत रो पूरो ध्यान राखूंला। वो राजस्थानी रो मान-सम्मान, इज्जत रो ध्यान आज तक नहीं राखिजो। राजस्थानी उपेक्षित होती जा रहयी है। दुर्भाग्य अठै आ गियो है कि आज राजस्थान रा जाया, जन्मा आपणां इण सदन में बैठ्या लोग भी पूछे कि कई राजस्थानी? राजस्थानी तो भाषा है कई? राजस्थानी भाषा है कि नहीं है, वह मैं बोल्यूं तो आपां न विश्वास नहीं हवे। कोई अंग्रेजी वालो, मोटो विद्‌वान बोले तो विश्वास हवे।

सभापति महोदय, उन बारे में मैं आपणे विश्वास दिलाऊं कि राजस्थानी रै वास्ते कुण कांई कहयो है। कर्नल टॉड, एक मोटा अंग्रेज अफसर हा, लेखक हा। पूरा भारत में फिर्‌या हा। राजस्थान में भी फिर्‌या हा। राजस्थानी रो इतिहास लेखन में कर्नल टॉड ने अथॉरिटी मानी जाय। विश्वसनीय मानी जाय कि वनैं जो लिख्यो है वह सही लिख्यो है। वनैं भी राजस्थान में फिरता वकत या बात कही कि जो राजस्थानी भाषा है वा अठा री भाषा है। वनैं भी स्वीकार कर्‌यो और कई जगहां किताबां में लिख्यो।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उनैं बाद 1912 में जार्ज गियर्सन लन्दन हूं अठै पधार् या। लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया पूरो आयोजन कर्यो। पूरा देश री भाषां को उनां आंकलन कर् यो। सर्वे करयो और सर्वे करवारे बाद वनैं रिपोर्ट में राजस्थानी भाषा रो उल्लेख कर्यो। उन जमानां में वनैं राजस्थान री 5 बोलियां मुख्य रूप सूं स्वीकार करी। जिनमें हाड़ौती है, मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, अडी मुख्य रूप सूं 5 बोलियां वनैं स्वीकार करी। डा. जार्ज गियर्सन 1912 में लिखर गया।

उनने बाद एक टेसिटोरी विद्वान हा, भाषा विज्ञानी हा। वह भी आया। उनैं भी अठै खूब सर्वे करयो। राजस्थानी भाषा रै माथे ऑथैंटिक सर्वे सबूं पहिलो जो लिखत-पढ़त हुई वा टेसिटोरी टाइम में हुई। वह जर्मनी हूं आया हा। भाषा विज्ञानी हा। उनैं बहुत अच्छी तरहां उन भाषा नै समझी और उन री पक्ष में बहुत जबरदस्त पैरवी करी। उनने बाद में राजस्थानी रा कई विद्वान व्हये गया। जनै बहुत शोध इन भाषा माथे करी। बहुत कुछ इन भाषा माथै लिखयो।

डा. सीताराम लालस अपनां एक विद्वान हुया। जिन्हां ना भारत सरकार बाद में पद्मश्री दियो, राजस्थानी भाषा माथै करेड़ा काम रै आधार माथे। आपां कई बार मजाक में और अज्ञान रै बस में कहवां कि राजस्थानी में कठै है कोई भाषा शब्दकोष, इनो व्याकरण कठै है। डा. सीताराम लालस जो 1909 में पैदा हुया हा। वे पद्मश्री प्राप्त करी भारत सरकार हूं। इन आधार माथै कि उनां राजस्थानी रो शब्दकोष लिखयो। 7,700 पेजां रो शब्दकोष है। 7,700 पृष्ट और लगभग 11 खण्डां में संकलित है। उनमें ढाई लाख बेसी राजस्थानी रा शब्द हैं। ढाई लाख रा शब्दां रो शब्दकोष, 11 खण्डां में 7,700 पेजां में सम्पादित करयो। उन शब्दकोष नै पूरी दुनिया मान्यता दी है। अबार-अबार ही, साल-दो साल पहले ही उन रो डिजीटल प्रूफ करायो है। पूरो शब्दकोष 7,700 पेजां रो ढाई लाख शब्दां रो शब्दकोष डिजीटल फार्म में ऑनलाइन करयो है।

उन ऑनलाइन करयोड़ा डिजीटल स्वरूप नै अमेरिका री बहुत मोटी शिकागो यूनिवर्सिटी, दुनिया में फेमस है, आप सब जानो उन नै। शिकागो यूनिवर्सिटी का सहयोग सूं डिजीटल फार्म ऑनलाइन हुयो है। शिकागो यूनिवर्सिटी उनमें कमेंट है, 'दक्षिण एशियाई भाषाओं के शब्दकोषों में राजस्थानी को भी अपनी वेबसाइट पर औपचारिक रूप से शिकागो यूनिवर्सिटी ने जोड़ा'। दक्षिण एशिया मैं जितनी भी भाषाएं बोली जायं, उनमें राजस्थानी नै आज, अबार 21वीं सदी में अमेरिका री शिकागो यूनिवर्सिटी, उन नै बहुत समृद्ध भाषा मानी और उन रा डिजीटल फार्म नै ऑनलाइन करबा मैं बहुत

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सहयोग करयो और महत्व दियो। शिकागो यूनिवर्सिटी में राजस्थानी री पढ़ाई री भी व्यवस्था है। राजस्थानी में डिग्री मिले। राजस्थानी में उठै पीएचडी हो रही है। अमेरिका री 2-3 यूनिवर्सिटी और भी हैं वठै भी राजस्थानी पढवा री व्यवस्था है।

उनी राजस्थानी री बारा में एक और पद्मश्री अवार्ड मिल्यो विजयदान जी देथा साहब नै। क्यों मिलयो? राजस्थान री जितनी लोक कथा हैं, पूरा राजस्थान म 33 जिला हैं। जितनी री लोक कथा प्रचलित हैं, उन सबरो उन नै संग्रह करयो और राजस्थानी में छापयो। 'बातां री फुलवारी' नाम हू, बातां री फुलवारी किताब रा कितनां खण्ड हो सकै, कल्पना करो, 14 खण्डों में वा किताब छपयोड़ी है। उन बातां री फुलवारी किताब रै कारण इण विजयदान जी देथा साहब नै पद्मश्री अवार्ड मिलयो। उन्हीं विजयदान जी देथा 'राजस्थानी हिन्दी कहावत कोष' संपादित करयो। दुनिया री कोई भी भाषा मैं इतरी कहावत और इतरा मुहावरा नहीं जितरा राजस्थानी में है। कहावत कोष विजयदान जी देथा साहब संकलित करयो, संपादित करयो और छपायो। राजस्थानी में लघु कथा, शोर्ट स्टोरीज, छोटी-छोटी, 800 रा लगभग लघु कथा विजयदान जी देथा साहब लिखी। उन आधार माथै, उन रा सब काम री आधार माथै पद्मश्री तो भारत सरकार दियो ही दियो, नोबेल पुरुस्कार वास्तै नाम भेजयो। राजस्थानी भाषा रा विद्वान रो नाम, राजस्थानी माथै करयोड़ा काम रै आधार माथै नोबेल पुरुस्कार वास्ते भारत सरकार नामित करयो। इतरो महत्व राजस्थानी रो मानी गयो। उन नै बाद भी 70 सालूं राजस्थानी इन्तजार कर रही है और खुद रा बेटा मुहंडा कहवे कि राजस्थानी? किसी राजस्थानी और कैड़ी राजस्थानी? तो ओ म्हारों आपने निवेदन है के नई शिक्षा नीति लागू होइजरी है। और नई शिक्षा नीति लागू होरी है तो उणमे स्पष्ट निर्देश है कि प्रारम्भिक शिक्षा, पांचवीं तक री शिक्षा आपणे मातृभाषा रे माध्यम सूं मिलणी चाहिजे। तो मातृभाषा आपणी जो है, राजस्थानी ने राजस्थान सरकार मान्यता देवे सबसू पेली तो। आपणो 1956 रो एक्ट है, राजस्थान आफिशियल लैंग्वेज एक्ट, उणमें सिर्फ एक हिन्दी भाषा लिखयोड़ी है। उणमें संशोधन लाओ, और उणमे राजस्थानी जोड़ो। राजस्थानी भाषा रो आप्शन देओ। और राजस्थानी माथे यदि किणने भी आब्जेक्शन है, जियां म कह सकूं, भरतपुर, धौलपुर, जो पांच-सात जिला हैं, जठे बृज भाषा ज्यादा चाले, बठे राजस्थानी समझ में न आवे। म पूरो राजस्थान फिरयो हूं, बार-बार फिरयो हूं और भाषा रे प्रति म्हारी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

रुचि है, भाषा विज्ञानी नहीं हूं मैं, विद्वान भी नहीं हूं पण भाषा रे प्रति म्हारी उत्सुकता है, रुचि है और इण वास्ते मैं जठे भी जाऊं, उठारी भाषा ने समझ बा री कोशिश करूं तो बृज प्रदेश में राजस्थानी समझ म नहीं आवे, मैं स्वीकार करूं। इण सदन ने भी स्वीकार करणो चाहिजे। राजस्थानी साथे बृज न भी डाल दो। उण पांच-सात जिला में बृज भी पढ़ाई हो जावे, बाकी जिला म राजस्थानी में पढ़ाई हो जावे। इणमें आप कह सको कि राजस्थानी भाषा रे माध्यम सूं किं कर पढ़ाई हो सके है तो सारी दुनिया ओ काम करयो है, आपां कोई नवे री तरह ना कर रया हां।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी फरमायो, 25 अगस्त, 1946 में 'हरिजन' में छाप्यो, 'रूस ने अंग्रेजी के बिना विज्ञान में इतनी तरक्की की है, आज अपनी मानसिक दासता की वजह से ही हम यह मानने लगे हैं कि अंग्रेजी के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। मैं इस पराजयवादी विचार को कभी नहीं मान सकता।' रूस कर सके है मेडिकल री पढाई, रूस म रशियन लैंग्वेज में हुवे थी, रूस टूट ग्यो, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट आफ सोवियत रशिया, बिखर ग्यो, 15-20 देश बणग्या, किर्गिस्तान बण ग्यो, अबार जो लड़ाई चाल री है वो यूक्रेन बन ग्यो, उण देशां इन तीन साल में, तीस साल हुया उण ने नवो देश बण्या, रशियन में तो पढ़ाई चाले ही चाले, काल ही म्हे, वा बच्ची जो जालौर में आयी है यूक्रेन सू, उणरे घरां गया, दिशा सांखला, उणसे मिल र आयो, उण से पूछ्यो म कि थे किण भाषा में पढ़ाई करी? यूक्रेन में किण भाषा में मेडिकल पढ़ाई पढावे? वा कही, या तो रशियन में पढ़ावे या यूक्रेनियन में पढ़ावे, इंग्लिश नहीं। जापान में इंग्लिश नहीं, जर्मनी में इंग्लिश नहीं, फ्रांस में इंग्लिश नहीं, चीन में इंग्लिश नहीं, कोरिया में इंग्लिश नहीं, कठै ही इंग्लिश नहीं, आपां ही ठेको लियोड़ो है इंग्लिश म? जब रशियन लैंग्वेज म मेडिकल साइंस पढ़ सके है, रशियन लैंग्वेज म स्पेस साइंस पढ़ सके है, तो हिन्दी म क्यूं नहीं पढ़ सकां? राजस्थानी में क्यूं नहीं पढ़ सकां? तमिल म क्यूं नहीं पढ़ सकां? गुजराती म क्यूं नहीं पढ़ सकां?

माननीय सभापति महोदय, हिम्मत री जरूरत है इण म, आत्मविश्वास री जरूरत है। मैं धन्यवाद देणो चाहूं हूं भारत सरकार न, भोपाल म मेडिकल कालेज नवो स्थापित व्हेयो है, जणमे हिन्दी माध्यम सूं शिक्षा देवेला, मेडिकल साइंस, एमबीबीएस की डिग्री हिन्दी माध्यम सू। और भी पांच-सात जगह इंजीनियरिंग कालेज भारत सरकार खोल्या है जणमें हिन्दी माध्यम

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सूं शिक्षा देणे री व्यवस्था व्हेगी। तकनीकी शिक्षा, विज्ञान री शिक्षा, मेडिकल शिक्षा भी हिन्दी माध्यम सूं देवा री तैयारी कर ली है। बाकी सब स्टेटां भी तैयारी कर रह्या है तो आपां क्यूं नहीं कर सकां? हिम्मत करो, आपणी मां न मान देराओ। आपणी मां ने मान देराओ और आपणी पीढ़ी रे साथे और संस्कृति रे साथे न्याय कराओ।

माननीय सभापति महोदय, भाषा संस्कृति रो वाहन है। संस्कृति एकजगै सूं दूसरी जगै भाषा से माध्यम सूं जावे। जिण दिन राजस्थानी भाषा लुप्त हो जावेला राजस्थानी संस्कृति भी विकृत हो जावेला, लुप्त हो जावेला, नहीं रवेला। आ जो गांवां म संस्कृति है वा शहरां म नहीं रही। तो वा एक मोटी दिक्कत आपणे सामने आणे वाली है।

माननीय सभापति महोदय, इणमें मोटो फायदो और कांई होवंला म बताऊं थानै। मोट्यार लोग पूछे, म्हाने कांई मिले? राजस्थानी माध्यम सूं प्रारम्भिक शिक्षा देवणी जिण दिन आप शुरू करोला तो पैलां तो काम मिलेला उण विद्वान लोगां न, शिक्षा शास्त्रियां न जो सिलेबस बणावेला। दूसरी किताबां लिखेला। उण रे बाद दूजो काम मिलेला अध्यापकां न जो उण राजस्थानी रा माध्यम सूं टाबरां न शिक्षा देवेला। राजस्थानी पढ्योड़ा टाबरां न मौको मिलेला, राजस्थानी म बीए, एमए, पीएचडी, बीएड, जणै करेड़ा है, उण लोगां न नौकरयां मिलेला।

माननीय सभापति महोदय, उण सूं भी आगे आपणे माध्यम सूं विशेष रूप से सदन रे ध्यान में लाणूं चाव्हूं, आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस, बारलां प्रदेशां सूं आ री यहां का धणी हो जावै। क्यों? क्योंकि आपरां विद्यारथ्या वास्ते, आपरां मोट्यारां वास्ते आपणी राजस्थानी भाषा नहीं है। राजस्थानी भाषा रो एक पेपर अनिवार्य होवेला, आरएएस म, आरपीएस म और आईएएस म भी जिण दिन अनिवार्य होवेला, उण दिन देखो राजस्थान रा कितरा टाबरां रो सलेक्शन होवेला। कितरा आईएएस बणेला, कितरा आईपीएस बणेला, एक चमत्कार हो जावेला। वो प्रिविलेज मिलेला राजस्थान रा बच्चा न, विशेषाधिकार मिलेला, उण भाषा म उण पेपर में जितरा नम्बर उण न मिलेला, उतरा तो वां न ना मिल सकेला, कोई नहीं ले सके तो वो एक मोटो फायदो आगे जाकर होणो है, और भी कई तरह रा रस्ता खुलेला। रोजगार रा रास्ता भी खुलेला। कोचिंग सेंटर भी खुलेला, और भी कई चीजां होगी। इण वास्ते इण भाषा न आगे बढ़ाणो बहुत जरूरी है। आगे बढ़ावां वास्ते मैं आपणे निवेदन

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

करूं, राजस्थान सरकार ने आपरे माध्यम सूं कि सबसूं पैली तो आप राजस्थान आफिशियल लैंग्वेज एक्ट म संशोधन कराओ, राजस्थानी, बृज उण म डाल दो। उण रे बाद में राजस्थानी रा जतरा विद्वान है, ओ झगड़ो पैदा होवेला, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, आ संकट आवेला। मैं लारला लगभग चालीस साल सूं इण आन्दोलन सूं जुड़ेड़ो हूं तो ओ झगड़ो तो है। वो झगड़ो मिटाबा वास्ते आपां अधिकृत नहीं हां। किसी राजस्थानी, हाड़ौती या ढूंढ़ाड़ी या मारवाड़ी, आपां तय नहीं करेला क्यूं कि आपां उण रा विषय विशेषज्ञ नहीं हां। जो विशेषज्ञ है, भाषा शास्त्री है, शिक्षाविद् है, उन विदानां री कमेटी बणा ल्यो, चार जणा मारवाड़ी वाला ले ल्यो, चार ढूंढ़ाड़ी वाला ले ल्यो, चार हाड़ौती वाला ले ल्यो, चार मेवाड़ी वाला ले ल्यो, और उण सबरी कमेटी बैठ र तय करे एक मानक रूप। लिखित में एक मानक रूप, बोली म तो फर्क रव्हेला ही, बोली म फर्क दुनिया री कोई ताकत नहीं मिटा सके। बोलियां तो रव्हेला ही, राजस्थानी में एक कहावत है कि बारह कोसां बोली पलटे, बारह कोस, आज की तारीख में गिन लो आप 35-40 किलोमीटर पर, बोली म परिवर्तन आवेला ही आवेला। बारहां कोसां बोली पलटे, तरवर पलटे शाखा, पेड़ म डालियां निकले तो रूप बदल जावे, बुढ़ापा में केश पलटे, लखण न पलटे लाखां। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता है, बाकी सब बदल सकता है।

श्री सभापति: कंक्ल्यूड करें माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर): माननीय सभापति महोदय, बोलियां तो रव्हेला ही, बोली समाप्त नीं होव्हेला, विशेषकर इ राजस्थान म तो, एक गांव में पांच बोल्यां मिलेला। विश्नोइयां री बोली अलग है, पुष्करणा ब्राह्मणां री अलग है, श्रीमाली ब्राह्मणां री अलग है, जाटां री बोली अलग है। राजपूतां री अलग टोन हो जावे, अलग शब्दावली हो जावे। अतरो फर्क है। अग्रवालां री बोली अलग है, ओसवालां री अलग है, माहेश्वरयां री बोली अलग है, माहेश्वरयां म भी जो राजस्थान रा है उणकी बोली अलग है और सिन्ध सूं, छाछरां सू आयोड़ा है वांकी अलग है। वो फर्क रव्हेला उण न अपण ना मिटा सकां।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन लिखित में, प्रिंट में जो भाषा जाये, वो उस भाषा का एक स्टेंडर्ड रूप होना चाहिए, एक मानक रूप होना चाहिए। वो विद्वान तय करे, वो हमारा विषय नहीं है। हम तो केवल इतना कर दें, उन विद्वानों को अधिकार दे दें कि राजस्थानी भी एक अधिकृत भाषा है, राजस्थान की राजभाषा के रूप में अधिकृत है, मान्यता प्राप्त है, यह चिन्ता

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

हम कर लें तो बाकी का काम विद्वान लोग कर लेंगे, बहुत सक्षम लोग बैठे हैं। बहुत समृद्ध भाषा है, व्याकरण भी लिखा हुआ है, शब्द कोश भी है, हमारे अलमारियां भरी पड़ी हैं, राजस्थानी की किताबों से, सिर्फ कमी है हमारी यहां की इच्छा शक्ति की, सरकार की इच्छा शक्ति की, सदन की इच्छा शक्ति की। जैसे हमने 2003 में संकल्प पारित किया था इसी पवित्र सदन में, उसी भावना के अनुरूप हम इसी सदन में इस एक्ट में संशोधन करें और राजस्थान के बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो आज भी हिन्दी नहीं जानते हैं, आज भी उनको मार मारकर सिखानी पड़ती है हिन्दी और इंग्लिश, स्वाभाविक जिस भाषा में वो बोल रहे हैं, उस भाषा में उनको पढ़ने का अधिकार मिले, यह इस पवित्र सदन का दायित्व है, इस सरकार का दायित्व है, उसको हम निभायें और राजस्थानी को ठीक से, सम्मानजनक स्थान प्रदान करें। हम करेंगे तो भारत सरकार अपने आप करेगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर): भारत सरकार ने इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से आपको पूरा अवसर दिया है, जो इस अवसर को चूकेगा तो फिर आने वाले पच्चीस-पचास साल तक उम्मीद नहीं कर सकता, राजस्थानी भाषा अपना अस्तित्व खो देगी, भविष्य खो देगी। इसलिए बार-बार मैं आपसे, सदन से करबद्ध निवेदन करता हूं कि डेढ़ सौ से ज्यादा विधायक लिख कर दे चुके हैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, डेढ़ सौ से ज्यादा विधायक लिख कर दे चुके हैं और 25 से अधिक विधायक अभी ध्यानाकर्षण दे चुके हैं कि राजस्थानी को आफिशियल लैंग्वेज बनायें। उस पर कृपया आप ध्यान दें, यह मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आप रो घणो-घणो आभार।

श्री सभापति: सुश्री दिव्या मदेरणा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सभापति महोदय, इस सदन में इस सत्र में मैं पहली बार बोल रही हूं। शिक्षा पर आज हम वादविवाद कर रहे हैं। जीवन में परिस्थितियां सिखाती हैं, चुनौतियां सिखाती हैं, स्ट्रगल्स एजुकेट करते हैं, hardship and betrayal आपको वाइज बनाते हैं, डिफिकल्टीज आपको जीवन में मैच्योर करती हैं और बहुत सारे लोग आपको मेंटोर करते हैं।

My grandfather was also a great role model for me. My

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

mother was that umbrella which kept us safe and secure during these turbulent times. But, my dad was my real hero without a shadow of doubt and will always be. I will start by paying a tribute to my Late. Father Shri. Mahipal Maderna in this House. इस सदन के प्रथम दिन अध्यक्ष महोदय जब मेरे पिता की शोकाभिव्यक्ति पढ़ रहे थे और मैं सुन रही थी, जज्बात इस कदर पेचीदा हुए और मैं सोच रही थी कि कितनी अनफार्च्युनेट, कितनी अभागन हूं कि इस पल मैं यह सुन रही हूं। शायद किसी और बच्ची को इस दौर से, इस समय से नहीं गुजरना चाहिये कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन उसी क्षण मैं अपने आपको बहुत प्रिविलेज्ड भी महसूस कर रही थी कि कितने विश्वास के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी देकर गये हैं कि मैं इस सदन में बैठकर उस शोकाभिव्यक्ति का हिस्सा बन रही हूं।

जब मैं शाम को गयी, कलम लेकर कागज पर अपने जज्बातों को उतारने के लिये तो अल्फाजों के पिटारे में मुझे शब्द नहीं मिले और निदा फ़ाजली की गजल मुझे उस वक्त याद आयी। वे जब यूरोप में पढ़ने गये, उन्होंने अपने पिता के ऊपर लिखी तो यूरोप की एक लेखिका ने उनसे कहा कि आप अपने पिता के मरने पर अभी भी लिखते हैं? इस पर निदा फ़ाजली ने कहा कि मैं जिस तबीयत से आता हूं, वहां पिता कभी नहीं मरते। हर पिता की मौत में सन्तान की मौत होती है। मैं उस गजल को इस सदन में पढ़ना चाहती हूं-

"तुम्हारी कब्र पर मैं फ़ातेहा पढ़ने नहीं आया,
मुझे मालूम था, तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते।
मेरी आंखें तुम्हारी मंजरों मे कैद हैं अब तक,
मैं जो भी देखता हूं, सोचता हूं,
वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी।
कहीं कुछ भी नहीं बदला,
तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं,
मैं लिखने के लिये जब भी कागज कलम उठाता हूं,
तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी कुर्सी में पाता हूं।
बदन में मेरे जितना भी लहू है

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

वो तुम्हारी लगजिशों नाकामियों के साथ बहता है,
तुम्हारी आवाज मेरे जेहन में बोलती है, मेरे जेहन में रहती है,
मेरी लगजिशों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम,
तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है, वह झूठा है,
तुम्हारी कब्र में मैं दफ़न हूं और तुम मुझमें यहां ज़िन्दा हो"।

वे चाटुकारिता की राजनीति से कोसों दूर सच को सच कहने का साहस रखते थे। दल, नीति, व्यक्ति, जो कोई भी किसान विरोधी रहे, उनके प्रखर आलोचक रहे वे। राजनीतिक नफ़ा-नुकसान नहीं देखा और यही कारण है कि उनका राजनीतिक जीवन संघर्षों में कटा। धैर्य के महासागर रहे और आशा के पर्याय रहे एक दशक में शिकन और चुनौतियों की बेबसी शायद हमारे चेहरे पर नजर आयी, पर उनके चेहरे पर कभी नजर नहीं आयी।

उन्होंने मुझे कर्ण की एक किताब महामृत्युंजय दी। कर्ण में विश्वास रखते थे वे। कर्ण वही था, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के बाद भी छल से मारा गया था, जिसका पहिया धंसा और फिर कृष्ण ने अर्जुन से उस पर वार करने को कहा था, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि उस युद्धभूमि में जीत के लिये कर्ण का मरना अनिवार्य था, इसलिये मैं बड़ी दृढ़ता से विश्वास करती हूं, लाभ-हानि, जीवन-मरण, यश-अपयश, विधि-हाथ, कर्तव्य और कर्म की चुनौती उन्हें स्वीकार थी। The wheel of life and was very hard over him, पर मौत के मंजर को भी उन्होंने आंख में आंख डालकर देखा। He was a true fighter. I salute him and I am a proud daughter of Mahipal Maderna, and this is what will drive my life forward. मैं उनकी आवाज और दूत बनकर काम करूंगी। It's an incredible loss for us. जान चली गयी, लेकिन सांसें रह गयीं।

"दिल तेरे ग़म को सह गया कैसे,
आग में फूल रह गया कैसे।।"

मैं यह इसलिये कहना चाहती हूं कि एजुकेशन की दो अप्रोच होती हैं cognitive and non-cognitive माहौल, environment, capacity building, teamwork, and ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से दिया जाता है। अपनी बच्चियों को पढ़ाइये। उसे वह माहौल दीजिये। उसे दोनों एजुकेशंस की अप्रोच दीजिये। उसे वह आत्म विश्वास दीजिये। उसे वह क्वालिटी एजुकेशन दीजिये कि वह खड़ी होकर अपने लिये बात कर सके।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आज जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है, मैं बड़ी आश्चर्यचकित होती हूं उसे देखकर। हिजाब, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कर्नाटक में क्या हुआ और फिर देश के कोने-कोने में किस तरह से वह फैला। How contagious it became. यह तो हम अमृत काल में नहीं आ रहे। This is not a new India. This is not an India at 75. आजादी के बाद का यह परिदृश्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहां जा रहे हैं। आज के अख़बार में था कि हम अगले साल चान्द पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और यहां हम हिन्दू-मुसलमान, हिजाब-बेहिजाब, नकाब-बेनकाब पर बात करते हैं।

पहले गाने बनते थे, "बेहिजाब आ गये हो" और अब हिजाब पहनकर आते हैं तो उस पर भी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि cognitive approach और non-cognitive approach बराबर डालने की जरूरत है। हमें उन बच्चियों की अक्ल पर काम करना है। उन्हें पढ़ाना है। उन्हें वह माहौल देना है। पूरे विश्व में हमारा सिर झुका। यह नये भारत की कल्पना है? हमारे संविधान के निर्माता अनुच्छेद 25 में सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने और धर्म के अनुरूप आचरण की स्वतंत्रता देते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन में गरिमा से जीने का अधिकार देता है। फिर यह छींटाकशी क्यों?

यूनिफार्म की बात करने वाले, जो कहते हैं कि यूनिफार्म होनी चाहिये, आप नयी लेकर आयेंगे, मैं यह कहती हूं कि चाहे सिन्दूर लगाकर आये, चाहे सिख अपनी टरबन पहनकर आये, उसे एजुकेशन से मत रोकिये। वह बच्ची, जिसका हिजाब खींच लिया, वह कभी उस शिक्षण संस्थान के द्वार पर नहीं आयेगी। आपने उस पर किस प्रकार का प्रहार किया। वे कोर्ट इसलिये गये, क्योंकि उनके एग्जाम्स नहीं हो पा रहे थे। उनके घर जाइये, उनके एग्जाम लीजिये। उसकी सोच को इतना इंडिपेंडेंट, इतना विकसित करिये कि वह अपना निर्णय स्वयं ले सके कि मुझे हिजाब पहनना है या नहीं। यूनिफार्म की बात करने वाले लोग वही हैं, जो स्कूल के गरीब, कुपोषित बच्चों की मिड-डे मील में अण्डा नहीं खाने देते।

धर्म-निरपेक्षता और वैज्ञानिकता की बात करने वाले लोग इन बच्चों को सिस्टमैटिक सोच के साथ कमजोर और बौना बना देना चाहते हैं। तकलीफ पता है किस बात की है इन्हें? तकलीफ इस बात की है, चाहे वह मुस्लिम लड़की हो, कोई और लड़की हो या कोई और बच्चा, बहुसंख्यकवाद को चुनौती देता है, वह इनसे बर्दाश्त नहीं होता। एक असुरक्षा का माहौल पैदा होता है,

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

क्योंकि परदे के पीछे ये हिन्दुत्व और आरएसएस का एजेंडा एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके से लाना चाहते हैं, पंगु बना देना चाहते हैं।

पहले एक नारा दिया था, "नहीं होगा महिलाओं पर वार, अबकी बार मोदी सरकार।" कहां है मोदी सरकार? "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" के नारे देने वाले, लाल किले की प्राचीर से बेटियों को और सशक्त करने वाले, आज यह माहौल बन गया है, कौन जिम्मेदार है देश में इस माहौल के लिये? 2014 से, 2014 में ही आये थे मोदी जी, कौन-सा काल लगा, शनि काल मान लीजिये, राहू काल मान लीजिये, क्या व्यवस्था दी आपने कि हमारा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2014 से स्लिप होता चला गया। 2021 में हम 165 से 119 लेकर आ गये। फिर मैंने दूसरे फ्रीडम इंडेक्सेज देखे इंडिया के, economic freedom - partly free, press freedom - mostly unfree, democracy India - difficult situation और वह तो हम देख सकते हैं कि आजादी के बाद हमारी सिचुएशन आज लोकतंत्र में कितनी डिफिकल्ट हो गयी।

मैं दूसरा ध्यान आपका ऑनलाइन शिक्षा की तरफ केन्द्रित करना चाहूंगी। मुझे नहीं लगता कि सदन में यहां से आने वाले लोग नेशनल एजुकेशन पालिसी पर बोलेंगे। सदन के उप-नेता ड्राफ्ट को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पालिसी नहीं पढ़ी। पढ़ी होती तो ये सब शिक्षा के वाद-विवाद में हिस्सा नहीं लेते। ऑनलाइन लर्निंग पर भी वह फोकस करती है और मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूं। यह भी नीति आयोग एक बायजूस करके ऑनलाइन क्लासेज लेकर आया जो पूरी की पूरी फ्रॉड थी। जो आपने कोरोना में चार घण्टे के अन्तराल पर बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया, सोचा भी नहीं कि मजदूरों की क्या हालत हुई, सबकी क्या हालत हुई और वहां शिक्षण संस्थानों में बच्चों की क्या हालत हुई, वह दयनीय है।

एक रिपोर्ट कहती है कि 70 प्रतिशत लोगों के पास में मोबाइल, इंटरनेट नहीं था, 9 प्रतिशत के पास में थे और वह भी जब पिता घर पर आते तो मिलते और लड़कियों को तो वे भी नहीं मिलते थे। ऑनलाइन कक्षा में क्या होता है? यू-ट्यूब पर आप देखते हैं कि सुनना चाहो तो सुनो, नहीं सुनना चाहो तो मत सुनो, कुछ सुन-सुनकर पागल हो रहे हैं और जिनको पढ़ाये आप प्रमोट कर रहे हैं वे बिना सुना जाहिल बन रहे हैं। किस तरीके की गुणवत्ता भरी एजुकेशन हम देना चाहते हैं, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

विशेष रूप से जब हम लॉकडाउन या कोई पेंडेमिक में प्रतिबन्ध करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि किस मौहल्ले या कहां पर आये वहीं पर करें। तुरन्त एक नीति लागू नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे हमारे बच्चों पर, हमारे एजुकेशन सिस्टम की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। यह ऑनलाइन शिक्षा के पीछे इनका एक प्रयोग और है। The National Education Policy अगर आप between the lines पढ़ें तो it is imposing the Hindutva RSS agenda in educational institutions. यह सेंट्रलाइज कर देना चाहती है, सब कुछ केन्द्रीयकरण करना चाहते हैं। हम बात करते थे गवर्नेंस को विकेन्द्रीकृत करने की। सभापति महोदय, आपको पता है कि आपके जमाने में एक साक्षरता अभियान चलाया जाता था और उसमें ढाणी-ढाणी एजुकेशन ले जायी जाती थी। लोक जुम्बिश और किस तरीके के उसमें कार्यक्रम करते थे और अब ये चाहते हैं कि सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाये। उस सेंट्रलाइजेशन के अन्दर जो कार्यक्रम पढ़ाया जायेगा वह भी यह तय करेंगे और स्टेट्स उसको एडाप्ट करेंगी। कितना कम्युनल एजुकेशन को करना चाहते हैं वह आप देखिये कि कितने सिस्टेमेटिक तरीके से करना चाहते हैं। इस सेंट्रलाइजेशन के पीछे क्या हाथ है? इसके पीछे भी बड़े-बड़े कारपोरेट्स हैं। वह पूंजीवादी व्यवस्था, जिसके ये हिमायती हैं, वह आज एजुकेशन में भी झलक रही है।

डिजिटल इण्डिया की बात इन्होंने की थी, क्या हाल है उस डिजिटल इण्डिया का? कितने लाख गांवों को आपको जोड़ना था और कुछ हजार गांव आप इंटरनेट से नहीं जोड़ पाये, सिर्फ शहर में इंटरनेट मिलता है। आपने एक डिजिटल डिवाइड क्रियेट कर दिया। राहुल गांधी जी सदन में कह रहे थे कि आप दो हिन्दुस्तान बना रहे हैं, एक गरीब का, एक अमीर का और वही हो रहा है। डेटा नहीं है, पैकेजेज नहीं हैं, मोबाइल नहीं हैं, स्मार्ट फोन्स नहीं हैं तो किस तरीके से वह बच्चा पढ़ेगा, क्या समझ पायेगा? हम अगर किसी से मिलते हैं, स्कूल में किसी को खेलते हुए देखते हैं तो प्रभावित होते हैं कोशिश करते हैं। लेकिन हम मोबाइल पर क्रिकेट देखते हैं तो हर कोई प्रभावित नहीं होता, फिर हम श्रोता ही बनकर रह जाते हैं। हमें टेक्निकली इक्यूप्ड बनाइये, ठीक है, लेकिन आप पूरे एजुकेशनल सिस्टम को ऑनलाइन पर मत कीजिये, यह हमारे लिए बहुत घातक है। मेरे पास एक बच्ची का पत्र है जिसने मुझे लिखा कि मैं पिछड़ चुकी हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तीन क्लास पीछे हो चुकी हूं। उसके नम्बर भी हैं। मुझे ऑनलाइन शिक्षा में कुछ समझ में नहीं आता और मैं आज जिस परिस्थिति में दो क्लास पीछे हो गई हूं, मुझे वहां पर

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

कुछ नहीं आया और पहले जो पढ़ा था वह मैं सब-कुछ भूल चुकी हूं। एजुकेशन ऐसी चीज है जिसे निरन्तर प्रयास चाहिए, अभ्यास चाहिए और अगर गैप आ जाता है तो ब्लैंक हो जाते हैं।

मंत्री महोदय जी, इसके बाद मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं जो बहुत जरूरी है कि जब हम ऑनलाइन कक्षा की बात कर रहे हैं तो आज लाइब्रेरीज की कोई बात नहीं कर रहा है। हम स्कूल तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि जब हम सब कुछ, बुक्स ऑनलाइन कर रहे हैं, हर किताब का एक ऑनलाइन वर्जन आ जाता है तो आजकल लाइब्रेरीज और पुस्तकालयों का कोई महत्व नहीं रह जाता। मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी इस सदन की लाइब्रेरी में कोई दिखता होगा, कोई एकाध एमएलए जाते हैं और कोई नहीं जाता, कोई उसका यूज नहीं लेता। Libraries store the energy that fuels the imagination. They open up windows to the world and inspire us to explore and achieve, and contribute to improving our quality of life, यह करना बहुत जरूरी है नहीं तो एक रट्टा विद्या चालू हो जाएगी जो इस वैज्ञानिक युग के अन्दर बेमानी होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर भी फोकस करें।

दूसरी बात आती है लेबोरेट्रीज की। आप विशेष रूप से इसका भी एक्सटेंशन कीजिये। 'Without laboratories men of science are soldiers without arms', प्रयोगशालाओं के बिना विज्ञान के लोग बिना हथियारों के सैनिक हैं। यह शोध ऐसा है कि लम्बा चलता है तब इसकी कोई गुणवत्ताभरी आउटकम निकलती है, एक दिन में नहीं हो सकती।

अब मैं हायर एजुकेशन पर आऊंगी। 80 per cent higher education is privatized. जो बार-बार सदन के उप नेता कह रहे हैं और व्यास विश्वविद्यालय पर कह रहे थे कि प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम बहुत हो रहे हैं, अनुरेगुलेटेड फीस का मामला हम देखते हैं, उनकी गुणवत्ता और क्वालिटी का कोई चैक नहीं है। लेकिन उसके पीछे हम भी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी सदन में बात कर रहे थे कि अमीरों का हिन्दुस्तान, गरीबों का हिन्दुस्तान और प्रधान मंत्री जी कह रहे थे नेहरू, नेहरू, नेहरू। राहुल गांधी जी ने बात की गरीबी पर, एमएसएमईज पर, बेरोजगारी पर, अर्थव्यवस्था पर, यूनियन ऑफ स्टेट्स पर, किसान पर, कैपिटलिस्टिज्म पर, चाइना पर, शिक्षा पर। प्रधान मंत्री जी का जवाब आया, कांग्रेस-नेहरू, कांग्रेस-नेहरू, साठ साल, कांग्रेस-नेहरू साठ साल।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

जयनारायण व्यास, जोधपुर पर भी आऊंगी मैं। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसने उस इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन को डिसमेंटल कर दिया, कुलपति जगदीश कुमार। पूरे विश्व में, जिसने एजुकेशनल सिस्टम की नींव को हिलाया, जो विश्व भर की चर्चा में रहे, जेएनयू का भट्टा बैठाने का श्रेय जिसे जाता है, राष्ट्रवाद के नाम पर उस शैक्षणिक संस्था को राजनीति का गढ़ बनाया। एकेडमिक माहौल के लिए जाना जाता है जेएनयू, उसका क्या हाल किया? घटिया मानसिकता का टैंक बनाना चाहते हैं। आरएसएस की नीतियों को आगे बढ़ाने के कारण इन कुलपतिजी को एक्सटेंशन मिलता है। बात वहां ही नहीं रुकी, उसके बाद इन्हें यूजीसी का चेयरपर्सन बना दिया जाता है और आप कहते हैं कि हम एजुकेशन के प्रति बहुत गम्भीर हैं। यह देखिये कि आप आरएसएस की आइडियोलाजी को कैसे प्रमोट करना चाहते हैं। कोई जांच नहीं हुई, कुलपति के मुंह से एक शब्द नहीं निकला जब वहां पर हमला हुआ। फिर अब नई जेएनयू की वीसी आयी हैं, मेरिट पर आई हैं नेचुरली, प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी, if I am not pronouncing it wrong. 2011 में पुणे यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सुनन्दा पंवार समिति ने उन आरोपों को सही पाया, पांच इन्क्रीमेंट रोके गये और जेएनयू की वीसी बन गईं। क्यों बन गईं? जिस राम की आरएसएस और भाजपा बात करते हैं, उसके महिमामंडन की प्रचारक थीं, नाथूराम गोडसे की समर्थक थीं, किसान आन्दोलन को परजीवी आन्दोलन कहने वाली, शाहीन बाग़ के प्रदर्शन को अवैध जिहादियों का प्रदर्शन कहने वाली, बाद में उन्होंने अपने ये ट्वीट्स डिलीट कर दिये, इनको जेएनयू की वीसी बनाया जाता है। कैसा भविष्य होगा, क्या हम देंगे? हमारे बेहतरीन पब्लिक एजुकेशनल सिस्टम्स को आप नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं और ये जेएनयू को जनेऊ बनाने का काम करेंगी, यह इनका एजेंडा है।

जामिया यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? नागरिक संशोधन अधिनियम का जो छात्र विरोध कर रहे थे उनको मारा गया, आंसू गैस छोड़ी गयी और शिक्षा के मन्दिर को जंग का मैदान बना दिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क्या हाल किया? अब्बाजान, गर्मी, इससे हमारा देश नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपको फिर भी आंकड़े बता देना चाहती हूं जो शिक्षा मंत्री ने 2021 में रैंकिंग की सूची जारी की। यही जेएनयू, इनके लाख प्रयासों के बाद भी आज दूसरे नम्बर पर आता है। यही जामिया, इनके लाख प्रयासों के बाद आज भी हिन्दुस्तान में छठे नम्बर पर आता है और वही अलीगढ़ हिन्दुस्तान में आज 10वें नम्बर पर

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आता है। यह हमने कितनी पुख्ता नींव रखी होगी। मंत्री महोदय जी, मैं आपसे विशेष अनुरोध करना चाहती हूं कि जिस नेहरू के बारे में बार-बार सदन में बात की जाती है, वह नेहरू थे जिन्होंने साइंटिफिक टेंपर की बात की। ये अपनी नेशनल एजुकेशन पालिसी में साइंटिफिक टेंपर की तो बात कर रहे हैं लेकिन between the lines, traditional knowledge की बात करते हैं, गाय, ऋषि-मुनि इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। आप माध्यमिक शिक्षा के अन्दर नेहरू को लाइये, आप माध्यमिक शिक्षा के अन्दर नेहरू के सेकुलरिज्म को पढ़ाइये। आप माध्यमिक शिक्षा के अन्दर नेहरू स्टडी केन्द्र बनाइये और बच्चों को बताइये that what is free India, what in new India, what is India and what is the foundation of India. इंडिया में हर साल 'March for Science' होता है और 2017 से इसकी शुरुआत हुई। विज्ञान और शोध के क्षेत्र में संघ सरकार द्वारा हमेशा इसकी कटौती की जा रही है विशेष रूप से ये scientific temper के लिए बता रही हूं।

आप अपनी National Education Policy बहुत flowery में यह नाम तो अडोप्ट कर लेते हैं, लेकिन देखिये, सिस्टमैटिक रूप से उसके विरोध में कैसे काम करते हैं और सभी शहरों के अन्दर वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता सड़क पर आकर हर साल प्रदर्शन करते हैं। विज्ञान को व्यवसाय की तरह मत देखिये, शोध से तत्काल परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह एक रचनात्मक गतिविधि है जिसको कई वर्ष लगते हैं और यह बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति आज आप भारत में क्रिएट कर रहे हैं। आप तो चाहते हैं, सिर्फ ऐसे पंगु लोग आयें, जो अन्ध भक्त हों।

अब मैं स्कालरशिप और एससी, एसटी पर आऊंगी। जो आप rationalize करना चाहते हैं। मैंने पिछले बार कहा था रोहित वेमुला that student, एससी का, जिसने आत्महत्या कर ली, यह आपकी देन थी। आप एससी, एसटी वर्ग पर हमला कर रहे हैं, दलितों का दमन कर रहे हैं। Right from educational institutions, एससी, एसटी के सात प्रतिशत पद आईआईटी, आईआईएम और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में खाली हैं, 12 हजार और दूसरे पद खाली हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए स्कालरशिप को युक्तिसंगत बनाने हेतु केन्द्र सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनायी गयी कमेटी प्रतिवेदन देती है, जो बहुत ही खतरनाक है तीन करोड़ विद्यार्थियों को प्रभावित करेगी।

एससी, एसटी, ओबीसी, माइनोरिटीज, इन जाति और कैटेगरी के

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

बावजूद समान स्कालरशिप इन्हें दी जाय, आप कमाल बात करते हैं। कान्स्टीट्यूशन इन्हें रिजर्वेशन देता हैं, इनकी परिस्थितियां बड़ी भिन्न हैं, आपस में लड़ाने के लिए आप rationalization कर देना चाहते हैं। अभी जो मुद्दा चल रहा है, वह हम सबने देखा है और हमने यूक्रेन के बच्चों की पीड़ा को महसूस किया। Unregulated fees के कारण और अफोर्ड नहीं कर सकते। वे इन्टेलीजेंट बच्चे यूक्रेन जाकर, मेडिकल, टेक्निकल और दूसरी चीजों में भर्ती लेते हैं। आपके मंत्री जोशी जी क्या कहते हैं, यहां पर जो बच्चे फेल हो जाते हैं, वे वहां यूक्रेन में जाकर दाखिला लेते हैं। आपको किसने सर्टिफिकेट देने के अधिकृत किया? Who are you to judge the intellect of those children? Who are you to give the certificate to those children? और वह भी जब जीवन और मरण की बात आयी हुई है। कौन किस कारण जाता है, वह जरूरी नहीं है, आप अपनी लीपापोती करना चाहते थे।

सदन के उप नेता समग्र चिन्ता की बात कर रहे थे, लेकिन कोई safe evacuation प्लान आपने बनाया नहीं। एक बोगस horrible advisory आपने निकाल दी कि खारकीव से आप अपने रिस्क पर निकल जाइये। अब आपने अपने मंत्री वहां खड़े कर रखे हैं कि पीआर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आप प्लेन में बैठें तो आप मोदी के जयकारे लगाइये। ये आप करना चाहते हैं।

आपरेशन गंगा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कोरोना की दूसरी लहर में, जब गंगा के अन्दर शव तैर रहे थे, तब आपको आपरेशन गंगा करना चाहिए था। तब आपको याद नहीं आया, लेकिन चूंकि यूपी में चुनाव है तो यूक्रेन के बच्चों को लाने के लिए आपने नाम दिया आपरेशन गंगा, क्या तालमेल हुआ? नमामि गंगे की क्या हालत है? खैर, एजुकेशन पर चर्चा कर रही हूं, इसलिए इस पर बात नहीं करूंगी, लेकिन आपको जब आपरेशन गंगा करना चाहिये था, तब आप दीदी ओ दीदी कर रहे थे और आपका खेला होवे हो गया। पीआर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं।

लास्ट में, मैं बात करना चाहूंगी हायर एजुकेशन पर, उप नेता सदन में बोल रहे थे और मैं उन्हें सुन रही थी, बहुत ही उम्दा वक्ता हैं, लेकिन प्रजेंटेशन उससे भी कहीं ज्यादा है। जिस आत्मविश्वास के साथ वे अपने तथ्यों को सदन में रखते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि कितनी कला के साथ वे पूरे सदन को गुमराह कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुकुरमुत्तों की तरह मशरूम हो रहे हैं। हर साल इस सदन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की आप

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

घोषणा करते हैं। आप क्या नये विश्वविद्यालय खोलने के खिलाफ हैं? मैं देख रही थी, प्लेन की उड़ान की तरह, ये भी जोधपुर आया, ये भी जोधपुर आया, क्या आप जोधपुर विरोधी हैं? जब आप सीकर से मेडिकल इंस्टीट्यूशन चूरू ले जाते हैं, तब हम तो प्रश्न नहीं करते।

एमबीएम विश्वविद्यालय की स्थापना के ऊपर आपने कहा कि स्थापना तो आपने कर दी लेकिन उसके अन्दर फैकल्टीज वगैरह आपने नहीं लगायी तो मैं आपको बता देना चाहती हूं कि आपकी शिक्षा नीति भी बहुसंख्या में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करती है। क्या आप उसका विरोध कर रहे थे?

मैं आपकी National Education Policy का पुरज़ोर विरोध करती हूं। वह प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, वह सेन्ट्रलाइजेशन की बात करती है, वह हिन्दुत्व के एजेंडा को बैकडोर से एन्ट्री कराना चाहती है। फिर आपने कहा कि एमबीएम विश्वविद्यालय के शिक्षक फैकल्टी की कोई व्यवस्था नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि उसमें कुलपति, रजिस्ट्रार तथा वित्त नियंत्रक की नियुक्ति महीनों पहले हो चुकी है।

एक और बात आपने कही, मैं उस पर नहीं जाऊंगी कि सरदारपुर और आपने जो एड्रेस पढ़े, वह सरदारपुर का एड्रेस तो था लेकिन वह सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र का एड्रेस नहीं था और वह जो कालेज खुलेगा, वह लूणी के विधान सभा क्षेत्र में खुलेगा।

आपने व्यास विद्यापीठ के इंस्पेक्शन कमेटी की बात की और आपने कहा कि जयनारायण व्यास के दो प्रोफेसर शामिल हुए, जो 2013 की भर्ती के थे। वे दोनों प्रोफेसर एमबीएम कालेज के थे और 2013 में एमबीएम कालेज में कोई भर्ती नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रोफेसर होना गुनाह है? आपने बात की कि इस विश्वविद्यालय को NAAC से एक्रिडिएशन नहीं हुआ है, पहले आप एक्रिडिएशन तो ले लीजिये। श्रीमान् जी, पहले विश्वविद्यालय तो स्थापित होने दीजिये, स्थापित होने से पहले एक्रिडिएशन कैसे लेंगे? फिर आपने कहा कि 28 शिक्षक गिरफ्तार हुए, क्योंकि आपका पोलिटिकल एजेंडा था, वे गिरफ्तारियां कराना और उन सबको आपने रेगुलर कर दिया।

मैं फिर आपको बताना चाहती हूं कि यह एकदम गलत तथ्य था। जो नियमित किये गये शिक्षक हैं, उनमें से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ था, एक

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

भी और जो गिरफ्तार हुए उनका मामला आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। फिर, आपने कहा कि तत्कालीन कुलपति जेल चले गये थे।

श्री सभापति: कंक्लूड करें, माननीय सदस्या।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): एक लास्ट पाइन्ट बोल रही हूं। मैं यह भी बताना चाह रही हूं कि जयनारायण विश्वविद्यालय के कोई भी कुलपति जेल नहीं गये। .

अब मैं बात करूंगी लास्ट में, जो आपका प्रमुख एजेंडा है, सीबीआई का। रीट पेपर लीक पर आप सीबीआई की जांच कराना चाहते हैं, चाहते हैं? तो मैं यह कहना चाहती हूं कि सदन में दो लोग हैं जिनको सीबीआई शोभा नहीं देती या तो आपको नहीं देती या मुझे नहीं देती, जब हम सीबीआई की बात करते हैं। क्या है सीबीआई? इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट से लेकर, आम व्यक्ति से पूछिये इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिये इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या है सीबीआई? ये वो टूल है जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर इस्तेमाल किया जाता है, राजनीतिक हत्या करने के लिये political murder for targeting your political opponents. क्या आप इस पर विरोधाभास रखते हैं? This is the new political culture. पहले अरेस्ट कीजिये फिर एविडेंस मैन्युफैक्चर करिये। ये सीबीआई और आपने सुना होगा जब शान्ती धारीवाल जी कह रहे थे। जब हम आते हैं इधर तो हम सीबीआई को नहीं मानते, जब ये इधर आते हैं, तब ये सीबीआई को मानते हैं, हम इधर आयेंगे तो हम भी सीबीआई को मानेंगे। मुझे लगता है कि सीबीआई का खेल अब बन्द कर देना चाहिए। जुडिशियल रिफार्म्स तो आप लाते नहीं हैं, flawed national education policy, नाम बदलने में महारत है आपकी, मेरा एक सुझाव है आपको।

श्री सभापति: समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): नाम बदलने में महारत है। प्रधान मंत्री की डिग्री सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, पक्का नाम बदलने में पीएचडी की होगी। सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन को centre of biased investigation का नाम दे देना चाहिए।

(समय: 15.00 बजे)

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): यह लास्ट पाइंट है एक। और इससे कहीं अधिक समग्र चिन्ता की जब आप बात करते हैं, धृतराष्ट्र अन्धे थे, गान्धारी ने कृत्रिम, एडोप्टेड अन्धापन धारण किया और मोदी जी जो कर रहे हैं, आप सबने वह एडोप्टेड समग्र अन्धापन धारण किया है। कम से कम इसमें तो एकराय होइये और कहिये कि सीबीआई को प्रतिबन्धित कीजिये। यह प्रताड़ित करने का क्रूरतम खेल नहीं जो अनवरत चलता रहेगा। 'Justice delayed is Justice denied' और मुझसे ज्यादा कौन जानता है इस सीबीआई की पीड़ा को, कौन समझ सकता है इस पीड़ा को। हम न्याय की उम्मीद में जीवन से चले गये। इन हाथों में मैंने उन्हें खो दिया न्याय की टकटकी के लिए। इसलिये सीबीआई के लिये चाहे मैं इधर बैठूं सदन में, चाहे उधर बैठूं किसी भी वक्त मैं सीबीआई की हिमायती कभी नहीं होऊंगी और लास्ट में ये चार लाइन कहकर उस पीड़ा को जो सीबीआई के लिए बात करती है कि सिर्फ इसलिये कि टोर्चर करा जा सके, एक नया पोलिटिकल टारगेट लिया जा सके। इस राजनीति से ऊपर उठिये, 'वहीं मुन्सिफों की रवायतें, वहीं फैसलों की इबारतें। उनका जुर्म कोई और था, उनको सज़ा कोई और मिली।' धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम।

श्री पब्बाराम (फलौदी): आदरणीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का अवसर दिया। हमारे सचेतक महोदय जोगेश्वर जी गर्ग ने अभी अपनी मातृभाषा राजस्थानी के बारे में पूरा विषय रखा। मैं समझता हूं कि जब बालक के दिमाग में सीखने की प्रक्रिया चलती है तो वह पहले अपनी मातृभाषा में सोचता है और उसके बाद में जो माध्यम है उसमें कन्वर्ट करता है और एक दोहरी प्रक्रिया उसको करनी पड़ती है। इस कारण से सीखने का प्रोसेस बहुत कम हो जाता है। किसी कवि ने कहा है,

'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल।' यानी कि अपनी मातृभाषा जो अपनी खुद की लैंग्वेज है उसके बगैर हिय का शूल, हिय का दर्द नहीं मिटा सकते हैं। हिय के दर्द को आप बाहर नहीं रख सकते हो और अभी-अभी सीताराम जी लालस ने बहुत बड़े शब्दकोश के बारे में जिक्र किया। दुनिया में सबसे बड़ा शब्दकोश है वह और कितनी समृद्ध मारवाड़ी और राजस्थानी भाषा है, इसका जिक्र यह है कि आप एक थोड़ा सा उदाहरण ले लो कि एक आदमी का और जानवर का किस तरह से अलग-अलग चीज का अलग-अलग रखा है जैसे आदमी का

(श्री पब्बाराम)

पेशाब है तो मारवाड़ी में मूत्र कहते हैं और वो ही रेवड़ का मूत्र है तो उसको छंगा कहते हैं और वो ही अगर ऊंट का है तो उसको चीड़ कहते हैं, यानी अलग-अलग के लिये अलग-अलग और ये ही स्थिति है कि ऊंट का गोबर है उसको मींगणो कहते हैं और रेवड़ का है उसको मींगणी कहते हैं और गाय का है उसको पोठो और गोबर कहते हैं और घोड़े का है तो उसको लीद कहते हैं, यानी कि आप अन्दाजा लगाओ कि कितनी समृद्ध भाषा है और इस समृद्ध भाषा को लाने के लिये पुरजोर वकालत की। मैं भी अपनी खुद की राय माननीय जोगेश्वर जी के साथ मिलाकर अपनी बात को शुरू करता हूं।

शिक्षा एक पवित्र पेशा है और मुझे गर्व है कि मैं उस सिस्टम से आया हूं। दुनिया में हर धन्धे में गलाकाट प्रतियोगिता है। एक राजनीतिज्ञ दूसरे राजनीतिज्ञ को गिराना चाहता है। व्यापारी दूसरे को फेल करना चाहता है परन्तु एक शिक्षक ऐसा है कि वह चाहता है कि मेरा शिष्य ऊपर से ऊपर और बुलन्दियों को छूये। यह शिक्षा क्षेत्र से आये व्यक्ति की पहचान है। कम से कम हमारा सबका प्रयास यह होना चाहिये कि हम राजनीति से शिक्षा को बिलकुल अलग रखें। अलग रखकर के राष्ट्र निर्माण की भूमिका में शिक्षा का ढांचा अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करे यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है। पाठ्यक्रम के अन्दर हमारे राष्ट्र का गौरव झलकना चाहिये परन्तु लम्बे काल खण्ड तक कांग्रेस इसका राजनीतिकरण करती आयी है। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को छुपाया गया है। आक्रमणकारी अकबर को महान बताया गया है जबकि महाराणा प्रताप को हारा हुआ बताया गया है। इस प्रकार की बातें, जब हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को हम शिक्षा के माध्यम से प्रदर्शित नहीं करते तो ये बातें जब बच्चों के कोमल मन पर हम प्रिन्ट कर रहे हैं, यह देश के प्रति कोई अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय, लॉर्ड मैकाले ने जब अपनी नयी शिक्षा नीति थोपी हिन्दुस्तान के ऊपर तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी शिक्षा नीति लाऊंगा जिसमें यहां का नागरिक रंग-रूप में तो भारतीय होगा, परन्तु आन्तरिक रूप से, चारित्रिक रूप से वह पूरा का पूरा काला अंग्रेज होगा। अब उसी पद्धति पर, उसी सिस्टम पर यह कांग्रेस चल रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हद तो तब हो गयी, सभापति महोदय, मैं लगभग 28 साल तक शिक्षक रहा। पिछले यूपीए काल के अन्दर सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अन्दर इस प्रकार से पाठ्यक्रम को लिखा गया, वह भारत के गौरव को चकनाचूर करने वाला था, भारत की

(श्री पब्बाराम)

आत्मा पर चोट करने वाला था। अकबर को महान और महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी को और महाराज सूरजमल जी जैसों को छापामार विद्रोही के रूप में, आप देखिये, 2004 से 2014 तक पाठ्य पुस्तकें सीबीएसई की देख लीजिये, ये सारी बातें लिखी हुई हैं।

मैं आधिकारिक तौर से आपको कहता हूं और रामायण और महाभारत के उन साम्यवादी लेखकों के लेख उसमें डाले गये जिसमें रामायण और महाभारत की सत्यता पर प्रश्न उठाये गये, उन्हें गडरियों के गीत कहा गया। इस प्रकार की बातें जब पाठ्यक्रम में जाती हैं तो समझ सकते हो हमारी संस्कृति के प्रति हमारा क्या भाव होगा। एक बालक किस प्रकार से पढ़कर तैयार होगा और उसी पाठ्यक्रम के अन्दर यह भी लिखा गया है, संयम जी लोढ़ा यहां पर नहीं हैं, भगवान महावीर के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये विक्षिप्त हो गये थे और 12 वर्षों तक जंगल में घूमते फिरते रहे, भटकते रहे, उनके कपड़े फट गये और नग्नावस्था में आ गये। इस प्रकार की लज्जा करने वाली बातें सीबीएसई के पाठ्यक्रम में लिखी गयीं और इसी प्रकार से रामसेतु के ऊपर भी प्रश्न उठाये गये कि यह प्रकृति निर्मित सेतु है, कोई सेतु नहीं है और इसलिये स्वत:स्फूर्त पूरा आन्दोलन पूरे भारतवर्ष में इस पाठ्यक्रम के खिलाफ तैयार हुआ और उसका नाम था शिक्षा बचाओ आन्दोलन और आप और हम में से बहुत सारे लोग उसका हिस्सा भी रहे हैं और वो ही परम्परा आगे भी चलती है और हार मान करके तत्कालीन सरकार को उन सभी गलत अंशों को हटाना पड़ा। अब भी शिक्षा ऐसे मंत्रियों के हाथ में से जा रही है जिन्होंने पूरी शिक्षा को भी नाथी का बाड़ा बना रखा है। उनका महाराणा प्रताप के बारे जो बयान था वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई को वह सत्ता संघर्ष मानते हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। यह राजस्थान के गौरव पर, हिन्दुस्तान के गौरव पर एक प्रकार का कालिख है। इस प्रकार की बात की हम सभी को भर्त्सना करनी चाहिये। ऐसा दर्शाया गया कि जैसे शिक्षा व विज्ञान का प्रसार अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ हो। जब यूरोप के लोग नंगा घूम रहे थे, अंग्रेज लोग नंगा घूम रहे थे, उस समय भारत में मानव सभ्यता पल्लवित हो रही थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसका उदाहरण है। जिस समय वह बगैर कपड़ों के जंगल में घूम रहे थे, उस समय यहां भारत में वेद, श्रुति, उपनिषदों का लेखन हो रहा था। आक्रमणकारियों के आने से पहले भारत की जीडीपी 70 परसेंट थी पूरे विश्व की।

(श्री पब्बाराम)

पुराने समय में शिक्षा ग्रहण करने के लिये, हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है, आप अगर अच्छी तरह से सोचेंगे तो पता लग जायेगा, बाहर के लोग यहां पर पढ़ने आया करते थे, आज हम बाहर जाते हैं। नालन्दा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो इतिहास में अंकित है, आक्रमणकारियों ने उसके पूरे के पूरे ज्ञान और विज्ञान को नष्ट और भ्रष्ट कर दिया और आग लगा दी जो कि छह महीनों तक जलती रही। आप अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा साहित्य हमारे पूर्वजों ने तैयार किया था और कहते हैं कि यहां अंग्रेजों से पहले एजुकेशन थी ही नहीं। जो भी देश स्वतंत्र हुआ उसने अपना इतिहास स्वयं दुबारा लिखा, पर भारत की गलत नीतियों के चलते आज भी अंग्रेजी लेखकों, साम्यवादी लेखकों के पाठों को जोड़ना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है।

हमारे यहां पर शिक्षा कभी सरकार का विषय हुआ ही नहीं करता था और हर व्यक्ति शिक्षित था। समाज स्वयं उसकी व्यवस्था करता था। पाठशालाओं में और आश्रमों में शिक्षा मिलती थी। व्यावहारिक ज्ञान का उपयोग प्रयोग द्वारा सिद्ध भी किया जाता था। हमारे यहां पर कितना विज्ञान उन्नत था, कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ सुई नहीं बनी। आप दक्षिण के उन मंदिरों को देख लीजिए किस प्रकार से कितने भारी कलश इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे होंगे, आप लोग कल्पना कीजिए। हजारों वर्ष पूर्व जो कैलेण्डर था वह सूर्य ग्रहण और चन्द्र ग्रहण की सटीक जानकारी दे देता था और कहते हैं कि अंग्रेजों के कारण विज्ञान आया है। हमारी एस्ट्रोलाजी कितनी तेज थी। चिकित्सकीय क्षेत्र में चरक, शल्य महर्षि, आयुर्वेद, कितना बड़ा ज्ञान था। उनको दरकिनार करके हम लोग पश्चिम का अंधाधुंध अनुसरण कर रहे हैं, यह देश का दुर्भाग्य है। वैमानिकी भी थी, इतिहास में जिक्र है कि भगवान राम श्रीलंका से जब वापस आये तो पुष्पक विमान में आये, यह कोई कपोल कल्पना नहीं है। आज के शिक्षाविद् कह सकते हैं कि गड़रियों के गीत हैं, परन्तु आज भी वेदों में इस चीज को ढूंढा जाये तो यह सारे विज्ञान मिल सकते हैं।

हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के प्रचार और प्रसार के लिये पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैनोरमाओं का निर्माण किया। पैनोरमा इसलिए बनाये कि लोगों को प्रेरणा मिले, क्रान्तिकारियों के नाम से प्रेरणा मिले। महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाया। लोक देवताओं का पैनोरमा बनाया। उनकी जीवनी के बारे में, उनकी प्रेरणा आम लोगों को मिले। इसी प्रकार से

(श्री पब्बाराम)

आध्यात्मिक संतों और महात्माओं का पैनोरमा बनाया। हम चाहते हैं कि पैनोरमा निर्माण की प्रक्रिया आगे से आगे बढ़नी चाहिये।

अभी नेता प्रतिपक्ष ने विषय उठाया कि इस प्रकार से धर्म परिवर्तन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर पिछले कार्यकाल में शुरू की हुई वंशावली लेखन प्रक्रिया को जारी रखते तो हर व्यक्ति को अपनी जड़ों तक जाकर अपने गौरवपूर्ण इतिहास तक पहुंचने का पूरा का पूरा लाभ मिलता और यह विषय ही नहीं उठता। वह कह रहे हैं कि हमको अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट दिया जाय, उनकी वंशावली उनके पास होती तो पता चल जाता कि हम कौन हैं, हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण है।

स्कूली शिक्षा में पिछली सरकार ने, आप कह रहे हैं कि 3500 विद्यालय हमने क्रमोन्नत कर दिये। पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने कहा हमने 7500 किये। कुल मिलाकर मैं समझता हूं प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से सैकण्डरी, सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी, कुल 9500 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया और उनमें शिक्षक भी लगाये। स्टाफिंग पैटर्न किया गया यानी कि जितने छात्र हो, उसके अनुपात में शिक्षक लगाये जायें। राजस्थान साक्षी है कि अंतिम छोर, बोर्डर के सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में भी 70 से 80 परसेंट पद भरे हुए थे और तब जाकर शिक्षा का यह ढांचा तैयार हुआ। उससे पहले प्राइवेट विद्यालयों के छात्र तो मेरिट में आ जाते थे, परन्तु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का जो अंतिम तीन साल का कार्यकाल था, उसमें गवर्नमेंट स्कूल के छात्र भी मेरिट में अपना जज्बा दिखाने लगे। यह बहुत बड़ी बात है, शिक्षा में गुणवत्ता की कसौटी है। अभी बार-बार कहा गया, टेबलें बजाई गईं कि 123 महाविद्यालय खोलेंगे, एक पत्थर नहीं गाड़ा। हमने जब कोई भी चीज खोली है तो उसके लिये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। मेरे वहां बाप महाविद्यालय का पिछली सरकार के समय में 6 करोड़ रुपये बजट जारी करके काम शुरू करवा दिया, परन्तु अभी भी वह एक छोटी स्कूल में महाविद्यालय चलने को मजबूर है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि वह लगभग पूर्णता की तरफ है। कम से कम आपके हाथ से उद्घाटित हो जाय, इसको पूर्ण करवा दीजिए। मामूली सी बात के लिये यह अधूरा पड़ा है और तीन साल से बच्चे बाहर बैठे हैं, एक प्राइमरी विद्यालय में बैठे हैं।

उपखण्ड पर आपने महिला विद्यालय खोलने का कहा था। मेरे यहां पर दो उपखण्ड हैं, उसमें से एक में भी महिला महाविद्यालय नहीं खोला। मैं

(श्री पब्बाराम)

फलौदी के महाविद्यालय में स्नातकोत्तर में कुछ विषय खोलने के लिये आपसे निवेदन करूंगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जरूर उस पर ध्यान देंगे।

बड़ी वाहवाही ली जा रही है कि हमने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोल दिये। आपने खोले, परन्तु उन छात्रों को जो हिन्दी माध्यम से लगातार पढ़ रहे थे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वीं में, उनको एकदम से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के लिये मजबूर कर देंगे क्या? माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं आपकी वक्र दृष्टि अभी मेरे तीन विद्यालयों पर और है। वह है बाप, 5000 जनसंख्या से अधिक का है। बूगड़ी की जनसंख्या 5 हजार से अधिक है और जेसला की जनसंख्या भी 5 हजार से अधिक है। उनके आस-पास 15 किलोमीटर तक कोई भी सीनियर सैकण्डरी विद्यालय नहीं है तो क्या वे छात्र 15 किलोमीटर दूर अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेने के लिए जायेंगे। आप किसी भी स्टूडेण्ट को अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेने से वंचित नहीं कर सकते और माननीय वासुदेव जी देवनानी द्वारा अभी-अभी इसके फैसले के बारे में बताया गया जो कि पीलवा की एक स्कूल के अन्दर आया तो ऐसा न हो कि दूसरे विद्यालयों के लोग और अभिभावक कोर्ट में जायें, इससे पहले इसे कर लीजिये। हमने स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल खोले। 6 हजार बिल्डिंगें बनायीं। बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। उसके लिए अलग से शिक्षक भर्ती किये। आपने न कोई शिक्षक भर्ती किया और न कोई और कुछ। अब 10 हजार शिक्षक भर्ती करने की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वह भर्ती पूरी नहीं होगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पब्बाराम (फलौदी): बस, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हर ग्राम पंचायत पर आपने सीनियर सैकण्डरी स्कूलें दी हैं पर कई पंचायतों पर प्राइमरी स्कूल भी अब खुलने जा रहे हैं तो कैसे कर पायेंगे? यह आप देखियेगा? अभी आपने पंचायत सहायकों के रूप में लिये, उनको पक्का करने की बात है। वे शिक्षक ही लगे हुए थे। एक स्कूल में लगा हुआ है और एक पंचायत में लगा हुआ, उनका क्या करेंगे? भवन निर्माण के लिए आप कह रहे हैं कि हम साढ़े तीन हजार कक्षा कक्ष दे रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक भी कक्षा कक्ष अपनी मद से नहीं दे रहे हैं। आप समसा के द्वारा दिये गये और केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के माध्यम से हमको दे रहे हैं, नहीं तो, मेरे विधान सभा क्षेत्र में

(श्री पब्बाराम)

आज तक एक भी नया कक्षा कक्ष पूरे तीन साल में नहीं बना है। नई शिक्षा नीति, 2000, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती इसी सरकार ने शुरू की थी।

श्री सभापति: समाप्त करें। आप सहयोग करें। विराजें। श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री पब्बाराम (फलौदी): राजीव गांधी पाठशाला खोली थी।

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: विराजिये, पहले ही बोलना चाहिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, शिक्षा एक ऐसा मंत्र है, जो जीवन में उजियारा लेकर आता है। सभापति महोदय, हर बार जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सुनते हैं कि इस देश में 70 साल में क्या हुआ? सभापति महोदय, आप यदि गांव में 80-90 साल के बुजुर्ग के पास बैठकर बात करेंगे तो पता चलता है कि इस देश में पिछले 70 सालों में शिक्षा में कितने नवाचार हुए हैं? जिस देश में बीस-बीस, पचास-पचास किलोमीटर की दूरी पर भी स्कूलें नहीं हुआ करती थीं, यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, कालेजें नहीं हुआ करती थीं, आज 70 साल में हमारी कांग्रेस पार्टी ने और हमारी सरकारों ने जो शिक्षा में नवाचार किये हैं, वे देखने लायक हैं।

सभापति महोदय, एक समय हुआ करता था, जब गांव में कोई बच्चा सैकण्ड या फर्स्ट डिवीजन आता था तो पूरे गांव में उसका हल्ला मचता था। आज हमारे गांव के बच्चे, ढाणियों के बच्चे, गरीब और किसान का बेटा मैरिट में आ रहा है, 99 परसेंट नम्बर लेकर आ रहा है। यह किसने किया है? क्या यह सात साल में मोदी जी ने किया है? आप बताइये ये आईआईटी कौन लेकर आया? आईआईएम कौन लेकर आये? ये यूनिवर्सिटी कौन लेकर आया? यह इंजीनियरिंग शिक्षा कौन लेकर आया? हर जिले पर मेडिकल कालेज खोलने का हमारी सरकार ने किया है, यह किसने किया है? सभापति महोदय, कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

एक समय वह था, जब इस देश के गरीब आदमी, किसान और मजदूर के पास खाने के लिए अनाज नहीं हुआ करता था। यह हरित क्रान्ति इस देश में कौन लेकर आया? श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश में हरित क्रान्ति लेकर आयीं। इस देश में जो नवाचार शिक्षा के मामले में हुए हैं, आज हमारे यहां के पढ़े हुए स्टूडेण्ट विदेशों में नाम कमा रहे हैं। ये किसने किया है? पिछले सात साल में असत्य बोलकर इस देश में राज किया। असत्य बोलने का काम किया, सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया। ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया, जिसको लेकर आज प्रचार करें। क्या जमाना बदला है? एक जमाने में जब चुनाव में लोग जाते थे, राजनीतिक लोग जाते थे, विकास की बातें करते थे कि हमारे क्षेत्र में यह विकास होगा। यह स्कूल खोलेंगे, कालेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे। आज चुनाव में क्या बातें होती हैं? गाय की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। जिहाद की बात करते हैं। सभापति महोदय, इस देश में जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने और हमारी सरकारों ने हमेशा इस देश में सामाजिक सौहार्द्र बनाने का काम किया है। प्यार-प्रेम बढ़ाने का काम किया है। 36 कौमों और सभी धर्मों को एक मानकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है।

सभापति महोदय, एक जमाना था जब एक गरीब और किसान का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने की बात नहीं करता था, क्योंकि लाखों रुपये फीस लगती थी। अभी फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य की बात मैं सुन रहा था। जिन शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की आप बात कर रहे हैं। यह उन्हीं की सोच का परिणाम था कि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ना चाहिये। गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ रहा है। लाखों रुपये की फीस देकर वह बच्चा नहीं पढ़ सकता, लेकिन उस शिक्षक के बेटे और किसान के बेटे गोविन्द सिंह डोटासरा जी की सोच थी कि आज गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ रहा है। बच्चों के एडमिशन की लाइन लगी पड़ी है, जो लोकप्रियता इन स्कूलों की हुई है, उसी को देखते हुए हमारी सरकार ने काफी संख्या में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का काम किया है और आगे भी बजट में घोषणा की है।

सभापति महोदय, मेरी भी उम्र 38 साल की है। इतनी संख्या में पहली बार स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं। 3800 के लगभग सैकण्डरी विद्यालयों को

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी एक इतिहास रहा है, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। इस देश को बांटने का काम नहीं किया है। आजादी दिलाने का काम इस देश में कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज इस देश को बांटने का काम किया जा रहा है। भाई-भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है। पहले हिन्दू-मुस्लिम को लड़ाया जाता है, फिर दलित-सवर्ण को लड़ाने का काम किया जाता है और ओबीसी के टुकड़े करने का काम किया जाता है। इस देश में जो जहर घोलने का काम किया जा रहा है, उसके लिए आने वाली पीढ़ियां इन लोंगों को माफ नहीं करेगी।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को शिक्षा के ऊपर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी सरकारें बदलती हैं, शिक्षक एक ऐसा पवित्र पेशा है कि गरीब का, अमीर का या किसी भी पार्टी का बच्चा वहां पढ़ता है तो वह अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन जब सरकारें बदलती हैं तो सबसे ज्यादा चिन्ता शिक्षक को तबादले की होती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि आप तबादला नीति बनाइये, ताकि हर बार, जो पांच साल में सरकारें बदलती हैं और सरकारें बदलने के बाद जिस तरह से शिक्षकों के तबादले किये जाते हैं, उनसे उनको मुक्ति मिले और वे निश्चिंत होकर उस विद्यालय में शिक्षा दें। आप देखिये कि केन्द्र सरकार की नौकरियों में जिस तरह की तबादला नीति है। क्यों नहीं, हम लोग भी उसी तरह से हमारे स्टेट में शिक्षकों के लिए तबादला नीति बनायें। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि कोई दस साल से बैठा है, कोई पन्द्रह साल से बाहर बैठा है और कोई एक साल में वापस आकर अपने क्षेत्र में नौकरी कर रहा है तो उनको भी न्याय मिलना चाहिये। तबादला नीति बननी चाहिये। शिक्षा मंत्री महोदय, यदि आप तबादला नीति बनाकर जायेंगे तो आपको आने वाला इतिहास याद करेगा। हर पांच साल में सरकार बदलती है तो उसी हिसाब से तबादले होते हैं। इन तबादलों से उनको मुक्ति मिलेगी और वह शिक्षक निश्चिंत होकर उस विद्यालय में शिक्षा देने का काम करेगा।

सभापति महोदय, उच्च शिक्षा की बात कर रहे थे। उच्च शिक्षा में सबसे ज्यादा कालेज खोलने का काम अगर किसी ने किया है तो इन तीन साल में हमारी सरकार ने किया है। इन तीन सालों में 179 नये गवर्नमेंट कालेज खोले। हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों की तरफ से जब बार-बार यह बात आती है कि

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

बजट का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पिछले लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और लगातार 15 साल से वहां की जनता कालेज की मांग कर रही थी। किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की, लेकिन जब हमारी सरकार आयी और हमने चुनाव में मुद्दा बनाया तो हमारी सरकार ने आते ही पहले बजट में वहां पर कालेज खोला। मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पहले बजट में कालेज खोला और पहले ही बजट में जुलाई में उसको चालू किया। आज थर्ड ईयर का सेशन वहां पर चल रहा है। बार-बार कह रहे हैं वहां पर भवन निर्माण नहीं हुआ। मेरे यहां पर जमीन का अलॉटमेंट भी हो गया, कोरोना की वजह से लेट जरूर हुआ और आज उस भवन का निर्माण कार्य भी वहां पर चालू है।

अभी इसी बजट में पावटा हमारे बड़ा सब-डिवीजन है, माननीय मंत्री महोदय राजेन्द्र यादव जी बैठे हैं, इनका और हमारा एक जगह सब-डिवीजन है, जाइंट है, उसमें भी गवर्नमेंट कालेज खोलने का काम किया है। मैं निश्चित रूप से यह मांग जरूर करूंगा मंत्री महोदय से कि जुलाई में इसी सत्र में पिछली बार की तरह उस कालेज को भी आप चालू कराने का काम करें ताकि बच्चों का एडमिशन इसी साल उस कालेज में हो।

सभापति महोदय, अभी बजट में हमारी जितनी सैकण्डरी स्कूल थीं, सभी सैकण्डरी स्कूलों को हायर सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत कर दिया गया। इसके अलावा हमारे पंचायत हैडक्वार्टर में जो स्कूल थीं, उन स्कूलों को भी क्रमोन्नत किया। लेकिन एक समस्या जरूर है, एक ग्राम पंचायत में चार-चार, पांच-पांच गांव हैं, जिनकी दूरी 5-5, 7-7 किलोमीटर भी है, वहां पर मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उनको किसी तरीके से क्रमोन्नत करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आप ऐसी स्कूलों को भी क्रमोन्नत करने का काम कीजिए जिनमें छात्र संख्या अच्छी है और जिनकी पंचायत हैडक्वार्टर से दूरी है, उन स्कूलों को भी क्रमोन्नत करने का काम कीजिए ताकि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। मेरे विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में ऐसी मिडिल स्कूल जो पंचायत हैडक्वार्टर पर नहीं है, लेकिन उनमें छात्र संख्या अच्छी है, दूरी पर है, उच्च प्राथमिक विद्यालय,

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

सुन्दरपुरा, बंदमुजफर, नीलका व फतेहसिंह वाला, ये चार स्कूल ऐसी हैं जो मिडिल हैं, इनको सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है क्योंकि पंचायत हैडक्वार्टर से इन स्कूलों की काफी दूरी है।

सभापति महोदय, आज विज्ञान का जमाना है, टैक्निकल का जमाना है। पिछले तीन साल में हमने मात्र एक-एक फैकल्टी खोली है स्कूलों में। विज्ञान के जमाने में भी हम बच्चों को आर्ट्स पढ़ा रहे हैं। विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता है। मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि इस बार विद्यालयों में साइंस फैकल्टी खोलने का काम जरूर करें। साइंस फैकल्टी के बिना हर जगह जब हम स्कूलों में जाते हैं तो ये ही मांग आती है कि साइंस फैकल्टी होनी चाहिए। मेरे विराटनगर विधान सभा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय भाभरू, बडनगर, बागावास अहीरान, गोविन्दपुरा धाभाई व बाड़ीजोड़ी में अच्छी छात्र संख्या है। इन विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने की मैं मांग करता हूं ताकि वहां के बच्चे भी, गरीब के बच्चे भी, किसान के बच्चे भी विज्ञान पढ़कर अच्छे डाक्टर बनें, इंजीनियर बनें और देश-दुनिया में अपना नाम रोशन करें।

सभापति महोदय, इस तकनीकी युग में अगर हम लोग बच्चों को विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे, पूरे विधान सभा क्षेत्र में मुश्किल से दो-दो, तीन-तीन स्कूलों में साइंस फैकल्टी है। क्यों नहीं हम ऐसा प्रावधान करें कि चार-चार, पांच-पांच स्कूलों का समूह बनाकर उनमें एक-एक विद्यालय में साइंस फैकल्टी खोलने का काम करें ताकि वहां के बच्चे भी पढ़ें।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में जो नया महाविद्यालय पिछले तीन साल से संचालित है, उसमें सिर्फ कला फैकल्टी चल रही है। मैं मांग करता हूं कि उस महाविद्यालय को पीजी. में क्रमोन्नत करें क्योंकि आसपास में 30 किलोमीटर की रेंज में कोई भी महाविद्यालय नहीं है। पी.जी. में क्रमोन्नत करें तथा उसमें वाणिज्य व विज्ञान संकाय खोलने का काम करें ताकि वहां के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे को टोकना मत क्योंकि मैं थोड़ा ही बोलती हूं और बोलकर बैठ जाऊंगी। टोकना मत, नहीं तो मैं मेरी बात भूल जाऊंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आपको सदन अगर फूफाजी के नाम से जानता है तो इनको भी जीजी के नाम से जानता है।

श्री सभापति: भाग्यशाली हैं हम दोनों।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने स्कूल और शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बहुत बड़े पैमाने पर खोलने के नाम पर बहुत वाहवाही लूटी है। परंतु इस प्रक्रिया में यह छुपा लिया गया है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं, जहां मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है। प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कम्प्यूटर, लैब आदि तो बस नाममात्र के हैं। 12वीं बोर्ड की परीक्षा होती है जब ये लैब वगैरह खुलते हैं, बाकी तो ताले में ही बन्द रहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, सूरसागर क्षेत्र है मेरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वहां स्कूलों की ऐसी दशा है कि टीचर हैं तो बच्चे नहीं हैं और बच्चे हैं तो टीचर नहीं हैं। ये स्कूलों की व्यवस्था है। मैं स्वयं आपको बताना चाहूंगी कि भट्टी की बावड़ी के अन्दर स्कूल है। स्कूल किसमें चलती है? स्कूल बगीचे के अन्दर। वाहवाही लूटती है सरकार। कोई भी सरकार हो, कहेगी हमने इतनी स्कूल खोली हैं, वहां पर जगह तो देखो। वहां किस जगह पर स्कूल खुलेंगी, मंदिरों के अन्दर बच्चे पढ़ते हैं। शोभावतों की ढाणी का स्कूल मंदिर के अन्दर है। सबको जमीनें दिलवाइए। ये व्यवस्था आप पहले कीजिए। जब आप स्कूल खोलते हैं तो स्कूल कहां खोलेंगे, उसकी व्यवस्था कीजिए। स्कूल बढ़वाओ, आप खोलो, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कोई भी सरकार हो शिक्षा के अन्दर कोई राजनीति नहीं है क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे जाकर अफसर बनेंगे। मगर कोई व्यवस्था नहीं है। पहले स्कूलें खोल देते हैं जबकि जगह नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, स्कूलों के अन्दर बाथरूम नहीं है। पीने के पानी की मटकियों के अन्दर कचरा भरा हुआ रहता है। आप क्यों नहीं एक्वागार्ड लगवाते हैं? जब लाखों रुपये का आप बजट देते हैं, लाखों रुपये आप खर्च करते हैं तो बच्चों के लिए भी तो करना चाहिए। स्कूल के अन्दर बड़े-बड़े अफसर हैं, उनके तो ए.सी. लगे होते हैं और बच्चों की स्कूलों के अन्दर लाइट तक नहीं होती है।

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

सभापति महोदय, मैं आंखों देखी सारी बात बताती हूं आपको। एक जमाने के अन्दर स्कूलों की ऐसी स्थिति थी कि कोई सरकारी स्कूल के अन्दर पढ़ने जाता और लाइन लगती थी कि हमारा नाम आना चाहिए। आजकल ये हो गया है कि लोग कहते हैं हम तो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। सरकारी स्कूल में मत जाओ। एक फोर्थक्लास का बच्चा होता है, वह भी कहता है मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा, आप थोड़ा फीस माफ करवा दीजिए। यह स्थिति है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की स्कूलों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

मैं बता रही हूं आपको जोधपुर के अन्दर, बाईजी का तालाब स्कूल। महाराजा उम्मेदसिंह जी की लड़की ने स्कूल बनवाई कि लड़कियां पढ़ी-लिखी होनी चाहिए तो आगे घर बसेगा, घर ऊंचा होगा। ये उनकी सोच थी। पानी की तकलीफ हुई तो तालाब खुदवा दिया। ऐसेऐसे लोग भी थे। शहर के अन्दर फतेहपोल स्कूल, कैसी स्कूल राजा-महाराजाओं ने बनाई। आज स्कूल की आप स्थिति देखो तो टूटी फूटी पड़ी है, स्थिति बहुत खराब है। पहले मैं शहर की एम.एल.ए. थी तो शहर की स्कूल है ये फतेहपोल, फतेहपोल को देखो आप, हुसैन मंडी को देखो, बाईजी तालाब को देखो आप। इन सारी स्कूलों की ऐसी ही स्थिति है। आप खूब फंड देते हैं तो कम से कम उसका यूज तो होना चाहिए। उनकी मरम्मत होनी चाहिए, स्कूलों में देखना चाहिए कहां पानी आता है या नहीं आता है, लैट्रिन-बाथरूम है या नहीं है। बच्चियां स्कूल में कैसे पढ़ती हैं? बच्चों को टाट-पट्टी बिछाने को नहीं है तो सरकारी स्कूल में कौन जाएगा? कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, विद्यालयों में प्रयोगशालाओं का उपयोग आरम्भ करवाने की ठोस नीति की आवश्यकता है। सरकारी विद्यालयों में प्राय: प्रयोगशालाओं का संचालन 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए ही किया जाता है। शेष सत्र में प्रयोगशालाओं में ताले ही नहीं खुलते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों में विज्ञान की प्रवृत्तियों का विकास हो ही नहीं सकता। सरकार विज्ञान, गणित क्लब के नाम पर राशि बांटती है जिसका मजबूरन खर्च करके सामग्री खरीद ली जाती है। कभी उस सामग्री का उपयोग नहीं होता है। मेरी मांग है कि सरकार विद्यालयों में प्रयोगशालाओं के सत्र पर्यन्त अनिवार्य उपयोग की नीति बनाकर विद्यार्थियों में प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के विकास का ठोस प्रयास करे। मेरा यह भी कहना है सरकार से ऑनलाइन माध्यम से दैनिक प्रयोगशाला गतिविधियों में संचालन की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर की जावे।

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूं, वह स्कूल सरकारी थी, उस जमाने के अन्दर। आज भी वह स्कूल मौजूद है बाईजी का तालाब। ऐसे-ऐसे टीचर थे, जब उसका इंस्पेक्शन हुआ और उस इंस्पेक्शन के अन्दर, लक्ष्मीनारायण जी कल्ला, एजुकेशन सैक्रेट्री थे, स्कूल देखने के लिए आये कि स्कूल में क्या स्थिति है? स्कूल की क्या हालत है? देखने आये तो आगे हैडमास्टरनी थी, उसने घाघरा, ओढ़ना और लहंगा पहना हुआ था तो किसी को एतराज हो गया तो उसने कह दिया मैं यह बात सुनने को तैयार नहीं हूं, मेरी क्लास देखो, मेरी स्कूल का रिजल्ट देखो, ये सरकारी स्कूल का मोरल था। मेरे कपड़ों को क्या देखते हो? मेरी वेशभूषा को मत देखो, मेरे स्कूल का रिजल्ट देखो कि मेरी स्कूल आठवीं तक है, इसका एक भी बच्चा फेल हुआ हो तो बताओ। ऐसे सरकारी स्कूल का नाम होना चाहिये। आज हर बच्चा प्राइवेट में जाता है। प्राइवेट में 100 में से 80-90 नम्बर लाता है और गवर्नमेंट की स्कूल में बच्चे जाते ही नहीं हैं। मैं स्कूलों में देखने जाती हूं, अभी दो-ढाई साल से तो कोरोना की वजह से, स्कूलों में जाना नहीं हुआ। मैं स्कूल में जाती हूं तो वहां 8 बच्चे, 6 मास्टर मिलते हैं। 8 बच्चे व 6 टीचर, क्या होगा? आपको आगे की बात बताऊं, आप कहेंगे तो आपको टेबल कर दूंगी। सातिये की तरह लगा दिया, पहली, दूजी, तीजी, चौथी, इस तरीके से बच्चों की हालत है, तो फिर स्कूल में कौन जायेगा? आप कहते हो हमने इतनी स्कूलें खोल दीं, इतना फण्ड दे दिया, फण्ड जाता कहां है? इसकी मोनिटरिंग होनी चाहिये। मोनिटरिंग होगी तो सरकारी स्कूल भी अच्छी चल सकती है।

मंत्री जी विराजमान हैं, यह भी जाति से कल्ला हैं। कल्ला के अन्दर कई कलाएं होती हैं। यह अपनी कला काम में लें। स्कूलों को सुधारें। सरकारी स्कूलों को सुधारना बहुत जरूरी है। सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगी, सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में नम्बर भी अच्छे लाते हैं। वहां अच्छे होते हैं, यहां तो बैठने को टाट-पट्टी नहीं होती। भट्टी की बावड़ी की स्कूल बगीचे में। शोभावता ढाणी मन्दिर में, ऐसे चलती है, ऐसे चलने से काम नहीं होता है। सबसे ज्यादा राज किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। इसके बारे में सोचना चाहिये। यह एजुकेशन का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं आनी चाहिये। इसके अन्दर बच्चों के भविष्य का काम है। बच्चे अफसर बनेगे, कहां से बनेगे? पढ़-लिखकर तैयार होंगे, तब बनेंगे न, नहीं तो क्या बनेंगे, नहीं तो उनके पास कुछ नहीं है। आप बच्चों के भविष्य की देखो।

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

पुस्तकालयों का उपयोग आरम्भ करने हेतु ठोस नीति की आवश्यकता है। सरकारी विद्यालयों के पुस्तकालय प्राय: खुलते ही नहीं, केवल वार्षिक बजट पूर्ण करके स्टाक इन्द्राज कर लिया जाता है। परन्तु वर्षपर्यन्त पुस्तकों के पठन-पाठन की गतिविधियों का संचालन नहीं होता है। शहरों में पदोन्नति के अभाव में पद रिक्त हैं।

माननीय सभापति महोदय, पदोन्नतियां ही नहीं होती हैं। स्कूलों के अन्दर टीचर होते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं। मैं स्कूल जाती हूं तो पूछती हूं कि बाहर क्यों खेल रहे हो। बच्चे कहते हैं कि बहन जी कोई सर्वे करने गयी है। क्यों लगाते हो? आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी, टीचर को टीचर के अलावा, किसी भी कार्य में नहीं लगायें। इलेक्शन होता है तो किसी को उसमें भेज देते हैं कि नाम लेकर आओ, वह करके आओ, यह नहीं हो। वह तो स्कूल में ही पढ़ायेगी, नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे।

माननीय सभापति महोदय, गांवों में पदस्थापन नहीं होने से पद रिक्त हैं। जहां पद भरे हैं, वहां केवलमात्र कागजी कार्यवाही है। मेरी मांग है कि सरकार ऑनलाइन माध्यम से दैनिक पुस्तकालय गतिविधियों के संचालन की सूचना शाला दर्पण पर की जाये।

अंग्रेजी माध्यम, अब अंग्रेजी कहीं है नहीं। मास्टर ही नहीं है, तो कौन पढ़ायेगा। गणित का नहीं होता है, कभी विज्ञान का नहीं होता है, कभी किसी का नहीं होता, इस तरह से नहीं चलेगा। आपको बहुत भारी विचार करना पड़ेगा। सरकार को इस बात के लिये सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे करें, बच्चों के भविष्य का मामला है।

माननीय सभापति महोदय, विद्यालयों में ललित कला, संगीत एवं चित्रकला आदि विषयों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता है। जोधपुर की बात करें तो संगीत और चित्रकला के सभी पद रिक्त हैं। केवल एक में उपलब्ध है। ऐसे में ललित कला का विषय षड्यन्त्रपूर्वक समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी मांग है कि सरकार ललित कला विषयों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देकर, इसके प्रोत्साहन हेतु रिक्त पद भरे और नये विद्यालयों में संगीत, चित्रकला शिक्षकों की नियुक्ति करावे।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तो बहुत थोड़ी बोलती हूं आप मुझे टोकना मत। आपने मुझे नहीं टोका। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

सभापति महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। सरकारी स्कूलों के अन्दर आप प्राथमिकता दिलवाइये। इस बार ऐसा करिये, सदन के नेता भी यह चाहते हैं कि होना चाहिये। सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता देकर, इनको ऊंचे स्तर पर पहुंचाओ, ताकि मध्यम श्रेणी के बच्चे भी स्कूल में जायें, नहीं तो वे कहते हैं प्राइवेट स्कूल में जायें, क्योंकि वहां पढ़ाते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मांग संख्या 24 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पक्ष, प्रतिपक्ष के साथियों ने अपने विचार रखे। सरकारी विद्यालयों के बारे में बहुत ने चिन्ता भी व्यक्त की । मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, जो अच्छा काम हो, उसे अच्छा भी बोलना चाहिये। पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, अगर कोई अच्छा निर्णय है, तो उसका स्वागत करना चाहिये। क्या यह सत्य बात नहीं है, 2018 की तुलना में 2021 तक, इन तीन वर्षों में स्कूलों की शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है? सभापति महोदय, यह रिकार्डेड है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन, सरकारी विद्यालयों में 20 प्रतिशत बढ़ा है। कोरोना महामारी होने के बावजूद भी, नामांकन का बढ़ना यह सिद्ध कर देता है कि लोगों का रुझान बढ़ा है।

सभापति महोदय, पूरे राज्य के सैकण्डरी विद्यालय, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के विधायक क्षेत्र में हों, इनको मुख्य मंत्री जी को साधुवाद देना चाहिये, राजस्थान के इतिहास में एक साथ 3820 विद्यालय क्रमोन्नत करने की घोषणा की। सारे विधान सभा क्षेत्रों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। सारे विधान सभा क्षेत्रों में 5 हजार से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं, वहां महात्मा गांधी अंग्रेज़ी विद्यालय खोलने की घोषणा की है। 5 हजार की आबादी है, अगर वहां अंग्रेजी विद्यालय नहीं खोल रही है तो बोलने का धर्म बनता है। जब सरकार राजस्थान में समानता का व्यवहार करे, फिर हम कमी निकालें तो उसमें आनन्द नहीं आता है।

इसी तरह, एक-एक हजार स्कूल शहर में व ग्रामीण में, दो हजार एक साथ, अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल। गरीब आदमी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने के लिये भेज सकता था, आज उसके बच्चे भी अंग्रेज़ी स्कूल में जा रहे हैं। आपको मुख्य मंत्री जी के कमिटमेंट को समझना पड़ेगा। एक साथ जब अंग्रेज़ी विद्यालय खोलने का निर्णय किया है तो एक साथ दस हजार अंग्रेज़ी माध्यम

(श्री बाबूलाल नागर)

के शिक्षक भर्ती करने की घोषणा की है। यह सोच है। हम अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालय खोल रहे हैं, अंग्रेज़ी के शिक्षक नहीं होंगे तो विद्यालय खोलने का क्या मतलब निकलेगा, लेकिन मुख्य मंत्री जी की दूरगामी सोच है। इस बजट में उन्होंने घोषणा की।

मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, पिछली बार उन्होंने कहा था, हम नये कक्षा कक्ष बनायेंगे। क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत का कार्य भी करेंगे। उन्होंने नाबार्ड से ऋण लेने के लिये आवेदन किया है। अभी ऋण स्वीकृत नहीं हुआ है, लेकिन मुख्य मंत्री जी की दूरगामी सोच कि जो-जो स्कूलें चयन हुई हैं, जहां कक्षा कक्ष बनाने हैं, लाइब्रेरी कक्ष बनाने हैं, मरम्मत होनी है, राजस्थान के उन तमाम स्कूलों के टेण्डर लगाने के आदेश जारी कर दिये हैं। अभी सैंक्शन नहीं हुआ है, नाबार्ड का लोन सैंक्शन नहीं है। क्यों इन्तजार किया जाये, क्यों देरी की जाये, जैसे ही नाबार्ड का लोन सैंक्शन हो, क्यों प्रक्रिया को लम्बी की जाये, उन्होंने राजस्थान में टेण्डर लगाने के आदेश कर दिये हैं। टेण्डर लग रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारी बच्चियों को नजदीक पढ़ने का मौका मिले। माध्यमिक स्तर के 389 विद्यालय खोलने की घोषणा की है। उच्च प्राथमिक स्तर की, अभी मेरे एक साथी बोल रहे थे, उच्च प्राथमिक स्तर व प्राथमिक स्तर, इनकी संख्या जरूर बढ़ानी चाहिये। आपने जब पूरे राजस्थान के, सारे सैकण्डरी विद्यालयों को सीनियर सैकण्डरी कर दिया है, तो जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, आपको उनको सैकण्डरी करना चाहिये। प्राइमरी को मिडिल करना चाहिये। आपने 1846 उच्च प्राथमिक विद्यालय लिये हैं। उधर आप तीन हजार से ज्यादा हायर सैकण्डरी विद्यालय खोलने के ले रहे हैं तो इसमें आपको कम से कम बढ़ाना चाहिए क्योंकि यह आपकी सोच रही है। मुझे याद है वह जमाना जब पहली बार प्रदेश में अशोकजी गहलोत मुख्य मंत्री बने थे तो वे राजीव गांधी पाठशालाएं लेकर आये थे। ऐसी छोटी-छोटी ढाणियां, एक-एक किलोमीटर, दो-दो किलोमीटर में जो स्कूलें नहीं थीं, एक साथ 26 हजार स्कूलें, राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं। उनकी एक सोच थी। उस जमाने में राजीव गांधी कहा करते थे कि अगर गांव को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, गांव के गरीब आदमी का परिवार शिक्षित होगा तो समुचित रूप से उस प्रदेश का भला होगा।

(श्री बाबूलाल नागर)

माननीय सभापति महोदय, एक साथ इतने विद्यालय खोलना मैं यह समझता हूं कि बहुत ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने किया था और अभी क्या किया पिछली सरकार ने, मैं उसके बारे में बताऊंगा। माननीय सभापति महोदय, आपने सरकारी महाविद्यालय खोलने में मैं समझता हूं कि रिकार्ड पैदा कर दिया। बहुत से साथी ऐसे कह रहे हैं कि केवल कालेज खोलने से काम थोड़े ही चलता है। जयपुर जिले में जितनी कालेज खोली है, फागी में खोली है, बस्सी में खोली है, जमवारामगढ़ में खोली है, बैराठ में खोली है, जयपुर में खोली है, गोविन्दगढ़ में खोली है, कोटपूतली में खोली है तो सारी जितनी भी नयी कालेज खोली है, उनका बजट आबंटन कर दिया, उनका काम चालू हो गया। मैं यह समझता हूं कि कालेज खोलते ही उसी सत्र में उनको चालू करवा देना, वहां पर बच्चे-बच्चियां दूर-दूर से 70, 80, 90 और 100 किलोमीटर से पढ़ने के लिए जयपुर आते थे, आज आपने उपखण्ड मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर वे बच्चे-बच्चियां पढ़ रहे हैं तो यह कमिटमेंट मुख्य मंत्रीजी का है। इसमें बजट दे दिया है, बिल्डिंग्स का काम चालू करवा दिया है।

अभी हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी मेरे यहां पर फागी गये थे, नींव लगाने के लिए गये थे, शिलालेख लगाकर आये हैं उच्च शिक्षा की इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे यहां पर इतनी बड़ी सोच कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन सरकारी महाविद्यालय हो गये। पहले से ही दो सरकारी महाविद्यालय थे, एक पिछली बार मुख्य मंत्रीजी ने खोली थी। हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी वहां पर गये थे, मैंने कहा कि आप यहां पर आये हो, आप मुख्य मंत्रीजी को बोलना, फागी में आपका भव्य स्वागत किया है तो कोई तो तोहफा देकर जाओ इस फागी को और यहां आकर मुख्य मंत्रीजी को क्या कहा इन्होंने पता नहीं और मेरे यहां पर कन्या महाविद्यालय खोल दी। आते ही दूसरे-तीसरे दिन ही बजट पेश करना था, उन्होंने कन्या महाविद्यालय खोल दी।

मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि सब तरह से, खेतान पोलीटेक्निक महाविद्यालय परिसर में 100 करोड़ रुपये की लागत से इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने की बात मुख्य मंत्रीजी ने की है। मुख्य मंत्रीजी ने अनुप्रति कोचिंग योजना में सात हजार छात्र-छात्राओं को लाभ प्राप्त हो रहा था, उसको भी बढ़ाकर पन्द्रह हजार विद्यार्थियों का प्रावधान कर दिया है। सावित्री बाई

(श्री बाबूलाल नागर)

फुले वाचनालय, अभी हमारी बहन बोल रही थीं, यह पुस्तकालय की बात कर रहे थे। राजस्थान के प्रत्येक जिले में मुख्य मंत्रीजी ने वाचनालय के लिए पचास लाख रुपये की लागत की घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि यह गरीब बच्चों को, मेरे से पूर्व वक्ता एक बात कह रहे थे कि मोबाइल, आज तकनीक का जमाना आ गया है। अब कोविड में भी हमने यह देखा है कि हमें शिक्षा में तकनीकी क्रांति लानी पड़ेगी। विद्यार्थियों के वाट्सएप ग्रुप बनाये जाने चाहिए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यूट्यूब-चैनल महाविद्यालयवार बनाये जायें। शिक्षकों के लेक्चर उसमें अपलोड करें और बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, चाहे छात्रवृत्ति की राशि से यह काट ली जाये, बच्चों को मोबाइल भी उपलब्ध करवाये जायें जिससे जो आधुनिक वर्तमान की तकनीक है, बच्चे उसका लाभ ले सकें। इसी तरह मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं आपको उच्च शिक्षा का एक टी.वी. चैनल, राजस्थान में टी.वी. चैनल के माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक एक अलग से आपको बनाना चाहिए।

(समय: 15.55 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, गुणवत्ता के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि गुणवत्ता का जो मूल्यांकन है मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, गुणवत्ता का मूल्यांकन का जो कार्य है यह पूरे देश में NAAC, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् करती है। National Assessment and Accreditation Council, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए राजस्थान में और NAAC गुणवत्ता के आधार पर महाविद्यालय को आपको ग्रेड प्रदान करनी चाहिए। महाविद्यालयों को ग्रेड प्रदान करनी चाहिए और राजस्थान में हमारे यहां पर जो सरकारी महाविद्यालय है, बहुत कम सरकारी महाविद्यालय ऐसे हैं जिनको ग्रेड मिला हुआ है। हमारे यहां पर बड़ेबड़े सरकारी महाविद्यालय भी हैं, भरतपुर में जैसे श्री जया राजकीय महाविद्यालय है, दौसा में भी बड़ा महाविद्यालय है। वहां पर भी ग्रेड नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञों को लेकर एक समिति बनानी चाहिए और समिति बनाकर कालेजों में संसाधन प्रदान कर NAAC की ग्रेडिंग हेतु प्रयास करना चाहिए। NAAC की

(श्री बाबूलाल नागर)

जब ग्रेडिंग होगी तो हमें केन्द्र सरकार से भी सहायता मिलेगी। ऐसे ही RUSA से अनुदान मिलेगा। RUSA से अनुदान किसको मिलता है? दो करोड़ रुपये तक का एक महाविद्यालय को RUSA से अनुदान मिलता है लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि NAAC की B+ ग्रेड होना आवश्यक है। अब जब B+ ग्रेड है ही नहीं तो जो भारत सरकार की योजना RUSA का अनुदान हमारे प्रदेश के सरकारी महाविद्यालय नहीं ले पा रहे हैं। हमें विशेष तौर से इसका ध्यान रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे यही कहना चहूंगा कि उच्च शिक्षा हेतु एक अच्छी विशेषज्ञों की समिति बनायी जाये। आई.आई.टी., आई.आई.एम. के बड़े प्रोफेसर्स, विशेषज्ञ और महाविद्यालय के अनुमति प्राप्त शिक्षकों को उसमें ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाये। चुनौतियों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे जमीनी सच्चाई का पता पड़े। आपको राज्य स्तर पर मंथन करने की आवश्यकता है।

आज राजस्थान की सरकार ने इन तीन सालों में इतना बड़ा इतिहास रच दिया उच्च शिक्षा का कि तीस साल में टोटल मिलाकर अगर हम महाविद्यालय जोड़ लें तीस साल के तो भी इन तीन साल में ज्यादा महाविद्यालय हमने खोले हैं, लेकिन हमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अभी निजी विश्वविद्यालय की बात आ रही है। इसी सत्र में, इसी विधान सभा में, इसी हाउस में हम निजी विश्वविद्यालयों को खोलने का यहां पर समर्थन करते हैं लेकिन एक बार अगर खोल दिया तो क्या इस विधान सभा में जिस निजी विश्वविद्यालय को हमने यहां उसका समर्थन करके उसको खोलने की अनुमति दी है तो क्या राजस्थान में जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं, क्या एक-दो उदाहरण भी ऐसे हैं जो इस विधान सभा ने उनकी स्वीकृति को विदड्रा किया है, हमें इस बात का भी चिन्तन करना चाहिए। हमें यह आवश्यकता है कि यह डिग्री बांटने का, यह पैसे कमाने का जो धन्धा शिक्षा जैसे पवित्र काम में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा हो रहा है, आपको तय कर लेना चाहिए, राज्य स्तर पर यह तय कर लेना चाहिए, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, एक नियामक आयोग आपको बनाना चाहिए निजी विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए और छह वर्ष से पुराने जो निजी विश्वविद्यालय हैं, उनके लिए आपको यह आवश्यक कर देना चाहिए, NACC की ग्रेडिंग प्राप्त करना आवश्यक

(श्री बाबूलाल नागर)

कर देना चाहिए। जब NACC की ग्रेडिंग आप आवश्यक कर देंगे तो निजी विश्वविद्यालयों में भी एक उच्च क्वालिटी की आप शिक्षा दे पायेंगे। इस सेवा के काम को जो व्यवसाय काम बना लिया है, व्यवसाय के काम से मुक्ति मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें निश्चित रूप से उच्च शिक्षा मंत्रीजी, उच्च स्तर पर, राज्य स्तर पर आपको एक सोच बनानी पड़ेगी। यह गरीब छात्रों को आजकल यह छात्रवृत्ति की पिछले सात-आठ महीने से बहुत प्राब्लम आ रही है। बहुत से बच्चे आते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारी छात्रवृत्ति नहीं हो रही है और बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए फार्म भरना पड़ता है, बच्चों को परीक्षा के लिए फार्म भरना पड़ता है। इसके अलावा

(समय: 16.00 बजे)

बच्चों को कोई दस्तावेज अपलोड करना होता है, बच्चों को तीन-तीन बार करना पड़ता है। एडमिशन में, स्कालरशिप में और परीक्षा में फार्म भरना पड़ता है। जब हम बच्चे को प्रवेश देते हैं तब एक ही बार सारी आवश्यकताएं बच्चे की कर लेनी चाहिए। तीन बार फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़े, तीन बार ई-मित्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़े, तीन बार बच्चों को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़े। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आपको बहुत फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। माननीय विद्वान मंत्रीजी बैठे हुए हैं डा बीडी कल्ला साहब, माध्यमिक शिक्षा में विषय अध्यापक और संस्था प्रधान के कक्षा 10 और कक्षा 11 के परीक्षा परिणाम के मापदण्ड तय कर रखे हैं और उसके बाद उसकी गुणवत्ता तय की जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि परीक्षा परिणाम वाले मापदण्ड को आप तय मत करो। आप तय करो उस विद्यालय में कितने बच्चे फर्स्ट डिविजन आये हैं। उस विद्यालय में कितनी बच्चियों को गार्गी पुरस्कार मिला है। कितनी बच्चियों को स्कूटी मिली है। थर्ड डिवीजन पास होकर चले जाओ, एडमिशन आगे मिलेगा नहीं, तो उस संस्था प्रधान या विषय अध्यापक को इनाम देने या प्रशंसा पत्र देने से क्या फर्क पड़ने वाला है। आपको उसकी ग्रेडिंग तय करते समय आपको देखना चाहिए। विद्यालय के सब्जेक्ट वाले अध्यापक ने क्या विशेष किया है जिसकी वजह से उसकी ग्रेडिंग तय की जानी चाहिए।

(श्री बाबूलाल नागर)

मैं कहना चाहूंगा कि विद्यालयों में खेल कालांश आवश्यक रूप से होना चाहिए। पीटीआई के पद अधिकतर खाली पड़े हैं। पूरे राजस्थान में चले जाओ। जिस तरह से आप शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, उसी स्पीड से आपको पीटीआई भर्ती करना पड़ेगा। कितना ही इन्टेलिजेंट आदमी हो, कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, वह स्वस्थ नहीं है, चारपाई पर पड़ा है, वह अपनी ऊर्जा को देश के लिए नहीं दे सकता है, प्रदेश के लिए नहीं दे सकता है। आपके पास शारीरिक शिक्षक होगा, बच्चों को व्यायाम करवायेगा, बच्चों को योगा करवायेगा, बच्चों को स्वस्थ रखेगा। जब स्वस्थ रखेगा तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश और देश की वह सेवा करेगा।

सभापति महोदय, बालिकाओं के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी एक उड़ान के नाम से ऐतिहासिक योजना लेकर आये हैं। आधी जनसंख्या महिलाओं की है। काबिले तारीफ है। जितनी इसकी तारीफ की जाए, उतनी कम है। उनको स्वस्थ रखने का, उनको बीमारी से बचाने का, इतनी बड़ी योजना लेकर आये हैं, इस योजना को कामयाब बनाने के लिए भी आपको तंत्र खड़ा करना पड़ेगा शिक्षा मंत्री महोदय। केवल योजना लागू करने से, स्कूलों में बांटने से इस उड़ान योजना का इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। आपको ऐसी कार्ययोजना बनानी चाहिए, ग्राम पंचायत लेवल पर तय कर देना चाहिए, किसी न किसी की जिम्मेदारी तय कर देनी चाहिए कि संबंधित ग्राम पंचायत में, संबंधित विद्यालय में जो बच्चियां पढ़ती हैं, उनके अलावा भी इसका लाभ मिलना चाहिए। सभापति महोदय, इसमें आपको प्रयास करना चाहिए।

सभापति महोदय, इसी तरह गांवों में कहीं भी स्कूल हो 9वीं से 12वीं में भाषा का विकास, चाहे हिन्दी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, उर्दू भाषा हो, इसके लिए आपको खुले सत्र आयोजित करने चाहिए। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर खुले सत्र आयोजित करने चाहिए। मैं समझता हूं, ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा।

व्याख्याता के पद आपने सृजित किये हैं। आपने व्याख्याता बहुत भर्ती किये हैं फिर भी अभी विषय के अध्यापकों की भारी कमी है। जब सबजेक्ट पढ़ाने वाला ही नहीं है तो उसका फायदा क्या है। आपने सबजेक्ट भी खोल दिया। सभापति महोदय, मैं तो कहना चाहूंगा कि चाहे विज्ञान और कृषि आज हमारे देश के 70 परसेंट लोग कृषि पर निर्भर कर रहे हैं तो आपको आवश्यक रूप से अनिवार्य विषय कर देना चाहिए। आपको माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान

(श्री बाबूलाल नागर)

और कृषि विषय को अनिवार्य कर देना चाहिए। हर विद्यालय में कृषि और विज्ञान होना चाहिए। जब कृषि का ज्ञान होगा, यदि नौकरी भी नहीं मिलेगी तो पढ़ा लिखा आदमी कृषि भी करता है तो बहुत ढंग से कृषि करेगा और पहले ही उसको उसके बारे में ज्ञान हो जाता है तो मैं समझता हूं, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, इसी तरह खेल विद्यालय ब्लाक स्तर पर करवाये थे आपने। पद भी स्वीकृत किये थे। सीबीईओ के पद भी स्वीकृत किये लेकिन अभी भी बहुत खाली हैं। एक मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि 3-3, 4-4 किलोमीटर पर बागरिया समाज, भील समाज, बंजारा समाज, गरीब समाज की जो ढाणियां थीं, पता नहीं पिछली सरकार में क्या दुश्मनी थी इन गरीबों से, इन दलितों के बच्चों से क्या दुश्मनी थी, क्या इनको परेशानी थी, एकीकरण के नाम पर राजस्थान में हजारों स्कूल बन्द कर दिये। इन तीन सालों में मारपीट करके, धक्का खाकर, जोर से बोल कर, धीरे बोल कर मुश्किल से 15-20 स्कूलों को हम चालू करवा पाये हैं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दूदू की बात कर रहा हूं। अकेले दूदू ब्लाक में 67 ऐसे विद्यालय बन्द कर दिये जो 2-2, 3-3 किलोमीटर तक कोई विद्यालय नहीं है। बागरियों के, बन्जारों के, भीलों के, एससी के, दलित समाज के जहां बच्चे पढ़ते थे, आज वे स्कूल बन्द हो गयें। पता नहीं, क्या मिला शिक्षा की बात करने वालों को। कोई दुश्मनी निकालनी थी तो मोटे स्कूलों से निकालते जो व्यवसाय चलाते हैं, सेवा का काम नहीं करते हैं, जो गरीब बच्चे ढाई-ढाई, तीन-तीन किलोमीटर में थे, उनको बन्द कर दिया।

सभापति महोदय, 15-20 स्कूल जो क्रमोन्नत हुईं उनका पता नहीं शिक्षा विभाग ने कौनसी कमेटी बनायी थी, हमारी ही सरकार में। मेरे तो यही समझ में नहीं आया। न हमसे बात की, अपने हिसाब से चुन-चुन कर बता दिया। मंत्रीजी ने भी यह कह दिया कि इनमें से आपको करानी हो, वह बता दो और रोकनी हो, उसको बता दो। रोकने का काम कैसे होगा? बाहर के विद्यालय को नहीं जोड़ सकते क्योंकि हमारी कमेटी ने फैसला किया है। कमेटी ने खाक फैसला किया है। गरीब जो बच्चे हैं, जो ढाणियों में रहते हैं, जो दूर-दूर रहते हैं, आज भी रो रहे हैं। आज तीन साल हो गये। मैं बी डी कल्ला साहब मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि ये बागरिया, भील, बन्जारे,

(श्री बाबूलाल नागर)

कौनसी कमेटी थी, किनको आपने बिठा दिया, कौन लोगों को यह काम दे दिया, जिन्होंने छांट-छांट कर उन्होंने विद्यालयों को बन्द कर दिया। अब जो खोले हैं, उनको कस्बों में खोल दिया जहां पहले से स्कूल चल रहा है। उसको और चालू कर दिया। वह राजस्व गांव था, उसमें दो स्कूल थे, उसमें एक ही जगह है, एक को चालू कर दिया है। उन ढाणियों का क्या होगा? क्या होगा स्वर्गीय राजीव गांधी के सपने का, क्या होगा अशोक गहलोतजी के सपने का, जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में शिक्षा को फैलाना चाहते थे। 26 हजार राजीव गांधी पाठशाला एक साथ लेकर आये। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। यह छोटी बात नहीं है। दूदू की 40 पंचायतें हैं और 67 स्कूल बन्द कर दिये। छांट-छांट कर बन्द कर दिये। कौन ऐसा है। गरीब लोगों की ढाणियों के स्कूल बन्द कर दिये। फागी में मेरी 20 पंचायतें हैं। बड़ा दु:ख होता है। 37 स्कूल मेरी फागी में बन्द कर दी। मैंने मंत्री महोदय को सूची दी है। मंत्री महोदय, पुण्य का काम है। जो गरीबों का पुण्य करता है, उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहता है। भगवान का आशीर्वाद भी छोटा होता है? अगर गरीब की दुआएं मिल गयीं न, तो भगवान का आशीर्वाद और गरीब की दुआ, उसका बड़ा आशीर्वाद होता है। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, बोलने के लिए तो मेरे पास और कुछ पाइन्ट हैं लेकिन मैं समझ रहा हूं, मेरा समय जितना दिया गया है, वह हो गया है, जैसाकि मुझे बताया गया है। मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद दे रहा हूं। कल्ला साहब, इस पुण्य को ले लो। विधान सभा चलती रहती है। एमएलए बनते रहते हैं। सरकारें बनती रहती हैं। वे ढाणियों के भील, बन्जारा, बागरिया त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। वह कौनसी कमेटी है, उसको भट्टी में डालो आप, जो कुर्सियों पर बैठकर, एसी में बैठकर ये लोग चयन करने का काम करते हैं और असली जो गांव का आदमी है वह चिल्लाता फिर रहा है। बड़ा दु:ख होता है, आंसू आते हैं। आपने भवन बना दिया, आपने मास्टर लगा दिया, क्या गुनाह कर दिया हम लोगों ने, जहां भवन बना हुआ है, टीचर लगा हुआ है और ताला लगा दिया। शिक्षा विभाग के कौन अधिकारी थे। कौन ऐसे तानाशाह लोग आ गये जिन्होंने इन गरीबों को मार दिया।

राजेन्द्र जी बैठे हैं, बहुत मजबूती से संघर्ष करते हैं। मैं आपकी बड़ी तारीफ करता हूं। आपका बड़ा फैन रहा हूं पर यह कैसे होने दिया, समझाया नहीं क्या आपने शिक्षा मंत्री को, आप किनके बन्द कर रहे हो? आपको

(श्री बाबूलाल नागर)

समझाना चाहिए था, यह आपने भी गलती कर दी, नहीं समझाया, आपको भी राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। आपका धर्म बनता है, मेरा धर्म बनता है, मेरी सरकार गलत काम करती है तो मैं बोलूंगा। मैं बोलता रहता हूं। कल्ला जी को याद होगा, जब ये मिनिस्टर थे। हमारे आरक्षण का मामला आया था तो मैंने कल्ला जी के खिलाफ खूब बोला, क्योंकि ये कार्मिक मंत्री थे। उस समय कार्मिक विभाग की गलती थी। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय कल्ला जी से कहूंगा कि मिडल स्कूल का जरूर ध्यान रखना। आपने केवल हायर सैकण्डरी थोक में की है। आप यह प्राइमरी स्कूल मिडल कर दो, मिडल से सैकण्डरी कर दो। लोग जय-जयकार करेंगे। वही अशोक गहलोत याद आ रहे हैं, जिन्होंने एक साथ 26-27 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं। ऐसे पूरा राजस्थान देख रहे हो आप, रोज 10-10 हजार आदमी, मैं भी गया था, माननीय सभापति महोदय, दूध के मामले में, पांच रुपये दिये थे और हम काफी लोग लेकर गये थे। वहां भीड़ ही नहीं समा रही थी। सिविल लाइन ही गूंज रहा था। वह पूरे राजस्थान की जनता को पता है लेकिन इन गरीबों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कल्ला साहब और माननीय हमारे यादव साहब, बहुत डायनिमिक मिनिस्टर हैं जयपुर जिले के नेता हैं। राज्य स्तर पर आज उच्च शिक्षा विभाग में अशोक जी गहलोत ने जो ज्योति जगाई है, इसकी राज्य स्तर पर कार्ययोजना बनाना और नीतिगत निर्णय तय करना, आपको दुनिया याद करेगी कि राजेन्द्र यादव नाम के एक मिनिस्टर आये थे। धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ग्राम बादनूं एक बड़ा गांव है। गांव के भिन्न-भिन्न विद्यालयों में बड़ी संख्या में बादनूं और उसके आस-पास के गांवों के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, किन्तु गांव में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा का सेण्टर नहीं होने के कारण इन विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा देने के लिये 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसलिए, मेरी मांग है कि बादनूं गांव में बोर्ड परीक्षा का केन्द्र खोला जाए।

माननीय सभापति महोदय, सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय की

(श्री गिरधारीलाल)

स्थापना हुए 9 साल हो गये हैं, पर बड़ा दुर्भाग्य है कि 9 साल में आज तक शेखावाटी विश्वविद्यालय में एक भी शैक्षणिक व अशैक्षणिक पद पर भर्ती नहीं हुई है। इससे शिक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय के तमाम संकायों में सभी पदों की तुरन्त भर्ती की जावे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में राजकीय महाविद्यालय को सरकार ने पी.जी. में क्रमोन्नत कर दिया, उसके लिये तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं पर मैं मांग करता हूं कि श्रीडूंगरगढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय के जितने भी पद रिक्त पड़े हैं, उन तमाम रिक्त पदों को तुरन्त भरा जाए।

माननीय सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के दुलचासर गांव में प्रतिवर्ष 500 से अधिक छात्राएं उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाद कालेज शिक्षा में प्रवेश करती हैं। साथ ही दुलचासर गांव के आस-पास 10-12 किलोमीटर से ज्यादा गांव, ग्राम पंचायत आते हैं। इसके अलावा, बड़ा गांव रिड़ी गांव, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राएं अध्ययन करती हैं। इसलिए, मेरी सरकार से मांग है कि दुलचासर और रिड़ी में सरकारी महाविद्यालय खोला जाए।

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दुलचासर, पूनरासर, सेरूणा, लिखमादेसर, मोमासर, लखासर, साधासर, बादनूं, सोनियासर, मिठिया, बाड़ेला, कितासर, कुचौर आथूणी के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोला जावे। गांव बापेऊ के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला संकाय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखमीसर उतरादा एवं सूडसर में कृषि विज्ञान संकाय खोला जावे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा के गांव पूनरासर, सावंतसर व कुंतासर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भूगोल एवं साधासर में राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त विषय खोले जावें।

माननीय सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में बड़ी संख्या में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि तमाम रिक्त पदों को तुरन्त भरा जावे और बन्द पड़े प्राथमिक विद्यालयों को शीघ्र खोला जावे और नये प्राथमिक विद्यालय भी खोले जावें।

माननीय सभापति महोदय, मैंने बदलती शिक्षा नीति पर विचार रखा

(श्री गिरधारीलाल)

और मैं आशा करता हूं सरकार से, कि जो मैंने सटीक मांगें रखी हैं, उन सटीक मांगों पर हमारे मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय हैं, वह निश्चित रूप से सकारात्मक रूख लेंगे और मेरी बातों पर गौर करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे शिक्षा, कला और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, हम आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव में बहुत सारी यादों को हम ताजा कर रहे हैं। इस अमृत महोत्सव के लिये, कि हम अमृत महोत्सव मना पाएं, इसके लिये हिन्दुस्तान के बहुत सारे वीरों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, अपने प्राणों का त्याग किया है। 15 अगस्त, 1947 में इतनी लम्बी लड़ाई के बाद 1857 से लेकर 1947 तक भारत आजाद हुआ। बहुतसे लोग इसको स्वतन्त्रता कहते हैं। कोई कहता है कि हम आजाद हो गये, स्वतन्त्र भारत में सांस ले रहे हैं। "स्व-तन्त्र" जब मैं इस शब्द के बारे में जानने की कोशिश करती हूं तो सभागार में अभी हमारे शिक्षा मंत्री बीडी. कल्ला जी बैठे हैं और यह बहुत अच्छेसे समझते हैं कि स्व-तन्त्र का क्या मतलब है? क्या हमारे हजारों लोगों ने अंग्रेजों से सत्ता हिन्दुस्तानियों के पास आ जाए, भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति के पास आ जाए, क्या सिर्फ इसीलिए हमने राजनीतिक संघर्ष किया था हजारों वर्षों से, कि अंग्रेजों से सत्ता लेकर हमारे हाथ में आ जाए, सिर्फ मात्र इतनी-सी चीज के लिये यह स्वतन्त्रता आन्दोलन था? माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं था। स्वतन्त्र में 'स्व' को अलग करिए और 'तन्त्र' को अलग करिए। हमारे स्वयं का तन्त्र होना चाहिए, ऐसी स्वतन्त्रता हमें चाहिए। हम अपने 'स्व' का तन्त्र विकसित करना चाहते थे। हमारी स्वतन्त्रता पर अंग्रेजों ने जो आघात किया था, जो मुगलों ने आघात किया था, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे। हम लड़ाई यह लड़ रहे थे कि जो हमारी जीवन पद्धति है, जो आर्यों की जीवन पद्धति है, जो इस भारत भूमि की जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति की आत्मा पर जो अंग्रेजों ने आघात किया था, वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम स्वतन्त्र होना चाहते थे, न कि मात्र इस बात के लिये स्वतन्त्र होना चाहते थे कि अंग्रेजों से सत्ता हिन्दुस्तानियों के पास में आ जाए। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, 70 सालों से जिन्होंने राज किया, उन्होंने उस तन्त्र को और छिन्न-भिन्न करने की कोशिश की, न कि विकसित करने की कोशिश की। (व्यवधान)

(श्रीमती अनिता भदेल)

अभी माननीय सदस्य, मैं उनके विधान सभा क्षेत्र को नहीं पहचानती हूं, इन्द्राज सिंह गुर्जर की।

एक माननीय सदस्य: विराटनगर।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, विराटनगर। इन्द्राज जी कह रहे थे कि आजादी का श्रेय कांग्रेस को है। यह उन्होंने अभी अपने वक्तव्य में कहा और यह इन्द्राज जी ने, जो विराटनगर से आते हैं, उन्होंने कहा था। आजादी का श्रेय कांग्रेस को है। हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और उन्होंने यह सही कहा है, इसलिए मैं कह रही हूं सही कहा, क्योंकि उनको पढ़ाया ही यही गया है। इन 70 सालों में जिन्होंने इतिहास लिखा, वह इतिहास लिखने वाले कौन थे? कांग्रेस से उपकृत होने वाले लोग थे। कांग्रेस से पैसा लेने वाले लोग थे। कांग्रेस के पदों पर जाने वाले लोग थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज सदन में यह 2 किताबें लेकर आयी हूं। इनका विश्लेषण मैं करूंगी। आप प्लीज मुझे टोकिये मत। यह है आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, भाग-1, कक्षा 11 और दूसरा है, आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, भाग-2, कक्षा 12, ये 2 किताबें इन्द्राज गुर्जर जी के वक्तव्य को सिद्ध करती हैं। यह इसलिए सिद्ध करती हैं क्योंकि 70 सालों से हमने अपने बच्चों को यही पढ़ाया है।

ओसियां से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि नेहरू जी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग की शुरुआत की। मैं जिस तंत्र की बात करती हूं, हमने वह तंत्र भुला दिया। हमने पश्चिमी देशों को ही मान लिया कि उन्होंने ही विज्ञान की उन्नति की है। उन्होंने ही विज्ञान की खोज की है। हमने चरक को भुला दिया। जिस जीरो को भारत ने जन्म दिया, उसको भुला दिया। मैकाले ने एक बात कही थी कि मैं हिन्दुस्तान में ऐसी शिक्षा पद्धति और ऐसे लोगों को तैयार करना चाहता हूं जो रंग, रूप, स्वभाव में दिखने से तो हिन्दुस्तानी हों, लेकिन उनके विचार पूरी तरह से पाश्चात्य हों। यही मानें कि हिन्दुस्तानी असभ्य हैं। वह पढ़े-लिखे नहीं हैं। अंग्रेजों ने यह बात कही थी। यही बात हमारी ओसियां से आने वाली माननीय सदस्या कह रही हैं कि नेहरू ने ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी की स्थापना की। उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाया। यह कौन थे जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की? यह कौन थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की? वह कौटिल्य कौन था जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की और जिसके आधार पर आज भी हम अर्थशास्त्र को पढ़ाते हैं। ये

(श्रीमती अनिता भदेल)

लोग कौन थे? ये हिन्दुस्तान की आजादी के बाद के लोग थे? लेकिन हमने 'स्व' को भुलाने की कोशिश की। हमने हमारे 'तंत्र' को भुला दिया। हम उन पाश्चात्य लोगों के पिछलग्गू बन गये।

अब मैंने जो यह कहा है, इसके लिये आगे बढ़ती हूं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एक तरफ तो माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ायेंगे। जब हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को यह 2 किताबें अतिरिक्त क्यों पढ़ा रहे हैं? यह इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कांग्रेस का गुणगान किया जा सके। मैं कुछ पृष्ठ उद्धृत करके साबित करूंगी।

अभी वे कह रहे थे कि महात्मा गांधी के बारे में आप कुछ सुनना नहीं चाहते। कुछ बोलना नहीं चाहते। आपने यह किताब लिखवायी है? राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों से लिखवायी है। इस राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों ने इस किताब में क्या लिखा है? अम्बेडकर जी के बारे में क्या लिखा है? यह भी मैं बताती हूं। बहुत बोलते हैं न कि हम अनुसूचित जाति को बढ़ावा देते हैं। हम अनुसूचित जाति के लोगों के लिये यह करते हैं, वह करते हैं। अम्बेडकर जी के साथ क्या किया कांग्रेस ने? उनको चुनाव हरवाया। उनके मरने के बाद भी दिल्ली में उनका दाह-संस्कार नहीं होने दिया इसलिए कि कहीं अनुसूचित जाति के लोग जागरूक न हो जायें। माननीय, आप अभी-अभी मंत्री बने हैं। आपको नहीं मालूम होगा, इस किताब में क्या लिखा है इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी।

सभापति महोदय, राजकीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एनसीईआरटी के अलावा कक्षा-11 और कक्षा-12 में यह 2 पुस्तकें प्रारम्भ की हैं। आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, भाग-1 और भाग-2, ये अनिवार्य रूप से लागू हैं। इस पुस्तक के 84 पृष्ठ हैं। माननीय मंत्री महोदय, इन 84 पृष्ठों में से 48 पृष्ठ भारत की आजादी के पहले के पृष्ठ हैं। किताब का नाम है आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत। इसमें आजादी के बाद के स्वर्णिम भारत का जिक्र होना चाहिए। इसमें आजादी के बाद की चीजें लिखी होनीं चाहिए लेकिन इसमें 84 में से 48 पृष्ठों पर आजादी के बाद का नहीं, आजादी के पहले का उल्लेख है। यह विषय-वस्तु किताब के शीर्षक से मेल ही नहीं खाती लेकिन हमने लिखी है क्योंकि हमें कांग्रेस का महिमा मण्डन करना है।

फिर आप देखिये, इस किताब में आजादी से पहले के कांग्रेस के सारे

(श्रीमती अनिता भदेल)

कार्यकलाप लिखे हैं, लेकिन एक बात को बहुत चतुराई से हटा दिया या उसको गौण कर दिया। कांग्रेस की स्थापना का उल्लेख तो इस किताब में है लेकिन कांग्रेस की स्थापना किसने की और किस उद्देश्य को लेकर की, यह इसमें बिलकुल गायब कर दिया। आप क्यों गायब करते हो? आप यह क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी और अंग्रेजों की नीतियों के समर्थन के लिये की थी। आप यह बात क्यों नहीं कहते हो? इतिहास में यह बात बच्चों को आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हो? वह नहीं पढ़ायेंगे क्योंकि वह बात हमारे विरुद्ध जाती है। इस कारण हम इसे क्यों पढ़ायेंगे?

माननीय सभापति महोदय, अब आप आगे देखिये, यह पुस्तक केवल पंडित नेहरू के व्यक्तित्व और कृतित्व पर समर्पित है जबकि कांग्रेस के और भी प्रधान मंत्री हुए हैं। उनका उल्लेख सिर्फ बिन्दु मात्र है। हम एक ही परिवार को कब तक उपकृत करेंगे और क्यों करेंगे? क्या कारण है? पंडित नेहरू की राष्ट्र निर्माण की भूमिका निश्चय ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पुस्तक स्पष्टतया यह सन्देश देती है कि इस अवधि में भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास यात्रा में अन्य कोई है ही नहीं। पूरे हिन्दुस्तान को इन 70 सालों में अकेले नेहरू जी ने ही आगे बढ़ाया, ना और तो कोई है ही नहीं? इसका क्या मतलब है?

माननीय सभापति महोदय, अब आप आगे देखिये, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वे कांग्रेस के ही थे। रियासतों का एकीकरण तो उन्होंने ही किया। माननीय मंत्री महोदय, आज हिन्दुस्तान जिस स्वरूप में है, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आप सीने पर हाथ रखकर के बोलें कि आज की यही भौगोलिक स्थिति होती क्या हिन्दुस्तान की? इतने महत्वपूर्ण कार्य को कांग्रेस ने बरसों तक भुलाया। इस पुस्तक में भी भुला दिया। आप देखिये, आजादी के बाद के स्वर्णिम भारत की बात हो या देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय का कोई उल्लेख इस किताब में नहीं है जबकि हैदराबाद और जूनागढ़ सहित 560 से अधिक देशी रियासतों का संघ में विलय स्वतन्त्रता के बाद स्वर्णिम भारत के निर्माण की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसको आपने हटा दिया।

माननीय सभापति महोदय, नेहरू जी की तुलना में सरदार पटेल की भूमिका को इग्नोर करने के उद्देश्य से इन्होंने कश्मीर समस्या, जो सिर्फ नेहरू के कारण से पैदा हुई, उस समस्या का उल्लेख इस पुस्तक में किया ही नहीं गया है, न ही रियासतों के विलय की कोई बात इसमें कही गयी है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से देश का विभाजन हुआ। इतनी बड़ी घटना हुई। 5 हजार से लेकर के 10 हजार लोग मारे गये लेकिन देश के विभाजन की व्याख्या इसमें कही नहीं है। इस पुस्तक में कहीं है ही नहीं। कहीं पर भी नहीं है।

इसी तरह से संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी हैं। आप देखिये, मैं पढ़कर के बताती हूं। इस पुस्तक के अध्याय 3 में संविधान निर्माण के लिये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रेय देने का इनका मंतव्य झलकता नहीं है। इसमें लिखा है, 'नेहरू ने पंथनिरपेक्ष भारतीय संविधान का निर्माण कराया'। यह इसके अंदर लाइन है। अम्बेडकर जी को जो श्रेय देना चाहिए था वह श्रेय नेहरू जी को दे रहे हैं। डा. अम्बेडकर जी के लिये इसमें क्या लिखा है, संविधान निर्माण का शब्द कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। पृष्ठ 30 पर उनको मात्र दलित वर्ग का नेता कहा है। ये इतने सारे उदाहरण हैं। कम से कम 20 उदाहरण हैं। यदि मैं इन सभी उदाहरणों के बारे में बताऊं तो आप मेरा समय खतम कर देंगे। सभापति महोदय, मेरा मंतव्य सिर्फ इतना सा है, मंत्री महोदय, कि आप इन किताबों में इन बच्चों को तो कम से कम गलत मत पढ़ाइये। आप क्या चाहते हो? शिक्षा का 70 सालों से अनुसूचित जाति के वोट लेकर राजनीतिकरण कर रहे हो लेकिन फिर भी अभी तक मन नहीं भरा है।

अब तो इंटरनेशनल लेवल पर लोग चले गये। नेट पर सारी चीजें अवेलेबल हैं। आज यूके में क्या हो रहा है? यूक्रेन में क्या हो रहा है? यह सब दिखता है। आपकी ये किताबें भी बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? उनके पेरेंटस क्या सोचेंगे? कितनी घटिया मानसिकता है आपकी। इसलिए मैं चाहती हूं कि इन किताबों को तुरन्त बदलना चाहिए, वास्तविक इतिहास इसमें आना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, हम यूनिवर्सिटीज की बात करें। अभी ओसियां से आने वाली माननीय सदस्या जामिया, जेएनयू, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात कर रही थीं। माननीय मंत्री महोदय, मुझे इस बजट में बता दें कि यह कौनसी संख्या पर लिखा है। जामिया, अलीगढ़ और जेएनयू यूनिवर्सिटी किस मांग संख्या में है? 24 वाली मांग संख्या में है क्या ये? आप मुझे जवाब देते समय बता दें कि मांग संख्या 24 में यह जेएनयू, जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी यहां-यहां लिखी हुई है। हम अपने पैरों की तरफ नहीं देखेंगे और

(श्रीमती अनिता भदेल)

दूसरे की कमियां खोजेंगे। हमने जो अच्छा-अच्छा किया वह बतायेंगे और जो हमने अच्छा-अच्छा नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे।

अभी इंटरनेट की बात कर रही थीं कि कालेज में, स्कूलों में, गांवों में इंटरनेट नहीं है, सही बात है, नहीं है इंटरनेट तो आपकी 70 साल की सरकार ने क्या किया जी? ये तो कोविड आ गया इसलिए इंटरनेट की इतनी ज्यादा आवश्यकता हो गयी, इतनी ज्यादा आवश्यकता महसूस करने लग गये लोग कि इंटरनेट होना चाहिए। प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी 5जी लेकर आये हैं, फाइबर केबल गांव-गांव में बिछा रहे हैं। आपके यहां तो कनिमोझी गयी थी न जेल। 2जी स्पेक्ट्रम का भूल गये कि वह कब हुआ था और उसमें क्या हुआ था? जेल गये थे। आपने क्या-क्या किया, ये सब चीजें गौण और नरेन्द्र मोदीजी क्या कर रहे हैं, रामजी का नाम ले रहे हैं, कृष्णजी का नाम ले रहे हैं, ऋषि-मुनियों का नाम ले रहे हैं, आज आप राम का नाम ले रहे हैं। आप खड़े होकर कह दीजिये, ओसियां से आने वाली माननीय सदस्य कह दें कि मैं राम को मानने वाली नहीं हूं, मैं ऋषि परम्परा को नहीं मानती हूं। हम जिस भूमि में पैदा हुए हैं, जहां से संस्कार हमें मिले हैं, हम हिन्दुस्तानियों की पहचान ही यही है। वो कहते हैं न कि रोम-इटली मिट गये जहां से, हिन्दुस्तान की छवि आज भी है, वह इसी के कारण तो है। आज यदि बदल जाओगे तो आपकी पहचान नहीं रहेगी। अपनी पहचान को क्यों खतम करना चाहते हो, क्यों खतम कर रहे हो? माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इन चीजों को आप देखें कि किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं हायर एजुकेशन के कुछ मुद्दों की ओर आना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, 26 फरवरी, 2022 को कोटा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में माननीय मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत द्वारा जो भाषण दिया गया, उस भाषण के जो मुख्य अंश थे उन अंशों को ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। वो ट्वीट क्या थे, राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में प्रतिबद्धता से काम कर रही है जिससे प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है, मुख्य मंत्रीजी की यह सोच अच्छी बात है लेकिन यह सोच रखने मात्र से काम नहीं चलेगा, माननीय मंत्री महोदय, इस सोच को कैसे हम इम्पलीमेंट करें उससे काम चलेगा। अब जब नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की जब बात करते हैं तो अभी सिरोही

(श्रीमती अनिता भदेल)

से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वनस्थली विद्यापीठ को यह रैंकिंग मिला है, और बाकी की यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग मिली है लेकिन यह हमारी वजह से नहीं मिली है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और वर्षों से चल रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के विश्वविद्यालयों को नैक की कितनी ग्रेडिंग मिली है, यह सोचने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताती हूं कि राज्य के 372 महाविद्यालयों में से, माननीय मंत्री महोदय, सिर्फ 73 राजकीय महाविद्यालयों को नैक का ग्रेडिंग मिला है। इन 73 में से सिर्फ 5 महाविद्यालय हैं सरकारी, जिनको नैक की ग्रेडिंग मिली है, बाकी के सरकारी नहीं हैं। 5 महाविद्यालयों को 'ए' ग्रेड मिला है, 299 कालेज तो नैक ग्रेडिंग के लायक ही नहीं समझते अपने आप को, उन्होंने तो आवेदन तक ही नहीं किया कि हमें नैक ग्रेडिंग दी जाये। राज्य के 5 विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन हुआ है, उनमें से 2 विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय और सुखाड़िया विश्वविद्यालय को सिर्फ 'ए' ग्रेड मिला है। बाकी को 'ए' ग्रेड नहीं मिला है। सीकर, अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा जैसे विश्वविद्यालयों में तो शैक्षणिक पदों पर भर्ती ही नहीं की गयी है। एक भी, एक भी सिंगल नहीं। जब शिक्षक ही नहीं है तो कौन पढ़ायेगा उन महाविद्यालयों में? इसी प्रकार से 80 परसेंट राजकीय कालेज अभी तक नैक से बाहर हैं, 80 परसेंट। माननीय मंत्री महोदय, यदि आपने ये 80 परसेंट में से 50 परसेंट को भी नैक ग्रेडिंग दिला दी तो आपका मंत्री के रूप में कार्यकाल, शिक्षा मंत्री के रूप में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा, यह मैं निवेदन करना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, अब ये बजट घोषणाएं, पिछले बजट भाषण में भी मैंने यह बात कही थी। पिछले बजट में 400 करोड़ रुपये की लागत से फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में, 200 करोड़ रुपये की लागत से इंस्टीट्यूट आफ एडवांस लर्निंग जयपुर में तथा 200 करोड़ रुपये की लागत से राजीव गांधी सेंटर फोर एडवांस्ड टेक्नोलोजी जयपुर में स्थापित करने की घोषणा की गयी है पर जवाब देते समय मुझे बता दीजिये कि 400, 200 और 200, कुल 800 करोड़ रुपये में से आपने कितने पैसे अभी स्वीकृत कर दिये, बजट में आबंटित कर दिये और उनकी स्वीकृतियां निकल गयीं?

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से गेस्ट फैकल्टी के बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि हमेशा से ही स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हम

(श्रीमती अनिता भदेल)

नहीं करेंगे और गेस्ट फैकल्टी के रूप में लायेंगे। आपने अपने जन घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम गेस्ट फैकल्टी को अवोइड करेंगे और स्थायी शिक्षकों की भर्ती करेंगे फिर भी आप, यह कहने के बावजूद भी, पुराने गेस्ट फैकल्टी वाले तो अभी तक नियमित हुए नहीं, आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है उसका क्या हुआ भगवान जाने, लेकिन नये लोगों को आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में वापस ला रहे हैं, यह बहुत गलत बात है। 372 कालेजों में से सिर्फ और सिर्फ, मात्र 25 कालेजों में शारीरिक शिक्षक और 27 कालेजों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हैं। ऐसे में जो हायर एजुकेशन है उसमें क्या प्राप्त करेगा बच्चा? जहां पोस्टें ही नहीं हैं, वहां ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया।

माननीय सभापति महोदय, देखिये आप, जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 36 और 28 पर सरकार में आने से पहले आपने जनता से वादा किया था, राजस्थान की जनता से यह वादा किया था कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जीरो करप्शन और जीरो हरेसमेंट की नीति पर काम करेंगे। पर अभी हो क्या रहा है, हरेसमेंट तो इस सरकार में इतना हो रहा है कि राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग तो ट्रांसफर करते हैं, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग, माननीय सभापति महोदय, क्या स्तर गिराया है आपने, कालेज एजुकेशन के बच्चे और शिक्षक, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के जिला समन्वयक उनको जो नेशनल बिल पास किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी नाम याद नहीं आ रहा, उस बिल के विरोध के लिये, हां, याद आया, नागरिकता संशोधन विधेयक, माननीय सभापति महोदय, नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध के लिए, माननीय मंत्री महोदय, आपको बताना चाहूंगी कि अजमेर महाविद्यालय के प्रिंसिपल ने छुट्टी लेकर सारे लोगों को बस में भरकर यहां लाये और नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में बस भर-भरकर यहां पर रैली में लाये तो यह तरीका ठीक है क्या कि राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग यह काम करेंगे जबकि राजनीतिक काम करने की तो मनाही है सरकारी कर्मचारियों को, फिर भी वो यह काम कर रहे हैं। इस तरह से राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग डराकर कितना करप्शन किया होगा, आर्थिक रूप से कितना भ्रष्टाचार किया होगा, माननीय मंत्री महोदय आपको यह मालूम नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इसी तरह से अजमेर यूनिवर्सिटी के बारे में निवेदन करना चाहती हूं। अजमेर शिक्षा का हब रहा है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

जयपुर, कोटा नहीं था। एक जमाना हुआ करता था, कई लोग आज भी विधान सभा में आते हैं और कहते हैं कि हम अजमेर के गवर्नमेंट कालेज से पढ़े हुए हैं। अजमेर के गवर्नमेंट कालेज से पढ़ने में गर्व महसूस करते थे लोग, अजमेर के मेडिकल कालेज से पढ़ने में गर्व महसूस करते थे लोग, अजमेर के मेयो कालेज जाते थे, अजमेर के तोपदड़ा स्कूल से पढ़कर आईएएस आफिसर आज भी इस लॉबी में बैठते हैं, माननीय मंत्री महोदय, लेकिन अजमेर की शिक्षा का क्या सत्यानाश हुआ? अजमेर में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, एमडीएस यूनिवर्सिटी और उस एमडीएस यूनिवर्सिटी में स्थायी शिक्षकों के सिर्फ 16 पद हैं, बाकी 42 पोस्टें खाली पड़ी हैं। ये सिर्फ अजमेर यूनिवर्सिटी का हाल नहीं है। राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी का यही हाल है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी यूनिवर्सिटीज कैसी चल रही हैं, 1500 विद्यार्थी, 900 विद्यार्थी, 800 विद्यार्थी, इनसे तो स्कूल ही अच्छे हैं। जहां कम से कम दो-दो, ढाई-ढाई हजार विद्यार्थी तो हैं, इनको यूनिवर्सिटीज कहेंगे क्या हम? हमको कहने में ही शर्म आती है कि ये यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटीज में शिक्षक ही नहीं हैं, विभाग ही नहीं है तो कौन पढ़ायेगा, इसलिए विद्यार्थी एडमिशन ही नहीं लेते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि आप कोई ऐसा सिस्टम डवलप कीजिये कि एक साथ सारी यूनिवर्सिटीज में शिक्षक उपलब्ध हो जायें क्योंकि यदि यूनिवर्सिटी स्तर पर भर्ती होगी तो कोई न कोई घटनाक्रम करप्शन का जरूर घटेगा, यदि घटेगा तो वह भर्ती रुक जायेगी। इसलिए वह भर्ती रुके नहीं और सीधी भर्ती होकर उनको शिक्षक मिल जाये, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, अभी चाइल्ड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की तो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने बात कर दी इसलिए मैं वह बात दोहराऊंगी नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो-तीन निवेदन करके अपनी बात खतम करना चाहूंगी। माननीय मंत्री महोदय, रमेशजी, आयुक्तालय कालेज शिक्षा में, कालेज शिक्षक के मात्र 10 पद स्वीकृत हैं जयपुर में, अब आपके यहां पर बैठे 10 की जगह 60 से 62 टीचर बैठे हैं, जिन टीचर्स की फील्ड में जरूरत है, किसी को बांसवाड़ा जाना है, किसी को अलवर जाना है, किसी को भरतपुर जाना है, उन कालेजों में भेजिये, ताकि वो बच्चों को पढ़ा सकें। यहां राजनीति करने के लिए 60 से 62 टीचर्स बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री महोदय,

(श्रीमती अनिता भदेल)

और वह भी बिना किसी पद की स्वीकृति के बैठे हैं। इसीलिये मेरा निवेदन है कि यदि इस व्यवस्था की आप बारीकी से मॉनिटरिंग करेंगे तो बहुत सारी चीजें वैसे ही ठीक हो जायेंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की दो-तीन चीजें कहकर समाप्त करूंगी। माननीय मंत्री महोदय, माध्यमिक शिक्षा मंत्री से मेरा निवेदन है कि आपने अंग्रेजी विद्यालय खोले, अच्छी बात है। हम इसे बुरा नहीं मानते हैं, पर आपने तरीका क्या अपनाया? जो विद्यालय आलरेडी चल रहे हैं, जिनकी बिल्डिंग्स हैं, उन्हीं को आपने कन्वर्ट कर दिया बिना एक पैसा लगाये, तो हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखो आये, वाह-वाही बहुत अच्छी हो गयी, लेकिन जिन विद्यालयों को आपने अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत किया है, उदाहरण के तौर पर देखिये आप, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा (अजमेर) में 500 लड़कियां पढ़ती थीं। अब इसे अंग्रेजी माध्यम कर दिया। गांव में दूसरा स्कूल है नहीं कोई। ऐसे में वे 500 लड़कियां अचानक से अंग्रेजी में कैसे पढ़ने लग जायेंगी? उन सबने टीसी ले ली। टीसी लेकर वे घर बैठ गयीं। जितने सारे बालिका विद्यालय आपने कन्वर्ट किये हैं, उन सबको as it is रखें और अंग्रेजी के अतिरिक्त विद्यालय आप खोलें।

माननीय सभापति महोदय, एक मैं छात्रवृत्ति की बात करूंगी। अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाएं सिर्फ छात्रवृत्ति के भरोसे पढ़ते हैं स्कूलों में, इसीलिये उनकी छात्रवृत्ति टाइमली मिल जाये, यह मंत्री स्तर से हमें मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, अन्त में एक निवेदन करूंगी, स्कूलों में आज-कल सब जगह नैतिकता का अवमूल्यन हुआ है और स्कूलों में बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं जिस कदर हर दूसरे-तीसरे दिन सामने आ रही हैं, मेरा आपसे निवेदन है, सरकारी हो अथवा निजी विद्यालयों में, जिन भी कर्मचारियों द्वारा यह कृत्य किया गया है, उन्हें सेवा से तुरन्त बर्खास्त करने का नियम आपको लाना चाहिये ताकि इन विद्यालयों में एक माहौल बने। वैसे ही मां-बाप बहुत मुश्किल से भेजते हैं बेटियों को स्कूलों में। ऐसे में ये शिक्षा के मन्दिर भी नहीं बचेंगे तो फिर और कौन-सी जगह बचेगी। जो शिक्षा देने वाला व्यक्ति है, जिसे हम गुरु कहते हैं, जिसे पूजनीय कहते हैं, वह यह काम करता है तो यह शर्म से डूब मरने वाली बात है। इतना कहकर मैं अपनी बात को पूरा करती हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाकर सात बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया गया।

माननीय श्री पुखराज गर्ग।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये आभार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि भोपालगढ़ में महिला महाविद्यालय की घोषणा उन्होंने की। साथ ही, मैं यह मांग करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के बाद दूसरी जो बड़ी ग्राम पंचायत है, वह आसोप है, जो कि भोपालगढ़ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां वर्तमान समय में सरकारी और प्राइवेट लगभग 38 स्कूलें संचालित हैं। उनमें लगभग 1724 छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में यह घोषणा की थी कि जहां 500 छात्राएं हैं, वहां पर एक कालेज खोला जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आसोप में भी महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा करें ताकि वहां के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। आसोप से भोपालगढ़ में दूरी होने के कारण ग्रामीण परिवेश के बच्चों को आने-जाने में बहुत दिक्कत रहेगी।

माननीय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, भोपालगढ़ में जोधपुर जिले का एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र का बीएड कालेज संचालित था, जो आज की तारीख में स्टाफ नहीं होने की वजह से बन्द होने की कगार पर है। उस बीएड कालेज में स्टाफ की नियुक्ति कराएं, दूसरे व्याख्याताओं को लगाएं

(श्री पुखराज)

ताकि वह कालेज संचालित रह सके। भोपालगढ़ मुख्यालय पर जो अभी परसराम मदेरणा महाविद्यालय संचालित है, उसमें भी जो सैंक्शंड पोस्ट्स हैं, उसके अभी 50 परसेंट व्याख्याता लगे हुए हैं। वहां व्याख्याता लगाये जाएं। साथ ही, दूसरे संकाय भी उसमें खोलने की जरूरत है। जो संकाय अभी संचालित हैं, उनमें भी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बावड़ी उप-खण्ड मुख्यालय है, वहां पर पिछले चार साल से महाविद्यालय संचालित है। उस महाविद्यालय का भवन नहीं है और वह प्राइमरी स्कूल के दो रूम्स में संचालित हो रहा है। लगभग साढ़े सात सौ छात्र-छात्राएं वहां अध्ययनरत हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी वह भवन बने और छात्र-छात्राओं को आधारभूत सुविधा मिले।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कालेजों में जो व्याख्याताओं की भर्ती होती है, उसमें रिजर्वेशन में रोस्टर सिस्टम का पालन नहीं हो रहा है, इसलिये मेरी मांग है कि आरक्षण में रोस्टर सिस्टम लागू हो और हर महाविद्यालय में एक रोस्टर रजिस्टर मेंटेन होना चाहिये ताकि शोषित, वंचित और जो रिजर्व्ड तबके के लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, उन्हें कालेज में सेवा करने का मौका मिले, रोजगार का अवसर मिले।

माननीय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि मेरे भोपालगढ़ में बहुत सारे माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें स्टाफ की काफी कमी है। वहां जल्दी से जल्दी प्रिंसिपल और व्याख्याता की जो कमी है, उसकी पूर्ति की जाये। साथ ही, अभी जो स्कूलें क्रमोन्नत होनी हैं, जिसकी सख्त जरूरत है, जहां विद्यार्थियों की काफी स्ट्रेंथ है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सांवत कुआं बूढ़ियों की बासनी और सुवाणा प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने के आदेश कराएं।

साथ ही, जो आशापुरा उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उसमें काफी बच्चियां भी अध्ययनरत हैं और नजदीक में कोई सैकंडरी स्कूल भी नहीं है, इसलिये आशापुरा उच्च प्राथमिक विद्यालय को भी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने का आदेश कराएं। माननीय, आपके

(श्री पुखराज)

माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो कालेजों में पिछली बार भर्ती निकली थी, उसमें पूरे प्रदेश में इंडिविजुअल एक-एक कालेज में एक-एक भर्ती निकाली थी और उस कालेज में फार्म मांगे गये थे। उस कालेज के प्रिंसिपल ने कलेक्शन किया और उन फॉर्म्स को लेकर फिर प्रदेश स्तर पर जयपुर भेजा। फिर नियुक्तियां जयपुर से दीं।

माननीय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह इनडायरेक्टली आरक्षण खतम करने की बात है। सारी वेकेंसीज इंडिविजुअल एक-एक महाविद्यालय की नहीं निकालकर पूरे प्रदेश की एक साथ निकाली जातीं तो निश्चित तौर पर जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनका भी नम्बर आता। ऐसी व्यवस्था पर अंकुश लगाएं और सारी वेकेंसीज एक साथ निकालकर ऐसे जो आरक्षित वर्ग के शिक्षित बेरोजगार हैं, उन्हें भी उसमें आने का मौका दें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का अवसर दिया।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा के बगैर व्यक्ति के जीवन में अंधेरा होता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था- 'शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पीयेगा वह उतना दहाड़ेगा।' शिक्षक एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व का धनी होता है कि उसकी गोद में प्रलय और निर्माण पलते हैं। शिक्षक राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। शिक्षक वह व्यक्ति होता है कि बच्चा जो मिट्टी के पुतले के समान होता है और जब वह विद्यालय में जाता है तो शिक्षक अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा व दीक्षा से उसको जैसे सांचे में ढालना चाहे वह ढाल सकता है। शिक्षक अपने जीवनकाल में चाहे वह आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे अन्य पदों पर हो, शिक्षक अपने जीवनकाल में अनेक शिष्यों को विभिन्न पदों पर सृजित करता है और वह खुश ही होता है कि उसका शिष्य आज बड़े-बड़े पदों पर बैठा है।

माननीय सभापति महोदय, आज मुझे बहुत ही अचम्भा हुआ जब हमारे अजमेर दक्षिण से आने वाली विधायिका इस सदन में हमारे महापुरुषों के

(श्री अमित चाचाण)

बारे में बोल रही थीं। वे शायद भूल गयीं कि आजाद देश में हम जो आजादी की सांसें ले रहे हैं, इस सदन में जो हम बोल रहे हैं, इस लोकतंत्र में जो हम रह रहे हैं, यह देन अगर किसी की है तो कांग्रेस पार्टी के महापुरुषों की देन है। इन्हें क्या पता कि आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गयी थी? इन्हें क्या पता कि यह देश कैसे आजाद हुआ था क्योंकि इनके लोगों ने तो अंगुली तक नहीं कटायी थी? वहीं कांग्रेस के महापुरुषों ने अपने त्याग और बलिदान की वजह से इस देश को आजाद कराया था। आज ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 70 साल के इतिहास में जब देश आजाद हुआ था तो उस समय क्या स्थितियां थीं। यह डैम का निर्माण किसने कराया? यह आईआईएम, आईआईटी का निर्माण किसने कराया? आज प्रत्येक गांव, ढाणी तक सड़कों का निर्माण या प्रत्येक गांव, ढाणी तक बिजली पहुंचाने का काम किसने कराया? यह तब सम्भव हुआ जब कांग्रेस के महापुरुषों ने जो पूर्व में हमारे प्रधान मंत्री रहे और उन्होंने देश के बारे में सोचा। आज तो नई-नई तकनीकें आ चुकी हैं, लेकिन उस दौर की भी हम बात करें जब इन्दिरा जी के समय हरित क्रान्ति लायी गयी थी या उस समय की बात करें जब पाकिस्तान के दो टुकड़े कर इन्दिरा जी के समय में विश्व का नक्शा बदल दिया गया था, उस हमारे समय की बात करनी चाहिए।

आज ये कहते हैं कि मोदी जी ने सात साल में सब कुछ किया। यह मोदी जी ने नहीं, यह भारत देश है जिसका मान और सम्मान सदियों से पूरे विश्व में होता रहा है। आज भाजपा के लोग यह कहते हैं कि विदेश में जब जाते हैं तो मोदी जी का मान और सम्मान होता है। यह बड़े शर्म की बात है कि वहां मोदी जी का नहीं बल्कि हमारे सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत देश का सम्मान होता है। इससे भी पूर्व जब-जब भी प्रधान मंत्री विदेशों में गये, इससे बढ़कर उनका मान और सम्मान किया गया था।

पिछले दिनों हम सबने देखा कि किस तरह से मोदी जी ने विदेश नीति की अवहेलना की और देश के अन्दर जहां पूरी दुनिया कोरोनाकाल से लड़ रही थी, मोदी जी नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे और उसमें बाद में उसका क्या हश्र हुआ, क्या हाल हुआ, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। आज हमें बड़ी शर्म आती है कि इस सदन में इस तरह की बातें हमारे महापुरुषों के बारे में कही गयीं लेकिन वे यह भूल गये कि गांधी परिवार वह परिवार है जिसके दो-दो सदस्यों ने देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए त्याग किया और

(श्री अमित चाचाण)

उनकी हत्या कर दी गयी थी, ऐसा गांधी परिवार है। अगर सोनिया जी चाहतीं तो वे भी प्रधान मंत्री बन सकती थीं लेकिन उन्होंने प्रधान मंत्री पद को ठुकरा कर देश के अर्थशास्त्री हमारे मनमोहन सिंह जी को उस कुर्सी पर बिठाया क्योंकि वे चाहती थीं कि इस देश का विकास हो, देश का भला हो और देश को आगे बढ़ाया जा सके।

कांग्रेस ने कभी जातिवाद की बात नहीं की, कभी धर्म की बात नहीं की। कांग्रेस ने 36 बिरादरी को साथ लेकर, सभी लोगों को आगे लाकर, चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, गरीब व्यक्ति है उसको आगे लाने का काम किया और कभी उन्होंने देश को बांटने का काम नहीं किया क्योंकि हमारे भारत देश में अलग-अलग भाषाएं हैं, अलग-अलग बोलियां हैं, अलग-अलग वेशभूषाएं हैं। हमारे नेताओं ने सदैव यही प्रयास किया कि हम पूरे देश को एक धागे में पिरोकर रखें और पूरे देश का समुचित विकास करें, सभी धर्मों को, सभी वर्गों का आगे लेकर आयें, यह हमारे नेताओं की सोच रही थी। आज की कथनी और करनी का फर्क हमारे सामने है। सात वर्षों से किस तरह से देश को लड़ाया जा रहा है, किस तरह से भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, किस तरह से जातिवाद का जहर हमारे अन्दर घोला जा रहा है यह हम सब देख रहे हैं।

आज चुनाव में विकास की बात नहीं होती, चुनाव में क्षेत्र को आगे ले जाने की बात नहीं होती और बात होती है तो सिर्फ जाति और धर्म की बात होती है। आज हमारे राजस्थान के 25 सांसद वहां गये हैं, आज विपक्ष के नेता यह पूछते हैं कि कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने तीन वर्षों में क्या किया लेकिन इन्होंने यह हिम्मत नहीं दिखायी कि लोक सभा के अन्दर जो 25 सांसद बैठे हैं, वे 25 सांसद राजस्थान की जनता के लिए क्या लेकर आये। अगर इनको इतनी पीड़ा और इतना दर्द राजस्थान के विकास के लिए है तो इनको 25 सांसदों की मीटिंग लेकर उनको भी यह कहना चाहिए कि आप भी लोक सभा में बोलें और राजस्थान के विकास के लिए नई-नई योजनाएं लेकर आएं, नये-नये कार्य लेकर आएं और अपने क्षेत्र का विकास करें।

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा पर आता हूं। पिछले तीन वर्षों में कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में, विकट स्थितियों में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने बहुत नवाचार किये। उनका साथ देने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री गोविन्द जी डोटासरा ने और

(श्री अमित चाचाण)

अब उस कार्य को अंजाम देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री बी. डी. कल्ला जी प्रयासरत हैं। इन तीन वर्षों में क्या नहीं हुआ? जो पूर्व की भाजपा सरकार ने जो हमारे युवा, उज्जवल भविष्य विद्यालयों में पढ़ते हैं उनके 20 हजार स्कूलों को बन्द करने का काम किया और हमारे तीन वर्ष के कार्यकाल में हमारी सरकार ने क्या किया कि 20 परसेंट नामांकन इन तीन वर्षों में बढ़े हैं। यानी राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास इन राजकीय विद्यालयों की तरफ बढ़ा है। वह क्यों बढ़ा? हमारे मुख्य मंत्री जी की सोच की वजह से, शिक्षा मंत्री के प्रयासों से जो मूलभूत सुविधाएं उन विद्यालयों में पूरी करने का काम किया है उससे बढ़ा है। जो नये-नये नवाचार लेकर आये हैं, जो हम राजकीय विद्यालयों में वार्षिक उत्सव, जो पहले प्राइवेट स्कूलों में हुआ करते थे, अब वे राजकीय विद्यालयों में होते हैं। उन वार्षिक उत्सवों से जो हमारी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उन्हें आगे आने का अवसर मिलता है।

इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा काम हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भामाशाह थे, वे उन राजकीय विद्यालयों से जुड़े और उस वार्षिक उत्सव के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में लाखों रुपये मिल रहे हैं जिससे उन मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जा रहा है।

इन तीन वर्षों में हमने प्रत्येक सेक्टर में अलग-अलग काम किये। सभापति महोदय, आज गरीब परिवार के बच्चे का सपना था कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में, महंगाई के इस दौर में वह प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा था, इंग्लिश मीडियम में नहीं जा पा रहा था। मुख्य मंत्री जी ने उनके दर्द को समझा और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का फैसला किया। पहले चरण में 1250 विद्यालय खोलने की घोषणा हुई और हमें गर्व होगा कि उन विद्यालयों में लाटरी के द्वारा एडमिशन किया जा रहा है, इतना जोश और उत्साह हमारे युवाओं में है कि वे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। इस बार मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार विद्यालय और खोलेंगे और इसके साथ ही 10 हजार अंग्रेजी माध्यम शिक्षक कैडर का भी सृजन किया, उसकी भी घोषणा की, यह मुख्य मंत्री जी की सोच है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने शनिवार को 'नो बैग डे' की घोषणा की। विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के लिए इस बार उन्होंने 3800 कमरों के लिए 200 करोड़ का प्रावधान रखा, जिसमें कक्षा कक्षों का निर्माण कराया

(श्री अमित चाचाण)

जायेगा, नवीन भवनों का भवन निर्माण कराया जायेगा क्योंकि वे चाहते हैं कि जिन राजकीय विद्यालयों में हमारे राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य पढ़ते हैं तो यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए पूर्ण मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायें, जिससे अच्छी और गुणवत्ता की शिक्षा उनको मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अभी 3820 विद्यालयों के क्रमोन्नत करने की घोषणा की। पहले प्रत्येक वर्ष में जो 200-300-400 विद्यालय क्रमोन्नत किये जा रहे थे पर उन्होंने पक्ष और विपक्ष को एक समान मानते हुए क्योंकि वे चाहते हैं कि हमारे समाज के, हमारे गरीब परिवार के बच्चे आगे आयें इसलिए पूरे राजस्थान के 3820 विद्यालयों को 12वीं तक क्रमोन्नत करने की घोषणा की।

इसके साथ ही चरणबद्ध रूप से वरीयता क्रम के हिसाब से बालिका विद्यालयों को भी अलग-अलग में क्रमोन्नत किया जायेगा। यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुए हैं तो हमारे उज्ज्वल भविष्य ही हुए हैं क्योंकि पिछले दो वर्ष से उनकी पढ़ाई का कार्य रुक चुका था, लेकिन मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा मिले तो उन्होंने पूरे जिले के लिए सावित्रीबाई फुले वाचनालय की भी घोषणा की, 50-50 लाख रुपये से, जिससे उस लाइब्रेरी में सभी तरह की किताबें उपलब्ध हों और वे किताबों से पढ़ सकें।

माननीय सभापति महोदय, यह एक जन-प्रतिनिधि का भी दायित्व होता है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में इन राजकीय विद्यालयों पर ज्यादा ध्यान दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने मेरे विधायक कोष से अधिकांश पैसा राजकीय विद्यालयों के लिए खर्च किया है। मेरा प्रयास है कि सब विद्यालयों में मैं शैड का निर्माण कराऊं। आज हमारे परिवार, समाज के बच्चे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बाहर खड़े रहकर उनको प्रार्थना भी करनी पड़ती है, वार्षिक उत्सव भी होते हैं, बाल सभाएं भी होती हैं तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में अगर शेड बनेंगे तो उस शैड के नीचे खड़े होकर बच्चे अच्छी तरह से प्रार्थना भी कर सकेंगे, बाल सभाएं, वार्षिक उत्सव भी किया जा सकेगा।

(श्री अमित चाचाण)

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत जी, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री भंवरसिंह जी भाटी और अब हमारे वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव जी जो कार्य कर रहे हैं, युवाओं के लिए वास्तव में सौगात लेकर आये हैं। पिछले तीन वर्षों में 123 राजकीय महाविद्यालय खोले गये और इस बजट में 53

(समय: 17.00 बजे)

महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गयी है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। पिछले बजट में मुझे भी कन्या महाविद्यालय की सौगात मिली। आज हमारे विपक्ष के साथी महाविद्यालय की डिमाण्ड भी करते हैं, वे सब यह भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में महाविद्यालय खुले, लेकिन दूसरी तरफ वे कहते हैं कि आपने महाविद्यालय तो खोल दिये, लेकिन इसका भवन नहीं है, यह छोटे भवन में चल रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आज हमने महाविद्यालय की घोषणा की और दो महीने के बाद ही वहां भवन निर्माण हो जायेगा। भवन निर्माण के लिए पहले हमें जमीन तलाशनी पड़ेगी, उसका आबंटन करना पड़ेगा, फिर हमें भामाशाहों से भी प्रयास करना चाहिए, जिससे कि बिल्डिंग का निर्माण हो सके और उसके लिए पहले विधायकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि जिस विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोला है, उसके अस्थायी संचालन के लिये अच्छे भवन की तलाश करें।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय की सौगात मिली और मैं इस मंच से धन्यवाद देता हूं, बियाणी परिवार को और नमन करता हूं स्व. गौरी शंकर जी बियाणी को, जिनकी वजह से 1984 में नोहर में कांग्रेस शासनकाल में राजकीय महाविद्यालय खुला था। उन्होंने उस समय अपनी बियाणी धर्मशाला नि:शुल्क अस्थायी संचालन के लिए दी थी और बाद में उनके परिवार के द्वारा ही नर्मदा देवी बियाणी कालेज की पूरी बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया। आज उसी परिवार द्वारा वही बियाणी धर्मशाला नि:शुल्क संचालन के लिये दी गयी है और हमें खुशी है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपये की लागत से कन्या महाविद्यालय का स्व. गौरी शंकर बियाणी जी के नाम से, उस भवन का कार्य भी शुरू हो चुका है, आने वाले एक साल में भवन का निर्माण शुरू हो जायेगा। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस भी विधायक के विधान सभा क्षेत्र में जो भी राज्य सरकार काम करे,

(श्री अमित चाचाण)

वह विधायक भी अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ उस कार्य का पीछा करते हुए, उस कार्य को पूर्ण करने का काम करे। यह सिर्फ राज्य सरकार की ही नहीं बल्कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को, जिन्होंने पुरानी पेंशन को लागू करने का काम किया। इसमें सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हो रहे थे तो हमारे शिक्षक साथी प्रभावित हो रहे थे, बड़ी संख्या में 2004 के बाद शिक्षकों की नियुक्ति हुई, लेकिन आज हमें खुशी है हर शिक्षक संघ कोई भी, चाहे वह किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखता हो, प्रत्येक शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि आज हमारे मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने हमारे युवा साथियों के उज्ज्वल भविष्य को, बुढ़ापे को सुनहरा करने का काम किया। उसके लिये भी मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके साथ ही मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये कहना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पल्लू, जिसको मुख्य मंत्री जी ने अभी तहसील के रूप में क्रमोन्नत किया, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पल्लू में 70 किलोमीटर की परिधि में कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। वहां चार-पांच निजी कालेज चल रहे हैं, हजारों युवा साथी अध्ययनरत हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे पल्लू क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की सौगात देते हैं तो उसकी बिल्डिंग निर्माण के लिए, मैं दानदाताओं को प्रेरित करके उसकी बिल्डिंग निर्माण कराने का भी कार्य करूंगा।

इसके साथ ही मेरे कुछ विद्यालयों में संकायों की आवश्यकता है, जिसकी मैंने सूची दे रखी है। कुछ हमारे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की सूची भी दी हुई है। मैं चाहता हूं कि प्रायोरिटी के साथ उन विद्यालयों को भी क्रमोन्नत किया जाय। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से कि आप जल्दी ही एक शिक्षा नीति बनाकर और इसमें पारदर्शिता लाते हुए आने वाले समय में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी ट्रांसफर करें, जो काफी वर्षों से यह चाह रहे हैं कि हमारे ट्रांसफर होने चाहिये, हम भी हमारे क्षेत्र में जाएं।

(श्री अमित चाचाण)

इसके साथ ही 2538 शिक्षकों का हमारे टीएसपी से नोन टीएसपी क्षेत्र में समायोजन करना चाहिए, क्योंकि वे भी चाहते हैं कि अगर हमारा वहां समायोजन होगा तो टीएसपी क्षेत्र में भी जो हमारे बेरोजगार हैं, उनके लिये नये पद सृजित होंगे, उन्हें भी इसमें रोजगार मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक बार पुन: मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री सुभाष पूनिया। माननीय श्री हरेन्द्र निनामा।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति जी, आपका और हमारा एक ही जिला है और झुन्झुनूं जिला बालिका शिक्षा में अव्वल रहा है। मैं आपसे इसी मामले में निवेदन करना चाहूंगा कि झुंझुनूं जिले में पिलानी में बिट्स जैसा संस्थान, विश्व और पूरे देश में रैंकिंग में अच्छे स्थान पर रहता है। वहां अध्ययनरत छात्र, जो भी वहां से निकले हैं, उन्होंने देश और परदेश में और विश्व में अलग पहचान बनायी है।

मैं आपके पड़ोस का ही हूं। मुझे आज बहुत ही लाचार होना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी सामने वाले भी कह रहे थे कि शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बुहाना उप-खण्ड जिसमें दो पंचायत समितियां आती हैं, दोनों पंचायत समितियों में मुख्य मंत्री जी की घोषणा थी कि 500 प्लस जहां छात्राएं होंगी, वहां हम बालिका महाविद्यालय देंगे। अभी तक कोई लेना-देना नहीं है, बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है। सभापति महोदय, मैं बजट के माध्यम से मांग कर चुका हूं, इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे एक कालेज देकर उन लड़कियों के लिए बोर्डर का विधान सभा क्षेत्र है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां की लड़कियां महेन्द्रगढ़ और नारनौल तक भी पढ़ने जाती हैं। राजस्थान शिक्षा में अव्वल है तो क्यों हरियाणा प्रदेश में हमारी लड़कियां जाएं? यह शोभा नहीं देता है। हां, कल्ला जी दें, यादव साहब दें, जो भी दें।

मैं आग्रह करना चाहूंगा अभी मुख्य मंत्री जी ने बजट में काफी कालेजेज की घोषणा की थी तो मैं चाहूंगा कि मुझे एक कालेज दें, 36 कालेजों

(श्री सुभाष पूनिया)

की अभी बजट में घोषणा की गयी है। अभी नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कालेज खोल दिये और भवन की व्यवस्था नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि कहीं सरकारी जमीन नहीं होती तो कहीं कोई दानदाता नहीं होता, हम भी उसके लिए करेंगे, लेकिन सरकार भी प्रयास करे, क्योंकि संख्या ठीक-ठाक हो चुकी है।

मेरे यहां सूरजगढ़ में कालेज दिया था, उसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं। आज से दो साल पहले दिया था, उसके लिए मैं धन्यवाद भी ज्ञापित कर चुका हूं, लेकिन लड़कियों के लिए वास्तव में बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि मेरे विधान सभा में तीन पंचायत समितियां हैं, यह आपको अच्छी तरह से मालूम है।

अब मैं हायर एजुकेशन से सैकण्डरी एजुकेशन के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। परिसीमन के बाद अपने झुंझुनूं जिले में 337 ग्राम पंचायतें हो चुकी हैं। उसमें से 292 ही सीनियर सैकण्डरी हैं, कुछ ग्राम पंचायतें तो ऐसी हैं, 13 ग्राम पंचायतों में तो पंचायत के अधीन किसी भी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है। कुछ पंचायतें ऐसी हैं, जैसे 32 पंचायतें जिले में ऐसी पड़ती हैं, उनके लिए अपनी घोषणा थी कि हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकण्डरी होगी उनको भी जल्दी करने का प्रयास करें। यह आपसे आग्रह रहेगा।

सभापति जी, अब मैं आपका ध्यान पैराटीचर्स के ऊपर, जो आपके जमाने में लगे थे, उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है, उनको नियमित किया जाय। सरकार की फ्लैगशिप योजना महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का जरूर अभाव है, नामांकन की स्थिति भी बहुत अच्छी है, इसलिए कक्षा कक्षों का निर्माण और अन्य सुविधाएं दी जाएं।

साथ ही साथ, यह बहुत अच्छी बात है। हम इस चीज के विरोधी नहीं हैं कि आपने अंग्रेजी स्कूल क्यों खोली, बहुत अच्छा प्रयास है और अच्छे रिजल्ट आयेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ हिन्दी मीडियम की जो स्कूल चल रही थीं, वे स्कूलें बन्द हो चुकी हैं। उसका बच्चों को जरूर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इंग्लिश मीडियम की जो स्कूलें खोली हैं उनकी व्यवस्था अलग से की जाए। यह भी आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा।

(श्री सुभाष पूनिया)

राज्य कर्मचारियों के लिये पुरानी पेन्शन योजना लागू करना वास्तव में मैं मानता हूं कि यह साहसिक कदम है। इसका अभी तक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें भी तो लाभ दिया जाये न, यह भी मेरा आपसे आग्रह है। शिक्षकों को रिसर्च में रूचि बढ़ाने के लिये एमएड, पीएचडी डिग्री के लिए पूर्व की भांति अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाये, यह भी आपसे आग्रह करूंगा। मेरी कुछ पंचायतें जो परिसीमन के बाद नवगठित पंचायतें हैं, उनमें जैसे गरढ़ानाकलां, लालामाण्डी, यह लालामाण्डी तो एक ऐसी नयी पंचायत बनी है जो पंचायत मुख्यालय बना है, उसमें कोई सरकारी विद्यालय ही नहीं है। एक भी सरकारी विद्यालय संचालित नहीं है अपनी सीनियर सैकण्डरी भी कहां से करेंगे? दूसरा गरढ़ानाकलां, आप अच्छी तरह परिचित हैं, कई बार आप जा चुके हैं, वहां भी सीनियर सैकण्डरी नहीं है। बनवास में जो नई पंचायत अभी बनी है आपके पड़ोस की ही है, बाकड़ों पंचायत से निकली है, उसमें भी उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसको भी अतिशीघ्र सीनियर सैकण्डरी में किया जाये। पिलोद पंचायत जो लुहारू के पास पड़ती है वहां भी आज तक सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, सीनियर सैकण्डरी वहां भी नहीं है। इसलिये मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो प्राथमिक विद्यालय चाहे सरकारें किसी की भी रही हों, शून्य नामांकन के ऊपर जो विद्यालय बंद हो गये थे आज निश्चित रूप से छात्रों का, अभिभावकों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ है इसलिये मैं चाहूंगा कि उन बंद विद्यालयों को भी खोलने का प्रयास करें क्योंकि छात्र संख्या वास्तव में आपको पर्याप्त रूप से छात्र मिल जायेंगे। यह भी आपसे निवेदन रहेगा।

अब मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक पद की जो एक नामांकन की सीमा 105 है उसको कम से कम 60 की जाये न्यूनतम ताकि बच्चों का शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास हो सके और खेल गतिविधियों में भाग ले सके और जो सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में भी शारीरिक शिक्षकों की कमी है उनको बहुत जल्दी पूरा करें और जो आधारभूत सुविधायें, मेरे पूर्व में भी अपने विद्वान सदस्यगण मांग कर रहे थे कि अपन ने विद्यालय तो खूब खोल दिये, सीनियर सैकण्डरी में भी क्रमोन्नत कर दिये, यूपीएस थी उनको सैकण्डरी में क्रमोन्नत कर दिये, उनमें भी आज तक कहीं शौचालय की व्यवस्था या कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है और कई जगह तो नामांकन की वृद्धि हुई है, इसमें मैं नहीं कहता कि अकेले सरकार ने किया है, जो विद्वान अध्यापक हैं उन्होंने

(श्री सुभाष पूनिया)

भी प्रयास किया है। कई विद्यालय तो ऐसे थे कि टीचर्स ने आपस में मिलकर वहां प्राइवेट व्हीकल भी लगा रखे हैं बच्चों के लिये तो वास्तव में शिक्षक भी अच्छा काम कर रहे हैं। सरकारी शिक्षक, तो नामांकन इसलिये बढ़ा है, तो कक्षा कक्षों की कमी आ रही है और लैब की सुविधाएं भी नहीं हैं, इनको भी अगर आप जल्दी कर देंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा में एक क्रांतिकारी कदम की ओर अपन बढ़ेंगे।

सभापति महोदय, पंचायती राज में पहले 1987-88 में आपको याद होगा 6-6 महीने के लिये टीचर्स को नियुक्ति दी गयी थी और जब जिला परिषद् द्वारा चयनित किया गया इनको तो दो वर्ष के बाद लाभ दिया गया, उनको उसी समय से लाभ दिया जाये, यह भी आपसे आग्रह रहेगा। अब मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करके एक बात और कहूंगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों के शिक्षकों के पृथक कैडर की घोषणा स्वागत योग्य है, इसकी नयी भर्ती बहुत जल्दी की जाये।

अंत में, मैं आपसे एक ही मांग करता हूं कि राजनीति से दूर करके और शिक्षा में राजनीति नहीं लाकर जो भी चाहे विपक्षी हों, पक्ष के हों जो भी वंचित विधान सभा क्षेत्र रहे हैं उनको अतिशीघ्र हायर एजुकेशन की चाहे कोई डिमाण्ड हो, चाहे सीनियर सैकण्डरी की तो आपने घोषणा कर ही दी लेकिन उनमें भी अतिशीघ्र अगर कालेज की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से उस विधान सभा क्षेत्र का विकास होगा। आप हायर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि उच्च शिक्षा का क्या महत्व है। मेरे को आपने मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती गायत्री त्रिवेदी।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले मैं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की हमीरगढ़ पंचायत को नगरपालिका बनायी और रायपुर एवं गंगापुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने सहित अनेक विकास कार्यों की बजट में घोषणाएं कीं। कोरोना के कारण राज्य की कमजोर राजस्व आमदनी के बावजूद बजट 2022-23 में सम्माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा के लिये जो घोषणाएं और जो फैसले किये हैं वे

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

सराहना के योग्य हैं। दिवंगत विधायक स्वर्गीय कैलाश चंद्र त्रिवेदी के नाम पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापुर खोली थी, उक्त महाविद्यालय प्रारम्भ हो गया है लेकिन अभी तक भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापुर के भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत करावें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा मानना है कि सातवें पे-कमीशन के बाद हमारा जो उच्च शिक्षा का स्टाफ है उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई है। चाहे किसी की भी सरकार हो, इन सब संस्थाओं को चलाने में एक बहुत बड़ी बाधा हम लोगों के सामने आती है।

महोदय, उच्च शिक्षा में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा विद्या सम्बल योजना के तहत महाविद्यालयों में सहायक आचार्य अतिथि शिक्षक की भर्ती हुई है, जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के सभी महाविद्यालयों को जीवनदान मिला है और युवाओं में उनकी नियमित कक्षाओं के संचालन से भारी उत्साह है। ऐसा सम्पूर्ण प्रदेश में भी है। अभी इन अतिथि शिक्षकों को वेतन कालांश के आधार पर दिया जाता है। यदि इनका वेतन मासिक आधार पर किया जाये तो इन अतिथि शिक्षकों को महाविद्यालय में कार्य करने में सम्बल मिलेगा।

इसी प्रकार मेरे जिले में एकमात्र सरकारी इंजीनियरिंग कालेज भीलवाड़ा में है जिसमें लगभग सौ कार्मिक नोन प्लान मद में कार्यरत हैं, जिनमें से कुछ सेवानिवृत्त हो गये हैं लेकिन वहां पर पेन्शन स्कीम लागू नहीं हुई है। यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय ने अभी बजट में पुरानी पेन्शन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। अत: मेरा अनुरोध है कि इंजीनियरिंग कालेज के लिये पुरानी पेन्शन स्कीम लागू कर कर्मचारियों के भविष्य को चिन्तामुक्त बनायें। यह कालेज राजस्थान के सरकारी कालेजों में सर्वोत्तम स्थान पर है तथा विश्वास दिलाती हूं कि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो जाने पर यह भारत का जाना माना कालेज बन जायेगा, जिस पर पूरे राजस्थान को गर्व होगा।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की रायपुर ब्लाक की राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तोलास, आशाहोली, बाडियाखुर्द, नान्दशाजागीर, सहाड़ा ब्लाक की कालीमंगरी, (डेलाना) सुवाणा ब्लाक की कुम्हारिया खेड़ा, (देवली) के विद्यालयों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करावें। इसी प्रकार रायपुर ब्लाक के राजकीय उच्च

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

प्राथमिक विद्यालय, भटेवर (भीरव), डांगड़ी (जोड़ोल), टूंगच (खाखरमाला), गल्यावड़ी (खेमाना), सरेवड़ी (भीटा) सहाड़ा ब्लाक के आलोली (अरनिया), बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, महेन्द्रगढ़ जबरकिया (सोनियाणा) सुवाणा ब्लाक की जवासिया (दूडिया) जागदरी (सेथूरिया), भैसाकुण्डल (देवली), कान्या खेड़ी (बिलियाकलां), शिवपुरा (दूडिया) को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करावें। इसी प्रकार सुवाणा ब्लाक की ग्राम पंचायत की बिलिया कलां के परिसीमन पश्चात् नयी ग्राम पंचायत बनी है। उक्त पंचायत मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलियाकलां को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और रायपुर ब्लाक की बोरयापुरा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करावें।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में सभी विद्यालयों के नाम पर जमीन आबंटित है लेकिन अधिकतर विद्यालयों की जमीन एवं खेल मैदान पर किसी न किसी का अतिक्रमण है। माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि चाहे खेल मैदान हो या विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण है, एक अभियान चलाकर उनका शीघ्र अतिक्रमण हटाया जाय। सरकार किसी भी योजना से, चाहे नरेगा से अथवा अन्य किसी योजना से, सभी विद्यालयों की जमीन की चारदीवारी एवं खेल मैदान की चारदीवारी का निर्माण कराये ताकि विद्यालय की जमीन सुरक्षित हो सके।

कोरोना के पश्चात् सभी सरकारी विद्यालयों में नामांकन काफी अच्छी मात्रा में बढ़ा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के विद्यालयों में शिक्षकों के पद काफी संख्या में रिक्त चल रहे हैं, इस कारण बच्चों की पढ़ाई में काफी परेशानी हो रही है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि जल्दी से जल्दी शिक्षकों के चल रहे रिक्त पदों को भरें ताकि सरकारी विद्यालयों का नामांकन बढ़ने के साथ-साथ शिक्षा का स्तर भी बढ़ सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैं आपसे दुबारा निवेदन करूंगी कि मेरी मांगों को सरकार पूरा करे। एक और निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रायपुर में बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें जल्दी से जल्दी आईटीआई को चालू कराया जाय ताकि सबको लाभ मिल सके। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस पर दो पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगी।

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

"राजस्थान का नाम और पहचान आपसे है
राजस्थान की आन और शान आपसे है।
आपके विकास कार्यों ने क्षेत्र की दशा बदल दी
राजस्थान की जनता के चेहरों पर मुस्कान आपसे है।"

जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: माननीय श्री हरेन्द्र निनामा।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरे वरिष्ठ साथियों ने अभी मांग संख्या 24 पर कई प्रकार के प्रश्नोत्तर किये हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है हमारे देश में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है और इस भाषा में जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्, यह पहली भाषा है जिसको जय भारत के नाम से भी बोली जाती है और भाषा के नाम से भी बोली जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गनोड़ा तहसील हैडक्वार्टर पर जब देश आजाद नहीं हुआ था, 1944-45 में एक संस्कृत विद्यालय शंकर लाल जी व्यास के द्वारा स्थापित किया गया। वह आज उस क्षेत्र में एक वट वृक्ष की तरह है। वह एक मात्र कालेज संस्कृत का चल रहा है। उस कालेज में लंबे समय से व्याख्याताओं के पद खाली पड़े हुए हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं उस संस्कृत कालेज में व्याख्याताओं की जल्दी से जल्दी भर्ती हो ताकि संस्कृत के विद्यार्थियों को बाहर न जाना पड़े।

जब मैं पढ़ता था और इससे पहले भी विश्वविद्यालय में इतिहास में एक ही नाम आता था नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इनके अलावा तीसरा नाम हमें इतिहास में पढ़ने को नहीं मिलता था। आज मैं पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उदयपुर में 2 कमरों में संचालित जनजाति विश्वविद्यालय को ट्रांसफर करके बांसवाड़ा जिले में गुरु गोविन्द के नाम से विश्वविद्यालय भी चल रहा है और इसके साथ जमीन का आबंटन किया और जमीन आबंटन के साथ ही बजट का आबंटन कर दिया। आप कोई भी माही डैम भ्रमण करने जाएं तो देखें माही डैम की सड़क के किनारे बहुत सुन्दर बिल्डिंग गुरु गोविन्द विश्वविद्यालय के नाम से, जनजाति विश्वविद्यालय के नाम से बन रही है।

सभापति महोदय, राजकीय महाविद्यालय उप खण्ड स्तर पर नहीं

(श्री हरेन्द्र निनामा)

होने के कारण घाटोल क्षेत्र के टीएसपी एरिये के लड़कों को प्राइवेट कालेज में पढ़ने जाने के लिये काफी दिक्कत आती है, फीस नहीं भर पाते हैं, आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में मैं सरकार से मांग करता हूं कि उप खण्ड स्तर की जो नीति आपने बनाई है, उसके तहत राजकीय महाविद्यालय घाटोल मुख्यालय पर खोलने का काम अगर आप करेंगे तो जनता आपको याद करेगी। गत दो वर्ष पूर्व के बजट में मेरी मांग के अनुसार आपने मेरे पीपलखूंट क्षेत्र में एक महाविद्यालय दिया, जो आज चल तो रहा है लेकिन वहां पर जमीन का आबंटन नहीं हुआ है, बजट का आबंटन नहीं हुआ है, भवन का निर्माण नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी पीपलखूंट की कालेज का बजट का प्रावधान किया जाय और भवन बनाया जाय।

सभापति महोदय, मैं देश के प्रधान मंत्री मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजादी के इतने लम्बे समय बाद में आपने शिक्षा की नीति को परिवर्तित कर नई शिक्षा नीति लागू की, जिसकी बड़ी प्रशंसा विदेशों में भी की गई कि वास्तव में शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता की पूर्ति माननीय मोदी साहब ने करके बता दी।

हमारे सत्ता पक्ष के साथी बार-बार यह कह रहे हैं कि 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दिल्ली में जाकर बैठे हैं, वह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं दो सांसदों का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे लोकल डूंगरपुर-बांसवाड़ा के सांसद श्रीमान कनकमल जी कटारा ने पिछले सप्ताह प्रधान मंत्री जी से सीधा सम्पर्क करके, आज तक बांसवाड़ा को रेल नहीं मिली थी तो रतलाम-डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा के लिये रेल परियोजना को चालू कराने की बात रखी। यही नहीं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पेयजल के लिये, गैस का प्लांट लगाने के लिये, घर-घर गैस लाने के लिये दिल्ली के हाउस में कनकमल जी ने बार-बार इस मामले को उठाया। मैं चित्तौड़ के माननीय सांसद सी.पी. जोशी जी के बारे में भी कहना चाहता हूं। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है चित्तौड़ में जो पुरानी रेल लाइनें थीं, वह जर्जर अवस्था में थीं, एक्सीडेंट हुआ करते थे, उनको बदलने का प्रयास करके बजट लेकर आज नई रेल लाइन का काम चित्तौड़ में भी हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ भी नहीं हुआ। मैं ज्यादा नहीं कहता, मेरे राज में आप आइए,

(श्री हरेन्द्र निनामा)

भैरोंसिंह जी शेखावत आये थे, पंचायतों में बैठने की जगह नहीं थी, किसी वृक्ष के नीचे पंचायतें भरी जाती थीं। जहां गधे नहीं जाते थे, ऐसी-ऐसी जगह पर पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिये 'काम के बदले अनाज' योजना लागू करके नई ग्राम पंचायत बनाने का काम किया। स्कूल के लिये कभी पक्की बिल्डिंग गांवों में नहीं मिलती थी, स्कूलों को पक्का बनाने का काम किया। मिडिल स्कूल हो या दसवीं का विद्यालय हो, शेखावत जी ने 'काम के बदले अनाज' योजना के माध्यम से बाउंड्री बनाने का काम भी किया। मेरे साथी कह रहे थे कि कुछ नहीं करते हैं। आपका 55 साल का विकास देखो, आपने राजस्थान में 55 साल तक राज किया। भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र साढ़े बारह साल का हिसाब है। साढ़े बारह साल का हिसाब और पचपन साल के हिसाब को देखो। बड़ी-बड़ी परियोजना, बड़े-बड़े काम जिसने किये, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। पिछले समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक आवास में हर पंचायत हैडक्वार्टर्स पर मिडिल स्कूल से दसवीं तक का स्कूल खोलने का काम किया। एक साथ सात हजार स्कूलों को सीनियर स्कूलों में बदलने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वह सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। उसका नेतृत्व माननीय वसुन्धरा जी ने किया था।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हमारे टीएसपी एरिये में जो आरक्षण है, जो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, स्केल नम्बर 1 से 9 तक, उनके लिए अलग से किया जाये। उदयपुर डिवीजन के लिए जनसंख्या के अनुपात में आप आरक्षण देने की मांग करें।

मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जब शिक्षा मंत्री थे, उस समय आपने चिन्ता की कि इस आदिवासी इलाके में लड़कों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती हैं, तो उन्होंने पहली बार नि:शुल्क पाठ्यक्रम लागू करने की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो उनका नाम गुलाब चन्द जी कटारिया है।

यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि आज यूक्रेन में जिस तरह की लड़ाइयां हो रही हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा के तलवाड़ा में हवाई पट्टी बनी हुई है वहां पर महीने में दो बार हवाई जहाज उतारने का प्रस्ताव आप भारत सरकार को भेजें। हम भी हमारे सांसद महोदय को कहेंगे, मंत्रियों को कहेंगे, क्योंकि खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर सम्भाग के लोग काम करते हैं। युद्ध

(श्री हरेन्द्र निनामा)

और महामारी में हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लड़के बाहर फंसे हुए थे। उनको आने में कितनी तकलीफ हुई, कितना समय लगा? अगर हमारे यहां पर हवाई पट्टी चालू होती तो हमारे लड़कों के सामने ये मुसीबत नहीं आती।

मेरे यहां पर वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय चलता है, उसको महाविद्यालय में तब्दील करने की मांग भी मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं।

हमारी सरकार जब भी आयी, रसोई की व्यवस्था की, दूध पिलाने की व्यवस्था की, साइकिल देने की व्यवस्था की, स्कूटी देने की व्यवस्था की और इसके साथ ही छात्रवृत्ति की व्यवस्था की, गार्गी पुरस्कार देने की व्यवस्था की। जब-जब भी पढ़ाई का अभियान चलाया, उस समय जो-जो कलेक्टर थे, उन कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिये कि आप गाड़ियों में नहीं बैठें, दिन में दो घंटे गांव में जाकर, पैदल चलकर शिक्षा के जागरण का अभियान चलायें। श्री भरत मीणा हमारे बांसवाड़ा में कलेक्टर थे, उन्होंने पैदल यात्रायें कीं। हमारे यहां डॉ.बी. शेखर थे, उन्होंने साक्षरता अभियान में पैदल चलकर काम किया। आज किसी परिवार से एक भी बच्चा घर पर नहीं है, यह पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में स्टाफ की कमी तो है ही, लेकिन वहां पर चपरासी आज तक नहीं लगाये गये हैं, एक पियोन नहीं है तो स्कूल का रख-रखाव कैसे होगा, यह चिन्ता का विषय है।

अभी नवीन पंचायतों का पुनर्गठन हुआ। पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो-जो पंचायतें नयी बनी हैं, पीपलखूंट में सात पंचायतें बनी हैं, घाटोल में तीन बनी हैं, इनमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय का अभाव है, वहां पर भी सरकार काम करे। जब हमारी सरकार थी उस समय एक आदर्श स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल खोला और खोला ही नहीं, उसके बजट का प्रावधान भी किया। छह करोड़ रुपये का एक सुन्दर भवन बनकर उपखण्ड स्तर पर आज तैयार है।

मेरा एक और निवेदन है कि जब बांसवाड़ा जिले की स्थापना हुई थी, उस समय राजा बासिया चरपोटा, जो कि आदिवासी था, उसने बांसवाड़ा जिले की स्थापना की। आजकल कई महाविद्यालयों का नामकरण राजनेताओं के नाम पर किया जा रहा है और किये भी हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से

(श्री हरेन्द्र निनामा)

निवेदन है कि उस राजा बासिया के नाम पर बांसवाड़ा में महाविद्यालय हो। अभी बांसवाड़ा में एक गुरु गोविन्द महाविद्यालय चल रहा है और विश्वविद्यालय का नाम भी गुरु गोविन्द है। बाहर से आते हैं तो लोगों के मन में टकराव पैदा होता है कि कौनसा महाविद्यालय है और कौनसी यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का नाम तो गुरु गोविन्द सिंह रखा जाये, लेकिन महाविद्यालय का नामकरण राजा बासिया भील चरपोटा के नाम से किया जाये तो बांसवाड़ा के आदिवासी हमेशा सरकार को याद करते रहेंगे।

बेणेश्वर धाम पर पेनोरमा स्थापित किया गया है। संत मावजी महाराज जो हुए हैं, उनका इतिहास इस संग्रहालय में रखा गया है और करोड़ों की लागत से वह संग्रहालय बना है। एक सुन्दर स्थान बनाने का काम किया है। उसके लिए जो बजट दिया था, उससे आज भी काम चल रहा है और आज भी पैसा खतम नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आदिवासी इलाकों में सरकारी देने के लिए। सन 1995-96 में जिला परिषद् की विज्ञप्तियां जारी हुईं। उस समय मैं भी जिला परिषद् सदस्य था। उसमें हमारे बांसवाड़ा जिले के लड़के मैरिट में नहीं आते थे। अध्यापक की नौकरी से वंचित रहते थे। उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने अलग से 15 प्रतिशत बोनस अंक जोड़कर हजारों बच्चों को नौकरी देने का काम बांसवाड़ा जिले में किया, जो कि एक ऐतिहासिक काम है। हर राजस्व गांव को शिक्षा से जोड़ने का काम किया। आज जो हाईवे बने हुए हैं, गांवों में सड़कें बनी हुई हैं। अगर सड़कें नहीं होतीं तो पढ़ाई का जो परसेंटेज आप बता रहे हैं, वह ऊपर नहीं जाता। इसके लिए मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करता हूं। उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने पीएमजीवाई की स्कीम लागू की और हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, जिसकी वजह से हमारा उदयपुर ट्राइबल डिवीजन हो या पूरा राजस्थान, पूरे हिन्दुस्तान की गांव-ढाणी सड़कों से जुड़े और आज एक मिसाल कायम करने का काम किया। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अन्त में, मेरी एक बात रह गयी है कि पैराटीचर्स हो या आरएसईबी में कार्मिक काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में कार्मिक काम कर रहे हैं, जो कि संविदा पर हैं, अस्थायी हैं, उनको पूरी स्केल नहीं मिल रही है, उनका सरकार स्थायीकरण करके पूरा-पूरा लाभ दे। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के साथियों ने कई बातें कही हैं। इनका तो स्वभाव ही है, जोर से बोलना और असत्य बोलना, ताकि आगे वाले का सच लगे। आज जब आदिवासियों को, दलितों को, गरीबों को कुएं का पानी पीने नहीं दिया जाता था, मन्दिरों में दर्शन करने नहीं दिये जाते थे, स्कूलों में शिक्षा का अधिकार नहीं था, अगर आज यह अधिकार दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, गांधी परिवार ने दिया है, यह सब भूल रहे हैं, यह मैं कहना चाहता हूं।

मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे आज राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान में 36 कौम के नेता जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसा बजट पेश किया, जिससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनकी जो आरएसएस की शिक्षण संस्था चल रही थी, वह बन्द होने के कगार पर है, इसलिए इनको इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोलने से दर्द हो रहा है कि गरीब का बच्चा हमारी स्कूल में न जाकर जो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली हैं, वहां पर पढ़ने जायेंगे और हमारा प्रचार-प्रसार रुक जायेगा, यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ है। ये शिक्षा नहीं चाहते हैं। जब अशोक गहलोत जी ने गांव-गांव, ढाणी राजीव गांधी स्कूल खोली थी, हर जगह खोली थी कि आदिवासी का बच्चा, गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा पढ़े, शिक्षा ले और आगे बढ़े। इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजीव गांधी का नाम मिटाने का काम किया। उन स्कूलों का नाम मिटाया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय करने का काम किया। ये काम इन्होंने किया है। अभी हमारे घाटोल से जो माननीय सदस्य आते हैं, उन्होंने बताया कि वसुन्धरा जी ने यूनिवर्सिटी खोल दी। वह यूनिवर्सिटी तो कांग्रेस की देन है। राजीव गांधी जनजाति यूनिवर्सिटी था। नाम बदल दिया। नाम कोई बात नहीं, गुरु गोविन्द के नाम से है, वह भी हमारे गुरु हैं लेकिन तुम नाम बदलने का काम मत करो। खाली नाम बदलकर, असत्य बोलकर, जोर से बोलकर चाहते हो कि हम राज में वापस आ जाएंगे लेकिन जनता अब जान चुकी है कि आप के बहकावे में अब जनता आने वाली नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, टी.एस.पी. क्षेत्र से मैं आता हूं, जनजाति बहुल क्षेत्र से आता हूं। हमारे कई स्कूल आज भी क्रमोन्नत नहीं हैं। मैंने माननीय मंत्री जी को सूची दी है। पहाड़ी इलाका है, कई नाले पड़ते हैं, कई जंगल पड़ते हैं, आवागमन के साधन भी नहीं जाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों

(श्री गणेश घोघरा)

को 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हर पंचायत स्तर पर स्कूल क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। काफी तारीफे काबिल है। गांव-ढाणियां 5-5 किलोमीटर दूर बसी हुई हैं, बड़े-बड़े गांव बसे हुए हैं, वहां भी स्कूलों को जैसे पांचवीं का हो तो उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक हो तो उसे माध्यमिक और माध्यमिक हो तो उसे सीनियर सैकण्डरी किया जाए। यह मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं।

आज मैं क्षेत्र में जाता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कई स्कूलों में रिक्त पद है। वह मांग करते हैं कि ये रिक्त पद जल्दी से जल्दी भरे जाएं। कई स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। बारिश में पानी टपकता है। कई स्कूलों में टैंट लगाकर पढ़ाई हो रही है। कई स्कूलों में पानी की, शौचालय की समस्या है। ऐसी सरकारी स्कूलों में सुविधा के अभाव में बच्चे सही तरह से पढ़ नहीं सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी स्कूलें जर्जर अवस्था में हैं, उनकी मरम्मत कराई जाए। पानी की समस्या है तो हैंडपम्प या बोरिंग कराया जाए। शौचालय की सुविधा नहीं है। आजकल कई घटनाएं घट रही हैं। ऐसी स्थिति में हर स्कूल में अच्छा शौचालय हो और पेयजल की समस्या को दूर किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, पूरे जिले में एस बी पी गवर्नमेंट कालेज एक बड़ा महाविद्यालय है।

(समय: 17.43 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

उस महाविद्यालय में हर साल एडमिशन को लेकर बच्चे रोड पर उतरते हैं। ज्ञापन देते हैं, धरना देते हैं और कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं जबकि हमें उन कालेजों में माननीय मंत्री महोदय जी हैं, मैं मांग करना चाहता हूं कि हर विषय में, हर संकाय में सीटें बढ़ाई जाएं क्योंकि प्राइवेट कालेज वालों ने काफी लूट मचा रखी है। काफी मोटी रकम वसूल करते हैं। गरीब का बच्चा आगे अध्ययन नहीं कर सकता है। टी.एस.पी. में सरकारी नौकरियों में 45 प्रतिशत आरक्षण किया है और कालेज में एडमिशन के लिए वह 45 परसेंट के हिसाब से कालेज में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि कालेज शिक्षा में 45 परसेंट के हिसाब से एडमिशन लिया जाए तो हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं छोड़नी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, कई प्राइवेट कालेज बिना नोर्म्स के खुल गयी हैं, उन कालेजों की जांच भी होनी चाहिए। कई बच्चों की छात्रवृत्तियां समय पर

(श्री गणेश घोघरा)

नहीं मिल रही है। सरकार से पैसा उठा रहे हैं लेकिन गरीब बच्चों को आज भी कमरा किराया समय पर नहीं मिलता है। स्कोलरशिप समय पर एस सी/एस टी के छात्रों को नहीं मिल रही है। मैं मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि आप इसकी जांच करवाएं और इनको समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान हो।

मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों में बच्चे ताला खोलते हैं, बच्चे झाड़ू लगाते हैं, बच्चे पानी भरते हैं, वहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोई नहीं है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि स्कूलों में अंशकालीन एस.डी.एम.सी., एस.एम.सी. के माध्यम से अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की जाए तो स्कूल में साफ-सफाई हो सके। उन बच्चों को झाड़ू नहीं निकालना पड़े, उन बच्चों को पानी नहीं भरना पड़े। ये पूरे राजस्थान की समस्या है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए कोई कदम उठाएं।

माननीय सभापति महोदय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), डूंगरपुर के कई सारे रिक्त पद हैं। इसमें व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, व्याख्याता के समकक्ष स्वीकृत पद 16 हैं और कार्यरत 01 है। 15 पद रिक्त हैं। स्टेनोग्राफर का एक पद स्वीकृत है और वह एक पद रिक्त है। पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी एक पद स्वीकृत है, वह भी रिक्त है। वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, सहायक कर्मचारी, वरिष्ठ व्याख्याता, उप प्रधानाचार्य आदि के स्वीकृत पद हैं 36 और कार्यरत हैं 15, रिक्त कुल पद हैं 21 और गवर्नमेंट कालेज में भी कई पद रिक्त हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा की टीएस.पी. को देखते हुए, जनजाति बहुल क्षेत्र को देखते हुए उन सरकारी कालेजों में शिक्षकों के पद जल्दी से जल्दी भरे जावें।

मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नानका नाला, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सलियाट, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खेरवाड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मालीफला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पीथापुल और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, टाडीओबरी, इन सभी विद्यालयों को मैं क्रमोन्नत करने की मांग रखता हूं। साथ ही टीएस.पी. क्षेत्र में, जनजाति बहुल क्षेत्र में जो 2018 में 1167 को लेकर जो कांकरी डूंगरी उपद्रव हुआ था, वह अनारक्षित पद हैं। 45 एस.टी. के लिए हैं, 5 एस.सी. के लिए हैं और जो 50 था वह अनारक्षित पद हैं। उसमें जो 60 परसेंट लाया, उन अनारक्षित पद में सभी हो गये, जनरल, एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. सभी हो गये। अब जो 36 परसेंट

(श्री गणेश घोघरा)

एस.टी. को पात्र माना है। जो 1167 शेष पद बचे हुए हैं, वे शेष पद एस.टी. से भरे जाएं। ये मैं मांग करता हूं क्योंकि उनको 36 प्रतिशत पात्र माना है। मैं इसी के साथ कहना चाहूंगा कि टीएस.पी. क्षेत्र में हमारे जनता की, युवाओं की मांग है कि सभी भर्तियों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिये और प्रशासनिक सेवा में राज्य का 12 प्रतिशत में से अलग से टी.एस.पी. को 6 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। यह हमारे टी.एस.पी. युवाओं की और पूरे क्षेत्र की मांग है। मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामप्रसाद।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

शिक्षा के सम्बन्ध में आज बात हो रही है। मैं खासतौर से आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उन प्राइमरी स्कूल्स में अभी जो स्टाफ होता है, वह एक या दो का होता है। मुझे याद है 1965 में जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे, उस वक्त दो का स्टाफ था। आज जहां 1 से 5 तक की क्लासें होती हैं, उस दौरान दो अध्यापक उन पांच क्लासेज को कैसे बैठाते होंगे? कैसे पढ़ाते होंगे? ये बड़ा शोचनीय विषय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल में स्टाफ बढ़ाया जाये। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, थर्ड ग्रेड टीचर हैं, जो नोन टीएसपी के टीएसपी में है, जो टीएसपी में हैं उनको नोन टीएसपी में भेजा जाये। नोन टीएसपी में है, उनको टीएसपी में लाया जाये। उसके अन्दर अगर और भी खाली रहते हैं, तो बेरोजगारों की भर्ती की जाये।

सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्कूल, कालेजेज हैं, वहां लेक्चरर, प्रिंसिपल के खाली पद हैं, उनको भरा जाये। थर्ड ग्रेड वाले हैं, उन पर तो प्रतिबन्ध लगा रखा है। करीबन 14 साल हो गये, उनके ट्रान्सफर नहीं हो रहे। मैं कहना चाहता हूं कि टीएसपी में जो लेक्चरर, प्रिंसिपल लगे हैं, उनके ऊपर प्रतिबन्ध होना चाहिये, जब तक यहां व्यवस्था नहीं हो तब तक उनका ट्रान्सफर नहीं हो। वह ट्रान्सफर कराकर आते हैं और कुछ दिनों बाद वापस चले जाते हैं, इससे वहां पढ़ाई बाधित हो रही है। आपसे यह खासतौर से निवेदन है।

शिड्यूल्ड एरिया में अध्यापक हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां दे

(श्री रामप्रसाद)

रखी हैं। बीएलओ का, जनगणना के समय जनगणना की, इस तरह की जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों से उनको मुक्त किया जाये। उनको 10 बजे से 3 बजे तक ऐसा कोई फिक्स टाइम होना चाहिये, जहां उनके पास किसी तरह की सूचना नहीं मांगी जाये। आज हम देख रहे हैं कि अध्यापक स्कूल में मोबाइल नहीं रख सकते, लेकिन उनके पास लगातार मैसेज आते रहते हैं कि यह सूचना दो, यह सूचना दो। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस तरह की जिम्मेदारी, इस तरह का काम, कोई फिक्स टाइम किया जाये। कोई व्यवस्था जमाई जाये।

सभापति महोदय, डूंगरपुर में बालिका शिक्षा है, उसमें पुरुषों से महिलाओं का अनुपात ज्यादा है। डूंगरपुर ज़िले में, आज हम देख रहे हैं, जहां भी स्कूल में जायें, मैजोरिटी में वहां बच्चियां पढ़ती हैं। हम पूरे डूंगरपुर ज़िले में देखें, डूंगरपुर में कन्या महाविद्यालय है, उसके अलावा कहीं भी डूंगरपुर ज़िले में नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गलियाकोट ब्लाक जो डूंगरपुर से बहुत दूर पड़ता है, वहां पर कन्या महाविद्यालय खोला जाये। साथ ही डूंगरपुर महाविद्यालय है, उसको पीजी में क्रमोन्नत किया जाये।

सभापति महोदय, प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे मील दिया जाता है, उस जिम्मेदारी से भी उनको मुक्त किया जाये, क्योंकि मिड-डे मील करके, उनको भ्रष्टाचार में लिप्त किया गया है। उनको डराने-धमकाने या जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, बच्चों का समय भी खराब होता है। मिड-डे मील की कोई व्यवस्था की जाये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, स्वतन्त्रता सेनानी के नाम से स्कूलों का नामकरण किया जाये। खासतौर से आदिवासी इलाक़ों में, जितनी भी प्राइमरी स्कूल हैं वहां पर खेल की कोई व्यवस्था नहीं है, पीटीआई नहीं होता है। मिडिल स्कूल से होते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। आपसे निवेदन है कि प्राइमरी स्कूल तक भी यह व्यवस्था की जाये।

सभापति महोदय, हमारा सरकारी अध्यापक अपने बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल होती है, 6 हजार रुपये मासिक उसको पेमेंट मिलता है, उसके हवाले करते हैं। मुख्य मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेज़ी स्कूल शुरू करके बहुत अच्छा किया है। मॉडल स्कूल की व्यवस्था की है उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी अंग्रेज़ी स्कूल शुरू

(श्री रामप्रसाद)

किया है, वह ब्लाक स्तर या पंचायत समिति स्तर पर किया है। मैं चाहता हूं पंचायत स्तर पर ऐसी स्कूल चालू की जाये, कम से कम पंचायत स्तर पर, जो उसके सेंटर में हो, वहां सारी सुविधा इंग्लिश मीडियम से चालू की जाये। वहां स्टाफ पूरा हो, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आयेगा।

सभापति महोदय, खासतौर से हमारा ओबरी इलाका है, वहां आईटीआई खोला जाये, जिससे बच्चे टेक्निकल शिक्षा लेकर, अपनी शिक्षा आगे बढ़ा सकते हैं। सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र का महाविद्यालय 1996 में शुरू हुआ, आज तक उसको क्रमोन्नत नहीं किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सागवाड़ा भीखा भाई महाविद्यालय है, उसको क्रमोन्नत करके पीजी किया जाये। वहां व्याख्याताओं की कमी है, उसको भी दूर किया जाये।

बांसवाड़ा में गुरु गोविन्द विश्वविद्यालय है, वहां वैदिक शिक्षा केन्द्र खोला गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां वैदिक शिक्षा केन्द्र नहीं खोलकर, वहां वैज्ञानिक शिक्षा केन्द्र खोला जाये। वह 70-80 परसेंट ट्राइबल इलाका है। उनको वैदिक शिक्षा देकर उनकी क्या मंशा है, यह मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है। इसलिये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, बांसवाड़ा विश्वविद्यालय को वैदिक शिक्षा केन्द्र नहीं करके, वैज्ञानिक शिक्षा केन्द्र बनाया जाये। यही आपसे निवेदन है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): शिड्यूल्ड एरिया में जो हालात हैं, उसको सुधारने के लिये मंत्री महोदय, सरकार से निवेदन है कि वहां जो भी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करते हुए, स्कूलों का सुधार किया जाये, जिससे स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिल सके, आगे बढ़ सकें। यही बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। जय जवान, धन्यवाद सर।

श्री सभापति: श्री ललित ओस्तवाल।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मार्च, 2020 से पूरा विश्व जब कोरोना की चपेट में आने लगा तो सामान्य जीवन व्यवस्था पूर्ण रूप से असंतुलित हो गई। पूरी वैश्विक व्यवस्था को महामारी ने झकझोर कर रख दिया। इस महामारी के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था, विशेष कर स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कोविड के कारण अचानक

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

(समय: 18.00 बजे)

स्कूलों के बन्द हो जाने के कारण राजस्थान में स्कूली शिक्षा लेने वाले बच्चे, विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश के बच्चे ज्यादा प्रभावित हुए क्योंकि उनके पास सीखने के लिए जरूरी अवसर या पर्याप्त संसाधन नहीं थे। लाखों विद्यार्थियों के लिए स्कूलों का बन्द होना, उनकी शिक्षा में अस्थाई तौर पर व्यवधान भर ही नहीं था वरन अनेकों छात्रों के लिए इसका अन्त हो गया। कई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के अभिभावक आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे जो अपने बच्चों को घर पर स्मार्ट फोन, लैपटॉप, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवा सके, यह भी उनकी शिक्षा में बाधा का एक कारण सिद्ध हुआ। हालांकि, महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा पर अत्यधिक निर्भरता ने शिक्षा सम्बन्धी सहायता के मौजूदा असमान वितरण को और बढ़ावा दिया। किसी भी राज्य के पास ऑनलाइन शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए बुनियादी ढांचा या नीतियां नहीं थीं, जिसके चलते सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके।

शिक्षा सरकार की पुनर्निर्माण योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए जिससे हर बच्चे को सुलभ शिक्षा मिल सके। अब समय आ गया है कि एक मजबूत शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण कर शिक्षा के अधिकार को और अधिक सुदृढ़ किया जाये। इसका उद्देश्य सिर्फ महामारी से पूर्व की स्थिति बहाल करना नहीं वरन व्यवस्था की उन खामियों को दूर करना होना चाहिए जिनके कारण लम्बे समय से स्कूल के दरवाजे सभी बच्चों के लिए नहीं खुले हैं।

सरकार को यह चाहिए कि वह स्कूली शिक्षा के लिए ऐसी मजबूत नीति का निर्माण करे जिससे हम कोविड-19 महामारी की तरह भविष्य में आने वाले संकटों का भी डटकर सामना कर सकें और हमारे बच्चों को आने वाले सुनहरे भविष्य को संवारने में अपनी महती भूमिका निभा सकें।

आज की वर्तमान स्थिति में जब हम धीरे-धीरे इस महामारी से उबर रहे हैं, सभी विद्यालय भी खुल रहे हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षा प्रणाली व शिक्षकों को एक अलग नजरिये व सामान्य शिक्षण से परे होकर सोचने व शिक्षण करने की आवश्यकता है। इसका मुख्य कारण यदि हम ऐसे विद्यार्थियों पर ध्यान केन्द्रित कर विचार करें जो इस कोरोना महामारी के दौरान विद्यालयों से लगभग दो वर्ष तक दूर रहे तथा विभिन्न व्यक्तिगत या राजकीय असफलताओं के कारण ऑनलाइन शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सका, उन छात्रों को क्रमोन्नति प्रक्रिया से दो कक्षा उत्तीर्ण कर दिया गया।

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

जैसा कि हम सभी यह जानते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है तो इस नाते शिक्षा सुनिश्चित करना तथा उसमें समय-समय पर सुधार करना केन्द्र के साथ-साथ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी में भी शामिल होता है। जुलाई, 2017 से जून, 2018 के आंकड़ों के आधार पर सात या सात वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के मध्य राज्यवार साक्षरता दर के बारे में सर्वेक्षण के अनुसार देश की साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत है। देश के ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर जहां 73.5 प्रतिशत है, वही शहरी इलाकों में यह दर 87.7 प्रतिशत है। इस अध्ययन के अनुसार केरल की साक्षरता दर 96.2 प्रतिशत के साथ पहले पायदान पर है जबकि आंध्र प्रदेश 66.40 प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्थान पर है।

महिला साक्षरता अभी भी एक बड़ी चुनौती है। रिपोर्ट यह बताती है कि देश में पुरुष साक्षरता दर महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा बेहतर है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों की साक्षरता दर 84.7 प्रतिशत है वही महिलाओं की साक्षरता दर 70.3 प्रतिशत ही है। केरल में 97.4 प्रतिशत पुरुष और 95.2 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, वही दिल्ली में 93.7 प्रतिशत पुरुष और 82.4 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में महिला की साक्षरता दर बड़ा कारण है। राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर पूरे देश में सबसे न्यूनतम स्थान पर है। यहां पर पुरुषों की साक्षरता दर 80.8 प्रतिशत है तो वही महिलाओं की साक्षरता दर केवल 57.6 प्रतिशत ही है तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि आबादी का यह बड़ा हिस्सा आखिर कब और कैसे साक्षर हो पायेगा?

शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के पश्चात् विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, शौचालय और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार और विद्यालयों तक बच्चों को लाने के लिए की जानी वाली पहल की वजह से सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है लेकिन एक चौथाई सरकारी विद्यालयों में आज भी बच्चों का नामांकन 60 प्रतिशत से कम है। आज भी कई ऐसे ग्रामीण विद्यालय हैं जहां पर कमरे व डेस्क बेंच, टाट-पट्टी जैसी मूल सुविधाएं भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं। बहुत से विद्यालयों में बच्चे बरामदे व पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हुए नजर आते हैं। गर्मी के मौसम में बच्चों को शुद्ध पेयजल के लिए भी भटकना पड़ता है। शौचालय विद्यालयों में अवश्य बनाये गये हैं लेकिन पानी की कमी से उनमें साफ-सफाई रखना मुश्किल है।

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के सभी छात्रों को नि:शुल्क पोशाकें वितरण करने की घोषणा की गयी थी लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी पचास प्रतिशत बच्चों के तो खाते भी नहीं खुले हैं। अधिकांश विद्यालय भवन छात्रों के बैठने की स्थिति में नहीं हैं। पानी टपकता है, ऊपर से गिट्टी सीमेंट कुछ न कुछ गिरती रहती है अत: सरकारी स्तर पर सर्वे करवाकर जरूरत वाले सभी विद्यालयों में भवनों की रिपेयरिंग करने की जरूरत है। रिपेयरिंग नहीं होने योग्य कक्षा कक्षों एवं भवनों को गिराकर वहां पर नये भवन बनाने की जरूरत है।

मैंने पिछले समय एक प्रश्न लगाया था, जिसका उत्तर यह आया। मैंने यह पूछा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक कितने विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं? इसका उत्तर आया कि एक भी नहीं। अभी जरूर नयी पंचायतें मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनी हैं, उनमें कुछ विद्यालय जरूर क्रमोन्नत होंगे।

आपने यह लिखा था कि कृषि संकाय को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान संकाय वाले 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जायेंगे जबकि अभी तक पचास परसेंट में भी नहीं खुले हैं।

महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल की बात लगभग कई वक्ताओं ने की है। मेरे यहां पर भी एक विद्यालय खुला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोहेड़ा में, जहां पहले से बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है, उसी विद्यालय में इस महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय को खोला गया है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि यह विद्यालय अलग से हो और बालिका विद्यालय भी चालू रहे, वहां के सब लोगों की यह इच्छा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय कालेज है बड़ी सादड़ी, वहां पर तीन लेक्चरर पोस्टेड हैं लेकिन वर्तमान में एक भी कार्यरत नहीं है। तीनों को सरकार ने दूसरी जगह पर, कहीं न कहीं प्रतिनियुक्ति पर लगा रखे हैं। आज की तारीख में उस कालेज में एक भी लेक्चरर नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि या तो उनकी प्रतिनियुक्ति निरस्त की जाये या नये लेक्चरर वहां पर बड़ी सादड़ी में लगाये जायें।

एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के बैकलॉग को शीघ्र भरने की घोषणा की है पर यह अभी तक पूरी नहीं हुई है,

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

इसको शीघ्र भरा जाये। वेतन विसंगति एवं सामंत कमेटी की रिपोर्ट पिछले तीन वर्षों से सरकार के पास अध्ययन के लिए लम्बित है, कमेटीज पर कमेटीज बनायी जा रही हैं लेकिन कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों का निवारण नहीं हुआ है। अत मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वेतन विसंगति का निवारण शीघ्र किया जाये।

यह बात पूर्व वक्ताओं ने भी कही है कि अध्यापकों से अध्यापन के अलावा जो भी कार्य कराये जाते हैं, वे बन्द होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एकाध चुनाव का कार्य अगर करवाना चाहे तो करवा सकते हैं क्योंकि चुनाव लम्बे समय तक नहीं होता है लेकिन कई काम तो ऐसे होते हैं जो उनको रोज करना पड़ता है और कई विद्यालयों में एक-दो अध्यापक कुल हैं तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि उनको दूसरे कामों से हटाया जाये।

एक निवेदन यह है कि पंचायती राज संस्था, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद् के मद से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वह विकास कार्य नहीं कर सकते हैं, यह अनुमत नहीं है तो इसको चालू किया जाये कि पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषद् उनको विकास काम करने की छूट दी जाये।

छात्रों को प्राथमिक शिक्षा के समय से ही कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाये।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, वे मैं रख देता हूं।

पंचायत समिति मुख्यालय डूंगला, धमोतर, भदेसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने का निवेदन करता हूं।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निकुम में विज्ञान संकाय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोहेड़ा में गणित व विज्ञान संकाय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंगलवाड़ में गणित संकाय खोलने की मांग करता हूं।

राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, मंगलवाड़ एवं चिकारड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नालवा, कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय कल्याणपुरा, नया खेड़ा, भाटों का मीन्नाणा, आकोलाखुर्द, बामनखेड़ी,

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

भालोट, तेजपुरीया की ढाणी, मानजी का गुढ़ा, सोमावास, करोली, रदईखेड़ा, भूतखेड़ा, सातलियावास, निमगांव, ऊंठेल, देवरी, फाचर, भूरक्याकलां, देवदा, मरावदिया को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। राजकीय प्राथमिक विद्यालय झाड़सादड़ी, आंतरिया, झांजलवास, नंगावली, रावलीमंगटी, किशोर सिंहजी का खेड़ा, रोड़जी का खेड़ा, बन्जारों का खेड़ा, पालखेड़ी, जलखेड़ी, झालमपुरा, लखमीपुरा, खेरमंगरी, तालाब, चीरवा, मोग्या आंबा, धावड़ीफला, बालिका बारावरदा, मालनखेड़ह, मगड़दा, हाल का खेड़ा, भीमलोद एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय संस्कृत दोवड़, भीयाहुरी, रोजमंगरी, खेड़ी, लक्ष्मीपुरा, बाघपुरा, फलासिया, गुमानपुरा, भूरक्याखुर्द, लाम्बी चोटी, तलाऊ, ऊंठेलखेड़ा, टपरीयाखेड़ी, जन्तोई, भागल, ओरवाड़िया को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

नये प्राथमिक विद्यालय नांगेड़ी, भीखाखेड़ा, बक्षीखेड़ा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन गांव निकुम, मंगलवाड़ और खोडीय की जनसंख्या 5 हजार से ज्यादा है। वहां पर कस्तूरबा महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय खोलने की कृपा करें।

ग्रामीण क्षेत्र कृषि प्रधान होने से विभिन्न विद्यार्थियों की कृषि के कोर्स में रुचि रहती है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाकों में कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु एनओसी प्रक्रिया सरकार ने जो बन्द कर रखी है, उसको चालू किया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार माननीय विधायक जो स्वर्गीय हैं, मेरा सरकार से निवेदन है कि मंगलवाड़ के मूल निवासी श्री वृद्धि चन्दजी जैन, उम्मेदपुरा खरदेवला निवासी श्री उदय रामजी धाकड़, जरखाना निवासी श्री शंकर लालजी जाट तथा बानसी निवासी श्री ललित सिंहजी शक्तावत, ये चारों विधायक रहे हैं, इन चारों स्थानों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नामकरण इन माननीय विधायकों के नाम पर किया जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय राजस्थान। जय चित्तौड़। जय प्रतापगढ़।

श्री सभापति: श्रीमती इन्दिरा देवी।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपकी अनुमति से मंत्रीजी से मेरे विधान सभा क्षेत्र के रियां बड़ी में कालेज की मांग करती हूं। 30-40 किलोमीटर की दूरी तक कोई कालेज नहीं है। दूसरा, मेरे मेड़ता विधान सभा

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय की घोषणा आपने कर दी, जो मीरा मेड़ता के नाम से ही जाना जाता है, उसका नाम मीरा के नाम पर ही रखा जाए। दूसरी मेरी मांग है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में धनेरिया और बुरयासनी सहित तीन चार गांवों की मांग है कि वहां 8वीं तक की स्कूल हैं, उनको 10वीं तक करने की आप घोषणा करें। वैसे तो सरकारी स्कूल हर गांव में है पर आज ऐसी स्थिति हो रही है कि बच्चे बाहर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो सरकारी स्कूल हैं, उनके भवनों की रिपेयर करवायें ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें। वैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में ही जाते हैं क्योंकि गरीब स्थिति है। बच्चों को खाने के लिए नहीं है। कपड़ों के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं आपसे मांग करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रियां बड़ी में कालेज हो जाए तो बेटियां अच्छी तरह से पढ़कर आगे बढ़ सकती हैं। मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि कृपा करके घोषणा करें कि रियां बड़ी में कालेज होनी चाहिए। वैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों में स्थिति ज्यादा खराब है। भवन जर्जर अवस्था में हैं। मैडम और सर बच्चों को बाहर बैठकर पढ़ाते हैं तो मैं आपसे मांग करती हूं कि भवनों की रिपेयरिंग जल्दी करवायें। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का मौका दिया। आज एजुकेशन पर चर्चा हो रही है तो मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं और यह बात इस सदन में रखना चाहता हूं कि क्या कारण रहे कि जिस सरकारी स्कूल के अन्दर 5 हजार छात्र पढ़ते थे, उसके अन्दर आज की तारीख सौ से डेढ़ सौ के लगभग मात्र छात्र बचे हैं। वही भवन है, वही एरिया है। बात एरियाज की हो रही है या सुविधाओं की हो रही है तो पश्चिमी राजस्थान में जरूर मैं मानता हूं कि वहां पर भवन की कमी है और नये स्कूल खोलने की आवश्यकता है वरना एक-एक गांव में भवन खण्डहर हो रहे हैं, खाली पड़े स्कूलों के। छात्र नहीं हैं। सभापति महोदय, कोई बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है लेकिन मेरे देश की विडम्बना है कि जो जनता का पैसा होता है या कोई उपक्रम जो सरकारी होता है, उसकी व्यवस्था अगर डांवाडोल हो रही है, अगर उसकी रेपुटेशन गिर रही है तो उसको इतनी चिन्ता से हम लोग नहीं लेते। प्राइवेट व्यक्ति जो होता है, उसको लगता है कि

(श्री बलजीत यादव)

मेरे संस्थान की इमेज गिरी तो मेरी इनकम गिर जायेगी, मैं फेल हो जाऊंगा तो वह छोटी-छोटी चीजों को नोट करता है और सुधार का प्रयास करता है।

सभापति महोदय, छोटे बच्चे का मन कोरे कागज की तरह होता है, वह चंचल होता है, नई-नई चीजों के प्रति अट्रेक्ट होता है और वह अपने आपको आस-पड़ोस से कम्पेयर करता है, आस-पड़ोस के बच्चों से कम्पेयर करता है और जब कोई पड़ोस का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में कलरफुल ड्रेस पहनकर जाता है तो नन्हा सा बच्चा जब उसको स्कूल में भर्ती करवाने की बात आती है तो वह अपने पापा से लिपट कर कहता है कि मुझे भी फलां प्राइवेट स्कूल में ही जाना है जिसमें वह बच्चा जा रहा है। प्रत्येक मां-बाप के लिए उसका बच्चा सब कुछ होता है चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो और वह कोशिश करता है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति करे। वह बच्चा जिद करके रखता है, बार-बार बोलता है कि मुझे उस स्कूल में जाना है क्योंकि उसको उसकी ड्रेस अट्रेक्ट कर रही है। कभी यह जानने का प्रयास हमने नहीं किया कि उसकी मनोभावना को।

सभापति महोदय, बड़ी-बड़ी विदेशी कम्पनियां आती हैं, बड़े-बडे एडवरटाइजमेंट करके वह लुभा लेती हैं और अपने प्रोडक्ट को बेच जाती हैं। इसी प्रकार से इस शिक्षा में भी हुआ कि लोगों ने इसको उद्योग बना लिया जबकि शिक्षा वेलफेयर के लिए होती है। छोटा बच्चा होता है वह सरकारी स्कूल में जाता है, हमारे यहां पर एक पीटीआई का पद है लेकिन खेल साम्रगी स्कूल में नहीं है और हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि गेम्स का पीरियड कौनसा होगा। प्राइवेट स्कूल में जाता है, स्पोर्ट्स की ड्रेस पहनकर जाता है, यह मेरे हाउस की ड्रेस है, यह फलां हाउस है, यह फलां हाउस है, महाराणा प्रताप हाउस है, यह पृथ्वीराज चौहान हाउस है या यह अब्दुल कलाम हाउस है या अलग-अलग अपने नाम से या महापुरुषों के नाम से जो बना दिये, वह उस बच्चे के साथ खेलता तो उससे पूछता है, आज यह कौनसी ड्रेस पहनकर गया है, आपका कौनसा हाउस है। वह सरकारी वाला कह रहा है कि अपना तो कोई हाउस नहीं है। पता ही नहीं। उसको ड्रेस भी मुझे नहीं पता, कैसे सलेक्ट करते हैं। मैंने किसी से पूछा कि सरकारी स्कूल के बच्चों की ऐसी ड्रेस है, यह किसी ने क्या सोच कर सलेक्ट की, तो कहा गया कि मैली नहीं होगी। मतलब हमने शुरू से ही सोच लिया कि यह तो गन्दगी में ही रहने वाला है, तेरी मैली नहीं होगी इसलिए यह पहन ले, धो या मत धो। यह सोच है हमारी क्योंकि हमने यह सोच लिया कि सरकारी स्कूल में तो वही पढ़ेगा तो बिलकुल मैला कुचला

(श्री बलजीत यादव)

ही होगा, वही जायेगा। यह हमने सोच लिया। हार तभी होती है जब व्यक्ति खुद सोच लेता है कि मैं हार गया।

सभापति महोदय, अभी कहा जा रहा है कि नामांकन बढ़ गया, यह बढ़ गया। अंग्रेजी स्कूल में लाटरी से एडमिशन हो रहे हैं। कभी किसी ने इस बात को सोचा, एक भी व्यक्ति ने नहीं बोला कि लाटरी से क्यों हो रहे हैं। क्या कोई पहाड़ टूट गया? धरती फाड़ दी या क्या कर दिया आपने। वही टीचर हैं, वही स्कूल हैं, वही भवन हैं, क्या कर दिया आपने नया? वह इसलिए गया सभापति महोदय, कि आपने अंग्रेजी स्कूल दिया, तो उसको लगा कि हां, समय के साथ ये बदल रहे हैं। बच्चे के मन में तो है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना है मुझे। माता-पिता ने कहा बेटा, सरकारी अंग्रेजी स्कूल आ गयी है तो उसके प्रति वह अट्रेक्ट हुआ, पेरेंट्स भी और वह बच्चा भी वरना कोई गरीब आदमी, जिसके अन्दर साल के 80 हजार से लेकर दो-दो लाख रुपये तक फीस देते हैं। कभी इस चीज का चार्ज, कभी उस चीज का चार्ज, कभी फलां चार्ज, कौन देगा, खाने को रोटी नहीं है लेकिन बच्चे को प्राइवेट में भेजने के लिये मजबूर हैं, उसको तरह-तरह से लूटा जा रहा है। क्या कभी किसी ने चैक किया इन स्कूलों को? मनमाने तरीके से फीस बढ़ा लेते हैं। मैंने इस विधान सभा में भी कहा था कि कोरोना समय में एक दिन क्लास नहीं लगी। क्या किसी ने जन-आन्दोलन चलाया इनके खिलाफ विपक्ष के लोगों ने या किसी और ने यह प्रयास किया किसी सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट गये कुछ अभिभावक लोग और वहां से भी क्या-क्या होता है, सब लोग जानते हैं आजकल क्या-क्या होता है। क्या किसी ने पैरवी की? देश की किसी सरकार ने चिन्ता जाहिर की कि हम लूटने नहीं देंगे, बड़े-से-बड़ा वकील खड़ा करेंगे, हम खुद पैरवी करेंगे। जब नेताजी पर केस हो जाता है न सी.बी.आई. का, तो राम जेठमलानी जैसे पैरवी कर लेते हैं लेकिन गरीब के ऊपर मुसीबत आ पड़ी तो किसी को चिन्ता नहीं कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, हारो-जीतो, अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, लो भाई हो गया काम तेरा। पीट-कूट, दे फीस। किनकी स्कूलें हैं ये? ये बड़ी-बड़ी स्कूलें किनकी हैं? करोड़पति-अरबपति लोगों की।

हमारे प्रधान मंत्रीजी का एक बयान आया। यूक्रेन में मेडिकल के बच्चे फंस गये तो कहा कि मैं तो खुद ही बोल रहा हूं यहां प्राइवेट ला रहा हूं यहां करें, वहां विदेश क्यों जाते हैं। प्रधान मंत्रीजी, मर्जी से विदेश कोई नहीं जाता, लेकिन वहां 25 लाख में एम.बी.बी.एस. में हो जाता है और यहां एक करोड़ में होता है। जब नहीं है तो जमीन बेचकर मुश्किल से 25 लाख जुटाकर मजबूर

(श्री बलजीत यादव)

होकर वहां भेज रहा है। यह केन्द्रीय मंत्री कहते हैं कि जो बच्चा फेल हो जाता है, वह विदेश में जाता है। फेल वह नहीं होता है, फेल हम होते हैं, फेल हमारी व्यवस्था होती है, तब वह विदेश में पढ़ने के लिये जाता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा +++ लेकिन यह क्या है, मैं समझ नहीं पाता इस चीज के लिये, माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं समय इतना ही मेरे पास है, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है आपके पास, कंगाल हो सब लोग, कुछ नहीं कर सकते तो उस गरीब के बच्चे के जुनून को जगा दीजिये, मोटिवेशनल क्लास चालू कर दीजिये और वह मोटिवेशन कौन देगा उसको? वह उसको शिक्षक देगा, जो गुरू उसको पढ़ा रहा है, वह देगा। आप सिर्फ उसको तनावमुक्त कर दीजिए, आप इतना-सा रहम कर दीजिए।

आपने टीचर की यह हालत बना दी है, मिड-डे मील, खाना बनाकर खिला। खाना बनाने वाली कितने की आएगी 1320 रुपये में। आप लाकर बता दो, आपके किसके घर पर खाना बनाने वाली 1320 रुपये में आती है। आप कोई भी बता दो, सबके घर पर सर्वेण्ट हैं, 1320 रुपये में कौनसा सर्वेण्ट मिल रहा है। इस सदन में आप यहां बता दें, क्या यह बात किसी को समझ नहीं आती? किसने यह रेट तय की थी कि 1320 रुपये में आ जाएगी, लेकिन कर दिया हमने तो, अब तू जाने, टीचर जाने।

कोई परेशान है, टी.एस.पी. में पडा है, बुजुर्ग होगा, मां-बाप को कैंसर होगा। वह परेशान है, आकर कहेगा कि मेरा तबादला कर दो। नहीं, यहां पर बैन है, नहीं होगा यहां से, क्योंकि झंझट करेंगे थर्ड ग्रेड वाले। आप जोखिम लेने से डरोगे क्या? सरकार में आये हैं तो जोखिम लेना पड़ेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, गुरू का सम्मान होता था। कबीर जी कहते थे -

'प्रथम वन्दना गुरू को, दूजा आदि गणेश,

तीजा माता शारदे, कंठ करो प्रवेश, माते कंठ करो प्रवेश।'

यह दोहा बताता है कि गणेश जी को पहले पूजते हैं, लेकिन उस जमाने में गणेश जी से भी पहले गुरू को पूजने के लिए कबीर जी ने कहा। कबीर जी ने कहा-

(श्री बलजीत यादव)

'सब धरती कागज करूं, और लेखन सब वनराज

और सात समुन्दर की मसी करूं, पर गुरू गुण लिखा न जाय।'

वह गुरू का महत्व बताते हैं। यहां गुरू धक्का खाते फिरता है। गुरू कहता है कि सूचनाएं मांगते हैं, माननीय सभापति महोदय, शाला दर्पण पर सारी सूचनाएं हैं, लेकिन लिखकर भेजा जाता है कि यह सूचनाएं दीजिए, वह सूचना दीजिए, फलांनी सूचना दीजिए। शाला दर्पण पर है, यह कह सकता है, आर्डर जारी हो सकता है कि जो भी सूचना चाहिए, वह सारी-की-सारी मिल जाएगी, लेकिन नहीं, स्कूल में देख, दो साल की दे, फिर पांच साल की दे। वह सूचना देते-देते परेशान हो जाता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, खतम कर रहा हूं तीस सैकण्ड में। वह सूचना बनाते-बनाते उसके अन्दर थक जाता है। एक खाना बनाते-बनाते थक जाता है, एक पत्तल उठाते-उठाते थक जाता है। माननीय सभापति महोदय, वह पढ़ाएगा कब? माननीय सभापति महोदय, किसी को बी.एल.ओ. बना दिया, किसी को और काम सौंप दिया। वह ड्यूटी, वह ड्यूटी करते-करते तनाव में जी रहा है। फिर वह चाहता है कि मेरे मां-बाप बीमार हैं, यहां ट्रांसफर कर दो तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर सिर्फ यह कहना चाहता हूं अगर इन सरकारी स्कूलों को अच्छा करना चाहते हो तो जो शिक्षक हैं, उनको एक बार सरकार बिठा ले। आप पांच-दस शिक्षकों को बिठा लें और कोई जाकर उन बच्चों को पूछ ले। माननीय सभापति महोदय, मैं जाता हूं मेरे स्कूलों में बिना सूचना के, किसी को नहीं बताता, जाकर बच्चों में बैठता हूं, बेटा बता क्या-क्या प्रोब्लम है? वह बताते हैं सर, हमें खेलने के लिये कह दो। सर वह बच्चे खेलते हैं, हमें खेलने का सामान दे दो। मैं उनको कहता हूं कि मैं दिलाता हूं। वह इतने खुश हो जाते हैं और गले के लिपट जाते हैं कि आप बहुत अच्छे एम.एल.ए. हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। आपके बाकी के अमूल्य सुझाव मंत्रीजी को मिलकर दे देना। श्री बिहारीलाल जी।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): इसलिए आप इतनी-सी सुनवाई कर लें, इतना मैं आपको कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 पर आपने बोलने का समय दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद। बजट में शिक्षा पर, इंग्लिश मीडियम विद्यालय पर बहुत-सी बातें हुईं। सरकार की अंग्रेजी मीडियम विद्यालय खोलने की ब्लाक में हर जगह मंशा है, मैं इसमें कोई मीन-मेख निकालना नहीं चाहता, लेकिन पिछली सरकार में जो अभिनव प्रयोग हुआ स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय का और वह बहुत मायने में इससे बेहतर है, उसमें भी प्राइमरी क्लासेज को शुरू करना चाहिए। सरकार को, माननीय शिक्षा मंत्रीजी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए और आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोल रहे हैं। एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने पिछले बजट में कहते हैं कि जिन बालिका विद्यालय में 500 छात्राओं की संख्या होगी, उनको हम कालेज का दर्जा देंगे। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक बानगी माननीय कल्ला जी, आपको बताना चाहूंगा। रोडा और कागड़ा, मेनसर, इन गांवों की बालिका सैकण्डरी विद्यालय को आपने महात्मा गांधी विद्यालय बना दिया। यहां पर छात्राओं की संख्या 500 से ज्यादा थी। मेनसर को तो आपने दुरुस्त किया, लेकिन रोडा और कागड़ा को आपने अभी तक ठीक नहीं किया। वहां दूसरे विद्यालय पड़े हैं, जो मर्ज हो चुके, उनको डी-मर्ज करके वहां 6 से 8 तक कक्षा-कक्ष भी बने हुए हैं, तो गांव वालों की बालिका शिक्षा के प्रति आप रूझान रखते हैं, सरकार की मंशा है तो इन विद्यालयों को बचाया जाए और मारवाड़ी में कहावत है -'गोदी हाला न छोड़, पेट हाला की आस करां तो वा बात ठीक कोनी।' यह फलते-फूलते विद्यालय हैं, जिनको हमारे मुख्य मंत्रीजी बजट में कहते हैं कि इनको महाविद्यालय बनाने की क्षमता रखते हैं, तो इन दोनों को दुरुस्त किया जाए। ऐसा मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं, पूरे प्रदेश भर में चलते हुए विद्यालयों को हम अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय बना रहे हैं। आप नये सिरे से एक नये विद्यालय को खड़ा करिए तो आम छात्रों को भी फायदा होगा और ग्रामवासियों को भी फायदा होगा और अभिभावकों को भी फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से, न्यू एजूकेशन पालिसी 2020 की हम बात करते हैं और उसमें प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा में होगी और आज मातृभाषा पर, मायड़ भाषा, अपनी मुंह बोली भाषा पर श्री जोगेश्वर गर्ग जी ने अपनी पूरी बात रखी। लम्बे विस्तार में बात रखी। मैं उन सारी बातों को ताईद करते हुए एक उदाहरण देना चाहूंगा।

(श्री बिहारीलाल)

अकबर के दरबार में एक बहुत बड़ा भाषा का विशेषज्ञ आया, जो 100 भाषाओं को जानता था और उसने 100 भाषाओं में अपनी जिरह की। इससे दरबार भी प्रभावित हुआ। अब उस भाषा विशेषज्ञ ने एक शर्त रख दी कि इन 100 भाषाओं में मेरी मातृभाषा कौनसी है, वह सदन बताये। अब सारे चक्कर में पड़ गये तो उन्होंने दुबारा से पूछा कि यह अपनी मातृभाषा में तो बहुत परफेक्ट होगा, लेकिन जब 100 भाषाओं में उसने शास्त्रार्थ किया तो 100 की 100 भाषाओं में उसकी मास्टरी थी। अब सदन तय नहीं कर पाया कि इसकी मातृभाषा कौनसी है? सवालिया निशान लग गया। जब कोई समस्या हो जाती है अकबर के दरबार में तो बीरबल काम आता है। बीरबल को बादशाह ने पूछा कि बीरबल आप बताओ, इसकी मातृभाषा कौनसी है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर बताया कि जहांपनाह एक कौड़ा मंगाया जाये और इस भाषा विशेषज्ञ को 100 कौड़े मारे जाएं। बादशाह ने आदेश दे दिया। अब कौड़े पड़ने लगे तो जब भाषा विशेषज्ञ की कराह निकली ओ मां रे, ओ बाप रे, तो वह मातृभाषा में ही निकली। उन 100 भाषाओं में से मातृभाषा का कितना अन्तर्मन से जुड़ाव है। यह एक उदाहरण से हमें समझना चाहिए। इसी सदन से मारवाड़ के गांधी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारी राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

माननीय सभापति महोदय, आदरणीय कल्ला जी, आप बैठे हैं। पूरे सदन की उपस्थिति में आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी मायड़ भाषा को, हमारी राजस्थानी भाषा को राजस्थान में द्वितीय राजभाषा का दर्जा तो कम से कम दें। आने वाली हमारी तरुणाई को, हमारी युवा पीढ़ी को इससे बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। अनेक कंपीटिटिव एग्जाम्स में हमारे राजस्थान के नौजवान बेहतर कर पायेंगे।

जिक्र अकबर का आया तो महाराणा को कैसे भूल सकते हैं। महाराणा को बीकानेर वाले तो कतई नहीं भूल सकते। महाराणा में भी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते-लड़ते कहीं शिथिलन आ गया और अकबर को एक पाती लिख भेजी तो बीकानेर के महाराजा पीथल ने तो उनको जगाने के लिये सन्देश भेजा कि 'म्हे आज सुणी है नाहरियो स्याळां रै साथे सोवै लो, म्हे आज सुणी है चातगड़ो धरती रो पाणी पीवै लो'। महाराणा की लड़ाई को, स्वाधीनता के संग्राम को जब सत्ता में बैठे लोग सत्ता का संघर्ष बता देते हैं तो जो प्रताप स्वाभिमान से देश के लिये, अपनी मिट्टी के लिये लड़े, सदन में भी हमारे

(श्री बिहारीलाल)

प्रताप बैठे हैं, प्रताप जी, आपने हमारे रामलाल जी के हाथ से कागज तो फाड़ दिये लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई को सत्ता की लड़ाई कहने वालों का क्या-क्या फाड़ा, यह सदन की जानकारी में लायें।

सभापति महोदय, रीट का विषय आया। पूरे प्रदेश में आपने रीट सैकण्ड तो रद्द किया। रीट फर्स्ट की जो अंक तालिका आयी है, कट आफ लिस्ट आयी है, उससे अंदाजा लगा लीजिये कि 95 प्रतिशत से भी ऊपर वह जा रही है। इससे अंदाजा लगा लीजिये कि जो रीट सैकण्ड में हुआ, वैसा का वैसा निश्चित रूप से रीट फर्स्ट में भी हुआ होगा। वह नौजवान भी आपकी तरफ देख रहा है कि आप क्या निर्णय करते हैं। हम सबकी मांग तो सीबीआई की है। आपके डीजी, एसओजी अशोक राठौड़ बाड़मेर, जालौर की सीमाओं में धूल फांकते घूम रहे हैं। कभी कोई बत्तीलाल मीणा पकड़ा जाता है तो मीणा गैंग हो जाती है। कभी कोई भजनलाल विश्नोई पकड़ा जाता है तो विश्नोई गैंग हो जाती है। जहां तत्कालीन मंत्री जी को माफी भी मांगनी पड़ती है। हमारे नेता, हमारे उप नेता, प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि सीबीआई जांच हो जाये तो इस गैंग का नाम डोटासरा, गर्ग गैंग हो जाये।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) मैंने दे दिये अंकित नहीं होगा। मैंने कह दिया अंकित नहीं होगा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: मैंने निर्देश दे दिये, प्लीज विराजिये आप ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज, अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: आसन की तरफ से निर्देश दे दिये कि अंकित नहीं होगा तो नहीं होगा। आसन को आप डिक्टेट मत करिये ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, यदि आपको सब्जेक्ट से नहीं बोलना है तो मैं दूसरे का नाम पुकारूंगा। नहीं, अलाउ नहीं करता हूं ...(व्यवधान)

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री सभापति: आप सब्जेक्ट पर कंसाइज करें। नहीं बोलना है तो दूसरे आदमी को बुलाता हूं। आसन को निर्देशित मत करिये। आसन निर्देश दे सकता है। आसन ने कह दिया कि अंकित नहीं होगा, नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजिये। प्लीज सहयोग करिये। अभी इतने लोग बोलने बाकी हैं। उन्हें बोलने दें। अंकित नहीं होगा। कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, क्यों हाई जैक कर रहे हो सदन का समय ...(व्यवधान) सदन को चलने दें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप। माननीय सदस्य, आपमें बड़ी क्षमता है। प्लीज विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय नेता, प्रतिपक्ष मैं सही 8 बजे कल्ला साहब को बुलाऊंगा। प्लीज आप सहयोग करें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज। विराजिये आप। अंकित नहीं होगा। बैठिये आप। विराजिये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप। माननीय मंत्री जी, एक मिनट विराजिये आप। हाउस को जिस तरह से आप चलाना चाह रहे हैं उस तरह मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। लोग सुबह से शाम तक यहां बैठकर के बोलने के लिये इंतजार में रहते हैं, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो पूरे सिस्टम को हाई जैक कर लेते हैं और दूसरों को बोलने का मौका नहीं मिलता है। पहले वाले एक-एक घंटा बोलते हैं। रात वाले को 2 मिनट देने में भी गुरेज करना पड़ता है। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। आप स्वयं कंसाइज करेंगे। अब तक मैं आपको 10 मिनट दे रहा था। अब मैं 7 मिनट में आपको कहूंगा कि आप विराजें तो आप विराजेंगे। आप सहयोग करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सभापति महोदय, 7 मिनट में मैं मेरी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति: क्यों अपना समय जाया करते हो?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मंत्री ही तो कर रहे हैं डिस्टर्ब।

श्री सभापति: प्लीज साइलेंट। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, इस बजट में अलग से एग्रीकल्चर एवं एनिमल हसबैंडरी का बजट आया है। इसका हम स्वागत करते हैं।

श्री सभापति: बोलने के लिये कुछ तैयारी करके आते नहीं हो। इधर का उधर और उधर का इधर बोलते हो। तैयारी करके आया करो। तैयारी करके नहीं आते हो इसलिए इधर, उधर से जोड़-जाड़ करके लाना पड़ता है। नाम आना चाहिए क्योंकि आजकल यू-ट्यूब पर आता है इसलिए नाम चलना चाहिए।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोग जो बिना तैयारी के आते हैं, उन लोगों का अंकित नहीं किया जाये, ताकि सदन की कुछ स्वस्थ परम्परा बने। आप लोग कुछ तैयारी करके आयें। तैयारी करके आते नहीं हैं, मन में जो आये बोल दिया। यह कोई ऐसी चौपाल नहीं है जहां जो आपके मन में आये बोल दें। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। बिहारीलाल जी, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, आपने 7 मिनट का समय दिया था।

माननीय सभापति महोदय, एग्रीकल्चर और एनिमल हसबैंडरी का अलग से बजट आया है। इसमें मैं माननीय कृषि मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वेटेरिनरी स्टूडेंट्स की जो लंबे समय से इंटर्न का भत्ता बढ़ाने की बात थी, मेडिकल स्टूडेंट्स के बराबर करने की बात थी, मैं, उनके और उनके पूरे डिपार्टमेंट का और फाइनेन्स सेक्रेटरी का, माननीय मुख्य मंत्री जी का भी इसमें बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अब इनके नीचे का जो स्टाफ है टेक्निकल, इनकी भी भर्ती की जाये। वीओ की जो आरपीएससी में भर्ती अटकी पड़ी है, 671 की एक नयी भर्ती भी है, इनको भी सही समय पर पूरा किया जाये जिससे सही मायनों में किसान और पशु-पालकों को इसका फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम एक किसान परिवार में जन्में एक ऐसे महात्मा, साधु स्वामी केशवानन्द जी के नाम पर है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी अलख जगायी। कृषि का छात्र अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है कि उसकी डिग्री पर उनका नाम विश्वविद्यालय के साथ में लिखा जाता है।

(श्री बिहारीलाल)

यही स्थिति महाराजा गंगासिंह जी के नाम से जो हमारा विश्वविद्यालय है, उसकी है। महाराजा गंगासिंह जी जो गंग नहर लेकर आये थे। ऐसे महान पुरुष के नाम से विश्वविद्यालय है। वहां भी पढ़ने वाला छात्र गौरवान्वित महसूस करता है।

इसी तरह से हमारे यहां बीकानेर में एक वेटेरिनरी विश्वविद्यालय है, उसका नाम भी गुरु जम्भेश्वर भगवान के नाम पर किया जाये। यह बहुत लम्बे समय से हमारी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, एग्रीक्लचर कालेजेज की मांग पर मैंने देखा कि हर कोई मुख्य मंत्री जी से कृषि महाविद्यालय मांग रहा है। पहले एग्रीकल्चर की एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। अब प्रदेश में 5 एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी हैं। संख्या बढ़ने से गुणवत्ता नहीं बढ़ती है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती रमीला खड़िया।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, आपने 7 मिनट का कहा था।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। श्रीमती रमीला खड़िया (अनुपस्थित)।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 7 मिनट का कहा था।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): जो बोलूंगा सच बोलूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री और सरकार को नयी पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के ऐतिहासिक और युग परिवर्तन फैसले के लिये राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों की तरफ से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, यह देश जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद समाजवादी मॉडल लागू किया गया। इस मॉडल को जवाहर लाल नेहरू और इन्दिरा गांधी के नाम से जाना जाता है। यह बात अलग है कि कुछ लोगों को इस नाम से बलत लगती है, लेकिन इलाज क्या है? यह लोक कल्याणकारी मॉडल थे जो हिन्दुस्तान के संविधान के प्रियम्बल में है।

सरकार का चेहरा लोक कल्याणकारी होना चाहिए। लोक कल्याणकारी

(श्री बलवान पूनियां)

सरकार सबसे पहले स्कूल बनायेगी। स्कूल बन्द नहीं करेगी। यह लोक कल्याणकारी सरकार के कदम होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस लोक कल्याणकारी कदम को ओपीएस से शुरू किया गया, इसी उत्साह को आगे बढ़ायें। पिछले 7-8 दिन से राजस्थान प्रदेश में और देश भर में जश्न है। मैं हिमाचल प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही देख रहा था। वहां कह रहे थे कि राजस्थान की तरह ओपीएस लागू करो। मैं हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही देख रहा था। वहां कह रहे थे कि राजस्थान की तरह हरियाणा में भी ओपीएस लागू करो। यह कुछ बड़ा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि आपने एक लाइन से 3862 स्कूल क्रमोन्नत किये हैं। आप इसी तरीके से स्कूलों में व्याख्याताओं, अध्यापकों के रिक्त पद भरने का काम करें। मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो 123 महाविद्यालय खोले गये हैं, उनमें भी रिक्त पदों को भरें।

यह बात सही है कि हमारे नोहर के साथी विधायक ने कहा कि विधायक का भी दायित्व है और उनकी यह डोल और औकात भी होती है कि वह किसी दानदाता को तैयार करें तो पांच-पांच, छह-छह लाख करोड़ रुपये दानदाता दे देते हैं, भवन तो हम बना लेंगे लेकिन आप रिक्त पदों को भरें। माननीय सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे भादरा में ग्रामीण कन्या महाविद्यालय चल रहा है, जो संस्था के द्वारा चल रहा है, तीन मंजिला भवन है, हॉस्टल समेत, उस कन्या महाविद्यालय को राजकीय कन्या महाविद्यालय में परिवर्तित करें। मैं मांग करना चाहता हूं कि हमारे शैक्षिक कैलेण्डर जो पिछले वर्षों में कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, उन शैक्षिक कैलेण्डर को आप शिक्षा मंत्री महोदय, व्यवस्थित करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, शैक्षिक कैलेण्डर में हमारी मांग है कि 15 मई तक वार्षिक परीक्षा करवाकर जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करें ताकि 1 से 15 मई तक के 15 दिनों का सदुपयोग किया जा सके। साथ ही मेरी मांग है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश को थोड़ा शोर्ट करके आप शीतकालीन अवकाश को थोड़ा बढ़ायें क्योंकि बीकानेर सम्भाग में लगातार एक महीने तक धुन्ध रहती है। हमारे बच्चे और हमारे अध्यापक उस धुन्ध से बड़े भारी परेशान रहते हैं, जानमाल का खतरा रहता है, आप इस चीज को भी थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। मेरी मांग है कि शैक्षणिक गतिविधियों में आप

(श्री बलवान पूनियां)

प्रार्थना सभाएं वापस शुरू कीजिये, अन्य गतिविधियां भी आप शुरू कीजिये। मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से भी चाहता हूं कि आप छात्र संघ के चुनाव भी शुरू करवाइये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं कि हमारे यहां ओपीएस की तरह ही एक जोरदार धमाका राजस्थान की सरकार करेगी। एक तो टीएसपी में जो अध्यापक हैं, उनको उनके क्षेत्रों में भेजेगी और एक तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के ट्रांसफर खोल दो सारे दिन बड़ी मांग करते हैं बच्चे। छोरे और छोरियां इतनी मांग करते हैं, इलाके में जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि म्हारा ट्रांसफर कद खुलसी? मैं कहता हूं, बीडी कल्ला साहब न पूछस्यां। ओ म्हे सिर्फ भुळा रह्या हां, लेकिन थे इ पर कदम उठाओ और जवाब देओ आज शाम न कि कद न कद जल्दी करस्यो।

माननीय सभापति महोदय, हमारी मांग है, थोड़ा ध्यान करिये आप। स्कूलों में जैसे अध्यापकों के पद रिक्त हैं वैसे ही पीटीआई के पद भी रिक्त हैं। शारीरिक दक्षता में हरियाणा से जो इलाका, पंजाब से जो इलाका लगता है, वहां पीटीआई के पद कम होने का मतलब या खाली होने का मतलब है विद्यार्थियों का शारीरिक दक्षता में निपुण न होना और दूसरा उनका मैदान पर नहीं जाना और मैदान पर नहीं जाने का मतलब है नशे की तरफ नौजवानों का जाना।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि हमारे बच्चे नशे की तरफ नहीं जायें। हम कहते हैं समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं उनमें छात्रवृत्ति भुगतान समय पर हो ताकि हमारी बच्चियां और बच्चे और आगे बढ़ सके। हम मांग करना चाहते हैं खाली पड़े प्रधानाचार्यों और नव सृजित उप प्रधानाचार्यो के पद वो तुरन्त प्रभाव से भरे जायें। पातेय वेतन प्राध्यापक वरिष्ठ 2009-10 को नियमित पदोन्नति का लाभ भी प्रदान किया जाये। मैं मांग करता हूं कि इसी सत्र में मातृभाषा राजस्थानी को आज राजकीय भाषा का दर्जा देंगे। आपने रीट में पंजाबी का सब्जेक्ट रखा है, आपने रीट में सिंधी रखा है, आपने रीट में दूसरी सारी भाषाओं को शामिल किया है, राजस्थानी भाषा की पूरे राजस्थान में बहुत तेजी से मांग उठ रही है। आप इसी सत्र में हमारी मातृभाषा को, हमारी सरकारी भाषा के रूप में घोषित करेंगे, ऐसी हम मांग करते हैं।

(श्री बलवान पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगों से आपको अवगत करवाना चाहता हूं। हालांकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा मंत्री महोदय एक साल में 16 हजार नामांकन बढ़े हैं, पिछली बार 23 हजार नामांकन थे, आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में 16 हजार नामांकन बढ़कर 39 हजार नामांकन सरकारी विद्यालयों में हुए हैं। पिछले दिनों में जो स्कूल क्रमोन्नत हुए, उन्हीं का असर था और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि जो अभी स्कूल क्रमोन्नत 3862 हुए हैं, उनमें से हमारे जो सारे सैकण्डरी स्कूल सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत हुए हैं अगली बार ये संख्या छात्रों की 60 हजार पार करेगी। जिस दिन विधान सभा के अगले सत्र में हम बैठे होंगे लास्ट सत्र में तो हमारे विधान सभा क्षेत्र में 60 हजार बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हुए मिलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे प्रभारी मंत्री जी का हमने कार्यक्रम रखा है। स्कूल खेल मैदान का, हमने हमारे एमएलए कोटे से स्कूलों में हॉल का निर्माण, स्कूलों में खेल मैदान के लिए पैसे दिये हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण और स्कूल खेल मैदान का अनावरण का कार्यक्रम है, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से विद्यार्थियों की मांग आती है, हमारे यहां मांग आ रही है विद्यार्थियों की हमारे यहां कला संकाय के साथ-साथ जिगासरी बड़ी विद्यालय में पोलिटिकल साइंस, कला संकाय के साथ-साथ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट खोला जाये। हमारे यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोगीवाड़ा जहां अभी एग्रीकल्चर कालेज मंजूर हुआ है वहां और डाबड़ी में और ढिलकी और बरवाली गांव में कृषि संकाय खोला जाये, जिससे हमारे विद्यार्थियों की संख्या बढ़े और हम एग्रीकल्चर कालेज का लुत्फ उठा सकें।

माननीय सभापति महोदय, हम मांग करना चाहते हैं कि विज्ञान संकाय के रूप में मेरे विधान सभा क्षेत्र के काफी गांव हैं जो बार-बार मांग कर रहे हैं, कुंजीगांव है, बड़ा गांव है, कलाणा बड़ा गांव है, जो विज्ञान संकाय की मांग कर रहे हैं। रामगढ़ और नेठाणा बड़ा गांव हैं, जहां विज्ञान संकाय की मांग कर रहे हैं। मैं मांग करना चाहता हूं कि आप हमारी एक-एक बात पर विचार करते हुए हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी क्रमोन्नत करने का प्रयास करेंगे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामबास, अमरपुरा, सवाई

(श्री बलवान पूनियां)

छानी चक, भोजासर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नम्बर दो, भादरा, शहर में कायमखानी बास में, ये विद्यालय है जो काफी सालों से क्रमोन्नत नहीं हुआ और जहां पर काफी संख्या में अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ते हैं, इस विद्यालय को भी आप क्रमोन्नत करने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पैतृक गांव मलखेड़ा, डूंगराना और डोबी गांव में जो संस्कृत विद्यालय हैं उनको आप प्रवेशिका विद्यालय में और गोगामेड़ी में जो प्रवेशिका विद्यालय है उसको उपाध्याय विद्यालय में क्रमोन्नत करने का काम करेंगे। मैं मांग करता हूं सदन से कि जो ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बांटा गया था, थोड़े दिन पहले जो ज्ञान दिया गया था कि यूक्रेन बच्चे इस बात के लिए गये, माननीय सभापति महोदय, यूक्रेन बच्चे इसलिए पढ़ने गये कि हिन्दुस्तान में एक करोड़ रुपये मेडिकल की फीस है और हे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के व्याख्याताओं, तनिक बाज आ जाओ, कमजोरी हमारी थी कि हमारे बच्चे यूक्रेन गये, ऐसी परिस्थिति में मध्यम परिवारों के बच्चे यूक्रेन गये जिनके सपने डॉक्टर बनने के थे। अपनों को लांछन देने की बजाय हमें हमारी व्यवस्थाएं चैक करनी चाहिए। मैं किसी पार्टी का नाम लिये बगैर यह बात कहना चाहता हूं कि हम हमारी कमियां ढांपने के लिए, ढंकने के लिए कभी हमारे बच्चों को, हमारे देश के नागरिकों को ओळमा देने से बाज आयें। इस देश में 70 साल में जो विज्ञान, औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जो हमारे एजुकेशन का विकास हुआ, माननीय सभापति महोदय, मेरे दादाजी अध्यापक थे, जो स्वामी केशवानन्द के पास सिर्फ चार साल अध्यापन का कार्य करके उन्होंने नौ गांवों में नौ स्कूल नये खोले, जिससे हमारे स्कूलों का विकास हुआ है। ऐसे-ऐसे विकास हुआ है कि लोगों ने अपने सिर पर तगारी ढो-ढोकर स्कूल खड़े किये हैं, उन स्कूलों को बन्द करने के बजाय मेरा आपसे निवेदन है कि जो स्कूल बन्द पड़े हैं, अंग्रेजी माध्यम स्कूल, आगे से उन्हीं विद्यालयों में खोले जायें। ऐसी जोरदार बिल्डिंगें गांव-गांव में खड़ी हैं, आप देखो तो अचम्भा करो कि ऐसे स्कूल भवन हैं। हमारे यहां जब शादी होती है, हम बच्ची की लास्ट में जब विदाई करते हैं तो उस समय जाजम पर बैठते हैं तो स्कूल के नाम पर दो-दो हजार, पांच-पांच हजार रुपये हैसियत के अनुसार लोग दान करके जाते हैं, इससे हमारी स्कूलें बनी हैं। सरकारों की मदद के साथ-साथ समाज ने मदद की है। इसलिए हम

(श्री बलवान पूनियां)

उम्मीद करते हैं कि आप इन स्कूलों के जो भवन खाली पड़े हैं, आज जो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारे प्रस्तावों पर उन स्कूलों में, खाली पड़े भवनों में आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जो स्कूल अभी हमारे सारे क्रमोन्नत हुए हैं इनको तेजी से धरातल पर लाने के लिए हमें एक ही काम करना है, वो जो रीट की भर्ती हुई है, उस भर्ती को समय पर कराना, उसके साथ-साथ पदस्थापन का, स्टाफिंग पैटर्न भी बदलने की जरूरत है क्योंकि स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है इसलिए स्टाफिंग पैटर्न भी आप समय पर करें, भर्तियों को समय पर पूर्ण करायें ताकि राजस्थान में शिक्षा का महत्व और तेजी से हो, हिन्दुस्तान में जिस तरीके से केरल मॉडल शिक्षा में माना जाता है, एक दिन राजस्थान भी मॉडल के रूप में स्थापित हो। कोरोना में जिस तरीके से राजस्थान का नाम आया, गाहे-बगाहे देश और दुनिया के अखबारों में छपा, हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान प्रदेश के लोग और जनप्रतिनिधि राजस्थान प्रदेश का युवा यह उम्मीद करता है कि राजस्थान भी एजुकेशन में टॉप होगा, हमारे बच्चे भी अंग्रेजी में फर्राटेदार बात करेंगे, मातृभाषा को भी मान्यता मिले, इसी उम्मीद के साथ आपने मुझे ध्यान से सुना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाकर आठ बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं इधर-उधर की बात नहीं करूंगा। आप मुझे दस मिनट दे देना। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात ही करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि शहीद भगत सिंह कालेज, रायसिंहनगर, प्रकृति के मनोहर वातावरण में शहर से दो किलोमीटर दूर, गांव 12 पीएस की जमीन पर गंग नहर की पीएस वितरिका के किनारे, रायसिंहनगर से गंगानगर मुख्य सड़क पर स्थित है। रायसिंहनगर तहसील से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय 70 किलोमीटर दूरी पर है। यह महाविद्यालय अन्तरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में स्थित है। महाविद्यालय का निर्माण रायसिंहनगर के दानदाताओं ने दान देकर करवाया। दिनांक 24 अगस्त, 1978 को श्रीमती प्रकाश कौर, शहीदे आजम भगत सिंह की बहिन की अध्यक्षता में श्री केदार नाथ शर्मा, मंत्री, राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। भूमि के रूप में महाविद्यालय के पास कुल 19 बीघा 12 बिस्वा जमीन है जिसमें से 8 बीघा जमीन पर यह महाविद्यालय बना हुआ है।

सभापति महोदय, पूर्व में महाविद्यालय के संचालन हेतु एक मैनेजमेन्ट कमेटी थी, परन्तु किन्हीं कारणों से वर्ष 1991 में मैनेजमेन्ट कमेटी को भंग कर राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप-5 के पत्रांक 89 दिनांक 14.02.1991 के आदेशानुसार उप-जिलाधीश रायसिंहनगर के स्थानीय एसडीएम को आगामी आदेश तक संस्था के प्रशासक पद पर नियुक्त किया गया, जो आज दिनांक तक महाविद्यालय के प्रशासक पद पर नियुक्त हैं और माननीय प्रशासक महोदय, एसडीएम रायसिंहनगर के आदेशानुसार महाविद्यालय संचालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा आयुक्तालय, कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्रांक 847 दिनांक 23.07.2021 में प्रदत्त आदेशानुसार माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट में शहीद भगत सिंह महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय घोषित किया गया।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, जयपुर के पत्रांक 1704 दिनांक 04.06.2021 के क्रम में राज्याधीन किये गये शहीद भगत सिंह महाविद्यालय रायसिंहनगर की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण हेतु निर्धारित प्रारूप में एमओयू अध्यक्ष प्रबन्ध समिति, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय रायसिंहनगर से समन्वय स्थापित कर स्टाम्प पर उक्त प्रारूप को सम्मिलित करते हुए दिनांक 11.06.2021 तक भेजने हेतु आदेशित किया गया था, किन्तु किये जाने वाले एमओयू के कुछ बिन्दुओं पर आपत्ति होने के कारण शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर आज दिनांक तक राज्य सरकार के साथ एमओयू न होने के कारण एक निजी महाविद्यालय के तौर पर संचालन हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे द्वारा पिछले तीन वर्षों से लगातार इस महाविद्यालय की बजट घोषणा के बाद भी सरकारीकरण की मांग को निरन्तर उठाया जा रहा है, किन्तु स्थिति जस की तस है, जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के युवाओं को उच्च अध्ययन हेतु जिला मुख्यालय या अन्यत्र स्थान पर जाना पड़ता है, जिससे स्थानीय आम जन एवं युवाओं को आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सभापति महोदय, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर का सरकारीकरण करने के सम्बन्ध में एमओयू अतिशीघ्र किया जाये, जिससे क्षेत्र के युवाओं को इसका लाभ मिल सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के श्रीविजयनगर उप-खण्ड मुख्यालय पर अभी तक कोई भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है, इसलिए श्रीविजयनगर कस्बे में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाये। इसके लिये यदि सरकार के पास बजट उपलब्ध नहीं है तो श्रीविजयनगर के कई भामाशाह जमीन देने को और वहां पर कालेज भवन का निर्माण करने को तैयार हैं।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीविजयनगर का भवन जर्जर अवस्था में है। पूरे गंगानगर जिले का एकमात्र विद्यालय है, जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि है। छात्र-छात्राओं द्वारा लगातार खेल मैदान और स्टेडियम की मांग की जा रही है, मगर आज तक सरकार द्वारा यहां न तो भवन का जीर्णोद्धार किया गया है और न ही खेल मैदान व स्टेडियम के लिए किसी प्रकार के प्रयास किये गये हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्कूल भवन का जीर्णोद्धार करवाया जाये व खेल मैदान और स्टेडियम का निर्माण भी करवाया जाये।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत 6 बीएलएम, श्रीविजयनगर के गांव 8 बीएलएम, गोगामेड़ी व गांव 4/5 एलएसएम बाण्डा, अनूपगढ़ बड़ी आबादी वाले गांव हैं, वहां अभी भी तीनों गांवों में उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूल हैं। उच्च माध्यमिक स्कूल दूर होने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। गांव 8 बीएलएम, गोगामेड़ी व गांव 4/5 एलएसएम बाण्डा, अनूपगढ़ में स्थापित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर माध्यमिक स्तर के विद्यालय घोषित किये जाएं। गंगानगर एक कृषि प्रधान जिला है। मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर को कुछ बड़े गांवों में कृषि संकाय खोले जाने की महती आवश्यकता है एवं छात्र-छात्राओं, अभिभावकों की इस सम्बन्ध में मांग भी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जिन-जिन विद्यालयों से कृषि संकाय खोलने के लिये प्रस्ताव आये हुए हैं, वहां कृषि संकाय शुरू किया जाये।

माननीय कल्ला साहब, मेरे कुछ विद्यालय हैं, जहां मैंने खुद गांव-गांव जाकर प्रस्ताव लिये। उन्हें क्रमोन्नत करने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे गांव वाले लोग गरीब परिवारों से हैं और एससी के लोग यहां रह रहे हैं। कुछ विद्यालयों के नाम मैं नोट करवा रहा हूं। कृपया पर्सनली संज्ञान लेकर इन्हें क्रमोन्नत करवाने की व्यवस्था करवाएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित विद्यालयों को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाये:-

i. राजकीय प्राथमिक विद्यालय 13 एपीडी बी
ii. राजकीय प्राथमिक विद्यालय 2 जीएम
iii. राजकीय प्राथमिक विद्यालय 6 एएस
iv. राजकीय प्राथमिक विद्यालय 17 जीएम ए
v. राजकीय प्राथमिक विद्यालय 17 जीएम बी
vi. राजकीय प्राथमिक विद्यालय 13 बीएलएम ए
vii. राजकीय प्राथमिक विद्यालय 3 पीएस
viii. राजकीय प्राथमिक विद्यालय 3 एनजेडपीडी ए
ix. राजकीय प्राथमिक विद्यालय 37 पीएस
x. राजकीय प्राथमिक विद्यालय 47 जीबी
xi. राजकीय प्राथमिक विद्यालय 15 पीएस

निम्नलिखित विद्यालय जो उच्च प्राथमिक हैं, माध्यमिक में क्रमोन्न्त किये जाएं:-

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

i. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 बीजीडी ए
ii. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 12 बीएलएम
iii. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 45 जीबी
iv. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोमावाली
v. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धांधड़ा 2 डीएम
vi. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 14 बीजीडी
vii. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 28 एमएल ए

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कम्पलसरी (रायसिंहनगर) को भी उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाये। निजी स्कूल पुन: शुरू करें, जो पूर्व में संचालित थे, परन्तु वर्तमान में बन्द हैं।

श्रीविजयनगर के गांव 51 जीबी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गांव 15 जीएम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गांव 10 जीएम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत उड़सर के गांव 30 एमएल में एक नया राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोला जाये।

माननीय कल्ला साहब, मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में शिक्षा विभाग से मुझे आईसीटी लैब से विहीन 36 स्कूलों की सूची प्राप्त हुई थी, जिस पर मेरे द्वारा लगभग सभी स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित करने हेतु विधायक कोटे से फंड जारी कर दिये गये थे, मगर बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज दिनांक तक उनमें से एक भी स्कूल में आईसीटी लैब स्थापित नहीं हुई।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के उच्च प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर के लगभग सभी विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का अभाव है। अधिकतर स्कूलों में कमरों के हालात खस्ता हैं या जर्जर अवस्था में हैं। कृपया सर्वे करवाकर जिन-जिन विद्यालयों में कक्षा कक्षों की आवश्यकता है, वहां नये कक्षा कक्ष बनवाये जाएं एवं जिन-जिन विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं, उन्हें भरा जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की ग्राम पंचायत डाबला, जो एक बड़ी आबादी वाली ग्राम पंचायत है, इसमें दो ऐतिहासिक स्थल- शहीद गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ साहिब और गुरु जम्भेश्वर भगवान की स्थली बिश्नोई मन्दिर स्थित हैं। डाबला ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 10 हजार है। अत: पंचायत मुख्यालय, ग्राम डाबला में एक महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाये।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

सभापति महोदय, मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब-जब हम विधायक कोष से सरकारी विद्यालयों के लिये कक्षा कक्ष हेतु राशि की अनुशंसा करते हैं तो जिला परिषद् के अधिकारियों द्वारा कई प्रकार के राइडर लगा दिये जाते हैं। कभी कहते हैं, कक्षा कक्ष के लिये की गयी अनुशंसा राशि कम है तो कभी बताते हैं कि स्कूल का पट्टा नहीं है। जब ऐसे सरकारी विद्यालय बरसों से चल रहे हैं, वहां पर बिजली, पानी, भवन, सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार द्वारा पूर्व में भी मुहैया करायी गयी हैं तो ऐसे आब्जेक्शंस क्यों लगाये जा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है।

माननीय सभापति महोदय, अभी विराटनगर से मेरे साथी विधायक कह रहे थे, कांग्रेस के राज में शिक्षा में नये-नये नवाचार हुए हैं। बिलकुल सही बात है। "रीट के साथ चीट", रीट के पेपर चोरी हुए, मंत्री जी के रिश्तेदारों को आरएएस बनाया, शिक्षकों के ट्रांसफरों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, यही कांग्रेस का नवाचार है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं, कल्ला साहब यहां विराजमान हैं, आप मांग का उत्तर देते समय मेरे क्षेत्र की मेरे द्वारा रखी गयी मांगों को कंसीडर कर स्वीकार करें। मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान में एक उच्च स्तर की पारदर्शी शिक्षा नीति बनायी जाये, जिससे शिक्षकों की नियुक्तियों से लेकर प्रमोशंस, ट्रांसफर्स तक की सटीक जानकारी शिक्षकों एवं जनता को मिल सके। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, मांग संख्या 24 - शिक्षा, कला और संस्कृति के बारे में बोलने का आपने मुझे समय दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद। सभापति महोदय, आज का विषय इतना बड़ा है कि हर समाज को, हर वर्ग को, हर इंसान को अन्धेरे से उजाले की ओर प्रदर्शित करने वाला विषय है। शिक्षा एक अमूल्य धन है, जिसे जो प्राप्त करता है और जैसे-जैसे खर्च करता है, वैसे-वैसे उसके अन्दर बढ़ोतरी होती रहती है। माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस बजट में और पिछले बजट में शिक्षा की अलख जगाने के लिये, शिक्षा को मजबूती देने के लिये गांव में, ढाणी में, दूर-दराज में रहने वाले गरीब के बच्चों को सम्बल देने के लिये, उच्च शिक्षा देने के लिये जो महान कार्य किया है, उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। जो ओल्ड पेंशन योजना लागू की

(श्री पदमाराम)

(समयः 19.00 बजे)

वह एक बहुत बड़ा काम किया है। स्कूल के अन्दर अध्यापक बन्धु विचार करते थे कि अभी तो अपने को बहुत तनख्वाह मिलती है पर 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद अपना सहारा कौन बनेगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आगे बढ़कर एक महान काम किया जो भारत के अन्दर कोई नहीं कर सकता था, वह काम किया इसलिए मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

अभी चर्चा चली कि पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी का क्या योगदान है, उनका क्यों नाम लिया जा रहा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा और 26 जनवरी, 1950 को जब संविधान सभा में पेश करने गये तो जब वहां से वापस आ रहे थे तब उस समय कुछ लोग खुशी बांट रहे थे और कुछ लोग आंसू बहा रहे थे, वे कौन थे? बंच आफ थाट्स के अन्दर गुरु गोलवलकर जी ने लिखा है कि हम प्रजातंत्र का संविधान लागू नहीं करना चाहते, हम मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहते हैं। वे कौन थे? आज जो महापुरुष, जिन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी के अन्दर इस देश को आजाद करने के लिए, इस देश के लिए किया, उनके पास क्या कमी थी? उनके पास क्या कमी थी जो यह कुर्सी हासिल करने के लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया? उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। आज भारत जिस वट वृक्ष के नीचे खड़ा है उसको तैयार करने की आधारशिला रखी, वह उन महापुरुषों ने रखी थी और उस कारण से उनका नाम लिया जाता है। इसलिए नहीं लिया जाता है कि हम एक-दूसरे की चमचागीरी करते हैं, हम बड़े-बड़े असत्य भाषण देते हैं, हम भ्रम पैदा करते हैं, हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राम के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें करके कुर्सी हासिल करके बैठ जायें। हर बात के अन्दर राजनीति। राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, आप अपनी बात रखो, आप अपना पक्ष रखो, हम राज के अन्दर हैं तो हमको कोसो पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भ्रम पैदा करके लोगों को गुमराह करने का काम मत करो।

श्री सभापति: अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कर दो आप थोड़ा बहुत।

श्री पदमाराम (चौहटन): दो मिनट बोल लेता हूं। समस्या तो गहलोत साहब ने कुछ रखी ही नहीं है और आगे जाकर हम साहब से और मांग लेंगे, समस्या की कोई दिक्कत नहीं है। आयेंगे, नहीं आयेंगे, अभी तो आये हुए हैं।

(श्री पदमाराम)

वह समय बतायेगा कि आप कौनसी बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इधर से देखो, उधर से देखो।

श्री सभापति: मुझे दूसरे वक्ता का नाम पुकारना पड़ेगा। माननीय सदस्य, मुझे दूसरे वक्ता का नाम पुकारना पड़ेगा। अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बता दीजिये।

श्री पदमाराम (चौहटन): साहब, आप मना करोगे तो मैं बैठ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं है। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि जो आपने शानदार स्कूलें खोली हैं तो इन स्कूलों के अन्दर नयापन लाओ। आज बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है और कई युवा साथी उच्च शिक्षा प्राप्त कर बेरोजगार बन गये हैं तो ऐसी नयी नीति लाओ जिससे सरकारी नौकरियों के साथ प्राइवेट नौकरी भी बढ़े, प्राइवेट धन्धा भी बढ़े और रोजी-रोटी के लिये नयापन हो उसके लिए नया करो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गोलवलकर के बारे में दो ही लोगों को ज्ञान है, या तो धारीवाल जी को है या इनको है।

श्री पदमाराम (चौहटन): दूसरा, मेरा निवेदन है कि पहले जितनी भी सीनियर सैकण्डरी स्कूलें हुई हैं उन ज्यादातर स्कूलों में साइंस फैकल्टी है और दूसरा सब्जैक्ट नहीं है तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वहां आर्ट्स की व्यवस्था करें।

जो इंग्लिश स्कूलें खुली हैं वह बहुत शानदार काम हुआ है। स्कूलों के अन्दर बच्चों की तादाद इतनी बढ़ रही है कि हर आदमी यह चाहता है कि मेरा बेटा इंग्लिश में पढ़े तो मेरा निवेदन है कि वहां इंग्लिश स्कूल खोल दी वह तो अच्छी बात है, परन्तु नजदीक में कोई पांचवीं की स्कूल नहीं है तो उस जगह पर नयी प्राइमरी स्कूल खोली जाये।

मेरा निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है, दूर-दराज का क्षेत्र है और वहां स्कूलों में लेक्चरर की कमी है, वरिष्ठ अध्यापकों की कमी है। जब भर्ती होती है तो उस समय आप काउंसलिंग के आधार पर उनसे विकल्प भराया जाता है और दूर-दराज कोई नहीं जाना चाहता है। मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जिन स्कूलों के अन्दर बच्चों की तादाद कम है और कई लोग कई सालों से एक जगह बैठे हैं उसमें आप जो अब ट्रांसफर नीति ला रहे हो, उसमें ऐसा प्रावधान करो कि वह दूर-दराज की जगह जायें। जहां पर उनकी जरूरत है वहां भेजें और एक जगह बैठकर वे काम नहीं करें।

(श्री पदमाराम)

दूसरा, उच्च शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो प्राइवेट कालेज हैं, उनमें कालेजों की धड़ाधड़ मान्यता दे रहे हैं पर उनके न तो भवन है, न ही वहां पढ़ाने वाला कोई लेक्चरर है तो उनकी जांच की जाये और बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। बच्चों के बैठने की जगह नहीं है और बच्चों को कहते हैं कि आप डोनेशन दो, स्कूल नहीं आना तो डोनेशन दो। ऐसे जो कालेज हैं उनकी मान्यता समाप्त की जाये और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।

मेरा निवेदन है कि इस बजट में सीनियर सैकण्डरी स्कूल हो गये हैं पर उच्च प्राथमिक स्कूल का कोई प्रावधान नहीं है और सैकण्डरी स्कूल का भी कोई प्रावधान नहीं है। जितने भी संसाधन हों उनके आधार पर नयी सैकण्डरी स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूल का प्रावधान किया जाये। जो प्राथमिक स्कूलें हैं और उनके 3-4 किलोमीटर नजदीक उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं हैं तो अभी तो भर्तियां बहुत हो रही हैं और 62 हजार नये थर्ड ग्रेड के टीचर आ रहे हैं तो ज्यादा संसाधन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां बिल्डिंग है और सिर्फ वहां एक वरिष्ठ अध्यापक लगाना जिसकी आपकी 10 हजार की भर्ती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो स्कूलें हैं जहां बच्चों की तादाद अधिक है और नजदीक कोई स्कूल नहीं है वहां पर प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्कूल करने की आप व्यवस्था करें। बहुत ही शानदार बजट दिया है जिसमें भवन और नये कालेज भी दिये हैं।

सभापति महोदय, दूसरा, मेरा निवेदन है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी महानुभाव हमेशा खड़े होते हैं और कहते हैं कि काम नहीं करते हैं तो क्या आपके समय में जितनी घोषणा हुई थी, वह पूरा हण्ड्रेड परसेंट कर दिया?

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): मेरा निवेदन है कि बजट पेश किया जाता है, नयी योजनाएं बनायी जाती हैं तो उसके अन्दर हर आदमी काम करने की कोशिश करता है। माननीय गहलोत साहब ने और हमारी कांग्रेस सरकार ने आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी को मजबूती देने के लिए जो काम किया है वह कोई कर नहीं सकता। उन्होंने किसानों को सम्बल देने के लिए काम किया है। शिक्षा का अलख जगाने के लिए, शिक्षा को मजबूती देने के लिए काफी नयापन हुआ है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 24-शिक्षा एवं कला पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरे से पहले सभी सदस्यगणों ने बहुत लम्बी-लम्बी बातें कीं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी आदिवासी छात्राओं में 65 परसेंट से ऊपर अंक लाने वाली बालिका को या तो स्कूटी दी जाती थी या फिर उसको छात्रवृत्ति दी जाती थी। परन्तु हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ट्राइबल की बहुत सारी बालिकाएं आज भी इंतजार कर रही हैं जिनको न तो स्कूटी मिली है और न छात्रवृत्ति मिली है। हमारे शिक्षा मंत्री महोदय बैठे हैं, आदरणीय मंत्री महोदय, हमारी उन छात्राओं को कम से कम एक तो बैनेफिट मिले वे गरीब छात्राएं हैं, उस दिन का इंतजार कर रही हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी पहले की सरकारों ने बालिकाओं को पढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, जो बहुत सारी घोषणाएं की हैं, उन पर खरी उतरी हैं। मैंने भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर प्रयास किया कि जो हमारी ट्राइबल की छात्राएं हैं, उनको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए।

सभापति महोदय, मैंने घोषणा की थी कि हमारे ट्राइबल में जो पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, 75 परसेंट से ऊपर अंक लायेगी तो उनको हवाई यात्रा करवाऊंगा। सभापति महोदय, ट्राइबल की छात्राएं 60-65 परसेंट से ऊपर अंक नहीं लाती थीं, मगर इस घोषणा से 75 परसेंट से ऊपर अंक लाने वाली तीस बालिकाओं को मैंने पूर्व में हवाई यात्रा करवायी है। हवाई यात्रा करवाकर यहां पर मुख्य मंत्री जी से मिलवाया और सभी मंत्रियों से, हमारे ट्राइबल मंत्री जी से और इन सबसे मुलाकात करवायी और उन्होंने विधान सभा का भी भ्रमण किया।

सभापति महोदय, मैं मांग कर लेता हूं, क्योंकि समय कम देंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिन विद्यालयों में लाइट, पानी, शौचालय, भवन और बाउण्ड्रीवाल नहीं है उनमें तुरन्त प्रभाव से बाउण्ड्रीवाल और भवन रहित या कक्षा कक्ष कम हैं, उनमें कक्षा कक्ष भी दिलवाये जाएं और बाउण्ड्रीवाल करायी जाय। यहीं नहीं, जिस विद्यालय में पानी व शौचालय नहीं है, वह भी आप करवायें।

जैसे हमारे घोघरा जी कह रहे थे, हमारे भवन जर्जर हैं। वास्तव में,

(श्री फूल सिंह मीणा)

इनकी सरकार में ही इनकी नहीं सुनेंगे तो हमारी तो क्या सुनेंगे। मगर उनकी बात का समर्थन करते हुए मैं यही कहूंगा कि हमारे ट्राइबल के अन्दर बच्चे बाहर बैठते हैं, भवन जर्जर हैं, उनके अन्दर पानी पड़ता है, प्लास्टर पड़ता है और किसी के लगती है और घायल हो जाते हैं। मैं मांग करता हूं कि ऐसे भवनों का जीर्णोद्धार करवायें और उनके ऊपर चाइना मोजेक या कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि उन भवनों की उम्र बढ़ जाय।

सभापति महोदय, पूर्व सरकार की बात करूं, हमारे भैरोंसिंह शेखावात साहब, जो मुख्य मंत्री हुआ करते थे। उस समय गुलाब चन्द जी कटारिया साहब शिक्षा मंत्री थे। हर पंचायत पर पांचवीं तक स्कूल हुआ करती थी और शिक्षा मंत्री जी और भैरोंसिंह जी ने मिलकर हमारे पूरे के पूरे राजस्थान के अन्दर एक ही आदेश में आठवीं तक स्कूल खोलने का काम किया। हमारे भैरोंसिंह जी शेखावत साहब और पूर्व गृह मंत्री गुलाब जी कटारिया साहब और नेता प्रतिपक्ष ने किया। आठवीं तक की स्कूल में ड्रेस भी एक जैसी लागू की। यहीं नहीं, उसके बाद दूसरी सरकारें बदलीं। मगर हमारे राजस्थान की शिक्षा को बढ़ाने के लिये कोई ऐसा काम नहीं किया। वसुन्धरा जी 2013 में आईं और उन्होंने एक ही आदेश के अन्दर आठवीं से दसवीं तक स्कूल, हर पंचायत मुख्यालय पर काम किया तो हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया।

सभापति महोदय, फिर हमारी बदकिस्मती, सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आई। उन्होंने 2008 से 2013 के अन्दर कुछ नहीं किया और हमारी सरकार 2013 में आई और उन्होंने देखा कि ट्राइबल की बालिकाएं पढ़ाई छोड़ देती हैं, दसवीं से बारहवीं तक नहीं पढ़ पाती हैं। एक ही आदेश निकाला वसुन्धरा जी ने और दसवीं से बारहवीं हर पंचायत मुख्यालय पर स्कूलें खोलकर, उन ट्राइबल बालिकाओं को पढ़ने के लिए अगर प्रोत्साहन दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज ये कह रहे हैं, पंचायत मुख्यालय पर हमने दसवीं तक स्कूल खोल दिये, पहले ही खुली हुई हैं। उसमें क्या खोल दीं, आपने नयी पंचायतें खोली हैं, वहां पर आपने जरूर खोली हैं, वह ठीक है। एक ही आदेश में जो हमारी बारहवीं तक स्कूलें खुली हैं, वे हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुली हैं।

सभापति महोदय, यही नहीं हमारे ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में दूर-दराज

(श्री फूल सिंह मीणा)

में पढ़ने वाली बालिकाएं, मेरी पंचायत में खजूरी आता था, उसमें स्कूल खोली थी। बालिकाओं ने पढ़ाई छोड़ दी और वसुन्धरा जी ने वहां खजूरी में स्कूल खोली तो मैं आपको एक सैम्पल बताना चाहता हूं। वहां पर स्कूल खोलते ही 35 बालकों ने एडमिशन लिया। उसमें 30 बालिकाएं थीं और पांच बालक थे। इसलिए, बालिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। पूर्व सरकार में हम बालकों को दूध पिलाते थे और नि:शुल्क पिलाते थे, उसको भी बन्द कर दिया। मैं मांग करता हूं कि उसको भी चालू करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि पूर्व शिक्षा मंत्री, पार्टी के मुखिया गोविन्द सिंह जी डोटासरा साहब कहते हैं कि महाराणा प्रताप तो सत्ता के लिए लड़ा था। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मेवाड़ का ही नहीं, पूरे राजस्थान का अपमान किया है। महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी तो अपने मेवाड़ का ही नहीं राजस्थान का मान रखने के लिए लड़ाई लड़ी थी। वह सत्ता का भूखा नहीं था। उनके लिये भीलू राणा, जिसने वास्तव में सेनापति का दर्जा पाया तो भीलू राणा बनकर उन्होंने हरावल दस्ते के रूप में जनजाति परिवार को लेकर आगे लड़ाई लड़ी, हमारा मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान भी स्वतंत्र रहे। मैं मांग करता हूं कि पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने हमारे महाराणा प्रताप के लिये ऐसे शब्दों का उपयोग किया, वह निन्दनीय है। मैं मांग करता हूं ऐसे शब्दों के लिये उनको सोचना चाहिये और सरकार से भी मांग करना चाहूंगा कि ऐसे शब्दों का उपयोग न करे। महाराणा प्रताप का राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में नाम लिया जाता है। ऐसे महापुरुष के लिये बोलना उचित नहीं है।

सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं प्राथमिक स्कूल खुलवाने के लिये मेरी ग्राम पंचायतों में अनेक ऐसे फळे हैं, जहां पर प्राइमरी स्कूल तो कम से कम खुले। जैसे सुरपाल, सुरू, झाबला, पाटिया, खजूरी, चणावदा, पाई, काया, चासदा और उमरेड़ा ऐसे गांव हैं, जिनमें फळे और बड़े-बड़े गांव हैं, उनमें प्राथमिक स्कूल खुलवाया जाय ताकि उनको शिक्षा मिल सके। सभी स्कूल में खेल मैदान की जो घोषणा की थी, उनके अन्दर खेल मैदान बनाकर उन बच्चों को खेलने के लिए भी प्रोत्साहित करें।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि ट्राइबल एरिया

(श्री फूल सिंह मीणा)

है। नाई एक ऐसा गांव है, जिसमें कम से कम 18 पंचायतें आती हैं। वहां विज्ञान संकाय खोलने की आपसे मांग करता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, अभी तो 5 मिनट हुए हैं 15 मिनट हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि रीट लेवल सैकण्ड के पेपर लीक होने पर सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। यह कैसे सम्भव है कि एक ही एजेंसी द्वारा करायी गयी परीक्षा, एक ही स्ट्रांग रूम में रखे हुए पेपरों में रीट लेवलटू का ही पेपर कैसे चोरी हुआ? क्या रीट फर्स्ट का पेपर लीक नहीं हुआ? मैं मांग करता हूं कि वास्तव में उन 26 लाख विद्यार्थियों के साथ यह कुठाराघात तो हुआ ही है। मगर आपने यह कहा है कि हम 62 हजार बालकों को परीक्षा दिलवाकर नौकरी देंगे तो हमारा यही है कि उसकी जांच तो सीबीआई से कराई जाय और यह भर्ती भी तुरन्त प्रभाव से लागू करके, हमारे इनको दिया जाय, बालकों को नौकरी मिले।

सभापति महोदय, यही नहीं, मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के माध्यम से रिटायर अधिकारियों को, रिटायर अध्यापकों को नौकरियां दे रहे हैं और आप कह रहे हैं युवाओं को नौकरी देंगे। सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं उन युवाओं को नौकरी दें। रिटायर को यदि आप उस स्कूल में लगा रहे हैं तो उनको रिटायर ही क्यों कर रहे हैं? हमारे युवा विद्यार्थी इतने बेरोजगार हैं, उनके लिये स्कूल में नौकरी का प्रावधान रखें, रिटायर की कहीं और व्यवस्था करायें।

सरकार से मांग करता हूं, स्थानान्तरण के अन्दर भ्रष्टाचार हुआ। सभापति महोदय, थर्ड ग्रेड का अध्यापक आज भी मांग करता है कि हमको हमारे जिले में भेजें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, एक मिनट में। जब शिक्षा की मीटिंग हो रही थी तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने अध्यापकों से पूछा कि आपसे पैसा तो नहीं लिया जा रहा है। मुख्य मंत्री जी के सामने कह रहे हैं, पैसे लिये बिना काम नहीं हो रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर और मंत्री महोदय, आप ऐसे पैसे लेने वाले को कोई दे रहा हो तो वह अध्यापक जो इतने वर्षों से काम कर रहा है।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): ...पहले तो यह कहा था कि स्वेच्छानुसार आपका...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: विराजिये आप। अंकित नहीं होगा। श्री खुशवीरसिंह। विराजिये। हो गयी मांग।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पाली जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र था हर दृष्टि से, चाहे शिक्षा की दृष्टि हो, सड़कों की हो, पेयजल की दृष्टि से हो, हर क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन पिछड़ा हुआ था। विकास के बहुत सारे आयाम स्थापित इन तीन वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री ने किये हैं और एक ऐसा काम करके दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी क्षेत्रवासियों ने। जब मैं चुनाव जीतकर 11 दिसम्बर, 2018 को मेरे निवास पर पहुंचा तो वह जो खुशी का माहौल था उससे दस गुना ज्यादा खुशी का माहौल सभापति महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे कांटा क्षेत्र में, मगरा क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में बालिका महाविद्यालय की घोषणा की और मैं पहुंचा तो चालीस किलोमीटर तक सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां मेरे साथ में थीं और पूरे गांव में मुझे गांव के बाहर से कन्धों पर बैठाकर उन युवाओं ने मुझे स्कूल तक पहुंचाया, इससे ज्यादा खुशी की बात सभापति महोदय, क्या हो सकती है उन क्षेत्रवासियों में, उन बालिकाओं में जो खुशी की लहर थी, वह वास्तव में बयां नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद देता हूं शिक्षा मंत्री महोदय, आपको और मुख्य मंत्री महोदय को कि एक नयी सौगात जिसकी कल्पना भी नहीं की थी और हमारे वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो टीवी पर बोलने लग गये कि यहां पर यह करने की क्या आवश्यकता थी क्योंकि उनको मालूम है कि पिछड़ा क्षेत्र है, पढ़-लिख गया तो फिर हमारी बातों में आकर हमें वोट नहीं देगा ये, इसलिये उनकी असलियत का पता चल गया हमारी जनता को।

मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो इंग्लिश मीडियम की स्कूलें दी हैं हमें, उनमें एक थोड़ी समस्या आ रही है कि जो हिन्दी माध्यम में पढ़ रहे थे बच्चे, उनकी यह मांग है कि दो शिफ्टों में अगर यह विद्यालय चलाया जाये तो जो हिन्दी

(श्री खुशवीरसिंह)

माध्यम में पढ़ना चाहते हैं जो ट्वेल्थ क्लास तक के बच्चे हैं तो उनको भी यह सुविधा मिल जाये अन्यथा थोड़ी परेशानी रहेगी। हालांकि अधिकांश लोग यह चाह रहे हैं अंग्रेजी माध्यम वाली, लेकिन फिर भी जब नयी क्लास आये तक तब तक यह व्यवस्था होनी चाहिये।

सभापति महोदय, दूसरा, मैं सुझाव ही दूंगा, समय का अभाव है, लम्बी बात नहीं करूंगा। मंत्री महोदय, एक जो हमारे अध्यापक हैं उनकी सबने बात बतायी है कि ये अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं और एक कार्य और जहां भी जाता हूं तो कहते हैं कि डाक देने गये हैं। यह डाक क्या है, यह अंग्रेजों के वक्त डाक चलती थी, वह आज भी इस युग में जो हम कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया 5जी की बात कर रहे थे अभी कोई माननीय सदस्य। हमारे यहां जब 5जी की बात कर रहे थे तो फिर यह डाक वाली व्यवस्था को तो बंद करवाओ। एक अध्यापक जी तो डाक में ही घूमते रहते हैं।

मंत्री महोदय, दूसरा मैं निवेदन करूंगा, आप इस पर गौर करें कि एसडीएम कार्यालय में, तहसील कार्यालय में, पंचायत समिति में अनायास हमारे अध्यापक बैठे हैं प्रतिनियुक्ति पर और लम्बे समय से वो बैठे हैं और विद्यालय में उनकी बहुत ज्यादा कमी है, उसके बावजूद कैसी व्यवस्था से जाते हैं, वो मुझे भी मालूम नहीं है तो आप इसको स्ट्रिक्टली कम से कम यह तो बंद कर सकते हैं, अपने हाथ की बात है, मंत्री महोदय।

सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे क्षेत्र में देवली आउवा गांव है और उस गांव में वहां के निवासी स्वर्गीय श्री खंगार सिंह जी चौधरी जो चार बार इस सदन के सदस्य भी रहे हैं और उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये अपने गांव में और सीनियर सैकण्डरी स्कूल तक उनके कार्यकाल में बन चुकी थी लेकिन मेरी मांग यह है कि आज वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके नाम से उस देवली आउवा स्कूल को स्वर्गीय खंगार सिंह जी के नाम से कर दी जाये तो गांव वालों में एक बहुत बड़ा उत्साह रहेगा और आने वाली पीढी भी याद करेगी, उन्होंने जो सराहनीय काम अपने गांव में किया है।

मंत्री महोदय, मेरा कुछ इतिहास की बात को लेकर आपसे अनुरोध रहेगा कि हमारे इतिहास में जो पढ़ाया जा रहा है पिछले सत्तर वर्षों से उसमें कुछ परिवर्तन करके एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेकर और उसमें अपन कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और उनको इतिहास में हम जोड़ सकते हैं जो हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है। आज की घटना हम याद करें रूस और यूक्रेन

(श्री खुशवीरसिंह)

की और सभी ने बताया कि यूक्रेन क्यों गये बच्चे मेडिकल पढ़ने के लिये तो उसके पीछे आर्थिक स्थिति थी, लेकिन उससे भी आगे आप देखो, जब यूक्रेन के बच्चे पोलेण्ड पहुंचे तो पोलेण्ड की सरकार ने वहां पलक पांवड़े बिछा दिये। विपक्ष कहीं गलतफहमी में मत रहना कि प्रधान मंत्री जी की वजह से पलकपांवड़े बिछाये हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, गुजरात के जामनगर के महाराज दिग्विजय सिंह जी को जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में एक हजार पोलिस बच्चों को अपने राज्य में पनाह दी, उनको शिक्षा-दीक्षा दी और आज पोलेण्ड के अन्दर वहां की संसद में उनकी शपथ के साथ में उनके नाम की शपथ ली जाती है। यह हमारे लिये बहुत गौरव की बात है, इसको भी पढ़ाया जाना चाहिये। मंत्री महोदय, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा वहां की पार्लियामेंट का। दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जाडेजा के नाम से शपथ ली जाती है, लेकिन हमारे देश के इतिहास में हम नहीं पढ़ायेंगे।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आज अकबर महान हम पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बप्पा रावल 712 ईस्वी में जो हमारे ऊपर आक्रमण किया मोहम्मद मीर कासिम ने और उस वक्त उन्होंने खदेड़ कर भगा दिया था और उन्होंने अपनी चौकी स्थापित की थी। बप्पा रावल की चौकी उसका नाम था पेडी और पेडी से नाम पड़ते-पड़ते रावलपिंडी हो गया क्योंकि वह बप्पा रावल द्वारा स्थापित की गयी थी, उसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं तो मैं चाहूंगा कि ऐसे जो इतिहास के पन्नों में हमारा गौरवशाली इतिहास छिपा हुआ है, उसको किस तरह से हमारी इस युवा पीढी को हम बता सकें।

सभापति महोदय, मैं यह भी चाहूंगा मंत्री महोदय, आपसे कि भारत निर्माण के अन्दर और भारत एकीकरण में जिन लोगों का योगदान रहा है, जिन रियासतों का योगदान रहा है उनके इतिहास के बारे में भी हमें पढ़ाया जाना चाहिये। वो इंडिपेंडेंट थे उस वक्त आजादी के वक्त वो चाहे जैसे रह सकते थे लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र को न्यौछावर कर दिया तो उनके इतिहास के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, 1996 में जब मैं इजराइल गया था सरकार की तरफ से और मेरे पिताश्री ने उस वक्त मुझे बताया था कि इजराइल जाये तो हाइफा जरूर जाकर आना और मैं हाइफा शहर गया और वहां जाकर जब पता किया तो हमारे जोधपुर के अदम्य साहस के धनी मेजर दलपत सिंह जी की समाधि वहां थी मैं वहां पुष्प अर्पित करके 1996 में आया था और वहां की

(श्री खुशवीरसिंह)

पाठ्यपुस्तकों में मेजर दलपत सिंह जी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जब मैं जिला प्रमुख था तब शताब्दी वर्ष था पहले विश्व युद्ध का। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से शहीदों के नाम से...

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): एक कार्यक्रम रखा था सभापति महोदय, और उसकी शुरुआत की लेकिन हमें अभी तक इतिहास में जगह नहीं मिली। आज इजराइल सामरिक दृष्टि से विश्व का पांचवां बड़ा देश है। इतना मजबूत देश है और वह हमारे उन महापुरुषों के इतिहास के बारे में वहां पढ़ा रहे हैं और हम यहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, साथ ही समय आपने बताया, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो हमारी लोक कला, लोक संस्कृति है, लोक संगीत है, लोक गीत है, जिसे हम हीन भावना से देखते हैं। कइयों ने मुझे कहा कि यह तो नीचा काम करते हैं। नीचा काम नहीं करते हैं, हमारे पास क़दरदानों की कमी है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा मिरासी समाज, मनहार समाज, पव्वा समाज, जो लोक संगीत के माध्यम से हमारी संस्कृति को संजोये हुए हैं उनके लिये आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की जाय और उनकी पूरी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो ताकि हमारी लोक संस्कृति और लोक कला बचेगी तो हमारा देश बच पायेगा अन्यथा हम और आप सब उस पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भागते फिरेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इसके साथ ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो सीनियर सैकण्डरी विद्यालय क्रमोन्नत किये हैं, मंत्री महोदय, मेरे यहां कुछ 8वीं से 10वीं माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा या मैं सूची टेबल कर देता हूं। मंत्री महोदय, यह बहुत ही जरूरी है और इसलिए जरूरी है कि 12वीं तक वह हो गई, लेकिन वह बच्चे 10-10 किलोमीटर दूर हैं, वह आगे पढ़ नहीं पायेंगे। उनको अगर 5वीं से 8वीं और 8वीं से 10वीं में आप क्रमोन्नत कर देंगे, मैं टेबल कर देता हूं, यह सब क्षेत्रवासियों की मांग है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया और राजस्थानी भाषा पर मैं बात नहीं करूंगा। बहुत सारे वक्ता इसके बारे में कह चुके हैं और मैं चाहूंगा, राजस्थानी भाषा हमारी मायड़ भाषा है, उसको भी मान्यता दी जाय। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2003 में संकल्प पारित कर रखा है। हम चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा को भी राज्य भाषा का दर्जा दिया जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जी जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शिक्षा, कला और संस्कृति पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद कांग्रेस तो शासन करने में लग गई और हमारी शिक्षा पद्धति रूस और चाइना के चेलों के जिम्मे कर दी। आज जो माननीय सदस्य ने सदन को बताया कि जिस गीता की कसम हम कोर्ट में खाते हैं, माननीय मंत्री महोदय, उस गीता के बारे में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। मुहम्मद गौरी 16 बार यहां से हार कर गया और 17वीं बार वह धोखे से जीता, उस पृथ्वीराज चौहान और चन्दबरदाई को हमारी पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता है। आजादी के आंदोलन में मानगढ़ धाम जो बांसवाड़ा जिले के कोने में है कुशलगढ़ में, उस मानगढ़ धाम में अंग्रेजों ने जलियावाला कांड से भी बड़ा कांड किया। 1500 आदिवासी भाइयों को एक साथ चारों तरफ से घेर कर अंग्रेजों ने मारा, वह मानगढ़ धाम पढ़ाया नहीं जाता। गोटिया अम्बा पढ़ाया नहीं जाता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी मातृभाषा के बारे में बात हुई। हमारे यहां हिन्दी के झगड़े हुए। दक्षिण में हिन्दी का विरोध हुआ और राजनीतिक रूप से हिन्दी का विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ, हिन्दी को हमारी मातृ भाषा कभी नहीं मान सकते, हमारी राष्ट्र भाषा हो सकती है, हमारी सम्पर्क भाषा हो सकती है। जो मायड़ द्वारा सिखाई जाती है वह मातृ भाषा होती है। इसलिए आजादी के बाद जो कन्नड़ का बच्चा है, तेलुगु का बच्चा है, वह पहले अंग्रेजी पढ़ेगा। उसको डाक्टर-इंजीनियर बनना है, अंग्रेजी पढ़ेगा। अंग्रेजी पढ़ने के बाद कंपीटिशन दे सकता है। अगर आजादी के बाद हमारी मातृ भाषा में पुस्तकें होतीं तो हमारा वह बच्चा कहां जाता, कब का वह पास हो गया होता। ऐसी व्यवस्था हमारी शिक्षा पद्धति में होनी चाहिये।

हमारे राजस्थान में लगभग आधे कर्मचारी बंधु शिक्षक हैं। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र था जो भ्रष्टाचार से मुक्त था। हमारा अध्यापक थोड़ी बहुत बेईमानी क्या करता था कि एक-दो पीरियड नहीं लिया, आधे दिन की छुट्टी ले ली परन्तु राज्य सरकारों ने उसको भी दलिये में, दूध में, बिल बनाने में, सर्व शिक्षा अभियान में, कमरा बनाने में लगाकर राज्य सरकार ने उसकी भी घेराबंदी कर दी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां परीक्षा पद्धति है। माननीय कल्ला जी ने बड़ी मुश्किल से यह पद संभाला है। हमारे यहां ग्रेजुएट करते ही आईएएस, आरएएस बन जाता है और वह राज करने लग जाता है परन्तु किसी आदमी को शिक्षक बनने के लिये उसको पहले बीए करना पड़ता है, बीए

(श्री धर्मनारायण जोशी)

के बाद कंपीटिशन देगा, फिर बीएड करे, फिर दो साल परीक्षा दे, लैसन तैयार करे, फिर बीएड की परीक्षा दे, फिर रीट पता नहीं कौन-कौनसी परीक्षा पास करके वह मास्टर बनता है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, शिक्षा में इस दोषपूर्ण परीक्षा पद्धति को भी हमको चेंज करना चाहिये।

आजकल अंग्रेजी का भूत है। पूरे राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जायेंगे। टीचर नहीं हैं, टीचर कौन हैं, पुराने स्कूल हैं। मेरी मावली में सनवाड़ बालिका स्कूल है, वहां लगभग 550 बच्चियां अध्ययन करती हैं, उसका भी इंग्लिश मीडियम के लिये आदेश आ गया है। वहां हिन्दी मीडियम की बच्चियां जायेंगी कहां? अध्यापक कहां से आयेगा? अध्यापक आयेगा उन्हीं टीचर्स में से इंटरव्यू होंगे और इंटरव्यू में सलेक्ट होकर वह वहां रहेगा। क्या इंग्लिश मीडियम हुआ? माननीय सभापति महोदय, किसी भी अभिभावक से पूछो कि आपका बच्चा कहां पढ़ता है। अगर वह अभिभावक कह देगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो सामने वाले का मुंह बिगड़ जाता है कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, बड़े स्कूल में नहीं पढ़ता है? माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है संसार में लगभग 200 देश हैं और केवल 6 देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। केवल 6 देशों की भाषा अंग्रेजी है, बाकी अंग्रेजी भाषा नहीं है। उसके बाद भी हमारे पर भूत सवार है कि अंग्रेजी खोलो, अंग्रेजी खोलो।

मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था विद्यालयों में, हॉस्टल में, माननीय जनजाति मंत्री जी विराजमान हैं, मेरा निवेदन था गांव के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं। शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन है, गांव में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, गांव का बच्चा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का फुटबाल का, वालीबाल का खिलाड़ी है, उसको मिनिमम मानदेय देकर एक-दो घंटे सवेरे शाम को उसको तैयार किया जाय तो उसमें से लिम्बाराम निकलेगा। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इसकी व्यवस्था कराई जाय।

मैं कालेज की बात करता हूं। आपने राजस्थान में 28 विश्वविद्यालय खोले। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय बैठे हैं, हमारे यहां आपकी पिछली सरकार में एक क्रीड़ा विश्वविद्यालय खुला था। आजकल कोई उसका नाम तक नहीं लेता। एक वीसी बने हैं, वह 2013 में नियुक्त हुए हैं, 2016 में वह चले गये। आज वह क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहां है, कौनसे कमरे में चल रहा है, कहां चल रहा है, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है। 120 कालेज खोले, 98 में प्रिंसिपल नहीं है, यह हमारी शिक्षा पद्धति की स्थिति है। 2020-21 के बजट में

(श्री धर्मनारायण जोशी)

आपने कहा कि राजस्थान में दो होम्योपैथी कालेज खोलेंगे, उनका कहीं अता-पता नहीं है। अबकी बार भी 36 कन्या महाविद्यालय खोले। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जी भाटी साहब से मेरा निवेदन है, उनके क्षेत्र में तीन कालेज खोले, आज उन कालेजों की स्थिति यह है कि एक तो धर्मशाला में चल रहा है और दो प्राइमरी स्कूल में चल रहे हैं, यह वहां के कालेज के भवन की स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि आपने जनजाति विश्वविद्यालय का नामकरण राजीव गांधी के बजाय गुरु गोविन्द किया, इसमें क्या बहुत अच्छा काम किया, हमारे आदिवासी क्षेत्र में उसकी वाहवाही हो गई। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा आपने जनजाति विश्वविद्यालय खोला, दो साल तक एक वीसी, एक चपरासी उदयपुर यूनिवर्सिटी के एक कमरे में बन्द रहे। वहां एक विद्यार्थी का एडमिशन नहीं हुआ। हमारी पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी उसको बांसवाड़ा ले गईं। आज वहां दो लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। वहां स्वयं का भवन बन गया। आपने पत्रकारिता विश्वविद्यालय खोला, आपने अम्बेडकर विश्वविद्यालय खोला, भाजपा सरकार ने बन्द कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, भोपाल में माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय चलता है, वहां दो लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमारे यहां पत्रकारिता विश्वविद्यालय चलता है, खासा कोठी में चल रहा है, दो करोड़ रुपये किराया है। उनका प्रशासनिक भवन शिक्षा संकुल में, एक करोड़ रुपया किराया है। वहां पर मासिक वेतन 29 लाख रुपये है। जो व्यवस्था वहां हुई है, मुझे लगता है कि राजस्थान के जयपुर में नया जेएनयू नहीं बन जाय क्योंकि आपने जिस वीसी को बैठाया है, उसके पास योग्यता नहीं है। कोई पीएचईडी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है। आप शायद संशोधन ला रहे हैं कि जिसने 20 साल तक पत्रकारिता की है। क्यों भई, 20 साल क्यों। फिर तो जो अच्छा व्यापारी है, उसको मैनेजमेंट कालेज का प्रिंसिपल बना दो, अच्छा खेती करने वाला हो तो उसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वीसी बना दो। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि शिक्षा में इस प्रकार की जो स्थिति आप लोगों ने खड़ी की है, उसकी मैं घोर निन्दा करता हूं। आज दो विश्वविद्यालयों में तीन साल में पांच रजिस्ट्रार बदले हैं। माननीय मंत्री महोदय, उदयपुर यूनिवर्सिटी की

(श्री धर्मनारायण जोशी)

हालत यह है कि वहां के रजिस्ट्रार के साथ लोगों ने मारपीट की है। उनके साथ मारपीट करके उनको भगाया है। मेरा निवेदन है कि इसको ठीक किया जाये।

अंत में मेरी दो-तीन मांगें हैं। मंत्री महोदय, बहुत छोटी-छोटी मांग हैं। मेरे क्षेत्र में चूण्डावत खेड़ी एक राजपूतों का गांव हैं। 80 बच्चियां वहां से चलकर जाती हैं, क्योंकि वहां आठवीं तक स्कूल है, उसको प्रमोट किया जाये। गुर्जर समाज का बाजमिया गांव है, उसमें भी बच्चियां बाहर जाती हैं। आप अभी एक स्कूल में एकलिंग जी पधारे थे। मेरी अभी आपसे कल-परसों ही बात हुई थी। आपको स्कूल देखकर अच्छा लगा और वहां के टीचर भी कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री जी इतना सहज होकर आये कि हमको भी मजा आ गया तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि विद्यालयों में मानिटरिंग की व्यवस्था भी की जाये। समय-समय पर बड़े लोग जायें, इससे स्कूल की व्यवस्था ठीक रहेगी। वहां पर साइंस और कामर्स के सब्जेक्ट की कमी है, उसको भी खोला जाये। जिन विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं, उनकी सब जगह पर समुचित व्यवस्था की जाये। मावली के कई स्कूलों में खेल के मैदान लगभग नहीं के बराबर हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको ठीक किया जाये। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्यसूची पूर्ण होने तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24 है। पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी यह चाहते हैं कि हमारी शिक्षा में सुधार हो। मैं सोचता हूं कि आलोचना को सुधार की तरफ लेकर काम करना चाहिए और सुधार करना चाहिये। यह नहीं कि मैं आलोचना कर रहा हूं, इसका मतलब बेकार काम कर रहा हूं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाह रहा हूं कि थोड़ासा इस पर ध्यान लगाइये। यह जो आपकी छात्रवृत्ति है। अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक। यह लगभग 2018-19, 2019-20, 2020-21 की ठीक है, जितने बच्चे हैं, उनको छात्रवृत्ति मिली है। मैं समझना चाहता हूं कि 2021-22 के दिसम्बर तक केवल 6 लाख 95 हजार रुपये छात्रवृत्ति जो कि 692 बच्चों को ही क्यों मिली? इसका जवाब जरूर देना। अगर आपके पास अभी हो तो देना, नहीं तो बाद में जरूर बताना कि आखिर क्या कारण हुआ कि इस साल इन बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी या उसका क्या कारण रहा है? ऐसा ही सभी जगह पर है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी ऐसा ही है। 2021-22 में केवल 16 लाख 19 हजार रुपये, 1599 बच्चों को मिले। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी ऐसा ही है। लगभग इसी दिसम्बर तक 89 लाख 39 हजार रुपये, 8 हजार 939 बच्चों को मिले। इसी तरह से अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों को एक भी पैसा नहीं मिला। अल्पसंख्यक की छात्रवृत्ति भी प्रक्रियाधीन है, कृपया करके अपने विभाग के अधिकारियों को कहें कि ये अगर प्रोग्रेस में है तो आप लोगों ने मानिटरिंग क्या की है? पूरा साल निकल गया, केवल तीन महीने बाकी बचे हैं।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं, अगर आपको समझ में आये तो आप इस ओर बढ़ने का प्रयास कीजिये। यह जो स्थानान्तरण नीति है। इस शिक्षा विभाग का सबसे कमजोर और दुखदायी कोई पाइंट है तो ट्रांसफर है। आप और मेरा बच्चा तो शहर में ही लगा रहेगा, घर के नजदीक रहेगा, दो किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना होगा, बाकी जो कहीं पड़े हैं, वे पड़े ही रहेंगे। 25 वर्ष तक कोटड़ा उसके भाग्य में लिखा है तो वह कोटड़ा ही पड़ा रहेगा। मैं चाहता हूं और हम सब लोगों ने प्रयत्न किया है। स्थानान्तरण पालिसी बनायी हुई पड़ी है। बिलकुल फाइनल स्टेज पर पड़ी है, लेकिन कहीं न कहीं, कोई न कोई, किसी न किसी के दबाव के कारण से वह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कागज वहीं का वहीं दब जाता है। कृपा करें, वह बनी हुई है। उस स्थानान्तरण नीति को लागू करके अध्यापक का सम्मान लौटा दो। अध्यापक हम राजनेताओं के सामने आकर भिखमंगे की तरह खड़ा न हो। यह राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छा और सुखद विषय होगा। इसमें आप पहल कीजिये और स्थानान्तरण पालिसी को लागू कर दीजिये, जिसके कारण शिक्षा का उद्धार हो सके। मेरी मांग है, चाहे वह आप कर सके या न कर सके। संस्था प्रधान चाहे वह मिडिल स्कूल का हो, चाहे सैकण्डरी का हो, चाहे हायर सैकण्डरी का हो, संस्था प्रधान का चयन शिक्षकों में से ही करें, पर वह व्यक्ति कोई विशेष प्रकार की एबिलिटी और काबिलियत रखने वाला व्यक्ति हो, क्योंकि विद्यालय वैसे चलेगा, जैसे संस्था प्रधान चलायेगा। जब कभी भी ट्रांसफर होकर अच्छा संस्था प्रधान गांव में आ जाता है, वह पूरे के पूरे विद्यालय को उठा लेता है। मैं सोचता हूं कि इस पोस्ट के लिए किसी बाहर के व्यक्ति को मत बुलाओ। जो अध्यापक आपके यहां काम कर रहे हैं, उनमें से ही अच्छा सलेक्ट करें और उसको लगायें। उसको भी जिन्दगी भर तक मत लगाओ। उसे दो साल का समय दें। अगर वह अच्छा परफोर्मेंस करता है तो उसको और आगे बढ़ायें। अगर संस्था प्रधान गलत है तो उसे तुरन्त बदल देना, यह शिक्षा के लिए बहुत ही भला हो। इस पर आप ध्यान देने का प्रयास करें।

यह जो जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक स्तर के जो अधिकारी हैं। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरा प्रस्ताव अभी तक वहीं का वहीं पड़ा है। मैंने कहा था कि जिला शिक्षा अधिकारी और ये जो ऊपर के अधिकारी हैं, उनका चयन शिक्षकों में से ही हो। इनकी भर्ती 50 परसेंट चयन के द्वारा हो और 50 परसेंट प्रमोशन से हो। होता क्या है, इस विभाग की जो दुर्गति हो रही है, लास्ट मूवमेंट पर जाकर 8 महीने, 12 महीने, 14 महीने का डीईओ बनता है तो वह बाबुओं के कंट्रोल में आ जाता है। वह सोचता हूं कि हम किसी तरह सुरक्षित होकर अपनी पेंशन लेकर विदा हो जाऊं तो वह किसी भी चीज का एफर्ट नहीं करता है। जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी कमजोर है, वह जिला शिक्षा अधिकारी नहीं हो सकता। एक नया 40-45 साल आयेगा, उसको 15-20 साल तक डीईओ और डिप्टी डायरेक्टर का काम करना है। वह निश्चित रूप से, मैं आपको कह रहा हूं कि गुणवत्ता में सुधार होगा। यह मेरा-पराया छोड़िये, 50 परसेंट का सलेक्शन और भी आरपीएससी से कराइये। अध्यापक ही बैठ सके, ऐसा आप राइडर लगा दीजिये। 5 साल की नौकरी हो,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

10 साल की नौकरी हो, यह उसकी क्वालीफिकेशन हो। कोई भी शिक्षक आये, चाहे वह थर्ड ग्रेड का शिक्षक हो, लेकिन वह उस कम्पीटिशन में आ सकता है। अगर सलेक्ट होता है तो वह निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को आगे बढ़ायेगा।

अध्यापक भर्ती राजस्थान की समस्या है। हम सब लोगों ने भुगती है। हम देख रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, मां-बाप परेशान हैं। सबसे ज्यादा तो बालक परेशान हैं, क्योंकि आपकी भर्ती समय पर नहीं होती है, वह बिलकुल अध्यापक के बिना रहता है। मैं सोचता हूं कि इसको परफेक्ट करने की दृष्टि से कोई कमेटी बनायें और उसे तीन-चार महीने का टाइम दें कि वास्तव में भर्ती किस प्रकार कर सकते हैं? जिला लेवल पर कर सकते हैं, संभाग लेवल पर कर सकते हैं, हर एक का पेपर अलग कर सकते हैं ताकि रीट का जो कचरा हुआ है और जिसके कारण से आपकी, हमारी और विभाग की जो बदनामी हुई है। इसका कोई स्थायी हल आपको और हमको मिल जाये, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिये। यह बहुत बड़ा एफर्ट अपन करेंगे।

प्रत्येक पंचायत पर हम जो विद्यालय खोलते हैं। मैं सोचता हूं कि इस पर विचार कीजिये। यह एलिमेंट्री डायरेक्टर, यह सैकण्डरी डायरेक्टर। किसी विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक कोई अच्छा प्रिंसिपल अच्छी तरह से संभाल ले तो इससे मैनपावर तो बचेगा। हमने मैनपावर को टुकड़ों-टुकड़ों में बांट दिया। इधर प्राइमरी अलग जा रहा है, उधर मिडिल अलग जा रहा है, सैकण्डरी अलग जा रहा है। व्याख्याता को जितना पीरियड मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पा रहा है। दो-तीन पीरियड। अच्छा है कि छह पीरियड पढ़ाने के लिए इसी अध्यापक से, इसी स्ट्रेन्थ से। अगर आप 1 से लेकर 12 तक एक ही स्कूल कर देते हैं। केवल और केवल हमारे यहां बच्चियों को बच्चों के साथ पढ़ाने में घबराते हैं, तो छठी से लेकर 12वीं तक लड़कियों का अलग कर दिया जाये। एक पंचायत में चार-चार स्कूल चल रहे हैं। एक लड़कों का प्राइमरी, एक बच्चियों का प्राइमरी और इधर सैकण्डरी, एक गांव में चार स्कूल चलाने की जरूरत क्या है? मैं सोचता हूं कि केवल और केवल उन बच्चियों की सुरक्षा की दृष्टि से आपको ठीक लगे, वह करने का प्रयास करें तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा।

एक मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो अध्यापक रेप जैसी घटना कर जाता है। बच्ची के साथ छेड़खानी का मुकदमा बन जाता है। कृपा करके अगर उसका केस चालान हो गया तो उसको अपने डिपार्टमेंट से निकालकर घर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रवाना कर दो। वापस अगर दोबारा जीत कर आ जाएगा तो ससम्मान पैसा लौटा देना लेकिन ऐसे दागी लोगों को विद्यालय में रखकर विद्यालय की प्रतिष्ठा गिराने का काम कर रहे हैं। जब तक चालान नहीं होता तब तक बात समझ में आ सकती है कि उसके ऊपर सही मुकदमा बना या नहीं बना लेकिन चालान बनने के बाद निश्चित रूप से ऐसे दागी अध्यापक जहां कहीं भी हो, उनको तुरंत बाहर निकालकर शिक्षा के पवित्र मन्दिर से बाहर कीजिए। अभी पता नहीं हम क्यों नहीं कर पाते हैं?

हम बच्चे थे, जब पढ़ते थे तो हमें सुलेख लिखाते थे, बार-बार अच्छी कलम से लिखाते थे। मैं सोचता हूं कि पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चों को शुद्ध लिखना आ जाए, शुद्ध पढ़ना आ जाए और उसकी राइटिंग अच्छी हो जाए तो वह बच्चा दौड़ता हुआ आगे चलेगा। मैं बहुत अच्छा लिखता हूं लेकिन मुझे 10 में से 6 नंबर ही मिलते हैं और एक जिसकी राइटिंग अच्छी होती है और वह लिखता है, वही चीज लिखी है उसने, वह 9 नंबर ले जाता है। मैं सोचता हूं जो प्रारम्भ में हम इसमें रुचि रखते थे कि बच्चे की हैंड राइटिंग कैसे सुधरे? बच्चे का शुद्ध लेखन कैसे हो चाहे वह हिन्दी हो या अंग्रेजी हो। उसको करने का प्रयास करें।

निश्चित रूप से इस विभाग की सबसे बड़ी कमजोरी है निरीक्षण की कमजोरी। कोई भी विद्यालय का निरीक्षण नहीं करता। अब इसमें कोई पैसा कोड़ी नहीं लगता है। सिस्टम बनाने की जरूरत है। राजस्थान में जितने प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल के हैड मास्टर को अधिकार दे दो कि उसकी बाउंड्री में चार स्कूल हैं, वह कम से कम तीन महीने में एक बार पूरा दिनभर वहां रुककर निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट बनाकर अधिकारी को दे। दसवीं के स्कूल वालों को उनके नीचे के दीजिए। बारहवीं के स्कूल वालों को उनके नीचे के दीजिए। सौ प्रतिशत साल में तीन बार अगर विद्यालय का निरीक्षण होगा और निरीक्षण रिपोर्ट को कोई देखने की तकलीफ करेगा तो अपने आप शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। केवल व्यवस्था को ठीक करना है। मैं सोचता हूं कि अगर विद्यालय को गांव के साथ जोड़ने का प्रयास करो।

कभी यह था कि हमारे गांव में मैं बचपन में सोचता था कि थानेदार को कोई जीमन में नहीं बुलाता लेकिन मास्टर साहब को गांव के अन्दर किसी के छोटा काम भी होता तो मास्टर साहब को निमंत्रण जरूर जाता था। उसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कारण से मास्टर और गांव के लोगों का आपस में मिलना जुलना होता। अब दुर्भाग्य क्या हो गया कि हमारा मास्टर बस से उतरता है और वापस बस की घंटी को देखता है और बस स्टैण्ड की तरफ देखता है। इस सिस्टम को बदलने का प्रयास कीजिए।

स्कूल के बच्चों को खेल के मैदान से जोड़ो। मैंने और आपने जो कुछ भी संस्कार पाया है बचपन में, वह खेल के मैदान में पाया है। वहां न जाति होती है, न गरीब होता है, न अमीर होता है। जो भी अच्छा खेलता है, अगर मेघवाल का बच्चा भी खेलता है तो सारे गांव के लोग उसको उठाकर, उस बच्चे को प्यार करते हैं। मैं सोचता हूं कि खेल का मैदान जितना कमजोर पड़ा है, उतने ही हमारे संस्कार कमजोर पड़ गये। एक जो सामूहिक भावना थी, वह जोड़ने का आपको प्रयत्न करना चाहिये। ऐसा मेरा सुझाव है।

जहां तक हायर एजुकेशन की बात है, इसको देखकर तो रोना आता है। हम कहने के लिए भले ही संख्या की दृष्टि से कितने ही आगे बढ़ गये लेकिन सच में हम जो कुछ करना चाहते हैं, वह इसमें हो नहीं पा रहा है। इसका कारण यह है कि हमारा सोचने का नजरिया ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा आपसे कहना है हायर एजुकेशन मिनिस्टर साहब, आप थोड़ा-सा इस पर ध्यान दीजिए। जो कुछ बजट मैंने देखा है, लगातार मैं कह रहा हूं कि 2018-19 से ये हायर एजुकेशन का पैसा वेतन में जाता है, वह उतना ही जा रहा है जितना आज भी है। लगभग 1 हजार 76 करोड़ रुपया वह 2019-20 में गया। लगभग वही है और आज भी पिछली बार आर.ई. में 1 हजार 113 करोड़ था, अबकी बार भी 1 हजार 108 करोड़ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके वेतन में किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं बढ़ रहा है। जब आप यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, जब आप कालेज खोल रहे हैं, जब इतने पद लग रहे हैं और ये नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब तय है कि आपने बजट में प्रोविजन ही नहीं कर रखा है कि उनको नौकरी दें और बच्चों की ठीक प्रकार से पढ़ाई हो।

आप केवल और केवल अपना पैसा बचाने की दृष्टि से जिस नीति पर चल रहे हैं, नीति बहुत दुखदायी होकर उस बच्चे का भविष्य बिगाड़ रही है। डिग्री लेकर जरूर फिरेगा लेकिन उसकी डिग्री कोई काम की नहीं। रद्दी की टोकरी में भी उसको रखेगा नहीं, ऐसी स्थिति बन रही है। मैं सोचता हूं कि केवल डिग्री बांटने का काम नहीं हो, इसको आप देखिए। बहुत अफसोस है कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पुस्तकालय का जो खर्चा है, वह तो आपका हर साल घटता चला जा रहा है। आप इतनी कालेज और यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय का जो पैसा देते हैं, वह आपका घटते-घटते कभी 1 करोड़ 3 लाख था, यह घटते-घटते 49 लाख पर आ गया। अब यह कैसे पुस्तकालय चलेगा? कैसे पुस्तकालय अध्यापक के बिना चलेगा? सारी की सारी पोस्ट खाली पड़ी है। 95 परसेंट पुस्तकालयाध्यक्ष है ही नहीं। कालेज एजुकेशन में वह चपरासी ही तो किताब दे रहा है और चपरासी ही किताब ले रहा है। कहां तो आपने इसका डिजिटाइजेशन किया और कहां इतना किया, मैं सोचता हूं कि इसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। आपका प्रयोगशाला का मामला भी ऐसा ही है, शारीरिक शिक्षा का मामला भी ऐसा ही है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर वास्तव में, मैं भी मागूंगा कि मुझे भी दे दो, उसे भी दे दो, जितनी आपकी व्यवस्था हो सके, उतना दो। मुझे 10 किलोमीटर पैदल जाकर अध्यापक पढ़ाएगा तो मैं ज्यादा अच्छा बन सकता हूं बनिस्बत मेरे घर की दुकान के बाहर ही खोल दो और मास्टर के बिना मैं वहां पढ़कर, केवल नाम लिखाकर वापस आऊंगा, क्या अर्थ निकलेगा? थोड़ा-सा मन को कठोर करना पड़ेगा निर्णय लेने के बारे में लेकिन निश्चित रूप से आप इसमें कर जाएंगे।

अब मैं आपकी यूनिवर्सिटीज का, पराकाष्ठा है, मतलब ये यूनिवर्सिटीज चल रही हैं या केवल और केवल नाम के लिए हमने लोगों को बैठा रखा है। इनकी दुर्गति देखिए आप। राजस्थान विश्वविद्यालय, 95 परसेंट पद खाली हैं, कितना? 95 परसेंट, कौनसे? प्रोफेसर के 95 परसेंट पद हैं, 61 कुल है उसमें से केवल 3 काम कर रहे हैं। आपके जयनारायण व्यास में 53 की संख्या है प्रोफेसर की, 6 काम कर रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 26 की है, 5 काम कर रहे हैं। कोटा विश्वविद्यालय में आपके 6 है, यहां 3 काम कर रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय 11 में से 3, मतलब 157 प्रोफेसर की जो पोस्टें हैं, ये जो विश्वविद्यालय मैंने बताए, केवल और केवल 20 प्रोफेसर काम कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं क्या तो वहां पीएचडी हो रही होगी? क्या उस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए रास्ते बन रहे होंगे? ऐसा का सारा का सारा ही है। लगभग 80 परसेंट पद खाली पड़े हैं।

अभी सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वी.सी. साहब के बारे में, सवेरे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने मुझ

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर आरोप लगाया, सच होगा तो मेरे को सज़ा मिलेगी, मुझे कोई डर नहीं है इस बात में। लेकिन वह जिस प्रकार की गन्दी और हल्की भाषा बोलता है, एक अध्यापक तो नहीं बोल सकता। मुझे डाउट है कि वह अध्यापक भी है या नहीं है। मैं आपको सही कह रहा हूं। एक अध्यापक इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, मर भी जाए तो नहीं कर सकता। वह कड़वा शब्द बोलेगा लेकिन वह भी कुछ मर्यादा में बोलेगा, लेकिन ये तो बिलकुल ही इस तरह से बोलता है, यह भी आपको आश्चर्य होगा कि इसने जिस प्रकार का घिनौना काम किया है और जिसके लिए हमारे चांसलर साहब ने कहा कि 7 दिन में इसकी रिपोर्ट दो। उसका रजिस्ट्रार है, आपका जो वित्त नियंत्रक है, उनको बुलाकर कहा कि आप वहां बैठो, ये जो प्राइवेट कालेज के लोग हैं जिन्होंने अपनी मान्यता का पैसा जमा नहीं कराया, जी.एस.टी. का चक्कर है, इनसे बैठकर बातचीत कीजिए, मैं अभी आ रहा हूं। अब यह कहकर वे दोनों लोग चले गये। उन्होंने उन गुंडा गैंगों को जिनके साथ बैठकर वह रोज गपशप मारता है, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का। उन लोगों के साथ बैठकर एक तरह से कहा, उसने तो आर्डर दे दिया लिखित कि आपको तो इस पर जी.एस.टी. नहीं लगेगी। वहां का जो रजिस्ट्रार है, इन्होंने कहा साहब कि कानून में ये प्रावधान है, मेरा पैरा बना हुआ है ए.जी. का और इस पैरे के कारण से मुझे जी.एस.टी. लेना पड़ेगा और इसलिए मैं जी.एस.टी. को छोड़ नहीं सकता। उन्होंने उन छोरों को कहा कि इसका मातम घोषित कर दो। अब आपने देखा कि जो आपका सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद है, आपका रजिस्ट्रार और आपका वित्त नियंत्रक इन बदमाशों के हाथ पिटा जाए, गैंग के हाथों और ये उसने कहकर करवाया कि तुम कर लेना। मतलब यह एक पराकाष्ठा हो गयी और वह जान-बूझकर पौन घंटे बाद आया। जान-बूझकर पौन घंटे बाद, उनको तो वहां भेज दिया और ये पौन घंटे बाद आया। तब तक तो उनका काम साफ हो गया। उसके बाद जो मुकदमा दर्ज करा दिया, न पुलिस कार्यवाही कर पा रही है, न कोई भी कार्यवाही कर पा रहा है। सारे लोगों ने उसका विरोध किया तो यहां चांसलर साहब ने कहा कि 7 दिन में इसकी जांच हो जाएगी। अब 7 दिन के बजाय एक महीना हो गया। वह जांच कमेटी कहां गयी और जांच कहां है? इस तरह के हालात हैं। इस आदमी ने सब पराकाष्ठा पार कर दी है। ईमानदारी से अगर मैं गलत हूं तो आप किसी टीम को भेजो जो शिक्षा को समझता हो और उसको भेजकर इसका पूरा पोस्टमार्टम कीजिए तो आपको लगेगा कि यह किस तरह से आया है। इसकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(समय: 20.00 बजे)

तो पूरी जन्मपत्री देखनी पड़ेगी कि यह वास्तव में वाइस चांसलर बनने लायक है या नहीं। मैं कोशिश करूंगा, मैंने स्पीकर साहब से भी कहा, कि इसकी डिग्री फर्जी है। यह दस साल को पूरा नहीं करता। मैं आगे कभी आऊंगा, तब बात करूंगा। परीक्षा की अनियमितता को लेकर, परीक्षा में काम करने वाले लोगों के खिलाफ, एक आरोप जुलाई, 2020 में लगा दिया। उसके लिये जांच कमेटी नहीं बनाई, खाली तलवार लटकी दी, आपने गड़बड़ी की, आपने गड़बड़ी की। 16 सीसीए की चार्जशीट दे दी। उसके बाद लगभग जून में एक कमेटी बनाई, वहां के फिजिक्स के हैड आफ डिपार्टमेंट हैं, उसको इसका बनाया। उसने इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट तैयार करके, उनको दे दी। देने के बाद, उस रिपोर्ट को पब्लिश करना था। उसने कहा कि नहीं, मैं कहूं जैसा लिखो। उसने कहा कि यह सम्भव कैसे हो सकता है, आपने मुझे जांच अधिकारी बनाया, तो आप जैसा कहोगे, वैसा मैं कैसे लिखूंगा, जो कुछ हुआ मैं वह लिखूंगा। उसने वह रिपोर्ट दफ्तर दाखिल कराकर, उनके ऊपर यह तलवार लटकाने का काम किया है। वित्तीय अनियमितता की भी इसने पराकाष्ठा कर दी। हमारी यूनिवर्सिटी 42 करोड़ के घाटे में तो पहले ही चली गयी। उसके बाद भी, यह रोज, कोई न कोई नया कोर्स खोलता है। रोज कोई न कोई नई घोषणा करता है।

मैं सोचता हूं, यह संविधान पार्क बनाया है, पार्क बने, बहुत अच्छी बात है। इसकी स्वीकृति 85 लाख की थी, इसने इस पर दो करोड़ का पेमेंट कर दिया। यह दक्षिण विस्तार, हमारी यूनिवर्सिटी का एक्ट यह है कि हमारी बाउण्ड्री के अन्दर कोई एक्टिविटी, वीसी चाहे तो खोल सकता है। इसने दक्षिण विस्तार के नाम से बिलोता में, चांसलर साहब को बुलाया। आप देखो, उनको भी भ्रम में रखा। हमारे स्पीकर साहब को भी वहां बुलाया, क्योंकि उनका क्षेत्र था। वहां भूमि पूजन करा दिया। आप कराओ एक्ट में अमेंडमेंट, इस विधान सभा के फ्लोर पर कराने के बाद ही, करा सकते हो, पहले नहीं करा सकते हो। केवल और केवल लोगों को इस तरह, अपनी ओर खींचने के लिये, इस प्रकार का काम करता है।

इसने एक और कमाल कर दिया। निम्बाहेड़ा में एक प्राइवेट कालेज है। उसको टेकआवर कर रहा है। क्या करना चाहता है भाई, वहां के अध्यापकों को रेगुलर करना चाहता है क्या? एक नहीं, इसकी अनेक अनियमितताएं हैं। सवेरे कुछ माननीय लोगों ने कहा। वहां महिला प्रोफेसर है, महिला प्रोफेसर के साथ जिस प्रकार के घटिया शब्द का प्रयोग किया, उसको एक तो हार्ट अटैक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हो गया। उसने कभी जिन्दगी में यह सुना ही नहीं होगा। जिसको कई प्रकर के अवार्ड मिले। एक नहीं, तीन-तीन महिलाओं के साथ। वह यहां आकर चांसलर साहब के साथ, स्वयं उपस्थित होकर, अपने दर्द को, बताकर गयी, उसके बाद भी, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं। मैं सोचता हूं, इसके बारे में आप निश्चित रूप से विचार कीजिये।

हायर एजुकेशन मिनिस्टर साहब, मेरा आपसे आग्रह है, हम लोगों ने भी बहुत बार कहा है कि इन प्राइवेट दुकानों को, यूनिवर्सिटीज को कन्ट्रोल करो। बहुत अधिक खुली हैं बहुत खुले, हमें कोई एतराज नहीं। हमारे कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों ने बहुत अच्छा काम किया है। पिलानी का आज भी नाम लेते हैं। आज भी वनस्थली का नाम लेते हैं। आज भी जो अच्छी संस्थाएं हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वह शिक्षा में हमारा योगदान करते हैं पर यह धन्ना सेठ, एक करोड़ रुपये जमा कर, जमीन लेकर, दुकान खोलकर सर्टिफिकेट बांटने का जो धन्धा करते हैं, इस पर लगाम चाहिये इसलिये नियामक आयोग लाइये। पहले भी बनाया था हमारे टाइम भी, इस पर कई बार मीटिंग हुई, कई बार कैबिनेट में हमने सहमति दे दी, पर भगवान जाने कहां से इन बड़े-बड़े लोगों का दबाव आता है कि फाइल फिर नीचे खिसक जाती है। फिर ऊपर लाते हैं, फिर नीचे खिसक जाती है। कई बार तो ऐसी स्थिति आई, दो दिन बाद ही घोषणा होने वाली है, पर यह तो बड़े दिग्गज लोग हैं। आजकल यह विश्वविद्यालय खोल रहे हैं न, यह शिक्षा के लिये नहीं आये हैं। इन्होंने कहा फैक्ट्री लगायें, 100 करोड़ लगाने के बाद भी, इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं। यहां तो एक करोड़ ही जमा कराना है। प्राइमरी स्कूल भी कभी ऐसी मान्यता नहीं लेता था, जिस प्रकार की घटिया स्थिति लाकर, हमने राजस्थान में शिक्षा का बंटाढार बिठाया। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं। सदन के सभी माननीय सदस्यों को कह रहा हूं। चाहे वह यूनिवर्सिटी मेरी हो, किसी की भी हो, इस पर कोई तो कन्ट्रोल करे।

एक, इन सारे प्राइवेट विश्वविद्यालयों का भी एग्जाम कराने की, कोई अपनी अलग से यूनिट बनाओ। आज सीबीएसई की मान्यता तो मिल सकती है, लेकिन सीबीएसई की परीक्षा तो वह ही करायेगा न। मैं आपको आज कह रहा हूं, यहां अधिकारी सुने तो। जितनी पीएचडी इन्होंने कराई है, प्राइवेट विश्वविद्यालय ने, राजस्थान के निर्माण से लेकर, मोहनसिंह जी मेहता के वाइस चासंलर से लेकर अब तक, जितनी यूनिवर्सिटी हैं, जितने डाक्टरेट नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बनाये, उतनी डाक्टरेट की डिग्री तो इन्होंने बांट दी। इस प्रकार की संस्था को भी अगर हम कन्ट्रोल नहीं करेंगे, तो मैं सोचता हूं कि हम इसको ठीक प्रकार से नहीं कर पायेंगे।

उच्च शिक्षा के अन्दर, अभी केन्द्र सरकार की नीति की घोषणा हुई है, उसका लाभ लेना चाहिये। उसमें कई प्रकार के फण्ड की व्यवस्था की है। कैसे एजुकेशन का मॉडल ठीक किया जा सकता है, उसका सहयोग लेकर अपन विश्वविद्यालय का ढांचा है, उसको ठीक कर सकते हैं।

एक, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के पेंशनर की बहुत भारी समस्या है। लगभग अब सभी विश्वविद्यालयों में आयेगी। कारण क्या है, पहले सरकार मैचिंग ग्रांट के रूप में देती थी, इसके कारण से पेंशन चुक जाती थी। अब धीरे-धीरे सरकार ने मैचिंग ग्रांट बन्द कर दिया, पैसा देती नहीं है। बार-बार, उनके फण्ड में से वह कितना पैसा उसमें से निकाल सकते हैं।

महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय में तो हालत यह है कि विश्वविद्यालय के 1212 लोग रिटायर हुए हैं। उसमें से 210 तो विधवा हैं, जो पेंशन का इन्तजार करती हैं और 16-16 महीने तक, पेंशन का पैसा नहीं मिलता है। आपने देखा होगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, 1200-1200 में, 450 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो रिटायर होकर, पेंशन का इन्तजार कर रहे हैं। मैं सोचता हूं, प्रयत्न किया। मैंने भी प्रयत्न किया था। यूआईटी के साथ, उनका एमओयू करके, कुछ जमीन निकालकर, उसको बेचकर, लम्पसम अमाउण्ट बना लें, ताकि कम से कम, ब्याज से उनकी समय पर पेंशन चुक जाए पर उसमें भी, कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। उसके कारण से ड्यू होता है। अभी आपने यहां सचिवालय स्तर पर कुछ व्यवस्था की है, कि यहां से सरकार उसको फण्ड दे देगी। एक बार उसके 6-7 महीने की पेंशन आप इसमें से चुका दोगे।

मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, इस प्रकार की हायर एजुकेशन और कुछ मैंने स्कूल एजुकेशन में आपको सुझाव दिये हैं, मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं, कम से कम भगवान के लिये ट्रान्सफर पालिसी बनी हुई है। मत सोचो कि मैं शिक्षा मंत्री क्या करूंगा। पचासों दूसरे काम हैं, मास्टर को इधर से उधर करना, क्या यही धन्धा है क्या? दुर्भाग्य है। अगर हम वास्तव में, शिक्षा को पवित्र बनाना चाहते हैं, शिक्षा को सम्मानजनक बनाना चाहते हैं, मास्टर हमारा थैला ढोकर, हमारे साथ चलता रहे, यह तो दुर्भाग्य का दिन होगा। हम लोगों ने भी प्रयत्न किया, पर इसको उस अन्जाम तक नहीं पहुंचा सके।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मेरी प्रार्थना है, मेरे सुझाव जो मैंने आपको दिये हैं, कृपा करके इसमें विचार करिये। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिये डीईओ, डिप्टी डायरेक्टर हैं, अच्छे लोग उन्हीं में से लो। टीचर्स के बाहर को मत लो कि टीचर का हक मरे, अच्छे लोगों को लो, जो 10-10, 15-15, 20-20 साल तक, इन पोस्टों पर रहकर, विभाग की व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से मजबूत कर सकें, तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: बुलाकी दास कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, "या देवीसर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:'', विद्या की दात्री मां शारदा के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात प्रारम्भ करता हूं।

आज राजस्थान विधान सभा के 28 माननीय सदस्यों ने 239 कटौती प्रस्तावों के माध्यम से अपनी बात यहां पर रखी। जो कटौती प्रस्ताव आये हैं, उनका तो मैं लिखित में जवाब दूंगा लेकिन मुख्य रूप से, आपको यह बताना चाहता हूं कि "विद्या ददाति विनयं, विद्या विनयेन शोभते।" विद्या से आदमी विनयशील बनता है। विनयशील व्यक्ति को विद्या शोभा देती है। विद्या ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। विद्या व्यक्ति को बनाने का माध्यम है।

सभापति महोदय, किसी भी विद्यार्थी से आप अगर किसी स्कूल में जाकर पूछें कि आप क्या बनना चाहते हो, तो विद्यार्थी सबसे पहले तो यह कहेगा कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, क्योंकि वह शिक्षक से प्रभावित होता है। किसी के घर में कोई डाक्टर होता है, स्टेथोस्कोप लगा हुआ देखता है, कहता है मैं डाक्टर बनूंगा। कई विद्यार्थी मिलिट्री के अफसर को देखते है, कहते हैं मैं मिलिट्री में जाऊंगा, वहां अफसर बनूंगा। एयरफोर्स का अफसर बनूंगा। कई बच्चे कहते हैं हम कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। कई खिलाड़ी होते हैं, वह कहते हैं हम अजहरूद्दीन बनेंगे, विराट कोहली बनेंगे, यानी हर व्यक्ति जीवन में, कुछ न कुछ बनना चाहता है। बनने का माध्यम केवल मात्र शिक्षा ही है। शिक्षा के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं बन सकता। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जो व्यक्ति को बनाने का एक मात्र साधन है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

मैं इस अवसर पर, खासतौर से यह कहना चाहता हूं, विद्या भी कोई सीख जाये, तो उसका अहंकार नहीं करना चाहिये। यह कहा गया है कि "विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति: परेषां परिपीडनाय। खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाया दानाय च रक्षणाय।" यानी, जिस व्यक्ति के पास विद्या है, वह दूसरों को सिखाने के काम में ले। जिसके पास धन है, वह परोपकार के कार्यों में खर्च करे। जिसके पास शक्ति है वह पीड़ित मानव की रक्षा करे। ऐसे व्यक्ति सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं और इसके विपरीत, जिसके पास विद्या है और वह कुतर्क करे, जिसके पास धन है, वह उसका अहंकार करे कि मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं, मैं धनपति हूं और जिसके पास शक्ति है वह दूसरों को परेशान करे, ऐसे व्यक्ति, माननीय सभापति महोदय, दुर्जन लोग कहलाते हैं।

विद्या की एक परम्परा है कि सरस्वती के भण्डार की बड़ी अपूरव बात ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़े और बिन खर्चे घटि जात। यदि विद्या को आप अपनी गांठ में ही रखो, सिखाओ नहीं तो धीरे-धीरे वह खतम हो जायेगी और विद्या को कोई चोर नहीं सकता। विद्या जो है वह व्यक्ति के पास रहती है, वह बहुत काम आती है। विद्या से ज्ञान प्राप्त होता है। आपको याद होगा कि मैंने बीच में एक बार एक यक्ष प्रश्न उठाया था, उसमें यह कहा था कि जल से पतला ज्ञान, ज्ञान जो है वह जल से भी पतला है और उसकी बारीकियों को कोई पा नहीं सकता इसलिए आज मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के ऊपर जो बहस हुई है इसके लिए मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने बहुत उपयोगी सुझाव दिये।

मैं प्रतिपक्ष के नेता की भी तारीफ करना चाहूंगा कि इन्होंने वास्तव में आज राजनीति से ऊपर उठकर निश्चित रूप से जो शिक्षा के बारे में सुझाव दिये हैं उनको निश्चित रूप से, माननीय सदस्यों को भी सीखना चाहिए पुराने लोगों से कि किस तरह से मांग की बहस के ऊपर बोला जाता है। केवल मात्र आलोचना के लिए आलोचना करना, केवल मात्र आपको बोलने के लिए बोलना, नॉन इश्यू को इश्यू बनाना, यह सदन में कम से कम अपने अनुभव का लाभ नये माननीय सदस्यों को देना चाहिए तो मैं तारीफ करूंगा कि आपने शिक्षा के सम्बन्ध में जो उपयोगी सुझाव दिये हैं, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है।

स्थानांतरण की नीति का प्रारूप मैंने बनाकर प्रोसेस में डाल दिया है, मैं यह समझता हूं कि शीघ्र ही वह सबके सामने आयेगा।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

माननीय सभापति महोदय, मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सबसे पहले, माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने यह देखा कि प्राइवेट स्कूलों के लोग बहुत ऊंचीऊंची फीस लेते हैं जिसके कारण साधारण परिवार के लोग जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं, जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, वे परिवार अपने बच्चों को उन ऊंचे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं। अत: हैल्दी कॉम्पिटिशन के लिए उन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल की शुरुआत की और आपको जानकार खुशी होगी कि राजस्थान में 558 विद्यालय खुल चुके हैं, 558 और उसमें 88 हजार विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है।

इसके पहले, वर्ष 2014-15 से पहले राजस्थान में 186 शैक्षिक ब्लाक, कुल मिलाकर 301 ब्लाक हैं, उनमें से उन 186 ब्लॉकों को शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ ब्लाक माना गया था और उनमें करीब 134 ब्लाकों में विवेकानंद मॉडल स्कूल खोले गये। इसके बाद वर्ष 2014-15 उन्हें बंद कर दिया गया। 52 ब्लाक आज भी ऐसे हैं जिनमें विवेकानंद मॉडल स्कूल के खुलने की आवश्यकता है। मैं तो यह चाहता हूं कि ऐसे मौके पर जैसे आज आपने इतने उपयोगी सुझाव दिये हैं, उसी तरीके से आप, कई मामलों में तो पक्ष और विपक्ष हों और जाकर हम यह कहें कि हमारे इन 52 ब्लाकों में जो शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं इनमें विवेकानंद मॉडल स्कूल केन्द्र सरकार हमको दे ताकि हम उन स्कूलों के माध्यम से अच्छी पढ़ाई, शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए ब्लाक हैं, उनमें शुरू कर सकें। मैं यह उम्मीद करता हूं कि ऐसे मामलों में जहां पूरे राजस्थान का हित हो, उसमें तो कम से कम हमको पक्ष और विपक्ष की दीवारों को तोड़कर एक होना चाहिए।

जहां तक शनिवार को नो बैग डे के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य और कई अन्य माननीय सदस्यों ने इसके बारे में बताया। शनिवार को जो नो बैग डे था, उसका काफी अच्छा प्रभाव है। एक दिन विज्ञान के बारे में, एक दिन खेलने के बारे में, एक दिन मान लीजिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में, इस तरह से इसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ा और विद्यार्थियों ने इसमें निश्चित रूप से रुचि दिखाई और इससे स्कूलों में एक्स्ट्रा-करिकुलर एक्टीविटीज, को करिकुलर एक्टीविटीज को प्रोत्साहन मिला और निश्चित रूप से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ये चीजें जरूरी थीं और इसके लिए मैं यह समझता हूं कि यह काम हमारे पूर्व

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

शिक्षा मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया और इससे स्कूलों में नामांकन भी बढ़ा है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विगत तीन वर्षों में 63120 नियुक्तियां दे दीं और 90 हजार पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू है। यह अपने आप में एक रिकार्ड है। 90 हजार और 63 हजार, यह 1 लाख 53 हजार व्यक्तियों को शिक्षा विभाग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध होना बहुत बड़ी बात है। मैंने एक शेर बचपन में सुना था-

"कहा था रोजगार मिलेगा हरेक घर के लिए

और कहां रोजगार मयस्सर नहीं शहर के लिए।

यहां दरख़्तों के साये में धूप पड़ती है,

चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए।"

आपके कार्यकाल में इतने लोगों को रोजगार नहीं मिला था और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि एक तरफ हमारी केन्द्रीय सरकार जो बनी है, उसने पहले यह कहा था कि हम दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, प्रतिवर्ष पन्द्रह लाख हरेक के खाते में डालेंगे, ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की जो स्थिति बनी थी उसको हल करने में राजस्थान की सरकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और खास तौर से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लागू करने के लिए कम्प्यूटर अनुदेशकों के 10453 पदों का सृजन पहली बार राजस्थान में हुआ है, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी का, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी समाज में यदि कोई परिवर्तन होता है, कोई क्रांति आती है, कोई नव जागरण होता है तो उसके पीछे केवल मात्र शिक्षा ही एक तरीके से है जो यह नव परिवर्तन, क्रांति और नव जागरण लाने का काम करती है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक अंधेरे से बाहर लेकर आती है। शिक्षा एक ऐसा चिराग है जो सामाजिक अंधकार को हटाकर व्यक्ति को रास्ता दिखाता है।

मैं आपको इस सम्बन्ध में यह बताना चाहूंगा कि हमारा विभाग भी इसी बात को लेकर गतिशील है और समय-समय पर हमको जो सुझाव प्राप्त होते हैं, उन सुझावों को हम ध्यान में रखते हुए और आम व्यक्तियों से भी जो राय मिलती है, उसको ध्यान में रखते हुए, माननीय सदस्यों की राय को ध्यान में रखते हुए विभाग को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि हमारा विभाग, शिक्षा विभाग जो है, जिस तरीके से शिक्षा का विस्तार हुआ है, राजस्थान में शिक्षा का विस्तार खूब हुआ है। आपने भी किया अपने कार्यकाल में, मैं ऐसा नहीं मानता कि आपने कुछ नहीं किया। जैसा कई लोगों की आदत है कि 70 साल, 70 साल तो कांग्रेस का शासन ही नहीं रहा। आप देखिये कि छह वर्ष तक अटल बिहारी वाजपेयीजी केन्द्र में रहे, आपके अभी साढ़े सात साल से नरेन्द्रजी हैं। उससे पहले चरणसिंहजी भी रहे, मोरारजी देसाई भी रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंहजी भी रहे, चन्द्रशेखरजी रहे, इन सबका कार्यकाल गिनो तो कांग्रेस लगभग 52-55 साल तक रही। 70 साल तक कांग्रेस का, यह जो जुमले आप गढ़-गढ़कर कहते हो तो इसका केलकुलेशन करके देख लो कि कांग्रेस कितने वर्ष रही और आप लोग कितने वर्ष रहे? लेकिन कुल मिलाकर जो अच्छे काम हुए हैं उनको बताना चाहिए कि यह अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है तो उसको भी बताना चाहिए कि यह ठीक नहीं हुआ है।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जो भी अच्छी राय देंगे, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी राय को मानकर अपने विभाग को बेहतर करने का पूरा प्रयास करूंगा।

अभी नयी शिक्षा नीति केन्द्र की सरकार ने लागू की है। उसमें पांच जमा तीन, जमा तीन, जमा चार तो यह तो वह ही पहले वाली बात हो गयी। पहले अपने हायर सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी के बाद में एक तरह से पी.यू.सी. का कोर्स करने से, प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स और उसके बाद में फिर थ्री-ईयर डिग्री कोर्स तो वह एक तरीके से पुरानी स्थिति में जाने की बात है लेकिन मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि इन सबके लिए बजट कहां है? बजट के प्रावधान के बिना नीति लागू नहीं हो सकती है।

मैं यह चाहूंगा कि केन्द्र सरकार नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत बजट दे और उसके बाद आगे मैं जब आऊंगा तो जोगेश्वरजी और अन्य लोगों की बातों का जिक्र करूंगा लेकिन मुख्य रूप से जो शैक्षणिक मॉडल केन्द्र ने दिया है उसके लिए धन के प्रावधान की आवश्यकता है। इसी प्रकार मैं विभाग की पिछले वर्षों की उपलब्धियों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। परफोरमेंस ग्रेड इन्डेक्स 2019-20 में देश भर में राजस्थान को वन प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ है। इंस्पायर अवार्ड में 2020-21 में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिट इण्डिया गतिविधि में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

सभापति महोदय, कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद स्माइल ई-कक्षा, आओ घर से सीखें जैसे नवाचारों का क्रियान्वयन किया गया है। बस्ते का बोझ कम करना, शिक्षा की पहुंच गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 24 हजार 965 पदोन्नतियां की गईं। 600 कृषि संकाय हमने मंजूर किये थे। 358 खोल दिये, 262 और खोलने बाकी हैं। वह भी हम खोलेंगे। अतिरिक्त संकाय 249 खोले गये। अतिरिक्त विषय 302 प्रारम्भ किये गये। 66 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं जिनके भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 292 विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया गया। 50 वर्ष बाद राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों का पुनर्लेखन किया गया है।

सभापति महोदय, अब मैं आपको 2013 से 18 और वर्तमान सरकार ने जो तीन वर्षों में काम किया है, उसका कम्पेरिजन करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। 5 वर्ष में पिछली सरकार ने एक भी प्राथमिक शाला राजस्थान में नहीं खोली। वर्तमान सरकार ने 80 प्राथमिक शालाएं अब तक खोल दीं। पूर्ववर्ती सरकार ने 178 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया। हमने अब तक तीन वर्षों में 877 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है। पिछले पांच वर्षों में 22 हजार 204 विद्यालयों को समन्वय के नाम पर बन्द कर दिया गया। हमने उनमें से 1200 स्कूलों को पुन: शुरू कर दिया और जहां आवश्यकता होगी, वहां पर उन स्कूलों को भी शुरू करेंगे। अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि दस स्कूल भी शुरू नहीं किये। अभी अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमने उनमें से 1200 स्कूल शुरू कर दिये।

ज्ञान संकल्प पोर्टल पर आपके कार्यकाल में 78 करोड़ रुपये आये। इन तीन वर्षों में 183 करोड़ रुपये हमें प्राप्त हुए। आईसीडी 828 लैब आपके कार्यकाल में हुए। हमने अब तक 1140 आईसीडी लैब बना दिये और 462 प्रक्रियाधीन हैं। आधारभूत ढांचा जिसमें कक्षा कक्ष, लैब वगैरह बनाते हैं, इन कार्यों में 1337 करोड़ रुपये आपने खर्च किये 5 वर्षों में। हम अब तक 2223 करोड़ रुपये इस कार्य के लिए व्यय कर चुके हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ये पैसे कहां से आये थे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, हमने नाबार्ड

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

से लोन लिया है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं, जिसमें भारत सरकार कुछ परसेंटेज देती है, कुछ हम देते हैं। केन्द्र के पास में भी राज्य सरकार का पैसा जाता है। हमारा टैक्स, यहां से एक्साइज वगैरह सब जाता है, इसमें से हमको बमुश्किल छोटा-मोटा हिस्सा मिलता है। नामांकन 81 लाख तक था 2018-19 तक, जो बढ़कर 97 लाख हो गया।

मैं अब माननीय सदस्यों को, जो उन्होंने डिबेट में बातें कहीं हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राम रखावे राजिया, राम रखावे राजिया नहीं है, मैंने बताया कि हमने उन्नति की है, अवनति नहीं की है। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ा है। विद्यालय को राजनीति का अखाड़ा हमने नहीं बनाया। आपने पाठ्यक्रम में क्या-क्या चेंज किये, मैं उसकी विगत में नहीं जाना चाहता लेकिन कुल मिलाकर, आप देखिये हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 3 हजार 820 सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में सीधा ही क्रमोन्नत किया है और यह अपने आप में सिद्ध करता है कि उन्होंने पक्ष और विपक्ष का कोई ध्यान नहीं दिया। सारे राजस्थान को समग्र इकाई मानकर यह सारा काम किया है।

इसी प्रकार आपने यह बताया कि महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल तो खोल दिये, अध्यापक कहां से आयेंगे। 10 हजार अध्यापक इंग्लिश मीडियम के सलेक्ट होंगे। यह भी बजट में घोषणा की है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए अलग से अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी, उनका सलेक्शन किया जायेगा।

सभापति महोदय, इस वर्ष 200 करोड़ की लागत से लगभग 3800 से अधिक कक्षा कक्षों का निर्माण किया जायेगा। आपने महाराणा प्रतापजी का नाम लिया। महाराणा प्रतापजी इतने शूरवीर थे कि 'कोनी कोरो नाम रेत रो हल्दीघाटी, अठै उग्यो इतिहास पूजी जै इणरी माटी' आप किसी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर रखते हो, यह उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि मैं और हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, महाराणा प्रतापजी का पूर्ण सम्मान करते हैं।

आपने रीट के बारे में विस्तार से बताया। एक आदमी कोई किसी में आ जाये तो पूरा संस्थान बदनाम नहीं होता। मान लीजिए आपके भी एक व्यक्ति कोई आरएसएस का पकड़ा गया तो क्या सारी आरएसएस खराब हो जायेगी? ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति खराब है, उसको प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है और उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

जहां तक सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षा से ही घर रोशन होते हैं, मैं सौ परसेंट इत्तफाक रखता हूं। कुल मिलाकर उन्होंने बाल सभा, स्माइल, सोशल मीडिया के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं, उनको हम समय-समय पर लागू करेंगे। कुल मिलाकर राजस्थान में 18 से लेकर 19 परसेंट तक बजट का पैसा खर्च किया जाता है। इसके लिए तो मैं समझता हूं कि आपको भी गौरव होना चाहिए। बाकी यूपी में 13 परसेंट, एमपी में 17 परसेंट, कर्नाटक में 13 परसेंट, गुजरात में 14 परसेंट, गुजरात को मॉडल बताते हैं लेकिन शिक्षा के ऊपर मात्र 14 परसेंट पैसा खर्च किया जा रहा है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान में शिक्षा के ऊपर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है शुरू से ही और माननीय मुख्य मंत्रीजी का तो दो बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान है। एक तो शिक्षा और दूसरा चिकित्सा। हमारा मानवीय संसाधन मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा और हम निरोग रहेंगे तो प्रदेश मजबूत होगा इसलिए निरोगी राजस्थान और मानवीय संसाधन का विकास, इन दो नारों के साथ राजस्थान आगे बढ़ रहा है।

जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थानी भाषा के बारे में काफी कहा। मं मारवाड़ी में ही बोलनो चाहूं क्योंकि थे भी मारवाड़ी में बोल्या। देखो, ऊंट शब्द है नी, वेरा 200 पर्यायवाची शब्द हैं और मारवाड़ी राजस्थानी भाषा एड़ी भाषा है, जिके में राम भगवान नहीं, एक राम नाम रो लड़को है, वै ने हिन्दी में कहूं, राम एक अच्छा लड़का है। अंग्रेजी में क्या कहूं? Ram is a good boy, पण राजस्थानी में अरे रामूड़ा आज फुटबाल खेलण न को चालै नीं, अरे रामूड़ा, दूध लेर आ। अरे रामसा आज डील ठीक कोनी। ऐ म्हारा रामजी है, आ बात कोन कह सके जोगेश्वरजी, आप राजस्थानी रा विद्वान हो। आ पत्नी कैवे। पत्नी रामूड़ा, राम सा, को कैनी, रामल्या को कैनी। ए म्हारां रामजी है तो विश्व में एड़ी कोई भाषा नहीं है, जिकी प्रथम परसन न, पहले व्यक्ति न सम्बन्ध रे आधार माथे पुकार सके, पण फिर कहेवतो फिर लाज आ रही है तो आपां सब लोग क्यूं नी एक होर प्रधान मंत्रीजी कन चालां। म्हां अठै पूरी विधान सभा सर्वसम्मति सूं प्रस्ताव पारित कर दियो और बैने आज तक संविधान री आठवीं अनुसूची में सम्मिलित क्यूं करियो कोनी। आपा सब जावें तो वानें करनो पड़सी, मान्यता देनी पड़सी और मान्यता दे देस्यां तो, जीकी नई शिक्षा नीति है, तो मायड़ भाषा में...

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप अठै कर लो, दिल्ली की जिम्मेदारी म्हांकी है।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): हां, प्रतिपक्ष रा नेता और सब लोग मिल चालौ, म्हें चालन रा तैयार हैं। हां, सब लोग चाल स्यां और चालर राजस्थानी ने संविधान री आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कर देस्यां हम निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत राजस्थानी भाषा में प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं। पर बात यह है...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज अपना उत्तर पूरा करें। कोई बीच में इन्टरवीन नहीं करेगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मान्यता दिलाने के लिये अपन सब लोगों को एक होना पड़ेगा। ओसियां से आने वाली माननीय सदस्या ने सर्वधर्म समभाव, महिला शिक्षा के सशक्तीकरण के साथ-साथ आपको कहना चाहूंगा कि हमारे जो शारीरिक शिक्षक हैं, उनको ट्रेण्ड करके जूडो, कराटे, योग शिक्षा देकर उनको ऐसा ट्रेण्ड करवाएंगे ताकि वह हमारी बेटियों को सशक्त कर सकें और उनको हर तरीके से शारीरिक रूप से, शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाएं ताकि वह किसी भी मोर्चे पर धोखा नहीं खा सकें।

जहां तक फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थानी भाषा के बारे में कहा, उसका उत्तर मैंने दे दिया है। कांग्रेस ने शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं किया, शिक्षा का राजनीतिकरण आप कर रहे हो।

सी.बी.एस.ई. का पाठ्यक्रम चालू कर दिया, इसके बावजूद भी अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्या ने किताबों को आगे करके कहा, किताबें आप पुरानी पढ़ो, उन पुरानी किताबों को पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुलेंगी कि आपने क्या-क्या किया था। हम तो पाठ्यक्रम में कभी भी दखल देते नहीं हैं। विषय विशेषज्ञ जो पाठ्यक्रम बना देते हैं, उन पाठ्यक्रमों को लागू कर देते हैं लेकिन आप तो आते ही कमेटियां बनाते हो, कमेटियां बनाकर उस पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाना चाहिए, उसमें इंटरफियरेंस करते हो, ऐसा हम नहीं करते।

विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने शिक्षा में नवाचार वगैरह का जो सुझाव दिया, उसको हम निश्चित रूप से आगे करेंगे।

जोधपुर, सूरसागर से आने वाली माननीय सदस्या ने कई स्कूलों के लिये जमीन के अभाव की बात कही। यह तो बहुत पुराने समय से मांग आ

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

रही है। वहां पर आप नई जमीन दे दोगे तो हम समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भवनों को बनाने का प्रयत्न करेंगे। कुछ जगह आपने यह कहा था कि छह बच्चे हैं और आठ मास्टर हैं। हमने स्टाफिंग पैटर्न लागू कर दिया है। प्रारम्भिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न लागू कर दिया है और बहुत शीघ्र विधान सभा सत्र के बाद हम माध्यमिक शिक्षा में भी स्टाफिंग पैटर्न लागू कर देंगे और जहां बच्चे अधिक हैं, वहां पर मास्टर भेजेंगे। जहां मास्टर अधिक हैं, उन मास्टरों को वहां पर से सरप्लस करके दूसरी जगह भेजेंगे। जहां बच्चे अधिक हैं, मास्टर कम हैं, वहां पर मास्टरों को भेजेंगे। स्टाफिंग पैटर्न का मतलब यही समानीकरण है। यह सब काम हम करेंगे।

दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने गुणात्मक सुधार के बारे में बातें कहीं और पांच हजार की आबादी पर महात्मा गांधी स्कूल खोलने की बात कही। यह घोषणा तो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी कर चुके हैं। इस साल हम एक हजार महात्मा गांधी स्कूल और एक हजार पूर्व प्राथमिक शालाओं में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने जा रहे हैं। उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में यह काम तेजी से आगे बढ़ेगा।

श्रीडूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केन्द्र शुरू करने की बात कही। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आटोनोमस बॉडी है। आपकी मांग वहां पर भिजवा देंगे। यदि वह उनके मैरिट के आधार पर होगा तो केन्द्र खुल जाएगा, नहीं तो नहीं खुल पाएगा।

जहां तक अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्या ने और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने यह कहा कि कुछ शिक्षक, जो हमारी बच्चियों का एक्सप्लोयटेशन करते हैं, उसके बारे में सरकार को सख्त होना चाहिए। अभी हाल ही में हमारे डायरेक्टर, सैकण्डरी एजुकेशन ने विस्तार से इस बारे में निर्देश जारी किये हैं। उस निर्देश में मैंने एक बात और जोड़ी है

'मातृवत् परद्रव्येक लोपरवत्'

परायी स्त्री को मां की तरह समझो और पराये धन को चोरे हुए धन के बराबर समझो। ऐसा हमारे शिक्षकों को हम सिखा रहे हैं और इस शिक्षा में जो नहीं आएंगे, निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है। सरकार ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं, जो हमारी बच्चियों को मां-बहन-बेटी की तरह नहीं समझते हैं। वे गुरु हैं बच्चों के, वे अभिभावक हैं और गुरु के लिये तो कहा गया है-

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

'गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णु, गुरू देवो महेश्वर:,

गुरु साक्षात् परब्रह्म् तस्मै श्रीगुरुवे नम:'।

इसी तरह-

'गुरु गोविन्द दोनों खड़े, काके लागूं पांय,

बलिहारी गुरु आपकी गोविन्द दियो बताय।'

जिसको इतना महान बताया गया है और वह ऐसा कृत्य करता है तो ऐसे व्यक्ति को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्रामीण क्षेत्र में भामाशाहों के द्वारा स्कूलों के विकास की चर्चा की और गरीबों की पढ़ाई में महात्मा गांधी शालाओं के योगदान का जिक्र किया, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात की। कई सारे माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि हमारे यहां प्राथमिक स्कूल खुलना चाहिए, हमारे यहां प्राथमिक स्कूल से उच्च प्राथमिक स्कूल बननी चाहिए, हमारे यहां उच्च प्राथमिक स्कूल से सैकण्डरी स्कूल बननी चाहिए। हायर सैकण्डरी तो सबकी बन गयी। इन प्रस्तावों में, जो हमारे निर्धारित मानदण्ड हैं, उसमें जो खरे उतरेंगे, उनको हमारे पास जितनी संख्या में स्कूल मंजूर हुए हैं गुणावगुण के आधार पर उनको क्रमोन्नत करने का प्रयास करूंगा।

मुझे बहुत सुखद लगा कि घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य ने 'जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम्' कहा। आदिवासी इलाके से चुनकर आने वाले माननीय सदस्य ने संस्कृत शिक्षा के बारे में कहा। संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत से ही भारत की पहचान है। हमारे वेद से, आयुर्वेद से और संस्कृत से पूरी दुनिया में पहचान है। उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया और संस्कृत की संस्थाओं के बारे में जो उन्होंने सुझाव दिये हैं, मैं उनको निश्चित रूप से क्रियान्वित करूंगा।

डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विद्यालयों को क्रमोन्नत करने, स्कूलों में पानी, टॉयलेट फैसेलिटीज की व्यवस्था करने के बारे में जो सुझाव दिये हैं, मैं उनको यथासमय ध्यान रखकर काम करूंगा।

सागवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अध्यापकों के रिक्त पदों

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

को भरने के लिये कहा है, तो उनको भी मैं आश्वासन देता हूं कि मैं इस काम को भी करूंगा। (व्यवधान) अब दो-तीन ही रहे हैं, ज्यादा नहीं हैं।

बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात की। वह हमारे क्राइटेरिया में फिट होंगे तो उनका काम भी करने का प्रयास करूंगा।

बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मोटिवेशनल क्लासेज लगाने का सुझाव दिया, यह उपयोगी सुझाव है। मैं चाहूंगा कि विषय विशेषज्ञ और हमारे पुराने जो टीचर्स हैं, वे मोटिवेशनल क्लासेज को लगाएं।

नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने नई शिक्षा नीति को मायड़ भाषा में देने की बात की, उसका मैंने पूरा जवाब दे दिया है और मैं समझता हूं कि जब तक राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक यह काम अधूरा रहेगा।

भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने शैक्षणिक कैलेण्डर नियमित करने की बात कही। कोविड पीरियड के कारण जो थोड़ा बहुत काम रह गया, उसको आने वाले समय में हम ठीक करेंगे। मैं समझता हूं कोविड जा रहा है और शैक्षणिक कैलेण्डर का अक्षरश: पालन कराया जाएगा।

रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य और चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने स्कूलों में नयापन लाने की बात कही। शैक्षिक नवाचार हम समय-समय पर जो करते हैं, उससे नयापन लाने का प्रयत्न करते हैं।

इसी प्रकार मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ अध्यापक डाक लेने गये हैं तो उसके लिये मैं निर्देश जारी कर दूंगा, डाक लेने-देने के लिये कोई अध्यापक नहीं जाएगा।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने नये विषयों को खोलने की बात की। इत्तेफाक से अभी इस बजट में नये विषयों के बारे में कोई घोषणा आयी नहीं है। मैं सदन की भावना को माननीय मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचाऊंगा और नये विषय मिलेंगे तो नये विषय गुणावगुण के आधार पर खोले जाएंगे।

प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने खास तौर पर संस्था प्रधानों के चयन के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी के चयन के बारे में कहा। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि अभी मैंने इस विभाग को कुछ महीने पहले ही सम्भाला है, जहां तक मेरी जानकारी है, 50 प्रतिशत का प्रमोशन और 50 प्रतिशत को आर.पी.एस.सी. के माध्यम से लेना शुरू कर दिया है। (व्यवधान) नहीं किया।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

अभी तक नहीं किया है। प्रस्ताव हैं तो उसको मैं मैरिट के आधार पर दिखवा लूंगा। जहां तक आपने स्थानान्तरण नीति का बताया। स्थानान्तरण नीति का प्रारूप बनाकर दे दिया, वह प्रक्रियाधीन है।

आपने व्याख्याताओं के पदों के बारे में, दागी अध्यापकों के बारे में जो बातें कहीं, उसका भी मैं उत्तर दे चुका हूं कि ऐसे अध्यापकों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

निरीक्षण की जो बात कही, वह वास्तव में बहुत मौजूं है। मुझे याद है कि मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ता था तो हमारे यहां इंस्पेक्टर आफ स्कूल का दौरा होने वाला था। स्कूल की पुताई हुई। फर्नीचर वगैरह जो खराब थे, वे ठीक हुए। अब वैसे निरीक्षण हो नहीं रहे हैं। अगर निरीक्षण स्कूलों के होंगे तो निश्चित रूप से वहां अध्यापक भी सावधान रहेंगे। विद्यार्थी भी सावधानी से पढ़ेगे। इन सब चीजों से मैं समझता हूं कि अच्छा काम होगा।

मुझे बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि असेम्बली चल रही है, वार्षिकोत्सव का समय आप बढ़ा दीजिये। मैं यह घोषणा करता हूं कि वार्षिकोत्सव का समय 26 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।

अब मैं प्रमुख घोषणाएं, जो बजट में हुई हैं, वह मांग के वक्त में मैं बताना चाहूंगा। राज्य के समस्त 3820 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बजट में आ गयी हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): कुछ चीजें बजट में नहीं हैं, वह इसमें आयेंगी।

श्री सभापति: कृपया शान्त रहें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): विद्यालय विहीन ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता से प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। रेगिस्तानी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और जोधपुर में प्राथमिक शिक्षा के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए नियमों एवं मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुए प्रथम चरण में 200 प्राथमिक स्कूल खोले जायेंगे।

ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही यथा आवश्यकता एवं मानकों के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

किया जायेगा। बालिकाओं को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने एवं ड्राप आउट कम करने की दृष्टि से राज्य में संचालित समस्त 379 बालिका माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के 1846 व प्राथमिक स्तर के 115 बालिका विद्यालयों को वरीयता से चरणबद्ध रूप में क्रमोन्नत किया जायेगा।

राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं हेतु 3800 से अधिक कक्षा कक्षों, लेबोरेट्री, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, नवीन भवन एवं वृहत मरम्मत आदि के कार्य करवाये जायेंगे जिन पर लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी।

राजा रामदेव पोद्दार रेजिडेंशियल स्कूल आफ एक्सीलेंस, इसके ऊपर 100 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

कोरोना के कारण लर्निंग गैप्स की भरपाई के लिये 3 माह की अवधि के लिये ब्रिज कोर्स चलाये जायेंगे। इनके लिये 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में 5 हजार से अधिक की आबादी वाले जो गांव बाकी रह गये हैं 558 के अलावा, उनमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जायेंगे। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए आगामी वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 1-1 हजार अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय खोले जायेगे। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का पृथक् से कैडर बनाया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इनको तो मुख्य मंत्री जी बोल गये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आप भी हैल्थ मिनिस्टर थे। तब आपने हैल्थ से सम्बन्धित मांगों को इसी सदन में दिया था और हमने सुना था तब आपने घोषणाएं की थीं। आपको पता है कि परम्परा है वही शिक्षा की है, घोषणाएं मांग पारित होने से पहले सदन को बताई जाती हैं।

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): एक हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक बाल वाटिकायें प्रारम्भ की जायेंगी।

शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन कराया जायेगा तथा राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना जायेगी, जिस पर 10 करोड़ की राशि खर्च की जायेगी।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

प्रदेश में भारत स्काउट एवं गाइड गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहट (पाली) में किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इन सभी घोषणाओं की क्रियान्विति के लिये विभागीय स्तर पर कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अन्त में, मैं, माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये संकल्पबद्ध होकर काम करेगा। मैं, विवेकानन्द के शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि हमारा लक्ष्य है, Awake, arise and stop not till the goal is reached. उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो।

हमारा लक्ष्य है राजस्थान को शत-प्रतिशत साक्षर बनाना। राजस्थान को आर्थिक रूप से और मानवीय संसाधनों की दृष्टि से मजबूत करना। इसके लिये हम कृत संकल्पित होकर काम करते रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति का प्रस्ताव जो मैंने प्रस्तुत किया है, उसको कृपा करके पारित किया जाये।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र यादव।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, वैसे तो आज हमारे इतने सीनियर कल्ला साहब और प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द जी ने बहुत लम्बा भाषण दिया है।

मैं उच्च शिक्षा के ऊपर, जो मांग संख्या 24 में हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव मुझे दिये हैं, जो बातें कही हैं, उनके लिये मैं कटिबद्ध हूं कि उन बहुमूल्य सुझावों को अपने विभाग में लागू करूं।

उच्च शिक्षा में माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेष ध्यान युवा पीढ़ी और बालिकाओं के लिये रहा है। उन्होंने लगातार पिछले 3 सालों में 123 महाविद्यालय खोले और उसमें भी बालिकाओं के यहां विद्यालय ज्यादा खोले हैं। जो 123 राजकीय महाविद्यालय खोले हैं, उनमें बालिका शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर रहा है। 2022-23 में 56 राजकीय महाविद्यालय खोले जिसमें से 42 कन्या महाविद्यालय हैं।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और यहां सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा अब तक कुल 179 महाविद्यालय खोले गये हैं जिनमें से 76 कन्या महाविद्यालय हैं, जबकि पिछली सरकार द्वारा अपने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल 81 महाविद्यालय खोले गये, जिनमें से केवल 7 कन्या महाविद्यालय थे। जो 81 खोले गये उनमें से भी 21 के लिये कोई बजट प्रावधान नहीं था।

जिस प्रकार से किसानों के 50 हजार तक के ऋण माफ करने का वादा किया जिसके लगभग 6 हजार करोड़ रुपये हमारी सरकार ने भुगतान किये। पीडब्ल्यूडी में बिना बजट के काम दिये गये। उन सारी चीजों को देखते हुए यहां भी 21 महाविद्यालयों की बिल्डिंग्स का लगभग 150 करोड़ रुपया हमारी सरकार आने के बाद खर्च हुआ।

सभापति महोदय, राज्य सरकार उच्च शिक्षा को लेकर मुख्यत: 5 बिन्दुओं शिक्षा की गुणवत्ता, प्रभावी और सुदृढ़ शिक्षण सेवा, शिक्षा तक सबकी पहुंच, संस्थाओं में संसाधन व्यवस्था, विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पर फोकस्ड है।

सभापति महोदय, सभी सदस्य क्वालिटी तथा दूसरी चीजों के लिये बार-बार कह रहे थे, उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। हमारी सरकार द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों में महाविद्यालय खोलने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किये जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आगामी वर्षों में सकल नामांकन अनुपात की दृष्टि से देखने को मिलेगा। हम शीघ्र ही नेशनल एजुकेशन पालिसी के 50 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

सभापति महोदय, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक राज्य के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 26 नवीन विषय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 40 नवीन विषय खोले गये।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022-23 में राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 4 संकाय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 1 विषय खोले जाने की घोषणा की गयी। जिसके अतिरिक्त 25 राजकीय कन्या महाविद्यालयों में नवीन संकाय खोले जाने की घोषणा की गयी।

सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि जहां उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, 11वीं एवं 12वीं में 500 से अधिक

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

छात्राएं अध्ययनरत होंगी, वहां बजट घोषणा 2021-22 की पालना में प्राथमिकता के आधार पर महाविद्यालय खोले जायेंगे। साथ ही जिन उप खण्ड मुख्यालयों पर महाविद्यालय नहीं है, वहां पर भी प्राथमिकता के आधार पर महाविद्यालय खोले जायेंगे। वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक राज्य में 18 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। इस वर्ष की बजट घोषणा में कुल 6 राजकीय महाविद्यालय, 4 कन्या, 2 सह शिक्षा को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने की घोषणा की गयी। गत सरकार द्वारा अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल में मात्र 24 महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया था। वर्ष 2019-20 में और 2021-22 तक राज्य के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में 27 नवीन संकाय खोले गये। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2022-23 में भी 3 राजकीय महाविद्यालयों में नये विज्ञान संकाय तथा 1 राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय खोले जाने की घोषणा की गयी।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत से माननीय सदस्यों ने उच्च शिक्षा पर काफी कुछ सुझाव जो दिये हैं और जो शंकायें जाहिर की हैं, उन पर मैं निवेदन करना चाहूंगा। अजमेर से आने वाले पूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि बिल्डिंग नहीं हैं, हमने इस बजट से पहले जो 123 महाविद्यालयों की घोषणा की, उनमें 40 महाविद्यालय निर्माणाधीन हैं। 50 की राशि आबंटित हो गयी और उनका टेंडर प्रक्रिया में है। 8 महाविद्यालय दानदाताओं के द्वारा बनाये जा रहे हैं, 12 में अभी जमीन की दिक्कत है। वो बार-बार कह रहे थे कि राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, निश्चित तौर पर है, मगर हमारे पास कुल पद हैं 7729, इनमें से हमारे पास 6972 पद राजकीय महाविद्यालय के और राजकीय महाविद्यालय सोसायटी के अधिकृत 757 हैं। इनमें नियमित तौर पर 4190 और विद्या सम्बल के तहत 1176 लोग काम कर रहे हैं। इसके सिवाय 918 पदों के अक्टूबर माह में एग्जाम हो चुके हैं, जल्दी ही वे पद भर जायेंगे। इसके सिवाय 1000 सहायक आचार्यों के पद और हो गये हैं जिसको वित्त विभाग ने 08.02.2022 को सहमति प्रदान कर दी है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह प्रदेश के महाविद्यालयों में अशैक्षणिक वर्ग के कार्मिक पदों की कुल स्वीकृत संख्या 4766 हैं, कार्यरत हैं 1973, रिक्त पद 2793 हैं। प्रयोगशाला सहायक 480 पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को अभ्यर्थना 30.12.2021 को भिजवायी जा चुकी है। शारीरिक शिक्षकों के 247 एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

रिक्त पद जिनकी चिन्ता नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे, 247 पदों की भर्ती हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति दिनांक 07.02.2022 को प्राप्त हो गयी है, शीघ्र ही वो भर्ती प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

कनिष्ठ लिपिक के 186 एवं शीघ्रलिपिक-स्टेनोग्राफर के 67 पदों पर भर्ती हेतु अर्थना प्रशासनिक सुधार ग्रुप-3 विभाग को भिजवायी जा चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य और पूर्व शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे कि हमने जोधपुर पर ज्यादा जोर दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि अजमेर में यूनिवर्सिटी किसने बनायी? 1965 में मेडिकल कालेज बना, वह किस सरकार ने बनाया? वहां पर आरपीएससी का दफ्तर अगर है या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आफिस है तो वह किसने बनाया? आप लगातार कई बार वहां से आ रहे हैं, केन्द्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपने अजमेर के लिए क्या किया? (व्यवधान)

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) विराजिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अगर एम्स वहां खुला है तो एम्स आप भी ला सकते थे, साढ़े सात साल से आपकी सरकार है। और भी बहुत सी चीजें केन्द्र सरकार से आ सकती थीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह परम्परा नहीं रही है।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): नैक के लिए चिन्ता जाहिर की है बहुत से साथियों ने ...(व्यवधान) जो सुझाव दिये हैं उनके बारे में मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि नैक के लिए अप्लाई पांच वर्ष से संचालित होने वाले महाविद्यालय ही कर सकते हैं। वर्ष 2015 तक संचालित 192 महाविद्यालयों में से 86 महाविद्यालयों का आज तक एक अथवा अधिक बार प्रत्यापन हो चुका है। आज की तारीख में 67 कालेज नैक के ग्रेडेड हैं जिनमें से 54 महाविद्यालयों को 'बी' एवं उच्चतर ग्रेड प्राप्त हुई है। हाल ही में 4 महाविद्यालयों को नैक ग्रेड प्राप्त करने के लिए री-अप्लाई कराया गया है। शेष पात्र महाविद्यालयों को भी हम इस वर्ष नैक हेतु अप्लाई करायेंगे। हमारे अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने,...

श्री सभापति: अजमेर को ही समर्पित कर दिया आपने तो सारा।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने आयुक्तालय में व्याख्याताओं के लिए कहा था। (व्यवधान) कार्य व्यवस्था में लगाने के बारे में तो मैं बताना चाहूंगा। गत सरकार की बात करें तो वर्ष 2018 की माह जुलाई में 60 शिक्षक व्यवस्थार्थ आयुक्तालय में थे। (व्यवधान) वर्तमान में मात्र 41 लोग कार्य व्यवस्था में हैं और वे भी क्योंकि पिछले डेढ़ साल से जो कार्य रुके हुए थे, कोरोना की वजह से उन सारे विभागीय कार्यों को करने की आवश्यकता को देखते हुए किया गया है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 2018 में सरकारी कालेजों में कुल बालिकाओं की संख्या 2,05,234 थी। वर्ष 2021-22 में वो बढ़कर कालेजों में 2,65,238 बच्चियां पढ़ रही हैं। हमारी सरकार के कार्यकाल में पढ़ने वाली बच्चियों की संख्या में तकरीबन 25 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य संयम लोढ़ाजी ने कहा था कि राजस्थान स्टेट एजुकेशन रेगुलेटरी अथोरिटी के गठन के लिए बनायी गयी रिव्यू समिति द्वारा प्रस्तुत विधेयक के प्रारूप पर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। विधि समीक्षा के लिए प्रक्रियाधीन है। विधि विभाग से समीक्षा उपरान्त मंत्रीमण्डल का अनुमोदन प्राप्त कर विधि विभाग के माध्यम से विधान सभा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(समय: 21.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं अन्त में आपके माध्यम से इस सदन से भी आग्रह करना चाहूंगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबकी चिन्ता होनी चाहिये। विशेषकर, उच्च शिक्षा में सकारात्मक विकास के लिये राजनीति से ऊपर उठकर सभी का सहयोग अपेक्षित है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा की गयी सभी घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिये हम कटिबद्ध हैं।

अत: मैं आग्रह करता हूं कि राज्य में उच्च शिक्षा के विकास की गंगा के निर्बाध प्रवाह हेतु सभी माननीय सदस्य सहयोग करें। अन्त में अपनी बात इन्हीं पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूं।

मांग संख्या 24 का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,05,84,73,34,000/- (चार सौ पांच अरब चौरासी करोड़ तिहत्तर लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 08 मार्च, 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.01 बजे मंगलवार, दिनांक 08 मार्च 2022 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

दीगोद में निर्माणाधीन नवनेरा बैराज

46. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कोटा की दीगोद तहसील के ग्राम ऐबरा में निर्माणाधीन नवनेरा बैराज का निर्माण कब तक पूर्ण होगा तथा उक्त इस पर कितनी राशि व्यय होगी? क्या उक्त बांध की पूरी भराव क्षमता पर पानी के भराव होने पर पानी के उपयोग की कोई योजना स्वीकृत नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परियोजना से कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां जिले को सिंचाई हेतु पानी देना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कुल कितने गांवों के कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी व उक्त जिलों को उक्त बैराज के निर्माण से क्या लाभ होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नवनेरा बैराज का निर्माण पूरा होने पर इसमें पूरी भराव क्षमता तक पानी वहां तब तक नहीं रोका जा सकता है जब तक कालीसिंध नदी पर नवीन उच्च स्तर के पुल का निर्माण नहीं होता है?

उत्तर

(1) कोटा जिले की दीगोद तहसील के ग्राम ऐबरा में नवनेरा बैराज निर्माणाधीन है, जो माह अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसकी पूर्ण भराव क्षमता 226.65 मिलियन घनमीटर है। परियोजना पर राशि रु. 1316.32 करोड़ खर्च होना प्रस्तावित है। नवनेरा बैराज की पूर्ण भराव क्षमता में से 54.00 मिलियन घन मीटर पानी पेयजल हेतु आरक्षित किया गया है तथा शेष पानी का उपयोग पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के घटक "नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा" लिंक के कार्य में किये जाने हेतु मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत प्रावधान है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में नवनेरा बैराज से कोटा, बून्दी, बारां व झालावाड़ जिले को सिंचाई हेतु पानी दिया जाना प्रस्तावित नहीं है। उक्त बैराज से कोटा व बून्दी जिलों के 749 ग्रामों एवं 06 कस्बों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए 54.00 मि.घ.मी. पानी पेयजल हेतु आरक्षित है तथा इस कार्य का निर्माण पूर्वी राजस्थान नहर के प्रमुख घटक के रूप में किया जा रहा है।

(जल संसाधन मंत्री)

(3) जी हां। कालीसिन्ध नदी पर बड़ौद के पास उच्च स्तर के पुल का निर्माण पूर्ण होने पर ही बैराज की पूर्ण भराव क्षमता तक जल भराव किया जा सकेगा। हाई लेवल पुल निर्माण का कार्य पी.डब्ल्यू.डी. से करवाये जाने हेतु विभाग द्वारा राशि हस्तान्तरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

बूंदी के सिंचित क्षेत्रों में खातेदारी अधिकार

52. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या उपनिवेशन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि असिंचित व सिंचित क्षेत्रों में तीन वर्ष पश्चात् गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने के प्रावधान की पालना नहीं करने वाले कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है? यदि हां, तो जिला बूंदी में विगत तीन वर्षों में कितने कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई व शेष के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

असिंचित व सिंचित क्षेत्रों में तीन वर्ष पश्चात् गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने के प्रावधान की पालना नहीं करने वाले कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही करने का संबंधित आबंटन नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

राजकीय अधिकारी/कार्मिक द्वारा उसको सौंपे गये दायित्वों का विधिवत निर्वहन नहीं करने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के प्रावधान हैं। गत तीन वर्षों में बूंदी जिले में तीन वर्ष से ज्यादा अवधि के गैर खातेदारी से खातेदारी देने योग्य प्रकरण अवशेष रहने के कारण तीन तहसीलदारान को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया है। इस तरह के प्रकरणों में अन्य कोई कार्मिक अपने दायित्व निर्वहन में दोषी पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

शाहपुरा बनेड़ा में सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण

60. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम बनाये जा रहे हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा में कितने गोदामों का निर्माण हो गया है व शेष ग्राम पंचायतों में उक्त समितियों में गोदाम कब तक बना दिए जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कितनी? उक्त पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम नहीं बनाये जा रहे हैं, अपितु प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर गोदाम बनाने की योजना संचालित की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा में 66 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनमें से 54 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्मित हैं, 4 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण कार्य निर्माणाधीन है, 7 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। शेष रही 1 समिति में भूमि विवाद होने के कारण गोदाम निर्माण नहीं हो सका है। समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर उक्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2020-21 में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने की घोषणा की गई है। भीलवाड़ा के शाहपुरा बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र में कुल 65 ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका क्षेत्र शाहपुरा सहित कुल 66 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इस कारण कोई भी ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पाली में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़े जाने की कार्ययोजना

61. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान किस-किस गांव एवं वार्ड में कब-कब कितने परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में निर्धारित मापदंड पूर्ण करने वाले परिवारों को भी उसमें जोड़ने की प्रक्रिया पर पूर्णतया रोक लगा रखी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान गांव एवं वार्ड में जोड़े गये 1821 परिवारों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। प्रदेश में चयनित लाभार्थियों की संख्या अधिक होने पर भारत सरकार को समय-समय पर सीलिंग सीमा में वृद्धि किये जाने हेतु पत्र लिखे गये। भारत सरकार द्वारा कवरेज मे कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद ही सम्भव होने के कारण वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानवा (नदबई) में मदरसा खोलने की योजना

62. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई के खानवा में अल्पसंख्यक समाज के लिए मदरसा खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मदरसा प्रबंधन समिति के द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन करने पर राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा नियमानुसार मदरसे का पंजीयन किया जाता है। राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसा स्कूल नहीं खोले जाते हैं। विधान सभा क्षेत्र नदबई के खानवा में अल्पसंख्यक समाज के लिए मदरसा स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चित्तौड़गढ़ के चिकित्सालयों में रिक्त पद

42. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ के जिला चिकित्सालय सहित अन्य श्रेणी के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व अन्य श्रेणी के कार्मिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने? चिकित्सालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में संचालित चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व अन्य श्रेणी के कार्मिकों के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-"अ" एवं ब पर संलग्न है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संविदा चिकित्सकों/स्टाफ के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) जी हां। विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को पी.जी. पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र भरने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी (दंत) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर यथासंभव भरने के प्रयास किये जाएंगे।

अराजपत्रित संवर्ग के पदोन्नति के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरने के प्रयास किये जाएंगे। सीधी भर्ती के रिक्त पदों को प्रक्रियाधीन भर्तियों/स्थानान्तरण/नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरने के प्रयास किये जाएंगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत् वर्तमान में सम्पूर्ण प्रदेश के लिए 8890 संविदा आधारित पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़ी में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना

43. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 11बी गुजरता है? उक्त राजमार्ग पर आये दिन गम्भीर दुर्घटनायें होती रहती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार दुर्घटनाग्रस्त गम्भीर मरीजों के तुरन्त उपचार हेतु बाड़ी उप जिला चिकित्सालय में ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। भारत सरकार की ट्रोमा गाइडलाइन के अनुसार घायल व्यक्तियों को किन्हीं भी परिस्थितियों में 50 किलोमीटर से अधिक परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़े, इसी क्रम में प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर ट्रोमा सेन्टर स्थापित किये जाने का प्रावधान है। बाड़ी से नजदीकी ट्रोमा सेन्टर धौलपुर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है तथा मनिया की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। अत: वर्तमान में बाड़ी में ट्रोमा सेन्टर खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के तुरन्त उपचार हेतु विभाग द्वारा राजकीय उप जिला चिकित्सालय बाड़ी में ट्रोमा स्टेबलाइजेशन यूनिट स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मेडिकल कालेजों को केन्द्र से प्राप्त सहायता

44. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकारी व राजमेस सोसाइटी के अन्तर्गत कितने मेडिकल कालेज संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मेडिकल कालेजों के लिए केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई है व दिसम्बर, 2021 तक कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त हेतु राज्य सरकार ने अब तक कितनी राशि उपलब्ध कराई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सरकारी क्षेत्र व राजमेस सोसायटी के अन्तर्गत कुल 15

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

मेडिकल कालेज संचालित हैं, जिनमें से 6 राजकीय क्षेत्र, 1 सोसायटी झालावाड़, 7 राजमेस तथा एक मेडिकल कालेज राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विद्यालय के संघटक महाविद्यालय के रूप में संचालित है।

इनके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा एम्स, जोधपुर तथा ई.एस.आई. सी. अलवर में संचालित है। सूची परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है।

(2) भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत विभिन्न मेडिकल कालेजों के लिए वर्ष 2011-12 से 2021-22 (दिसम्बर, 2021 तक) राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में अन्य सुविधाओं के लिए राशि 830.40 करोड़ तथा राजमेस के नवीन महाविद्यालय एवं उन्नयन हेतु राशि रुपये 963.00 करोड़ (कुल 1793.40 करोड़ रुपये) की राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई एवं राशि रुपये 813.68 करोड़ एवं 955.65 करोड़ रुपये (कुल 1769.33 करोड़ रुपये) की राशि व्यय हुई, जिसमें राज्यांश भी शामिल है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में उक्त अवधि में दिसम्बर, 2021 तक 737.16 करोड़ रुपये की राशि राज्यांश के रूप में उपलब्ध करवायी गयी है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मालपुरा में उन्नत बीजों का नि:शुल्क वितरण

45. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बजट घोषणा 2021-22 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में कितने कृषकों को नि:शुल्क बायोफर्टिलाइजर्स व बायो एजेन्ट्स, कम्पोस्ट यूनिट, माइक्रो न्यूट्रेन्ट्स किट, उन्नत किस्म के बीज, डिग्गी व फार्म पौण्ड, स्प्रिंकलर व मिनी स्प्रिंकलर उपलब्ध करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार कृषक कल्याण कोष से बजट उपलब्ध करवाकर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना संचालित की जा रही है। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में वर्ष 2021-22 में विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों अनुसार योजनावार लाभान्वित कृषकों का विवरण निम्नानुसार है:-

(कृषि मंत्री)

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभान्वित कृषक (संख्या में)
1	बायो फर्टिलाइजर्स एवं बायो एजेन्ट्स	409
2	सुपर कम्पोस्ट यूनिट	215
3	माइक्रो न्यूट्रेन्ट्स किट	1151
4	उन्नत किस्म के बीज	418
5	फार्म पौण्ड	274 प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है, जिसमें से 111 कृषकों को वित्तीय स्वीकृति जारी कर लाभान्वित किया गया है।
6	डिग्गी	0
7	स्प्रिंकलर	0
8	मिनी स्प्रिंकलर	0

उदयपुर में भवन रहित पशु चिकित्सालय

46. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला उदयपुर में कितने पशु चिकित्सालय एवं पशु स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? नाम, स्थान एवं उक्त में स्वीकृत पद, कार्यरत कर्मचारी व पदों का विवरण पशु चिकित्सालय एवं पशु स्वास्थ्य केन्द्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पशु चिकित्सालयों एवं पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पद एक वर्ष से भी अधिक समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले के पशु चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र जो भवनरहित संचालित हैं, वह कब से संचालित हैं? उक्त के भवन निर्माण के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में वर्तमान में कुल 442 पशु चिकित्सा संस्थाएं

(पशुपालन मंत्री)

(बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय-01, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय-36, पशु चिकित्सालय-77, पशु आरोग्य चल इकाइयां-03 तथा पशु चिकित्सा उपकेन्द्र-325) स्वीकृत हैं।

इन पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत एवं कार्यरत कर्मचारी व पदों का नामवार, संस्थावार एवं स्थानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उदयपुर जिले की पशु चिकित्सा संस्थाएं जहां स्वीकृत पद एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त हैं, का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उदयपुर जिले में वर्तमान में समस्त पशु चिकित्सा संस्थाएं पंचायत/दानदाताओं द्वारा प्रदत्त अथवा विभागीय भवन में संचालित की जा रही हैं।

उदयपुर जिले में 51 पशु चिकित्सा संस्थाओं के राजकीय भवन निर्माण हेतु राशि रु. 772.62 लाख की स्वीकृति जारी कर निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं।

राजकीय भवनविहीन पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण का कार्य विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार कराया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

उष्ट्रपालन को बढ़ावा देने की योजना

47. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार में प्रदेश के उष्ट्रपालकों को उष्ट्र प्रजनन पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना संचालित थी? यदि हां, तो उक्त योजना में कितने पशुपालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संचालित उक्त योजना को बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा उष्ट्रपालन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उष्ट्र प्रजनन योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किये गये पशुपालकों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ऊष्ट्र प्रजनन योजनान्तर्गत निम्नानुसार व्यय किया गया है।

वर्ष	**व्यय (लाखों में)**
2018-19	702.75
2019-20	797.95
2020-21	187.56
2021-22	20.62

(3) जी हां। उष्ट्रपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्‌वारा वर्ष में दो बार ऊष्ट्र कल्याण अभियान के रूप में ऊष्ट्र कल्याण शिविर एवं ऊष्ट्र पालकों की गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।

भारत सरकार द्‌वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत (60:40) ऊष्ट्रपालन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2021-22 में स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी (एस.एल.एस.सी.) द्‌वारा "ऊष्ट्र विकास योजना-2" के तहत कुल लागत राशि रु. 2365.00 लाख स्वीकृत की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर में शुद्‌ध पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना

48. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार का उद्देश्य जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है?

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी व झल्लारा पंचायत समिति में विगत दो वर्षों में कितने नये हैंडपंप लगाए गये व कितने हैंडपंप एवं जल कनेक्शन, जल सप्लाई की खराबी को ठीक करवाया गया तथा कितने अभावग्रस्त क्षेत्र में हैंडपंप लगवाए जाने प्रस्तावित हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की वर्णित पंचायत समितियों में हैण्डपम्प निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 28 नवीन हैण्डपम्पों के निर्माण कार्य हेतु जारी स्वीकृति के विरुद्ध, समस्त सफल 28 हैण्डपम्प स्थापित कर जल योजनाओं अंतर्गत चालू किये गये। ग्राम पंचायतवार स्थापित किये गये हैण्डपम्पों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 की अवधि में 43वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान अंतर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र की वर्णित पंचायत समितियों में 941 हैण्डपम्प तथा दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि में 44वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान अंतर्गत 1351 हैण्डपम्प, इस प्रकार कुल 2292 मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों को सुधारा गया। सुधारे गये मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

पंचायत समिति सराड़ा एवं सलूम्बर के ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 73 एवं 2020-21 में 63, इस प्रकार कुल 136 जल संबंध जारी किये गये हैं। जारी किये गये जल संबंधों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

पंचायत समिति सराड़ा, झल्लारा एवं सलूम्बर के ग्रामों में पेयजल आपूर्ति अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में क्रमश: 78 एवं 84, इस प्रकार कुल 162 लीकेजों की मरम्मत की सुधार कार्य किया गया। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति, झल्लारा, सराड़ा एवं सलूम्बर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 36 नवीन हैण्डपम्प निर्माण एवं स्थापना उपरांत चालू किये जा चुके हैं। स्थापित किये गये हैण्डपम्पों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त पंचायत समिति सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी एवं झल्लारा में क्रमश: 19, 12, 04 एवं 02, इस प्रकार कुल 37 नवीन हैण्डपम्पों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इन हैण्डपम्पों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कुल सम्मिलित 325 आबाद राजस्व ग्रामों में सतही/भू-जल आधारित विभिन्न जल योजनाओं से जल उपलब्धतानुसार निर्धारित मानक गुणवत्ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशानुसार उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों को घर-घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा वर्ष 2024 तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है । इसकी अनुपालना में उक्त विधान सभा क्षेत्र के 206 ग्रामों हेतु 66 जल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

उक्त स्वीकृति के विरुद्ध 70 ग्रामों हेतु 34 योजनाओं के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, 47 ग्रामों हेतु 17 योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा संबंधी तथा 89 ग्रामों हेतु 15 जल योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

सतही जल स्रोत यथा सोम-कमला-अम्बा बांध एवं जयसमन्द झील से उक्त विधान सभा क्षेत्र के क्रमश: 76 एवं 25 ग्राम तथा भू-जल स्रोतों से 18 ग्राम, इस प्रकार कुल 119 ग्रामों को उक्त मिशन के तहत लाभान्वित करने हेतु सलाहकार फर्म मैसर्स नेबकॉन्स, जयपुर द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। डी.पी.आर. बनने के उपरांत इसकी स्वीकृति जारी की जाकर इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

आमेर शहर में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत

49. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आमेर शहर की विभिन्न कालोनियों व ढ़ाणियों में जनवरी, 2020 से 02 जनवरी, 2022 तक हैण्डपम्प्स व नलकूप खराब होने के संबंध में कब-कब व किन-किन माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सतीश पूनियां)

(2) उक्त प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कब-कब किया गया तथा कितनी शिकायतों का निस्तारण किया जाना शेष है एवं क्यों? शिकायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त खराब अथवा बंद पड़े हैण्डपम्प व नलकूप को कब तक ठीक करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शहरी जल योजना, आमेर अंतर्गत आमेर शहर की विभिन्न कालोनियों एवं ढाणियों में पेयजल आपूर्ति हेतु स्थापित हैण्डपम्प एवं नलकूपों के खराब/बंद होने के संबंध में, दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 02 जनवरी, 2022 की अवधि में विभिन्न माध्यमों से क्रमश: 396 एवं 138 शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई।

उक्तानुसार प्राप्त शिकायतों संबंधी विवरण क्रमश: परिशिष्ट-'अ' एवं परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(2) आमेर शहर में वर्णित अवधि में खराब/बंद पाये गये हैण्डपम्प एवं नलकूपों को चालू करने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त उक्त समस्त शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त अवधि में प्राप्त किसी शिकायत का निस्तारण किया जाना वर्तमान में शेष नहीं रहा है।

उक्तानुसार प्राप्त शिकायत एवं इनके निस्तारण संबंधी वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' एवं परिशिष्ट-'ब' में निहित है।

(3) उपरोक्तानुसार। दिनांक 01 जनवरी, 2020 से दिनांक 02 जनवरी, 2022 की अवधि में प्राप्त शिकायतों अंतर्गत खराब/बंद समस्त हैण्डपम्प एवं नलकूपों को सुधारा जाकर चालू कर दिया गया है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' एवं परिशिष्ट-'ब' में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सूरजगढ़ में इंटीग्रेटेड वाटर सिक्योरिटी प्लान

50. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के किन-किन गांवों को इंटीग्रेटेड वाटर सिक्योरिटी प्लान के तहत चिन्हित किया गया है? उक्त की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं भू-जल विभाग में इंटीग्रेटेड वाटर सिक्योरिटी प्लान के नाम से कोई योजना प्रस्तावित नहीं होने के कारण विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्रामों को उक्त प्लान के तहत चिन्हित नहीं किया गया है।

नागौर में ऋण माफी योजनाओं में अनियमितताओं की शिकायतें

51. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ऋण वितरण एवं ऋण माफी योजनाओं में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में प्राप्त शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों के आधार पर की गई जांच का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जांचों के परिणाम के आधार पर अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध सारसण्डा, भगवानपुरा, मून्दीयाड, रायधनू, निम्बोला बिस्वा, देऊ एवं जसनगर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ऋण वितरण एवं ऋण माफी योजनाओं में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विगत दो वर्षों में प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त शिकायतों के आधार पर की गई जांच का शिकायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त जांचों के परिणाम के आधार पर अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आसीन्द में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवार

52. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में खाद्य सुरक्षा में पात्र परिवारों के राशन कार्ड में नवीन सदस्यों के नाम भी नही जोड़े जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। प्रदेश में चयनित लाभार्थियों की संख्या अधिक होने पर भारत सरकार को समय-समय पर सीलिंग सीमा में वृद्धि किये जाने हेतु पत्र लिखे गये। भारत सरकार द्वारा कवरेज मे कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद ही सम्भव होने के कारण वर्तमान में दिनांक 18.05.2020 से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों की आधार सीडिंग के दौरान विवाह, मृत्यु, स्थाई पलायन, दोहरे/तिहरे राशन कार्ड/यूनिटस एवं स्पष्ट अपात्र यथा सरकारी कर्मचारियों आदि का नाम चिन्हित प्रक्रिया व मापदण्डानुसार हटने पर सीलिंग में जगह होने पर वर्तमान में लम्बित आवेदनों में से 92,987 (बानवे हजार नौ सौ सत्तयासी) परिवारों के नाम जांच उपरांत जोड़े गये।

नोन एनएफएसए राशनकार्ड में नवीन सदस्यों के नाम जोड़े जा रहे हैं।

ब्यावर में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

53. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कितनी राशन की दुकानें किन-किन स्थानों पर संचालित हैं? संचालनकर्ता के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि परिवारों की संख्या में वृद्धि होने के कारण नई राशन की दुकानें खोला जाना आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर नवीन दुकानें खोला जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में राशन की 130 दुकानें संचालित हो रही हैं। संचालनकर्ता के नाम सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभागीय निर्देश दिनांक 07.04.2010 एवं 26.12.2019 द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित 500 राशनकार्डों अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित हैं।

विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में निम्नलिखित स्थानों पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोला जाना प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील
1	रूपारेल	बलाड	ब्यावर
2	बस्सी	किशनपुरा	ब्यावर
3	कुण्डाल	नाईकला	ब्यावर
4	केलावास	टाटगढ़	टाटगढ़

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीएसआर कोष की स्थापना

54. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में निगमन सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण द्वारा वर्तमान एवं विगत दो वर्षों में किन महत्वपूर्ण सामाजिक एवं संरचना परियोजनाओं को सामाजिक दायित्व निधियों के माध्यम से पूर्ण करवाया गया है एवं उक्त पर कितनी-कितनी धनराशि का व्यय हुआ है?

(2) बजट घोषणा के अनुपालन में निगमन सामाजिक दायित्व कोष की स्थापना किस तिथि को की गई? कोष के अंदर स्थापना से अब तक प्रति वर्ष कितना अभिदाय प्राप्त हुआ है तथा प्राप्त अभिदाय का उपयोग किस प्रकार किया गया है?

(3) क्या निगमित उपक्रम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र विशेष के सामाजिक विकास के लिए अपने सामाजिक दायित्व निधि का उपयोग किया गया है? प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयास एवं उसके परिणाम क्या रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण के औपचारिक पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण प्राधिकरण द्वारा किसी भी सामाजिक एवं संरचना परियोजनाओं को सामाजिक दायित्व निधियों के माध्यम से पूर्ण नहीं कराया गया है तथा किसी भी प्रकार की धनराशि का व्यय नहीं किया है।

(2) कारपोरेट सामाजिक दायित्व कोष की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई बजट घोषणा नहीं की गयी है। राजस्थान कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकरण की कार्यवाही प्रकियाधीन होने के कारण कोई अभिदाय प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नं. 06/2018 (परिशिष्ट-1) में यह स्पष्ट किया है कि कम्पनियां जिस क्षेत्र में संचालित हैं, उस क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सीएसआर गतिविधियों का संचालन करें।

राज्य सरकार द्वारा सीएसआर कम्पनियों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने हेतु सीएसआर वेब पोर्टल (www.csr.rajasthan.gov.in) विकसित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 में राजस्थान सीएसआर समिटों का आयोजन कर सीएसआर के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाली कम्पनियों तथा क्रियान्वयन एजेंसियों को सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निरंतर सीएसआर कम्पनियों के साथ विचार-विमर्श कर उन्हें सीएसआर गतिविधियों के संचालन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर में संचालित नवीन बसें

55. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला उदयपुर में विगत तीन वर्षों में कितनी बसें बंद की गईं व कितनी नई बसें प्रारम्भ की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उदयपुर जिले में विगत तीन वर्षों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बन्द की गई बसों की सूची परिशिष्ट "1" पर एवं प्रारम्भ की गई नई बसों की सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, परिवहन)

उदयपुर जिले में विगत तीन वर्षों में कुल 304 प्राईवेट बसें बंद की गईं व कुल 451 नई प्राइवेट बसें प्रारम्भ की गईं। इनका विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बस्सी में संचालित निगम की बसें

56. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के किस-किस ग्राम पंचायत मुख्यालय को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व ग्रामीण बस सेवा से जोड़ा हुआ है? ग्राम पंचायतों के नाम व संचालित बसों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र की शेष ग्राम पंचायतों तथा बड़े गांवों को निगम की बस सेवा से कब तक जोड़ दिया जावेगा?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने तथा किस-किस मार्ग पर निजी बसों को चलाने का परमिट दिया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा से जुड़ी ग्राम पंचायतों की सूची मय संचालित बसों की संख्या परिशिष्ट "।" पर संलग्न है।

(2) निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र की शेष ग्राम पंचायतों तथा बड़े गांवों को निगम की बस सेवा से जोड़ने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(3) बस्सी विधान सभा क्षेत्र के 10 मार्गों पर 167 निजी वाहनों को अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं। इनका विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रामगंज मण्डी के गांवों का विद्युतीकरण

57. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गांवों के विद्युतीकरण किये जाने के क्या मानदण्ड हैं? प्रदेश में कितने गांव विद्युतीकरण से वंचित हैं?

(श्री मदन दिलावर)

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में उक्त मानदण्डानुसार विद्युतीकरण हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई, कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है व शेष रहे गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश मे गांवों के विद्युतीकरण किये जाने के मापदण्ड की नई परिभाषा (2004-05) के अनुसार किसी गांव को विद्युतीकृत माना जाएगा यदि:-

1. दलित बस्तियों/पुरवों, जहां ये स्थित हैं, के साथ-साथ आबादी वाले इलाके में वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनों जैसी मूल सुविधाएं दी जा चुकी हों। (गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत के जरिए विद्युतीकरण हेतु वितरण ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं है)।

2. स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ केन्द्रों, डिस्पेंसरियों, सामुदायिक केन्द्रों इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थानों में बिजली पहुंचा दी गई हो।

3. गांव में कुल आवासों के कम से कम 10 प्रतिशत आवास विद्युतीकृत हों।

राज्य में 707 अविद्युतीकृत गांव में से 644 गांव 2011 की जनगणना के अनुसार गैर आबाद हैं व 63 गांव वर्तमान में गैर आबाद/वनक्षेत्र/डूब क्षेत्र/विस्थापित गांव है। योग्य गांवों में विद्युत की मांग उपलब्ध होने पर विद्युतीकृत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में 179 गांव हैं जिनमें से 174 गांवों का विद्युतीकरण विद्युत लाइनों से किया जा चुका है एवं शेष 5 गांव वन क्षेत्र में होने के कारण विद्युत विभाग द्वारा विद्युत तंत्र से विद्युतीकरण करना सम्भव नहीं है एवं इन गांवों में निम्नानुसार में निगम द्वारा जारी Off Grid सोलर सिस्टम से विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। विवरण निम्नुसार है:-

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

क्र.सं.	गांव का नाम	2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम कोड	परिवार की संख्या	विवरण
1	मन्दरगढ़	102140	199	18 आवेदक आफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर आधारित बिजली का उपयोग कर रहे हैं।
2	दामोदरपुरा	102142	43	0
3	केशवपुरा	102138	58	5 आवेदक आफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर आधारित बिजली का उपयोग कर रहे हैं।
4	अखावा	102104	50	50 आवेदक आफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर आधारित बिजली का उपयोग कर रहे हैं।
5	कोलीपुरा	102109	85	85 आवेदक आफ ग्रिड सोलर सिस्टम पर आधारित बिजली का उपयोग कर रहे हैं।

अधीक्षण अभियन्ता (टी.डब्ल्यू.) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर के आदेश क्रमांक 1804 दिनांक 05.01.2022 से मैसर्स गणेश इलेक्ट्रिकल जयपुर को मन्दरगढ़, दामोदरपुरा, केशवपुरा के शेष रहे Household का सर्वे करवाकर आफ ग्रिड सोलर सिस्टम से विद्युत आपूर्ति की जाने की कार्यवाही की जा रही है।

पुष्कर में भरी गईं वी.सी.आर.

58. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2018 के पश्चात् समस्त श्रेणियों

(श्री सुरेश सिंह रावत)

के बिलों में फिक्स चार्ज, नगरीय उपकर, फ्यूल चार्ज, अतिरिक्त चार्ज आदि में वृद्धि की गई है? यदि हां, तो 30 नवम्बर, 2018 तक उक्त सभी चार्ज की दरें क्या थीं व वर्तमान में क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में वर्ष 2019 से अब तक समस्त श्रेणियों में कितनी वी.सी.आर. भरी गई व इससे श्रेणीवार कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2019 से अब तक उक्त विधान सभा क्षेत्र में भरी गई वी.सी.आर. के उपभोक्ता के नाम, पते व वी.सी.आर. राशि एवं छूट राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिसम्बर-2018 के पश्चात् केवल एक बार फरवरी, 2020 में विद्युत दरों में वृद्धि की गई है। विद्युत दरों, फिक्स चार्ज में की गई बढ़ोतरी का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

फ्यूल सरचार्ज का निर्धारण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। दिसम्बर, 2018 से मार्च, 2021 के दौरान वसूले गये फ्यूल सरचार्ज का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त विद्युत बिलों में वसूल किये जाने वाले जल संरक्षण उपकर, नगरीय उपकर व इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की 30.11.2018 व उसके पश्चात् वर्तमान तक की प्रति यूनिट दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है जिनके लिये वसूल की जाने वाली प्रति यूनिट दरों का विवरण निम्नानुसार है-

1. विद्युत कर (बिलिंग माह जुलाई-2004 से प्रभावी)
   (अ) कृषि श्रेणी के अतिरिक्त - 0.40/- रु. प्रति यूनिट
   (ब) कृषि श्रेणी - 0.04/- रु. प्रति यूनिट
2. जल संरक्षण उपकर (बिलिंग माह सितम्बर-2009 से लागू)
   घरेलू एवं कृषि श्रेणी के अतिरिक्त सभी श्रेणी- 0.10/- रु. प्रति यूनिट
3. नगरीय उपकर (नगरीय क्षेत्र में बिलिंग माह मई-2010 से लागू)
   कृषि श्रेणी के अतिरिक्त सभी श्रेणी- 0.15/- रु. प्रति यूनिट
   (नगरीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं से 100 यूनिट/माह से अधिक उपभोग पर देय है।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

(2) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में वर्ष 2019 से समस्त श्रेणियों में भरी गई वी.सी.आर. एवं प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में वर्ष 2019 से भरी गई वी.सी.आर. के उपभोक्ता के नाम, पता व वी.सी.आर. राशि एवं छूट राशि का विवरण परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बिजली कम्पनियों का राजस्व घाटा

59. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश की बिजली कम्पनियों का कुल कितना राजस्व घाटा था और विगत तीन वर्षो में कितना हो गया है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वितरण कम्पनियों द्वारा विगत तीन वर्षो में घरेलू एवं व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं पर अलग-अलग तरह के सैस व सरचार्ज लगाकर राजस्व घाटे की भरपाई का प्रयास किया गया है? यदि हां, तो कब-कब, कितना-कितना सैस व सरचार्ज लगाया गया व उससे कितना राजस्व घाटा कम हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कोयला आधारित थर्मल इकाइयों में कोयला आपूर्ति के अभाव में उत्पादन बन्द हो गया था? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं?

(4) क्या सरकार थर्मल इकाइयों में कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन बन्द होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 में बिजली कम्पनियों का कुल राजस्व घाटे का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलबध है।

(2) राजस्थान इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी एक्ट-1962 के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना की अनुपालना में विद्युत कर, नगरीय उपकर एवं जल संरक्षण उपकर विद्युत उपभोक्ताओं से बिलों के माध्यम से संग्रहित कर राज्य

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

सरकार को सौंप दिया जाता है जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उक्त राशि का उपभोग वितरण कम्पनियों द्वारा नहीं किया जाता है।

इसके अतिरिक्त विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ रेगुलेशन की अनुपालना में विद्युत खरीद की निर्धारित दर एवं वास्तविक खरीद मूल्य में अन्तर की राशि को फ्यूल सरचार्ज के रूप में वसूल किये जाने का प्रावधान है। फ्यूल सरचार्ज का निर्धारित त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

उक्त सैस/सरचार्ज का विद्युत निगमों के घाटा भरपाई से कोई संबंध नहीं है।

(3) गत वर्ष 2021 के मानसूनी महीनों जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में अत्यधिक वर्षा के चलते कोयला खदानों से खनन कम हुआ, साथ ही गत वर्षों की तुलना में विद्युत की मांग में वृद्धि एवं निगम की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण कोयले की खपत की मात्रा जुलाई व अगस्त माह में अधिक रही। परिणामस्वरूप कोयला आपूर्ति बाधित हुई। सामान्य परिस्थितियों में कोल इंडिया से प्रतिदिन लगभग 11 कोल रैक की आपूर्ति हेतु अनुबंध है परन्तु वर्षा ऋतु के चलते कोल इंडिया की खदानों में पानी भर जाने के कारण कोयला आपूर्ति बाधित हुई। इस देशव्यापी कोयला संकट का सामना न केवल उत्पादन निगम विद्युतगृहों को अपितु देश के अन्य विद्युतगृहों को भी करना पड़ा जो कि अपरिहार्य था। इस कोयला संकट का प्रभाव निगम के विद्युतगृहों पर पड़ना भी स्वाभाविक था, जिसके कारण निगम के सूरतगढ़ तापीय विद्युतगृह, सूरतगढ़ सुपरक्रिटिकल तापीय परियोजना (इकाई 7) एवं कालीसिंध तापीय विद्युतगृह की इकाइयों से अलग-अलग समय पर विद्युत उत्पादन प्रभावित रहा।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के हस्तक्षेप के पश्चात् भी कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों एनसीएल एवं एसईसीएल से प्रतिदिन लगभग 7 कोल रैक की आपूर्ति की जा सकी। तथापि राज्य सरकार एवं विद्युत उत्पादन निगम द्वारा किये गये अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप कोल इण्डिया द्वारा अतिरिक्त कोयले का आबंटन किया गया है तथा कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगातार स्थिति का आंकलन करते हुए विद्युत गृहों में कोयले की आपूर्ति को बढ़ाने के लिये कोल इंडिया एवं रेलवे को दिशा-निर्देश जारी किये गये।

उक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

कंपनियों एसईसीएल एवं एनसीएल एवं छत्तीसगढ़ राज्य में निगम को आबंटित कोयला खदानों से कोयले की नियमित आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में कोयले की नियमित आपूर्ति हेतु राज्य सरकार एवं विद्युत उत्पादन निगम निरन्तर प्रयासरत है। उपरोक्त कारणों से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त कोयला संकट एक देशव्यापी समस्या रही जिसका सामना न केवल निगम के विद्युतगृहों को अपितु देश के अन्य विद्युतगृहों को भी करना पड़ा, जो कि अपरिहार्य था।

अत: उपरोक्त तथ्यों के अनुसार किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं होती है।

(4) उपरोक्तानुसार कोयला संकट एक देशव्यापी समस्या रही जिसका सामना न केवल निगम के विद्युतगृहों को अपितु देश के अन्य विद्युतगृहों को भी करना पड़ा, जो कि अपरिहार्य था। इस स्थिति से निपटने हेतु निगम द्वारा राज्य सरकार के साथ निरन्तर संयुक्त प्रयास किये गये, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में निगम की किसी भी इकाई में कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित नहीं है। उपरोक्त बिन्दु संख्या 3 के अनुसार किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं होती है। अतः इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करना अपेक्षित नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चूरू के आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पद

60. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने बजट 2021 में अजमेर, जोधपुर में राजकीय होम्योपैथी महाविद्यालय व सीकर में आयुष चिकित्सालय की घोषणा की थी? यदि हां, तो जनवरी, 2022 तक घोषणानुसार कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह सही है कि चूरू जिला मुख्यालय में स्वीकृत जिला आयुर्वेद औषधालय में बड़ी संख्या में चिकित्सकों व परिचारकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र चूरू के अन्तर्गत कितने आयुर्वेद औषधालय बिना भवन के संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(4) क्या यह सही है कि चूरू के उंटवालिया व सहनाली छोटी में आयुर्वेद औषधालय भवन बनने के पश्चात् भी सरकार द्वारा भवन में औषधालय संचालित नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय होम्योपैथी महाविद्यालय केकड़ी, अजमेर में राशि रुपये 900.00 लाख एवं होम्योपैथी महाविद्यालय, करवड़, जोधपुर हेतु राशि रुपये 900.00 लाख की लागत की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में क्रमशः राशि रुपये 50.00 लाख एवं 50.00 लाख, कुल राशि रुपये 100.00 लाख का बजट आबंटन किया गया है। राज्य सरकार से विश्वविद्यालय को आबंटित राशि रुपये 100.00 लाख का हस्तान्तरण निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत कार्यकारी एजेन्सी एन.एच.एम. जयपुर को हस्तान्तरित कर दिया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत राज्य वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2019-20 में एकीकृत आयुष चिकित्सालय सीकर के नवीन भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 450.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। उक्त कार्य में जनवरी, 2022 तक राशि 0.47 लाख का व्यय किया गया है।

(2) जीं नहीं। जिला मुख्यालय पर स्वीकृत राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, चूरू में चिकित्सक का एक भी पद रिक्त नहीं है। राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, चूरू में चिकित्सक एवं परिचारक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार हैः-

क.सं.	संवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	चिकित्साधिकारी	03	03	00
2	परिचारक	05	04	01

(3) विधान सभा क्षेत्र चूरू के अन्तर्गत संचालित कोई भी आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय बिना भवन के संचालित नहीं है। विधान सभा क्षेत्र चूरू के अन्तर्गत 25 चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं जिनमें से 23 विभागीय/दान में प्राप्त भवन में, 01 सी.एच.सी. में एवं 01 अन्य सरकारी भवन में संचालित है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(4) आयुर्वेद विभागान्तर्गत राजकीय आयुर्वेद औषधालय उंटवालिया दिनांक 25.08.2017 से नवीन निर्मित भवन संचालित है तथा सहनाली छोटी में आयुर्वेद विभाग का औषधालय स्वीकृत नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आयुष नर्सेज का कैडर रिव्यू की कार्ययोजना

61. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है आयुष नर्सेज कैडर रिव्यू के अभाव में जिस पद पर नियुक्त होते हैं उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आयुष नर्सेज के पदों हेतु कैडर रिव्यू की प्रक्रिया विगत चार वर्षों से लम्बित है? यदि हां, तो उक्त को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आयुष नर्सेज द्वारा ग्रामीण सेवा के कैडर को समाप्त किये जाने की मांग लगातार की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मांग पर विचार कर ग्रामीण सेवा का कैडर समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जीं नहीं। आयुष विभाग में नर्सिंग संवर्ग में कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है एवं समय-समय पर विभाग द्वारा नियमानुसार कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर से वरिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर, वरिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर से नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-।। एवं नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-।। से आयुर्वेद नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-। के पद पर पदोन्नति दी जाकर कार्मिक सेवानिवृत्त होते हैं।

(2) जी हां। नर्सिंग संगठनों से प्राप्त नवीन कैडर रिव्यू प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, जिस पर वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां। राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 2008 के निरसन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी)

कोटा नगर विकास न्यास के इंजीनियर की नियम विरुद्ध पदोन्नति

महोदय,

कोटा नगर विकास न्यास के इंजीनियर पर सरकार इतनी मेहरबान है कि एसीबी में मामला दर्ज होने के बावजूद उन्हें तीन बार पदोन्नति दे दी गई और अब उन्हें मुख्य अभियन्ता के पद पर लगाकर सरकार द्वारा उपकृत कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि यूआईटी के इंजीनियर श्री ओ.पी. वर्मा की पदोन्नति से एसीबी के अधिकारी भी हैरान हैं। जांच में दोषी पाये गये, चालान का निर्णय हो चुका, लेकिन सरकार की शिथिलता, लापरवाही एवं राजनीतिक संरक्षण के कारण लगातार प्रमोशन होते गए और श्री वर्मा को अब न्यास का मुख्य अभियन्ता बना दिया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एसीबी केस रहते पदोन्नति देकर सरकार दागी अफसर को उपकृत कर रही है।

महोदय, सरकार के नियम यह है कि एसीबी में केस या जांच लम्बित रहने पर पदोन्नति नहीं दी जाती है लेकिन आरोप प्रमाणित होने व अभियोजन स्वीकृति के बावजूद भी वर्मा को तीन प्रमोशन दिये जा चुके हैं। हास्यास्पद बात तो यह है कि 16 सितम्बर, 2016 को कार्मिक विभाग के उप शासन सचिव अवधेश सिंह के हस्ताक्षर से श्री वर्मा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी हुई थी। अब यही श्री अवधेश सिंह जी जो वर्तमान में नगरीय विकास विभाग में संयुक्त शासन सचिव तृतीय हैं, उन्ही के हस्ताक्षर से 29 अक्टूबर, 2021 को जारी आदेश में श्री वर्मा को चीफ इंजीनियर पद पर प्रमोट किया गया है। यही नहीं, सरकार के परिपत्र तो ऐसे भी जारी हुए हैं कि किसी के खिलाफ 16 सीसीए की चार्ज शीट हो तो उसे भी पदोन्नत नहीं किया जाए। फिर श्री वर्मा पर संगीन आरोप जिनके आधार पर सरकार ने अभियोजन की मंजूरी दी, बावजूद पदोन्नति देना सरकार की मेहरबानी नहीं तो और क्या है?

यह काफी लोक महत्व का मामला है इसलिए विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से कार्यवाही हेतु निवेदन कर रहा हूं।

श्री कालूराम (डग)

डग में अतिवृष्टि से किसानों की नष्ट हुई फसलों का मुआवजा

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में विगत 2021-22 में अतिवृष्टि होने की वजह से खरीफ की फसल, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मक्का व अन्य फसल खराब हो गई। किसानों को अभी तक मुआवजा व बीमा क्लेम की राशि नहीं मिली है। अतिवृष्टि होने के बाद पटवारी द्वारा गिरदावरी समय पर नहीं की गई व अगस्त माह में गिरदावरी पेश कर दी गई जबकि गिरदावरी रिपोर्ट 15 सितम्बर तक देनी रहती है। जिस समय गिरदावरी होनी थी, उस समय पटवारी हड़ताल पर थे। सितम्बर में लगातार बारिश होने की वजह से किसानों की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई, मगर पटवारियों के अभाव में मौके पर जाकर गिरदावरी नहीं की गई व तहसील से ही फसल खराबे के आंकड़े दर्शाये गये, जो सही नहीं है।

कृषि विभाग द्वारा फसल की क्रोप कटिंग की गई, जिसमें सोयाबीन की फसल में 60 से 90 प्रतिशत तक नुकसान होना पाया गया है। मगर अभी तक मुआवजा व बीमा क्लेम राशि नहीं मिली है व पिछले साल 2020-21 में भी फसल खराब हुई थी, उसके मुआवजे की राशि कई किसानों की अभी तक बाकी है। पटवारियों के किसानों के आंकड़े फीडिंग नहीं होने की वजह से छोटे किसानों को अभी तक मुआवजा की राशि नहीं मिल पाई है व रबी 2021-22 में भी शीतलहर व पाला गिरने से किसानों की फसल खराब हो गई। इसका भी मुआवजा व बीमा क्लेम राशि दिलवाया जाये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर)

नागौर के गोगेलाव औद्योगिक क्षेत्र में ई-ऑक्शन में आबंटित 38 भूखण्डों का निरस्तीकरण

महोदय

उपरोक्त विषय में सादर अनुरोध है कि शहर के पास गोगेलाव औद्योगिक क्षेत्र में ई ऑक्शन के जरिये 38 भूखण्डों का आबंटन बोली लगने के महज 10 दिन बाद ही बिना किसी सूचना के निरस्त करने का कार्य किया है जबकि इसमें बोली भी बेस प्राइस से ज्यादा की लगाई गयी थी। रीको उद्यमियों के निवेश का उत्प्रेरक था, जो अब निवेश के लिये सहायक के बजाय रीयल एस्टेट कम्पनी बनकर रह गयी है। नागौर के गोगेलाव में नव

विकसित औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें 425 भूखण्ड हैं जिनकी आरक्षित दर 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी, जिसमें से मात्र 75 भूखण्डों के लिए ही ई-बिड के लिए निविदा आमन्त्रित की गई। इनमें से 71 की बोली लगी व 4 भूखण्ड पर कोई बिड नही आई। 7 भूखण्ड पर सिंगल बिड आई जो आरक्षित दर से ज्यादा है। बाकी 64 भूखण्ड पर एक से ज्यादा लोगों ने बोली लगाई, जिसमें से सिर्फ 33 भूखण्ड ही आबंटित किये गये। बाकी इसलिये खारिज कर दिये क्योंकि प्रबन्धक के मन चाही दर नही आई, जो कि गैर वैधानिक है और औद्योगिक निवेश के विरुद्ध है। उसको लेकर क्षेत्र के उद्यमियों में भारी रोष व्याप्त है। एक तरफ तो सरकार निवेश को बढ़ावा देने को लेकर पिछले ही महीने में समिट आयोजन करती है तो अब आबंटित भूखण्डों को आपके ही अधिकारियों द्वारा निरस्त किया जाता है। इससे निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है जिसकी जांच सक्षम स्तर पर करवायी जाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें ताकि व्यवसायी क्षेत्र के लोग अपनी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिला सके।

अत: आपसे अनुरोध है कि प्रदेश के आम उद्यमी की भावनाओं को मध्यनजर रखते हुए इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना कार्य करके आबंटन रद्द करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये ताकि आगे से कोई इस तरह का कार्य नहीं कर पाये।

अत: महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि जनहित के उक्त महत्वपूर्ण विषय पर कार्यवाही करवाकर समस्या का निस्तारण कराये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर)

खानपुर में स्वीकृत सड़कों का निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पिछली सरकार द्वारा तीन वर्ष पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़कें स्वीकृत की गई थीं, उनका निर्माण बजट के अभाव में व संवेदक की लापरवाही से अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जो निम्न प्रकार है:-

खेडली हरिपुरा, खंडिया से गोविंदपुरा, पनवासा से डाबड़िया, हरीपुरा (रीछवा) गणेशपुरा (आगरिया) गोपालपुरा (रीजोन) सारोला रोड से पिपलाद,

सारोला कला से चापाखुर रोड 2 किमी करनवास से मालनवासा व साथ ही निम्न पुलियाओं की महती आवश्यकता है। खेरिया से पिपल्या नग्गा, देवरिया से बराना व मरायता इनकी स्वीकृति जारी की जाये, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा)

जीडीसी घग्घर नदी पर रावतसर से सूरतगढ़ रोड पर जर्जर पुलों का पुनर्निर्माण

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नहर वर्ष 1965 के लगभग बनी थी, अब नहर का पुनः लाइनिंग बेड का कार्य हुआ है व शेष बचा कार्य मार्च की बंदी के बाद होगा, परंतु इंदिरा गांधी नहर पुनर्निर्माण के कार्य में जो नहर पर पुल बने थे उनका किसी प्रकार पुनर्निर्माण या सुधार की व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि नहर जर्जर है। नहर के साथ पुल भी जर्जर हो चुके हैं। इस नहर पर किशनगढ़, हनुमानगढ़ मेगा हाईवे लखवाली में स्थित है। मेगा हाईवे का निर्माण हुए 10 साल हो गए, परंतु पुल बहुत पुराना है, क्षतिग्रस्त है। प्रतिदिन लोडिंग व अन्य छोटे-मोटे वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं। पुल की क्षमता से अधिक लोडेड वाहन गुजरते हैं। इसी प्रकार मोधूनगर के 84 आरडी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण 3 साल से बंद है। आमजन व काश्तकारों को मंडी में आने के लिए घूम कर आना पड़ता है। इसी के साथ जीडीसी घग्गर नदी पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त है। यह सड़क रावतसर से जाखडावाली सूरतगढ़ को जोड़ती है। यह रास्ता महत्वपूर्ण रास्ता है। स्यागावाली ढाणी 99 आरडी जो खिदासरी की तरफ रास्ता जाता है यह पुल भी क्षतिग्रस्त है। 108 आरडी खोड़ा का पुल भी क्षतिग्रस्त है।

श्रीमानजी, आपके माध्यम से निवेदन है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण काफी वर्षो पहले हुआ था। जब सरकार नहर को जर्जर मानकर उसका पुनर्निर्माण री-लाइनिंग कार्य करवा रही है। लखवाली आरडी 84, मोधूनगर आरडी 99, स्यागावाली ढाणी, आरडी 108 खोड़ा जीडीसी घग्गर नदी रावतसर से सूरतगढ़ रोड पर पुल महत्वपूर्ण रास्ते पर है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि वाहनों का आवागमन अधिक होने के कारण इन जर्जर पुलों पर कभी भी हादसा हो सकता है। मैं बार-बार सदन के माध्यम से सरकार को उपरोक्त जर्जर पुलों के पुनर्निर्माण के लिए मैं सदन से

मांग करता आ रहा हूं। उपरोक्त विषय काफी लोक महत्व का मामला है, इसलिए विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से कार्यवाही हेतु निवेदन कर रहा हूं।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द)

आसीन्द के स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसींद-हुरड़ा में मैंने 3 सीएचसी तथा 2 पीएचसी व 2 उप स्वास्थ्य केन्द्र की मांग की थी, जिसमें सिर्फ 1 सीएचसी अन्टाली की घोषणा आपने की, उसके लिए आपका आभार।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कंवलियास पीएचसी गुलाबपुरा से 25 किमी की दूरी पर है और 6 लेन एनएच-79 पर होने से वहां आये दिन एक्सीडेंट पैशेंट आते हैं और आसपास लगभग 60-70 गांव पड़ते हैं। दूसरी पीएचसी ब्रा. की सरेरी आसींद से 20 किमी तथा भीलवाड़ा से 35 किमी की दूरी पर है। यह भी एनएच 158 पर स्थित है। आये दिन एक्सीडेंट के केस आते रहते हैं तथा आसपास लगभग 100 से भी ज्यादा गांव ढाणी पड़ते हैं। बरसनी उप स्वास्थ्य केन्द्र है और पंचायत की आबादी लगभग 10 हजार की जनसंख्या है तथा आसपास में चिकित्सा का कोई साधन नहीं है। आसींद से 20 किमी व शम्भूगढ़ पीएचसी से 12 किमी की दूरी पर है। भादसी पंचायत जो कि अरावली की पहाड़ियों पर बसी हुई ग्राम पंचायत है, उसके आसपास भी पहाड़ पर बहुत सारे गांव बसे हुए हैं। वहां से बदनौर 15 किमी से भी ज्यादा दूरी पर है। मगरा बैल्ट होने के कारण वहां के हजारों लोगों को चिकित्सा की कोई उचित सुविधा नहीं मिल पाती है। इसलिए भादसी उप स्वास्थ्य केन्द्र को पीएचसी में क्रमोन्नत करने तथा झालरिया पंचायत का मरेवड़ा गांव जो कि आसींद तहसील का अंतिम बोर्डर का गांव है, वहां पर भी आस-पास कोई चिकित्सा सुविधा नहीं होने से मरेवड़ा व आस-पास के कई गांववालों को उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है।

अतः मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आसींद, हुरड़ा विधान सभा वासियों की इस वाजिब व उचित मांग को मानते हुए बिन्दु निम्न प्रकार है:-

1. कंवलियास पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत।

2. ब्राह्मणों की सरेरी पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत।

3. बरसनी उप स्वास्थ्य केन्द्र को पीएचसी में क्रमोन्नत।

4. भादसी उप स्वास्थ्य केन्द्र को पीएचसी में क्रमोन्नत।

एवं मरेवड़ा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कृपा करावें।

अर्जुन लाल जीनगर (कपासन)

चित्तौड़गढ़ में सैटलमेंट विभाग द्वारा तनाजा भूमियों के प्रकरणों का री-सर्वे

महोदय,

उपरोक्त विषय में राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि तनाजा भूमियों की समस्या के समाधान की ओर निम्न बिंदुओं पर ध्यान चाहूंगा:-

01. चितौड़गढ़ जिले में कुछ वर्षों पूर्व राजस्व के सैटलमेंट विभाग द्वारा सैटलमेंट किया गया था। सैटलमेंट विभाग द्वारा कई गांवों की जमीनों को ओवरलेप (तनाजा) करके दो गांवों में एक ही खातेदार की जमीनों को दर्शाया गया है जिससे किसानों को समस्याएं आ रही हैं।

02. ग्राम मेडीखेड़ा तथा ग्राम आजोलिया खेड़ा, तहसील-गंगरार, जिला-चित्तौड़गढ़ के 46 किसानों के खसरे दोनों गांव की सीमा पर दर्ज किये गये है। एक गांव में एक खसरा बिलानाम/चरागाह में दर्ज है तथा दूसरे गांव में वही खसरा नंबर खातेदार के नाम दर्ज करके ओवरलेप (तनाजा) घोषित किया गया है।

03. उक्त 46 खसरा नम्बरों में खातेदारों के नाम दर्ज जमीनों का भूमि रूपान्तरण नहीं किया जा रहा है जिससे किसान परेशान हैं तथा विकास कार्य बाधित हो रहे हैं।

मेरा उक्त सरकार से आग्रह है कि उक्त दोनों गांव में तनाजा भूमियों के प्रकरण की री-सर्वे करवाकर तनाजा हटाकर समस्या का समाधान करावें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन)

हस्तशिल्प कला को संरक्षण

महोदय,

पाली एवं गोड़वाड़ क्षेत्र हस्तशिल्प कला में आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। मध्यकालीन इतिहास से ज्ञात होता है कि पानी उत्तर-पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र था। इस तथ्य की पुष्टि कर्नल

जेम्स टॉड, मुंहतानैणसी इत्यादि इतिहासकारों के ग्रन्थों से मिलता है। उस वक्त पाली उत्तर भारत का प्रमुख "ग्रेट एम्पोरियम" शहर था जहां सुदूर क्षेत्र के उत्पादों का व्यापार होता था। पाली में अफगानिस्तान से घोड़ों और मेवों को व्यापार के लिए लाया जाता था। पाली के बाजार में ढाका के उच्च कोटि के कपड़े से लेकर अफ्रीकी हाथी दांत का क्रय-विक्रय एवं हाथी दाँत के चूड़ों का निर्माण कर रंगाई की जाती थी जो सुहागन के 16 श्रृंगारी में अहम श्रृंगार माना जाता था। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शिल्पग्रामों की स्थापना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

यह सभी लोकसंगीत व हस्तशिल्प कलाएं तेजी से विलुप्त हो रही हैं। शिल्पग्राम की स्थापना से इन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। गाड़ोलिया लौहार अपनी उत्कृष्ट धातु कला के लिये विख्यात हैं। पाली के बगड़ी नगर के कारीगरों के लकड़ी के वित्ताने मध्यकाल से विख्यात हैं। टैराकोटा की कलाकृतियों लकड़ी के विलौने, कांस्य धातु निर्मित मूर्ति कला आदि सामग्री पर बेजोड़ कारीगरी देखने को मिलती है। राजसमन्द जिले में मोलेला विश्वविख्यात टैराकोटा व मिट्टी के बर्तन उत्कृष्ट उत्पादों के लिये प्रसिद्ध हैं। सरकार को इन सब कलाओं को प्रोत्साहन देने के साथ लोकसंगीत को भी प्रोत्साहन देकर इन कलाकारों के उत्थान एवं प्रशिक्षण हेतु शिल्पग्रामों की स्थापना करनी चाहिये। इससे हमारी हस्त कला व लोकसंगीत को विश्व स्तर पर आगे बढ़ा-कर निर्यात कर सकते हैं। आजकल विश्व में हस्तशिल्प उत्पाद की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऑनलाइन बाजारों में भी ऐसे उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे कलाकारों को बढ़ावा देकर विश्व में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि राजस्थान प्रदेश के लुप्त होती हुई इस धरोहर को संरक्षण प्रदान कर आगे बढ़ाने का कार्य सरकार को प्रत्येक जिले में शिल्पग्राम स्थापित करके करना चाहिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना)

ग्राम पंचायतों में जनता जल योजना में एग्रीकल्चर उपयोग के नलकूपों का वाणिज्यिक कनेक्शनों में परिवर्तन

महोदय,

प्रदेश के कई गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी जनता जल योजना के माध्यम से निर्धारित कर रखी है

जो ग्राम पंचायतों के लिए अभिशाप है। मेरे क्षेत्र की कई पंचायतें तो पूरे वर्ष का बजट बिजली का बिल भरने में खर्च कर देते हैं। बहुत बड़ी विडम्बना है कि दोनों विभाग जलदाय और बिजली आपस में सामंजस्य नहीं रखने से पंचायतों पर लाखों रुपये का व्यय भार अतिरिक्त पड़ता है। इसका मात्र एक ही कारण है कि यह जो बिजली कनेक्शन नलकूपों पर दिये गए हैं, उनको वाणिज्यिक माना गया है, जबकि बिजली सप्लाई कृषि फीडरों से दी जाती है।

बिलिंग ऊर्जा विभाग द्वारा कामर्शियल उपयोग से की जा रही है जो नियम अनुसार गलत है। बिजली का बिल उपयोग के अनुसार साधारण श्रेणी से ही जारी होना चाहिए। सभी पंचायतों में जनता जल योजना के जो नलकूप चल रहे हैं वे एग्रीकल्चर उपयोग बिजली तंत्र से चल रहे हैं जबकि ऊर्जा विभाग लाखों रुपयों का बिल वर्षों से पंचायतों से वसूल रहे हैं।

मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि ग्राम पंचायतों से जनता जल योजना को वापस जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सुपुर्द की जावे अन्यथा जो गलत बिजली बिल जारी हो रहे हैं उनको सही करवाकर राहत प्रदान करावें।

सधन्यवाद।

श्री रोहित बोहरा (राजाखेड़ा)

तीर्थराज मचकुण्ड धाम (धौलपुर) को स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट में सम्मिलित करना

महोदय,

श्रीमान् जी, मैं आपका ध्यान धौलपुर स्थित तीर्थराज मचकुण्ड की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट विकसित किया जा रहा है जिसमें भगवान श्रीकृष्ण की लीला स्थलियों को जोड़ा जा रहा है जिसमें केन्द्र द्वारा 1000 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। श्रीमान् जी, धौलपुर में स्थित मचकुण्ड धाम को इस योजना में सम्मिलित किया जाये। धौलपुर मुख्यालय पर स्थित मचकुण्ड भी भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ा हुआ भाग है। मचकुण्ड धाम धौलपुर में भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी रणछोड़ लीला भी की थी, जब दैत्य कालयवन और भगवान श्रीकृष्ण के बीच युद्ध के समय भगवान श्रीकृष्ण निशस्त्र होकर रणक्षेत्र को छोड़कर भागे, तभी से भगवान श्रीकृष्ण का एक नाम रणछोड़ प्रसिद्ध हुआ। जिसके तहत कालयवन दैत्यवध को महाराज मुचुकुन्द के द्वारा सुनिश्चित कर इसी

मचकुण्ड धाम में महाराज मुचुकुन्द के साथ मिलकर यज्ञ सम्पन्न किया। तत्पश्चात् द्वारिका गमन किया और श्रीकृष्ण भगवान के अनेकों नामों में से एक नाम रणछोड़ इसी पुण्य धरा तक ही रहा। यही से भगवान श्रीकृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा है। तीर्थराज मचकुण्ड को सभी तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। तीर्थराज मचकुण्ड धाम मथुरा नगरी से लगभग 100 किमी की दूरी पर स्थित है और बृजक्षेत्र में भी आता है। इसलिए इस योजना में सम्मिलित किये जाने से यह पयर्टन स्थल के रूप में और भी विकसित होगा। पर्यटक स्थल बनने से देश-विदेश से सैलानियों के भ्रमण से यहां पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मेरा आपसे निवेदन है कि तीर्थराज मचकुण्ड जिला धौलपुर को स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट में सम्मिलित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर सम्मिलित करावें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़)

भोपालगढ़ की ग्राम पंचायत खांगटा में बांध एवं डायवर्जन चैनल का निर्माण कर बरसाती पानी का संरक्षण

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में अब सर्दी के मौसम में भी पानी की विकट समस्या है। आगामी गर्मियों में क्या हाल होगें, भगवान ही जाने। सरकार से अनुरोध है कि क्षेत्र में पेयजल संकट से बचाने के लिए जलप्रदाय योजनाओं को मंजूरी प्रदान करें। साथ ही मेरा एक सुझाव है कि ग्राम पंचायत खांगटा व चौकड़ी महादेव झरना स्थित पहाड़ी क्षेत्र हैं। यहां औसतन वर्षा अधिक होती है एवं इस क्षेत्र में बरसाती पानी की आवक बहुत ज्यादा है। यह पानी व्यर्थ में बह जाता है और भूमि कटाव कर खेतों को नुकसान पहुंचाता है। यदि इस क्षेत्र के बरसाती पानी का संरक्षण किया जाता है तो स्थानीय जन मांग अनुसार पेयजल के साथ ही कुछ गांवों में सिंचाई हेतु भी पानी उपलब्ध होने की प्रबल संभावना है। इस हेतु खांगटा स्थित बड़ा तालाब जिसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि यहां प्राकृतिक रूप से पानी इकट्ठा होता है। यदि इस क्षेत्र में एक बांध का निर्माण किया जाता है तो बरसाती पानी के संरक्षण से स्थानीय जनता को पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा और बांध के निर्माण से भूजल स्तर भी बढ़ेगा।

मेरा मुख्य मंत्री जी एवं जल संसाधन मंत्री जी से सदन के माध्यम से विशेष आग्रह है कि खांगटा में बाघ एवं डाईवर्जन चैनल जिसकी अनुमानित लागत 2 करोड़ होगी, का निर्माण करवाकर प्राकृतिक एवं बरसाती पानी का संरक्षण करने एवं स्थानीय जनता की पेयजल समस्या के समाधान हेतु शीघ्र निर्णय लेकर निर्माण हेतु बजट स्वीकृति जारी कर स्थानीय जनता को राहत प्रदान करावें। यह योजना क्षेत्र के विकास में मिल का पत्थर साबित होगी।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल)

घाटोल के हरो बांध की भराव क्षमता में वृद्धि

महोदय,

उपरोक्त विषय में मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल में हरो बांध में पानी की भराव क्षमता को बढ़ाकर 11 मीटर किया जावे। इसमें चौकड़ी, कांजी का घड़ा, गरनावट व घाटोल बोदला पाड़ा, हरों के किसानों की जमीन डूबने से उनकी फसल हर वर्ष खरीफ एवं रबी की दोनों फसलें खराब हो जाती हैं। माही विभाग की नहरें निकालने से पानी आने से हरो बांध का पानी का भराव क्षमता कम किया जावे।

अतः माननीय मंत्री महोदय से विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उपरोक्त विषय पर उचित कार्यवाही करवाई जाये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत)

सोजत के किसानों को फसल खराबे पर बीमा कम्पनियों द्वारा क्लेम के भुगतान में विलम्ब

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत के पश्चिमी क्षेत्र में फसल खराबे के बावजूद राजौला, धुरासनी, शिवपुरा, झूपेलाव, चाडवास, चौपड़ा, रूपावास, रेपडावास, धाकड़ी, धीनावास, सुरायता, गागुड़ा बीलावास ग्राम पंचायतों के किसानों को क्लेम नहीं मिल पा रहा है, जबकि बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों से बीमा राशि वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

महोदय, जब खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं तो किसान रोता है, उसके आंसू धरती पर गिरते हैं, लेकिन इन बीमा कंपनियों के आगे सब बेबस है। इन कंपनियों ने अपने अलग-अलग नियम-कायदे बना रखे हैं। मैं कई बार इस मुद्दे को सरकार व प्रशासन के सामने ला चुकी हूं, लेकिन समस्या जस की तस है।

मैं इस विधान सभा के मंच से कहती हूं कि अभी भी समय है। माननीय मंत्रीजी संबंधित अधिकारी या जिला कलेक्टर को निर्देशित करें, जिससे इस अन्याय रूपी गर्त में धकेले हुए किसानों को यथोचित क्लैम मिले। उनके घरों की रोशनी को मत छीनिये। आज के समय में भी यदि किसी किसान के साथ अत्याचार होता है तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराने की कृपा करें।

श्री अमर सिंह (बयाना)

बयाना में सिंचाई हेतु चम्बल लिफ्ट परियोजना से पानी की आपूर्ति

महोदय,

माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना का अधिकांश भाग पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है। वहां पर भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध बंध बारैठा है। बंध बारैठा बांध में पानी की कमी होने के कारण वहां से नहरों के माध्यम से सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी की आपूर्ति सम्भव नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि धौलपुर जिले की चंबल नदी से चंबल लिफ्ट योजना अन्तर्गत कार्ययोजना बनाकर बंध बारैठा में पानी की आपूर्ति की जावे और पूरे डांग क्षेत्र नहरीकरण के माध्यम से सिंचाई एवं आवारा पशुओं के लिए पीने के पानी के साथ-साथ क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था भी हो जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि चंबल लिफ्ट परियोजना से बंध बारैठा में पानी की आपूर्ति होने से इस बांध से नहरों के माध्यम से नदबई एवं वैर विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा भी लाभान्वित हो जायेगा। मैं और मेरे क्षेत्र की जनता सदा आपकी आभारी रहेगी।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर)

आशापुरा सिक्योरिटी गार्ड एवं भूतपूर्व सैनिक सोसायटी बाली (पाली) द्वारा डूंगरपुर हास्पिटल में कार्यरत संविदाकर्मियों का भुगतान नहीं करना

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कई वर्षों से डूंगरपुर सामान्य

हास्पिटल में संविदाकर्मी के रूप में कार्यरत हैं। इन सभी कार्मिकों का पिछले 2 माह का वेतन बकाया है जो कि आशापुरा सिक्योरिटी गार्ड एवं भूतपूर्व सैनिक सोसायटी, बाली जिला पाली (प्लेसमेंट एजेंसी) संस्था द्वारा नहीं दिया जा रहा है। संस्था प्रधान से वेतन की बात करने पर पद से हटाने की धमकी दी जाती है तथा कार्मिकों का आर्थिक एवं मानसिक शोषण किया जाता है। कार्मिकों द्वारा जानकारी जुटाने पर ज्ञात हुआ कि संविदा पर रखने वाली यह संस्था पूर्णतया फर्जी है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निविदा की शर्तों को पूरा नहीं करती है परन्तु अस्पताल के अधिकारियों के द्वारा कमीशन के एवज में अवैध रूप से टेंडर दिया गया है।

सभी संविदाकर्मी अल्पवेतनभोगी हैं। प्लेसमेंट एजन्सी द्वारा कार्मिकों के वेतन में से पीएफ के नाम पर अवैध कटौती की जाती है। अतः निवेदन है कि इस प्लेसमेंट एजेंसी के टेंडर को निरस्त कर सभी कार्मिकों को आरएमआरएस में समायोजित कराने की कृपा करावें तथा भविष्य में इस प्रकार की किसी भी प्लेसमेंट एजेन्सीज को अधिकृत नहीं करें जिससे कार्मिकों के अधिकारों का हनन न हो सके।

सादर।

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली)

1. विधान सभा क्षेत्र मावली में माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र मावली में महाविद्यालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़)

3. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के बाधनू में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन परीक्षा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में कृषि, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के दुलचासर में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज)

8. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के केलवाड़ा में स्नातकोत्तर महाविद्यालय क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के नाहरगढ़ में महाविद्यालय क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में केलवाड़ा में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के माध्यमिक विद्यालय में कृषि विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
12. विधान सभा क्षेत्र किशनंगज में फलदी एवं पीपल्दा माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा)

13. विधान सभा क्षेत्र नोखा के पांचू पंचायत समिति मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
14. विधान सभा क्षेत्र नोखा के मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय में स्नातक में भूगोल एवं गृह विज्ञान विषय प्रारम्भ करने तथा स्नातकोत्तर में स्वयंवित्त पोषित योजना (एसएफएस) में चल रहे रसायन शास्त्र एवं समाज शास्त्र को सरकार द्वारा पूर्णकालीन नियमित विषयों के रूप में सम्मिलित करने तथा राजनीति शास्त्र विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
15. तहसील मुख्यालय नोखा के राजकीय बाबा छोटूनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आउटडोर व इनडोर स्टेडियम बनाये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण)

16. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगरा (भजनगंज) को स्वयं का भवन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
17. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के संचालित माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान विकसित किये जाने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
18. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के कोठी अजमेर में स्ववित्त पोषित योजना (एसएफएस) के तहत चलाये जा रहे विषय को सरकार द्वारा पूर्णकालीन नियमित विषयों के रूप में घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
19. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के पांच उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर)

20. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्‌यालय, बाड़मेर में स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी विषय खोलने एवं राजकीय स्नातकोत्तर विद्‌यालय, बाड़मेर में विज्ञान स्नातकोत्तर एवं वनस्पति शास्त्र की शाखा खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्‌यालय एवं लगवा में कला संकाय, आदर्श माध्यमिक विद्‌यालय में विज्ञान संकाय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्‌यालय गांधी चौक बाड़मेर एवं महावार में कृषि संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में उच्च माध्यमिक विद्‌यालय महावीर नगर, बाड़मेर शहर में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के रूप में प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. राजकीय कन्या महाविद्‌यालय, बाड़मेर में स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान एवं कृषि विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता)

24. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के रियां बड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्‌यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्‌यालय, गोटन में विज्ञान संकाय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्‌यालय, लाम्बा जाटान में कला संकाय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के गांव भूरियासनी, करकवाल डूकिया व धनेरिया में माध्यमिक विद्‌यालय तथा गांव मोकलपुर में बालिका माध्यमिक विद्‌यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्‌यालय व कन्या महाविद्‌यालय में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय माध्यमिक विद्‌यालयों के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा)

29. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र भादरा में राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र भादरा के ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र भादरा में राजकीय महाविद्यालय के नाम का नामकरण शहीद भगत सिंह के नाम से करने के संबंध में विभागीय पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र भादरा के कलाना, कुजी एवं रामगढ़ में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय एवं जोगी वाला एवं डाबड़ी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा)

34. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के राजकीय कन्या महाविद्यालय, हेतमसर में विज्ञान संकाय व उर्दू संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद सरकार की जिम्मेदारी तय किये जाने तथा विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, चुड़ैला में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां)

36. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में माध्यमिक विद्यालय में भवन निर्माण एवं रिक्त पद भरे जाने के संबंध में तथा कन्या महाविद्यालय, तिवरी-मथानिया में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द)

37. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राज्यावास व रा.उ.मा.वि. पीपली आचार्यान में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजनगर में कक्षा नवीं व दसवीं में हिन्दी माध्यम प्रारम्भ करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के स्वर्गीय श्रीमती किरण माहेश्वरी कन्या महाविद्यालय, कुंवारिया में छात्राओं की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के स्वर्गीय श्रीमती किरण माहेश्वरी कन्या महाविद्यालय को सह-शिक्षा महाविद्यालय बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन)

41. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा कक्ष की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता के रिक्त पद भरने, बालिका महाविद्यालय खोलने तथा कालेज व्याख्याता के रिक्त पद पर भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर)

43. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के कुराबड़ पंचायत समिति में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. स्वामी विवेकानन्द राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कुराबड़ (उदयपुर) की घोषणा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर)

45. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में तखतगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतु भूमि आबंटन करवाने व भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राजकीय महाविद्यालय, सुमेरपुर में भवन निर्माण पूर्ण करवाये जाने व द्वितीय फेज हेतु आवश्यक राशि स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण)

47. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय एवं संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में

विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कक्षा कक्षों का निर्माण, प्रयोगशाला एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में ग्राम पंचायत मुख्यालयों से अधिक दूरी वाले राजस्व गांवों में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के नवीन परीक्षा केन्द्रों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैतारण में बजट घोषणा के उपरांत विज्ञान संकाय की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने एवं स्थानीय महाविद्यालय में प्रिंसिपल एवं प्रोफेसर सहित अन्य रिक्त पदों पर अतिशीघ्र नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर)

52. विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्रातीशीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मानपुरा माचेड़ी में विज्ञान संकाय एवं कला संकाय में अतिरिक्त विषय खुलवाये जाने, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांट में अतिरिक्त विज्ञान संकाय खोले जाने, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलौंची में विज्ञान संकाय में गणित विषय खोले जाने तथा जालसू के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में कक्षा-कक्षों के निर्माण, प्रयोगशालाओं एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55 विधान सभा क्षेत्र आमेर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं से अधिक शुल्क एवं मनमानी फीस वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर)

57. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में जर्जर पड़े मध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनों की मरम्मत व नये कक्षा-कक्षों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में राजकीय महाविद्यालय में सभी संकायों में सीटें बढ़ाने, रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता तथा निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा मनमानी राशि वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के संबंध में।

60. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था तथा शौचालयों के निर्माण के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर)

62. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के राजकीय शहीद मुकुट बिहारी महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़)

63. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की तहसील आंधी में कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के राजकीय सैकण्डरी स्कूलों को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा)

65. विधान सभा क्षेत्र महुवा में देवनारायण महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र महुवा के तहसील बैजूपाड़ा में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र महुवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गढहिक्य सिंह, हडिया, सालिमपुर, गहनौली, समलेरी व बालाहेडा में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास)

68. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा)

71. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के एमबीआर कालेज, डीआरजे कन्या महाविद्यालय एवं कल्याणपुरा महाविद्यालय में खेलकूद हेतु विभिन्न खेलों के मैदानों के निर्माण एवं खेल सामग्री उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में बालोतरा के बालक/बालिका एवं कल्याणपुरा के महाविद्यालयों में सभी श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के एमबीआर कालेज एवं डीआरजे कन्या महाविद्यालय में नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर के अपर्याप्त भवन वाले विद्यालयों में मानदण्ड अनुसार भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य सभी श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर)

76. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की बकानी तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के ब्लाक खानपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नागौनिया को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के ब्लाक खानपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली)

79. राजकीय महाविद्यालय, मावली में स्नातकोत्तर में कला वर्ग एवं स्नातक में वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग कक्षाओं की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र मावली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, कला व भूगोल के संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र मावली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूण्डावत खेडी, कलबास, वाजमिया व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वांगरोही (मावली) को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)

82. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजकीय माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में भूमिविहीन विद्यालयों के लिए भूमि आबंटन कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अन्य स्थानों पर करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के आलीसर, कालाडेरा, सामोद, धोबलाई आदि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धोरागुढा में कला संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़)

86. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान के निर्माण हेतु विभागीय पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में आवश्यकतानुसार कक्षा-कक्ष निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लैबोरेट्री (प्रयोगशाला) स्थापित किये जाने तथा कक्षा-कक्ष निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. जिला झुंझुनूं के बुहाना में बालिका महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर)

91. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं के.एन. बालिका महाविद्यालय, जोधपुर में संगीत शिक्षण हेतु मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. राजकीय कन्या महाविद्यालय, सूरसागर एवं राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर में संगीत एवं ललित कला संकाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिवांची गेट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अल्पभाषा राजमहल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलदेव नगर एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याशाला में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोतवाली को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. प्रदेश के सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिये प्रयोगशालाओं का नियमित उपयोग अनिवार्य करने की कार्ययोजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़)

96. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के महाविद्‌यालय, भोपालगढ़ में शिक्षकों के पदों को भरने तथा महाविद्‌यालय, बावड़ी का भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा)

97. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के प्रताप सिंह बारहठ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्‌यालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा) में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्‌यालयों में शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय बालिका उच्च महाविद्‌यालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा) के जीर्ण-शीर्ण भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के राजकीय माध्यमिक व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्‌यालय में विज्ञान प्रयोगशाला खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय महाविद्‌यालय, बनेड़ा में नये संकाय खोले जाने एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा)

102. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के माध्यमिक विद्‌यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के माध्यमिक विद्‌यालयों में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

104. छबड़ा-छीपा बड़ौद जिला बारां के राजकीय महाविद्‌यालय के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन)

105. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के लाखेरी उपखण्ड स्तर पर राजकीय महाविद्‌यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के इन्दरगढ़ कस्बे में राजकीय महिला महाविद्‌यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़)

107. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के गुरूशरण छाबड़ा महाविद्यालय की क्षतिग्रस्त चारदीवारी का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के गुरूशरण छाबड़ा महाविद्यालय में नये विषय एवं संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में स्थित राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में नये कक्षा-कक्ष निर्माण एवं क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन)

110. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन के देवली उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण पूर्व विधायक स्व. खंगार सिंह जी के नाम पर किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम चेलाबान, (ग्राम पंचायत गादाना) निचली निम्बड़ी ग्राम पंचायत बोरीमादा कारवाड़ा, ग्राम पंचायत चगोड़ा, राजोला खुर्द, ग्राम पंचायत बोदनड़ी माला जी गुड़ा, ग्राम पंचायत गजनीपुरा, डायलाना खुर्द एवं ग्राम पंचायत डायलानाकलां में पेंवी कल्ला तथा ग्राम पंचायत पनोवना के उच्च माध्यमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की मरम्मत एवं चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर)

113. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम बुडतरा, बोकड़ा, बिजली, पलसिया खुर्द, रसियाबाग खुर्द के विद्यालय को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़)

114. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब के लिए एमएलए लैड से बजट स्वीकृत होने के बाद भी आईसीटी लैब की स्थापना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना व अनूपगढ़ में कन्या महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं (शौचालय, चारदीवारी व खेल मैदान) नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के संबंध में।

117. अनूपगढ़ के सेठ बिहारी लाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़)

118. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, दलीर, अरनोड में विज्ञान, वाणिज्य, कृषि संकाय खोलना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कूणी में विज्ञान संकाय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डाबड़ा में आर्ट (कला) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कूणी में विज्ञान एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निमड़ी में वाणिज्य संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

119. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में स्ववितपोषित संकाय को सरकार द्वारा वित्त पोषित करने व आवश्यक संकाय खोलने एवं नये महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने तथा आमाड उपखण्ड, भचुण्डला में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़)

120. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के श्यामपुरा प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने तथा क्षेत्र जखराना, माजरी, मांढण, काठूवास पहाड़ी के माध्यमिक विद्यालयों में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खूंदरोट, मांढण, तलवाड़ में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग)

122. विधान सभा क्षेत्र डग के महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण)

123. विधान सभा क्षेत्र कोटा के राजकीय महाविद्यालय के मूल भवन में कला संकाय का कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर)

124. प्रदेश के ग्राम पंचायत मुख्यालय के अलावा बड़े गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर)

125. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की करीब 30 राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 105 कक्षा-कक्ष, 10 विद्यालयों में चारदिवारी व शौचालय निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों, भावरी, खैरवा, पावा, खिवान्दी, डेन्डा, खौड, लोवी, तख्तगढ़, बसंत, साण्डेराव, किश्वा में विज्ञान विषय, चाणोद बालिका में गृह विज्ञान, चाणोद बालक में जीव विज्ञान, तख्तगढ़ में जीवन विज्ञान, चाणैद बालक तथा तखतगढ़ में गणित व कृषि विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमित्रा देवी पन्नालाल जी चैरीटेबल ट्रस्ट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुजाना को अंग्रेजी माध्यम घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा)

128. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, इटावा में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

129. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, इटावा में विज्ञान एवं कृषि संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. कोटा जिले के महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं सुल्तानपुर व इटावा के माध्यमिक विद्यालय में भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करवाने में विभागीय विफलता के संबंध में चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ढीपरी एवं जाखजेंदा सहित विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी)

132. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में माध्यमिक विद्यालयों में

अतिरिक्त कक्षा-कक्ष एवं पुस्तकालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में महाविद्यालय, बस्सी को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने तथा विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़)

135. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में भवन विहीन राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत)

137. विधान सभा क्षेत्र सोजत के माध्यमिक विद्यालय में कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर)

138. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर सराड़ा, सेमारी, झल्लारा तहसीलों में माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान का निर्माण करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर)

139. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के गिगला बालिका विद्यालय को उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सभी माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर सराड़ा सेमारी, झल्लारा माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़)

143. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों के निर्माण एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में बजट घोषणा 2020-21 में विभिन्न स्कूलों में नवीन संकाय खोलने के उपरांत भी संबंधित विषयों के अध्यापकों का पदस्थापन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय महाविद्यालय, अराई में विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं की नियुक्ति एवं राजकीय आर.के. पाटनी महाविद्यालय, किशनगढ़ में प्राचार्य एवं अन्य व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की गुजरवाड़ा (अराई) डांग, भामोलाव बालिका, भगवंतपुरा (अराई) वार्ड नं. 17 किशनगढ़ कुचील बालिका, फलौदा, (सिलौरा) नोहरिया (सिलौरा) राजकीय लूणकाण बाहेती किशनगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिरोज में विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोराड़ा में विज्ञान, सार्दुल स्कूल किशनगढ़ में चित्रकला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिलोनिया में कला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरपा में जीव विज्ञान एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हरमाड़ा में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग)

148. ग्राम पंचायत स्तर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र डग के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र डग के उमरिया, जेलाखेड़ी, सखर, पिपलीया कला एवं सरकनीया के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)

151. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के जर्जर माध्यमिक विद्यालय के भवनों का जीर्णोद्धार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के माध्यमिक विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण व व्याख्याताओं के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना)

156. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना की सभी ग्राम पंचायत स्तर पर राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के जावर में रिक्त राजकीय उच्च बालिका प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के बुधवाड़ा में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा)

160. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरैना में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल स्थित बालिका उच्च

माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित करने पर तथा नवीन हिन्दी माध्यम सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभर एवं फुलेरा के राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में फर्नीचर, लैब एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में नवीन संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत)

165. विधान सभा क्षेत्र सोजत में माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र सोजत में खेल मैदान बनाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष)

167. शिक्षा विभाग के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में लम्बे समय से विभिन्न श्रेणी के पदों की भर्ती समय पर नहीं होने से शिक्षा के स्तर में हो रही गिरावट के संबंध में चर्चा के लिये।

168. मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति के पद पर शैक्षणिक एवं अनुभव पूर्ण नहीं होने के पश्चात् भी नियुक्ति दिये जाने तथा कुलपति द्वारा वित्तीय अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना)

169. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने एवं नवीन माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी)

171. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों के संकाय खोलने के उपरांत भी अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करने एवं थानागाजी के गांवों में माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन)

172. विधान सभा क्षेत्र कपासन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

173. राजकीय महाविद्यालय, कपासन एवं मण्डफिया में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र कपासन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जर्जर कक्षा-कक्षों की मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

175. विधान सभा क्षेत्र चूरू के माध्यमिक विद्यालयों की चारदीवारी व खेल मैदान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र चूरू में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास व साइंस लैब नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

177. चूरू के राजकीय महाविद्यालय में परेड ट्रैक बनवाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र चूरू के राजकीय महाविद्यालय में शौचालयों की बदहाल स्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

179. चूरू के राजकीय महाविद्यालयों में विषय विशेषज्ञों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़)

180. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के मांढण में कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में नये संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़)

183. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के बस्सी और बदेसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर)

184. प्रदेश के विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव कराये जाने के संबध में विभागीय पहल कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति व नये भवन व कक्ष निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित राजकीय कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों के स्थान पर अन्य राजनीतिक व्यक्तियों को बुलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर स्थित राजकीय विद्यालयों में शौचालयों की बदहाल स्थिति एवं पुरुष व महिला शौचालय अलग-अलग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में कालेज भवन निर्माण व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द)

189. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के हुरड़ा के आठवीं तक के विद्यालयों को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के संबध में चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के हुरड़ा तहसील में आठवीं तक के विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण)

191. कोटा के वाणिज्य/कला/विज्ञान एवं अन्य राजकीय कालेजों में विद्यार्थियों के लिए कैंटीन/एटीएम/इंडोर गेम्स आदि सुविधाओं का विस्तार के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. कोटा के नान्ता महल स्थित भूमि विहीन राजकीय माध्यमिक विद्यालय को भूमि आबंटित एवं भवन निर्माण करवाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर)

193. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में ब्लाक मूण्डवा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनाना में बोर्ड परीक्षा का केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में जर्जर माध्यमिक विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं नये भवनों हेतु बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ब्लाक मूण्डवा में स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

197. नागौर जिले के खींवसर मुख्यालय पर स्थित राजकीय कालेज को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर)

198. विधान सभा क्षेत्र आहोर में भाद्राजून चादराई, हरगी में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र आहोर में बागरा, हरगी में स्थित बालिका विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी)

200. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की 2 ग्राम पंचायत रास्तापाल व नागरिया पचैला में बालिका माध्यमिक विद्यालय व छात्रावास खोलने के संबध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

202. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के सभी माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत बारापाल में हिन्दी माध्यमिक विद्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जिन माध्यमिक विद्यालय में चारदीवारी नहीं है, उनमें चारदीवारी बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर)

205. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन्दुन्दा (जहाजपुर) में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्र स्वीकृत करने संबंधी आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लुहारीकलां एवं सरसिना में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गडबोडिया एवं आगरिया कोटडी विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने संबंधी आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, धोड में नवीन बालिका महाविद्यालय खोलने तथा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरसिया को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल)

209. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के उपखण्ड पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पीपलखूंट क्षेत्र की धरतीपुरा में उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा-कक्ष निर्माण तथा पीपलखूंट महाविद्यालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर)

212. विधान सभा क्षेत्र नोहर में नवसृजित तहसील पल्लू में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र नोहर की वंचित ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र नोहर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. विधान सभा क्षेत्र नोहर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र नोहर के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिये रिक्त पड़ी भूमि को आबंटन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

217. राजकीय महाविद्यालय, फागी में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. प्रदेश के डी.डी.पी. ब्लाकों में महिला महाविद्यालय खोलने तथा राजकीय महाविद्यालय, दूदू को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. प्रदेश में विगत वर्षों में बन्द किये गये माध्यमिक विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर)

220. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर तथा हिन्दुमल कोट में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देने तथा राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर)

222. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालोतरा, दत्ताणी, सिरोडी, निमतलाई, पीथापुरा एम, माटासन, बांट, कोटडा, जैतावाडा, हाथल-सेलवाडा, अनापुर-हरणी, अमरापुरा, वडवज रायपुर, राजगढ-लूणोल, गोरेली-मरावल, वासडा तथा जैतावाडा को माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. सिरोही जिले की राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर)

224. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के माध्यमिक विद्यालयों में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर)

226. विधान सभा क्षेत्र नगर के राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़)

227. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के नौगावां उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के वडोदा मेव में कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. कला कालेज, अलवर में उर्दू विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. अलवर जिले में मेवात आवासीय बालिका विद्यालयों को दसवीं तक क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. रामगढ़ (अलवर) महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा)

232. विधान सभा क्षेत्र सहाडा के कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापुर का भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र सहाडा के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार)

234. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के समसा योजनान्तर्गत माध्यमिक विद्यालय भवनों के निर्माण में अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष एवं भवनों के निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर)

236. प्रदेश के निजी माध्यमिक विद्यालयों की मनमानी फीस वसूली आदि रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

237. प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये जाने हेतु नियामक आयोग गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. प्रदेश में अनेक राजकीय महाविद्यालयों के भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

240. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापकों के अधिकांश पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद)

241. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, शिवपुरा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

242. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अखैपुरा (पीसांगन) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, समरथपुरा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के उपखण्ड मुख्यालय पीसांगन पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

245. बाड़मेर जिले के सीमावर्ती माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा)

246. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा को भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा में आचार्य/सह-आचार्य एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा के कक्षा-कक्षों की कमी वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय जसवंतपुरा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर)

251. अलवर जिले के कठूमर में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेड़ा कल्याणपुर व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जखाड़ा में विज्ञान संकाय है। अत: इनमें से एक में विज्ञान वर्ग हटाकर कला संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के माध्यमिक विद्यालयों में नवीन भवन एवं कमरे बनाने हेतु ज्यादा से ज्यादा बजट स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कुटटीन सावदास, इन्द्र कालोनी, मंगोलाकी, रामपुरा पाटन, नागल रूपा आदि नई ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, इमलाडी, इरनिया, खेरली सूनिया, डयोपना को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जावली में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)

256. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम बादड़िया के उच्च माध्यमिक विद्यालय में समस्त रिक्त पदों को भरने की आवश्यक्ता पर चर्चा के लिये।

258. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में आर.टी.ई. के तहत माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

259. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में समसा के अंतर्गत 10वीं और 12वीं के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी)

260. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नयाखेड़ा (केवलपुरा) को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

261. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नालवा (नकोर) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निकुम्भ में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

263. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चिकारड़ा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

264. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, मंगलवाड़ को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन)

265. प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में भारत एकीकरण, भारत निर्माण में योगदान करने वाले महापुरूषों के जीवनवृत को जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर)

266. अजमेर की एमडीएस विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

267. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर सहित प्रदेश के सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

268. अजमेर जिले सहित सम्पूर्ण प्रदेश में जर्जर माध्यमिक विद्यालय भवनों के स्थान पर पुन: नये भवनों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

269. माध्यमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति के प्रावधान को प्रदेश में सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू)

270. विधान सभा क्षेत्र बारां में स्वीकृत नवीन कन्या महाविद्यालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

271. विधान सभा क्षेत्र बारां के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बमूलिया, तहसील बारां को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

272. विधान सभा क्षेत्र बारां के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खेड़ली बारूला, तहसील अटरू को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

273. विधान सभा क्षेत्र बारां के राजकीय महाविद्यालय में नवीन संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर)

274. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में श्रीबिजयनगर उपखण्ड पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

275. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की श्रीबिजयनगर तहसील के गांव डाबला में माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

276. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में शहीद भगत सिंह कालेज के सरकारीकरण की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी करायी जाकर प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के गांव 14 बीजीडी तथा गांव 17 एपीडी के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी)

278. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में उच्च प्राथमिक विद्यालय, खखेड़ा गाम पंचायत बिलोदा, पंचायत समिति अरथुना को माध्यमिक में, माध्यमिक विद्यालय, चिकनपाडा, ग्राम पंचायत मण्डेला पाडा, पंचायत समिति अरधुना, पंचायत हेडक्वार्टर को माध्यमिक विद्यालय, बाका, ग्राम पंचायत अरनीया, पंचायत समिति तलवाड़ा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय, माजीया, ग्राम पंचायत नाहली, पंचायत समिति अरथुना को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

279. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत)

280. विधान सभा क्षेत्र सोजत में कक्षा-कक्ष व पेयजल की सुविधा से वंचित माध्यमिक विद्यालयों में उक्त सुविधाएं सुनिश्चित किये जाने पर चर्चा के लिये।

281. विधान सभा क्षेत्र सोजत में कालेज की चारदीवारी के निर्माण तथा पुस्तकालय की सुविधा सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़)

282. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर)

283. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में कालेज खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

284. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ओडा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

285. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के ग्राम जोगीवाड़ा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू)

286. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के ग्राम पंचायत अथारी में काटल के राजकीय उच्च प्राथमिक को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

287. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में बालिका विद्यालय, झाडोली नादिया अजारी को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

288. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू की नवगठित ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

289. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा-कक्ष, चारदीवारी व शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

290. विधान सभा क्षेत्र शिव के गडरा रोड व शिव के कालेज के भवनों के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

291. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति गडरा रोड में माध्यमिक विद्यालय, देतानी, खानीथानी, राटांसर-शहदाद, कामार व पंचायत समिति रामसर में राजनकापर बीन्देकापार अयेकावार में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

292. जिला बाड़मेर की पंचायत समिति गडरा रोड, रामसर व चौहटन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर)

293. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुंदरपुरा, बंधमुजफर, नीलका व फतेहसिंहवाला को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

294. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

भामरू, बड़नगर, बागावास अहीरान, गोविन्दपुरा धाभाई व बाड़ीजोड़ी में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

295. राजकीय महाविद्यालय, विराटनगर को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने के लिए एवं विज्ञान व वाणिज्य विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना)

296. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम पंचायत मुख्यालय पादरू (सिवाना) में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

297. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

298. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर (पी.जी.) में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

299. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के राजकीय महाविद्यालय, सिवाना, समदडी एवं सिणधरी में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

300. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिवाना, पादरू, सिकरे व चाडों की ढाणी में विज्ञान संकाय, इन्द्राणा में कृषि विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी)

301. जय नारायण मोहन लाल पुरोहित राजकीय माध्यमिक विद्यालय, फलौदी में विभिन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में चर्चा के लिये।

302. पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय, बाप के भवन निर्माण के लिये बजट राशि जारी किये जाने के पश्चात् भी भवन निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

303. पूर्ववर्ती सरकार द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शुरू किये गये स्टाफिंग पैटर्न (छात्र संख्या अनुसार पदों की संख्या) को पूर्ण रूप से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना)

304. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों के

निर्माण तथा राजकीय महाविद्यालय, डेगाना में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़)

305. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदानों को अतिक्रमण मुक्त करवाकर उनका विकास करवाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

306. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की पूर्ति करने एवं जर्जर विद्यालयों की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

307. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

308. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के चारदीवारी विहीन माध्यमिक विद्यालयों की चारदिवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी)

309. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झोथरी का नामकरण स्वतंत्रता सैनानी शिवराम रोत व राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भीलवा पचैला का नामकरण स्वतंत्रता सैनानी सैगा भाई रोत के नाम से करने के संबंध में चर्चा के लिये।

310. राजकीय भोगीलाल पण्ड्या महाविद्यालय, डूंगरपुर में विज्ञान संकाय के रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

311. गोविन्द गुरू विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में कम्प्यूटर शिक्षा के लिये एमसीए संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद)

312. माध्यमिक विद्यालय के दुराचरण वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

313. बच्चों में अनुशासन की भावना पैदा करने हेतु एनसीसी. का माध्यमिक विद्यालय में विस्तार करने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

314. शिक्षा के साथ विद्यालयों में खेल पर ध्यान देने की आवश्यकता हेतु

सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के स्वीकृत पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

315. माध्यमिक शिक्षा की मोनिटरिंग करने हेतु उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी को जिम्मेदारी देकर प्रति माह नियमित जिला कलक्टर द्वारा समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा)

316. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में स्नातकोत्तर महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

317. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाबा की बार में कृषि संकाय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

318. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के गलियाकोट ब्लाक में कन्या महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी)

319. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सैपऊ में महिला महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

320. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बंद किये गये माध्यमिक विद्यालयों को पुन: संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

321. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में नवीन पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

322. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा में उर्दू विषय संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन)

323. माध्यमिक शिक्षा में प्रतिनियुक्तियों पर रोक लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

324. महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा)

325. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल व शौचालय की स्थायी व्यवस्था करने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

326. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के राजकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

327. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में एकीकरण से बन्द माध्यमिक विद्यालयों को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

328. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर)

329. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में महात्मा गांधी माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर)

330. विधान सभा क्षेत्र जालोर में संचालित समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की सुविधा हेतु उचित स्थान पर सेनेटरी पैड वितरण एवं निष्पादन मशीनें लगाये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

331. विधान सभा क्षेत्र जालोर में संचालित समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

332. जालोर जिले में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

333. जालोर जिले के उपखण्ड मुख्यालय सायला में नवीन राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर)

334. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के नापासर कस्बे में कन्या महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

335. राजकीय महाविद्यालय, लूणकरणसर की चारदीवारी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

336. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राणीसर (ग्राम पंचायत शेरेरा) के नव स्वीकृत माध्यमिक विद्यालय के लिये आवंटित भूमि पर कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

337. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के मौलानिया, कतरियासर, जामसर, जलालसर, रावासर, नकीदेसर, आडसर, राजासर उर्फ करणीसर, साबनीया, शेरपुरा, भीखनेरा, खींसेरा में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

338. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राणीसर (ग्राम पंचायत रामबाग) गैरसर, जगदेवाला उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़)

339. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में संचालित राजकीय जालान महाविद्यालय, रतनगढ़ में स्नातक में एसएफएस में चल रहे भूगोल को राजकीय विषय घोषित करना एवं स्नातकोत्तर में अंग्रेजी, हिन्दी एवं संस्कृत विषय स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

340. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में संचालित राजकीय कन्या महाविद्यालय, रतनगढ़ में रिक्त पदों को भरने, स्नातक में इतिहास व भूगोल एवं स्नातकोत्तर में संस्कृत विषय स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

341. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पडिहारा में विज्ञान संकाय व रतनगढ, राजलदेसर, छापर एवं पडिहारा में नवीन राजकीय माध्यमिक विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

342. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में संचालित जेगनियां बीकान, भोजलाई, जोरावरपुरा, कुहाडिया, छाबडी मीठी, छाबडी खारी, बालिका विद्यालय, चाडवास व ढढेरू एवं भामूवान के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्न्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा)

343. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के सभी राजकीय महाविद्यालयों तथा

राजकीय उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों के सभी श्रेणी के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

344. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के मालपुरा शहर में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

345. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण व जर्जर भवनों की मरम्मत करवाने तथा फर्नीचर उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

346. राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा के जर्जर व क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत, चारदीवारी निर्माण करवाने तथा महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।